



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2019/फाल्गुन 23, 1940

No. 88]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2019/ PHALGUNA 23, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2019

अंतिम जांच परिणाम

विषय : टर्की और रूस के मूल के अथवा वहां के निर्यातित 'सोडा एश' के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 7/4/2018-डी जी ए डी.—1. जबकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां प्राधिकारी कहा गया है) ने टर्की और रूस (जिसे यहां संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडा एश" (जिसे यहां संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद अथवा डिसोडियम कार्बोनेट कहा गया है) के आयातों पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने की सिफारिश करते हुए दिनांक 9 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या 14/3/2011 – डी जी ए डी के अनुसार अंतिम जांच परिणाम जारी किए। तदनुसार, केंद्रीय सरकार की अधिसूचना संख्या 08/2013 – सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के अनुसार निर्णायक पाटनरोधी शुल्क लागू किए गए।

- और जबकि, प्राधिकारी ने नियम 23 के अंतर्गत एक मध्यवर्ती समीक्षा जांच आयोजित की और प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर लागू किए गए पाटनरोधी शुल्कों को दिनांक 22 जुलाई, 2017 के अंतिम जांच परिणामों के अनुसार रद्द कर दिया।
- और जबकि, दिनांक 22 जुलाई, 2017 के अंतिम जांच परिणामों को 2017 के विशेष सिविल आवेदनों संख्या 14203, 14205 और 14207 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय ने दिनांक 31 जुलाई, 2017 के अपने आदेशानुसार भारतीय संघ सरकार को दिनांक 22.07.2017 के एम टी आर अंतिम जांच परिणामों पर कार्रवाई करने से रोक दिया।

4. और जबकि, केंद्रीय सरकार ने दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना सं. 51/2017 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के अनुसार दिनांक 18 अप्रैल, 2013 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 08/2013 – सीमा शुल्क (ए डी डी) को रद्द कर दिया और कहा कि ऐसी मंदी 2017 के विशेष सिविल आवेदनों संख्या 14203, 14205 और 14207 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अध्यक्षीन आस्थगित बनी रहेगी।
5. और जबकि, मै. निरमा लिमि. और मै. डी सी डब्ल्यू लिमि. (जिन्हें यहां “याचिकाकर्ता” कहा गया है) ने अधिनियम और नियमों के अनुसरण में, टर्की और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए, और पांच वर्षों की अवधि के लिए शुल्कों का विस्तार करने हेतु “सोडा एश” के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा को आरंभ करने की मांग करते हुए एक संयुक्त याचिका दायर की थी।
6. और जबकि, घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका की जांच के आधार पर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि टर्की और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा एश के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा आरंभ किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और तदनुसार, निर्णायक समीक्षा याचिका पर प्राधिकारी के निर्णय से सूचित करते हुए दिनांक 5 अप्रैल, 2018 को अनुरूप आदेश (स्पीकिंग आर्डर) जारी किया गया।
7. और जबकि, उक्त अनुरूप आदेश के विरुद्ध, घरेलू उद्योग ने अहमदाबाद में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की विशेष सिविल आवेदन संख्या 5798 और 2018 की 5808 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त दिनांक 12.04.2018 के निर्देशों के उद्धरण यहां नीचे दिये गये हैं :

“इस याचिका की स्वीकृति और अंतिम सुनवाई को लंबित रखते हुए, यह माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 16.04.2018 को अथवा उससे पहले नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के दूसरे परंतुक के तहत निर्णायक समीक्षा आरंभ करने के लिए निर्देश देता है और इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी संख्या 1 को मूल अधिसूचना के समाप्त होने की अवधि अर्थात् 17.04.2018 को अथवा उससे पहले निर्णायक समीक्षा के निष्कर्ष को लंबित रखते हुए अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 18.04.2013 की सीमा शुल्क अधिसूचना के द्वारा लगाये गए शुल्क के विस्तार/ जारी रखने के लिए अधिसूचना की धारा 9क (5) के दूसरे प्रावधान की शर्तों में एक उचित अधिसूचना को जारी करने के निर्देश देता है।”

8. माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के ऊपर बताए गए आदेशों के अनुसरण में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना एफ सं. 7/4/2018 - डी जी ए डी दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के अनुसार पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ संशोधन अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसरण में वर्तमान निर्णायक समीक्षा आरंभ की।
9. तथापि, वर्तमान निर्णायक समीक्षा विशेष सिविल आवेदन संख्या 2018 की 5798 और 2018 की 5808 और 2017 की विशेष सिविल आवेदन 14203, 14205 और 14207 में निष्कर्ष के अध्यक्षीन थी, जो सभी माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थीं।
10. माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने 11.06.2018 के आदेश के अनुसार मध्यवर्ती समीक्षा में स्वीकृत अंतिम जांच परिणामों को अलग रखा और तदनुसार टर्की और रूस से सोडा एश के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्कों को 5 वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की। तदनुसार, वर्तमान निर्णायक समीक्षा किसी कानूनी अशक्तता का सामना नहीं करती।

ख. प्रक्रिया

11. जांच के संबंध में नीचे वर्णित कार्य प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :
 - i. प्राधिकारी ने दिनांक 16 अप्रैल, 2018 की जांच शुरुआत अधिसूचना की प्रतियां भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों, उपलब्ध सूचना के अनुसार ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उत्पादकों को भेजीं। ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से प्रश्नावली के उत्तर दायर करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया।
 - ii. निर्यातकों को भेजे गए पत्रों और प्रश्नावलियों की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों की सूची के साथ संबद्ध देशों के दूतावासों को संबद्ध देशों से निर्यातकों/ उत्पादकों को निर्धारित समय के भीतर प्रत्युत्तर भेजने की सलाह देने के अनुरोध के साथ प्रेषित की गई।

- iii. आवेदकों की ओर से दायर आवेदन की अगोपनीय प्रतियां ज्ञात निर्यातकों, घरेलू उत्पादकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को ए डी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसरण में भेजी गई।
- iv. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्णायक समीक्षा आरंभ करते हुए पब्लिक नोटिस की प्रति अग्रेषित की और उन्हें नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसरण में पत्र के जारी किए जाने की तारीख से 40 दिन के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया :

सोडा सनाई ए. एस. टर्की टर्की सिसे वी कैम फैब्रिकलारी ए. एस. आई एस कुलेलेरी, कुले - 334330 4, लिवेंट इस्तांबुल टर्की
ई टी आई सोडा, सिनेर ग्रुप, पसालीमणि कैड नं. 4, उस्कुडर 34674, इस्तांबुल टर्की
एस ए एस एस सोडा एश सेल्स एंड सर्विसेज, एम. टोलमाचीवेस्की पर. 10 आफिस 7, 8 119017 मास्को रूस
जे एस सी बशकीरिएन कैमिस्ट्री 8, बी पोलूयारोस्लावीसी पेरेयूलोक, मास्को, 105 120, रूस

- v. संबद्ध जांच की शुरुआत की प्रतिक्रिया में, टर्की और रूस से निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर कर प्रयुत्तर दिया है और अनुरोध किए हैं:
- सोडा सनाई ए. एस. टर्की
 - मै. ट्रेड हाउस लिमि. (बशकीरियन कैमिस्ट्री), रूसी संघ
 - मै. ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी "बेरेजिनकी सोडा वर्क्स", रूसी संघ
 - मै. पब्लिक स्टॉक कंपनी, क्रीमिया सोडा प्लांट, क्रीमिया संघ, रूसी संघ
- vi. ए. डी. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसरण में आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी गई :

गुजरात गुआरडियन लिमि., ग्राम - कोंध, वालिया रोड, प्लांट स्टेट हाइवे सं. 13, अंकलेश्वर, भरुच - 393001
फ्लोट ग्लास इण्डिया लिमि., टी-7, एम आई डी सी इंडस्ट्रीयल एरिया, तलोजा, महाराष्ट्र
हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमि., रिशरा, पश्चिम बंगाल
प्रोक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थकेयर, मंडीदीप प्लांट एल एंड सी - एम एफ जी, प्लॉट सं. 182, मंडीडीप, मध्य प्रदेश
एडवांटेज इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि. धनाली, ग्राम - धनाली, अल-कादी, जिला मेहसाना, गुजरात
यू. पी. ग्लास मैन्यूफैक्चरर, सिंडीकेट, 14 मोनापुरम, नियर गणेश नगर, फिरोजाबाद - 288203, उत्तर प्रदेश
फेना (प्रा.) लिमि., ए-237, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली - 20
पोलाची चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, आर. पी. काम्पलेक्स, द्वितीय तल, 14, बालागोपालापुरम स्ट्रीट,

पोलाची – 642001
पावर सोप लिमि., 62 बी, नार्थ बोआग रोड, टी. नगर – चैन्नई – 600017
अलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमि. अलेम्बिक रोड, बरोडा, (वडोदरा), गुजरात
दीपक नाइट्रेट लिमि., 4/12, कैमिकल काम्पलैक्स, जी आई डी सी, ननफेसारी, बरौदा (वडोदरा), गुजरात
हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमि., पार्टी एड्रेस दक्षिण बिल्डिंग, 8वां तल, प्लांट सं. 2, सेक्टर-11, सी बी डी बेलापुर, नवी मुम्बई।
अल ब्राइट मोरारजी एंड पंडित लिमि. अंबर नाथ, जिला – थाने, महाराष्ट्र
सेंट गोबाइन ग्लास इंडिया, हेड आफिस एंड प्लांट : ए-1, सिपकॉट इंडस्ट्रीयल पार्क श्री पेरंबदूर – 602 105, कांचीपुरम, जिला तमिलनाडु
असाही इंडिया ग्लास लिमि., 5वां तल, टावर-बी, ग्लोबल बिजनेस पार्क, महरौली – गुडगांव रोड, गुडगांव – 122002 (भारत)
श्री यूनियन आर्गेनिक्स प्रा. लिमि., बी एस – 3 एपीजे, 130 मुम्बई, समाचार मार्ग, मुम्बई – 23
वसुंधरा रसायन लिमि., सी-104, एम आई डी सी इंडस्ट्रीयल एरिया, महेद, जिला – रायगढ़, महाराष्ट्र।
शांतिनाथ डिटरजेंट प्रा. लिमि., पी-15, कलाकार स्ट्रीट, कोलकाता – 700007
एडवांस होम एंड पर्सनल केयर लिमि., एडवांस सरफेक्टेंट इण्डिया लिमि., 511/2/1, ग्राम रजोकरी, नई दिल्ली – 38
एस. कुमार डिटरजेंट प्रा. लिमि., प्लांट नं. 34, सेक्टर-2, इंडस्ट्रीयल एरिया, पीतमपुर – 454775, जिला धार, मध्य प्रदेश।
हिंद सिलिकेट्स प्रा. लिमि., 3ए, आकलैंड प्लेस, 5वां तल, कोलकाता – 17
पी एंड जे क्रेटकेम (प्रा.) लिमि., 318, स्वप्नलोक, 92/93, एस डी रोड, सिकंदराबाद – 500003, आंध्र प्रदेश, भारत
जे जे पटेल इंडस्ट्रीज, गोंडल रोड, बी/एच राजकमल पेट्रोल पम्प, वावडी, राजकोट – 360004
मार्डन ग्लस इंडस्ट्रीज, कोल साइडिंग रोड, एस एन रोड, फिरोजाबाद – 283203
संदीप आर्गेनिक्स प्रा. लिमि., 104 नेन कृपा, 118/122, काजी सईद स्ट्रीट, मस्जिद बुंदर (वेस्ट), यादगडी, मुम्बई 400003
अलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमि. अलेम्बिक रोड, बड़ौदा, (वडोदरा), गुजरात
रोहित सरफेक्टेंट्स (प्रा.) लिमि., 117/एच-2/202, पाण्डू नगर, कानपुर – 05
बी डी जे ग्लास इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि., 1 काईद स्ट्रीट प्लेस कोर्ट, प्रथम तल, सूट – 14-ए, कोलकाता – 700016
जगतजीत इंडस्ट्रीज लिमि., प्लाट नं. 78, सेक्टर-18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव – 122001.
हाल्लिन ग्लास गुजराज लिमि., 9, गायत्री कमर्शियल काम्प्लेक्स, बिहाइंड मित्तल इंडस्ट्रियल इस्टेट नं. 5, अंधेरी कुरला रोड, मारोल नाका, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई – 400059
हीपोलिन लिमिटेड, मधुवन, चतुर्थ तल, एलीसब्रिज, अहमदाबाद – 380006
मॉर्डन ग्लास इंडस्ट्रीज, कोल साइडिंग रोड, एस. एन. रोड, फिरोजाबाद – 283203
डिटरजेंट मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन (दिल्ली क्षेत्र) 148, न्यू ओखला इंडस्ट्रीयल काम्प्लेक्स-1, नई दिल्ली – 110020

मौली एक्सपोर्ट्स, प्लॉट नं. 97-98, सेक्टर - 25, पार्ट-II इंडस्ट्रीयल एरिया, हुडा, पानीपत - 132 104, हरियाणा
मैसर्स कैम्पेक्स इंटरनेशनल, 393/II/6 बाजेर, बीकानेरियन, कटरा आहलूवालिया, अमृतसर, पंजाब
टाटा कैमिकल्स लिमि., लीला बिजनेस पार्क, अंधेरी कुरला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई - 59.
मैसर्स तूतीकोरियन अलकाली कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमि., 534, अन्ना सलाई, तेनमपेट, चैन्नई - 18
ए जी आई ग्लास पैक, ग्लास फैक्टरी रोड, मोती नगर, पोस्ट बाक्स 1930, शांतिनगर, हैदराबाद - 500018
पावर सोप लिमि., ए-18, पहला मेन रोड, अंबादुर इंडस्ट्रीयल इस्टेट, चैन्नई 600058
हिंदकॉन कैमिकल्स (प्रा.) लिमि., 62/बी, ब्राउन फ्लैड रॉ, प्रथम तल, कोलकाता - 700 027
अम्पायर इंडस्ट्रीज लिमि., अम्पायर हाउस 414, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई - 13.

- vii. उपर्युक्त अधिसूचना के प्रयुक्त में, निम्नलिखित आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली उत्तर दायर किए और निवेदन किए।

क. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड

- viii. निम्नलिखित एसोसिएशनों को भी जांच शुरुआत अधिसूचना भेजी गई :

डिटरजेंट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (दिल्ली क्षेत्र)
इंडियन केमिकल्स मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन
बल्क ड्रग मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (इंडिया)
इंडियन ग्लास मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन
द डायर्स एंड केमिकल्स मर्चेंट्स एसोसिएशन
आल इण्डिया ग्लास मैन्युफैक्चर्स फेडरेशन
अलकाली मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
इंडियन सोप एंड टायलेटरीज मेकर्स एसोसिएशन

- ix. इस जांच की अवधि के दौरान निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा भी निवेदन किए गए :

- घरेलू उद्योग - मैसर्स निरमा लिमि. और मैसर्स डी सी डब्ल्यू लिमि.
- मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, रिपब्लिक ऑफ टर्की
- दि ट्रेड रिप्रेजेंटेशन, रूसी संघ
- सोडा सनाई, ए. एस., टर्की
- जे एस सी बशकिरियन केमिस्ट्री, रूसी संघ
- पी जे एस सी सोडा क्रीमिया प्लांट, रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया, रूसी संघ
- डिटरजेंट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया
- इंडियन ग्लास मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन

- ix. हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमि.
- x. सेंट गोबाइन इंडिया प्रा. लिमि.
- x. जिन निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया अथवा इस जांच के संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।
- xi. जांच 1 अप्रैल, 2016 से आरंभ कर 30 सितंबर, 2017 (पी ओ आई) की अवधि के लिए की गई थी। तथापि, क्षति जांच 2013-14, 2014-15, 2015-16 की अवधि और पी ओ आई के लिए आयोजित की गई थी। पी ओ आई के पश्चात् विश्लेषण के लिए 1 अक्टूबर, 2017 से 30 सितंबर, 2018 की अवधि विचारित की गई है।
- xii. जांच की अवधि और पी ओ आई के पश्चात् की अवधि के अतिरिक्त पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विवरणों का प्रबंध करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से अनुरोध किया गया था। इसलिए, प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा और अपेक्षित विश्लेषण के परिकलन के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों का सहारा लिया है।
- xiii. उत्पादन की दृष्टतम लागत और भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्माण और बिक्री की लागत को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन की तुलना में निम्न पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होंगे। क्षतिरहित कीमत (एन आई जी) को ए डी नियमावली के अनुबंध III के तहत निर्धारित किए गए सिद्धांतों की शर्तों में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है।
- xiv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 25 जुलाई, 2018 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने मत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने मत प्रस्तुत किए थे उन्हें पुनरुत्तर निवेदनों के साथ मौखिक रूप से प्रस्तुत मतों को लिखित में दायर करने का अनुरोध किया गया।
- xv. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी जरूरत थी, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और उसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन नहीं किया गया। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का यथेष्ट अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
- xvi. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार वर्तमान जांच की अवधि के दौरान अन्यथा आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
- xvii. प्राधिकारी ने दिनांक 8 फरवरी, 2019 के प्रकटन विवरण द्वारा सभी पक्षकारों के लिए विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया। सभी पक्षों को प्रकटन विवरण के संबंध में उनकी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। प्रकटन विवरण के संबंध में सभी पक्षों के अनुरोधों को रिकॉर्ड में लिया गया और वर्तमान जांच परिणाम में उचित स्थान पर उनकी जांच की गई।
- xviii. *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और ए डी नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार गोपनीय समझी गई सूचना को निरूपित करता है।
- ixx. प्राधिकारी द्वारा पी ओ आई के दौरान प्रचलित 1 अमरीकी डालर = 65.67 रुपए की औसत विनियम दर को अपनाया गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

- 12. मूल जांच तथा वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) 'सोडा एश' है। वर्तमान जांच में पी यू सी का निम्नानुसार परिभाषित किया गया था।

"i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद डिसोडियम कार्बोनेट है जो Na_2CO_3 रसायनिक फार्मूले सहित सोडा एश के रूप में भी ज्ञात है। सोडा एश दो रूपों में उत्पादित किया जाता है लाइट सोडा एश और डेंस सोडा एश। दोनों प्रकारों में अंतर बल्क डेंसिटी है। इसे सिंथेटिक रूट और डिसोल्यूशन प्रक्रिया के रूप में ज्ञात प्राकृतिक रूट के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है। वर्तमान जांच में सोडा एश के सभी प्रकार और रूप शामिल हैं।"

"ii. सोडा एश डिटरजेंट, साबुन, क्लीनिंग कंपाउंड, सोडियम आधारित केमिकल्स, फ्लोट ग्लास, कंटेनर और स्पेशिएलिटी ग्लासिस, सिलीकेट्स और अन्य औद्योगिक रसायनों के विनिर्माण में एक अनिवार्य घटक है। इसका वस्त्र निर्माण, कागज, धातु उद्योग और अलवणीकरण संयंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। सोडा एश को उपशीर्ष संख्या 2836.20 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के तहत वर्गीकृत किया गया है तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

13. किसी भी आयातक, प्रयोक्ता, निर्यातक, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के कार्यक्षेत्र के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र वही बना रहा है जो मूल जांच में था।

घ. घरेलू उद्योग और उसका आधार

याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया अनुरोध

14. घरेलू उद्योग के मत और कार्यक्षेत्र के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
- भागीदार कंपनियों के उत्पादन घरेलू उद्योग का एक प्रमुख समानुपात स्थापित करते हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता कंपनियां पात्र घरेलू उत्पादक हैं। अतः, ए. डी. नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थों के भीतर भागीदार कंपनियां घरेलू उद्योग स्थापित करती हैं।
 - निरमा के संबंधित निर्यातक ने जांच की अवधि में वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, जहां तक घरेलू उद्योग के संघटन पर यहां ऊपर किए गए दावों का संबंध है, इसने पहले दायर किए गए अनुरोधों में इसे लिखित रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है। किसी एस एस आर जांच में नियम अनिवार्य नहीं है, नियम 23 में समीक्षाओं का सामना करने के लिए नियम 5 को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में, जहां याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार्य रूप से क्षति न होने का दावा किया है, घरेलू उद्योग को लगातार क्षति से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किए जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। अतः, अन्य उत्पादकों के आंकड़ों की मांग करने का कोई आधार नहीं है। पक्षपात के बिना, याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है और इसलिए याचिकाकर्ता को केवल इस कारण से राहत के लिए मना नहीं कर सकते क्योंकि अन्य उत्पादकों ने संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

15. घरेलू उद्योग के मत के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
- अपनी याचिका के पैरा 32 में, याचिकाकर्ताओं ने दृढ़ता से कहा है कि मैसर्स निरमा लिमि. का भारत से बाहर एक संबद्ध उत्पादक है और यह कि पी ओ आई के दौरान भारत को उक्त संबद्ध उत्पादक द्वारा कोई निर्यात नहीं किए गए हैं। एच यू एल ने प्रस्तुत किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या वास्तव में संबद्ध उत्पादक ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत निरमा को एक पात्र घरेलू उद्योग प्रस्तुत करने के लिए, जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।
 - याचिका के पैरा 28 में, याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि मैसर्स जी एच सी एल, टाटा केमिकल्स लिमि., तूतीकोरिन अल्काली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स भारत में पी यू सी के अन्य घरेलू उत्पादक हैं। तथापि, उन्होंने यह भी कहा है कि जी एच सी एल ने पी यू सी का आयात किया है और टाटा केमिकल्स मूल जांच को दृष्टि में रखते हुए अपात्र है। ऐसे दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है। वर्तमान जांच की पिछली पुनरावृत्तियों में जी एच सी एल ऐतिहासिक रूप से घरेलू उद्योग का भाग रहा है। एच यू एल ने जी एच सी

एल से उपयुक्त सूचना की मांग और यह आकलन करने के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि क्या इसके आयात इस घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने के लिए वास्तव में अयोग्य बनाते हैं। एच यू एल ने आगे अनुरोध किया है कि आयातों की मात्रा विद्यमानता ए. डी. नियमावली के नियम 2(ख) के तहत किसी घरेलू उत्पादक को स्वतः ही अपात्र नहीं बनाती। जी एच सी एल की वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण दर्शाता है कि उनका सोडा एश प्रभाग अपने लाभों में *** की वृद्धि तथा *** प्रतिशत से अधिक के क्षमता उपयोग के साथ असाधारण रूप में निष्पादन कर रहा है।

- iii. टाटा केमिकल्स को शामिल न किया जाना कानून में अनुमति नहीं है और यह गैर कानूनी है। संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित किसी पक्षकार को शामिल करने अथवा न करने का विवेकाधिकार प्राधिकारी के पास सुरक्षित है। जहां घरेलू उद्योग ने इस आधार पर टाटा केमिकल्स को घरेलू उद्योग के सीमा क्षेत्र से बाहर रखा है कि इसका केन्या में एक संबंधित उत्पादक है, वहीं इसने मैसर्स निरमा को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में मानते हुए, जिस का यू एस ए में एक संबद्ध उत्पादक है एक बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। घरेलू उद्योग के सीमा क्षेत्र में टाटा केमिकल्स को शामिल न करके, याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारी को नियम 2(ख) के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करने के अवसर से वंचित किया है।
- iv. ऊपर उल्लिखित कारणों से, याचिकाकर्ता नियमावली के नियम 23(1)(ख) की शर्तों में एक निर्णायक समीक्षा को आरंभ करने के लिए अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहा है। प्राधिकारी से सिर्फ इसी एक आधार पर समीक्षा को समाप्त करने का अनुरोध किया जाता है

प्राधिकारी द्वारा जांच

16. प्राधिकारी नोट करते हैं ए. डी. नियमावली का नियम 2(ख) निम्नानुसार कहता है :

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

17. ए. डी. नियमावली के नियम 2(ख) में व्यवस्था की गई है कि घरेलू उत्पादक जो निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हैं या जो स्वयं कथित पाटित वस्तुओं के आयातक हैं, को कुछ विशेष स्थितियों में घरेलू उद्योग का निर्धारण करते हुए बहिष्कृत रखा जा सकता है। प्राधिकारी का विचार है कि नियम 2(ख) में पद “हो सकता है” का प्रयोग यह सुझाव देता है कि प्रश्नाधीन दो प्रकार के उत्पादक अर्थात् संबंधित उत्पादक और पाटित उत्पाद का आयात करने वाले उत्पादकों को स्वतः ही घरेलू उद्योग का भाग बनने से बहिष्कृत नहीं रखा जा सकता। तदनुसार, यह लगातार अभ्यास रहा है कि ऐसे उत्पादकों के बहिष्करण का निर्णय सभी सम्मिलित कानूनी और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।
18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में भी कुछ घरेलू उत्पादक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में शामिल थे अथवा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों/ आयातकों से संबंधित थे। मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग और इसके आधार पर कार्रवाई की है। मूल जांच में प्राधिकारी ने ए. डी. नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) की अनिवार्यताओं के अनुसरण में, जी एच सी एल, निरमा लिमि. और डी सी डब्ल्यू लिमि. को “घरेलू उद्योग” माना है। वर्तमान समीक्षा याचिका निरमा लिमि. और डी सी डब्ल्यू लिमि. द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है।
19. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी नोट करते हैं कि डी सी डब्ल्यू लिमिटेड ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है न ही वह संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, निरमा लिमि. ने क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया। यह कहा गया है कि निरमा का यू. एस. ए. में एक संबंधित उत्पादक है जो भारत को संबद्ध वस्तुओं के आयात में सम्मिलित था। प्राधिकारी ने अवलोकन किया है कि निरमा लिमि0 के संबंधित उत्पादक यू.एस.ए. में स्थित हैं न कि संबद्ध देश में। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि निरमा ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है न ही यह किसी आयातक से संबंधित है। अतः यह धारित किया जाता है कि निरमा लिमि. और डी सी डब्ल्यू लिमिटेड ए डी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) की शर्तों में घरेलू उद्योग के रूप में पात्र कंपनियां हैं।

ड. गोपनीयता**याचिकाकर्त्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध**

20. याचिकाकर्त्ताओं द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- i. जहां तक धारा VI में दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता का संबंध है, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वह घरेलू उद्योग की मूलभूत लागत निर्धारण की सूचना अंतर्निहित करता है और घरेलू उद्योग के संबंध में वास्तविक सूचना का प्रकटन उत्पाद के भावी कारोबार को संकट में डाल सकता है। यह देखना आश्चर्यजनक है कि निर्यातक ने यह मुद्दा तब उठाया है जबकि निर्यातक ने प्रत्युत्तर के एन सी वी को दायर ही नहीं किया है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- i. याचिकाकर्त्ताओं ने याचिका में विभिन्न सूचनाओं और आंकड़े पर गोपनीयता का दावा किया है, जो डिटरजेंट मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (डी एम ए आई) की उनके हितों की रक्षा करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से समाप्त करता है क्योंकि अनिवार्य तथ्य उन्हें ज्ञात नहीं है। विशेष रूप से, याचिकाकर्त्ता कुछ विशेष अनिवार्य तथ्यों पर गोपनीयता का दावा करने के लिए एक उचित कारण उपलब्ध कराने में असफल रहा है, जैसा कि ए डी करार के अनुच्छेद 6.5 और ए डी नियमावली के नियम 7 द्वारा अपेक्षित है। यह अनुरोध किया जाता है कि निर्यात बिक्री मात्रा, कैप्टिव खपत, माल सूची और नियोजन से संबंधित सूचना को वास्तविकता के अनुसार रिपोर्ट किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी सूचना को इस तथ्य के कारण गोपनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि इसका प्रकटन न तो डी एम ए आई को एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है और न ही यह महत्वपूर्ण रूप से याचिकाकर्त्ताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करता है।
- ii. ए डी नियमावली के नियम 7 और ट्रेड नोटिस 1/2013 में प्रतिष्ठापित अनिवार्यताओं के अनुसार, याचिका के अगोपनीय पाठ में एक सूचीकरण और/ या गोपनीय आंकड़ों का सारांश शामिल करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को समुचित रूप से समझा जा सके। ट्रेड नोटिस 1/2013 के पैराग्राफ (vi) में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गोपनीयता पर सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना किया गया कोई अनुरोध निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड पर नहीं लिया जाएगा। अर्जेंटीना सिरेमिक टाइल्स में डब्ल्यू टी ओ पैनल द्वारा यह जांच करते हुए कि क्या प्राधिकारियों को उनके निर्धारण में गोपनीय सूचना पर भरोसा करने की अनुमति थी, यह विचार किया गया कि अगोपनीय सारांशों का प्रयोजन हितबद्ध पक्षकारों को सूचित करना है ताकि वे अपने हितों की रक्षा करने में समर्थ हो सकें। निर्दिष्ट प्राधिकारी केवल सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार द्वारा गोपनीयता का अनुरोध करने पर ही सूचना को गोपनीय नहीं मान सकते। स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्रा. लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2003 (158) ई एल टी 673 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि नियम 7 के तहत गोपनीयता को स्वतः ही माना नहीं जा सकता। ऐसी सूचना को प्रस्तुत करने वाले पक्षकार द्वारा एक अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराना अपेक्षित है। यदि किसी स्थिति में पक्षकार इसे उपलब्ध करना नहीं चाहते तो उन्हें ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का सारांशीकरण क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा सकता। न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया है कि अन्य दूसरे पक्ष को संगत सामग्री उपलब्ध न कराना उनकी एक प्रभावी अपील को दायर करने की क्षमता को अपंग बना देता है। न्यायालय के इस विचार की बाद में भारत संघ और ए. एन. आर. बनाम मेघमणि आर्गेनिक्स लिमि. एवं अन्य के मामले में पुष्टि की गई।
- iii. याचिका का अगोपनीय पाठ ट्रेड नोटिस 1/2013, नियम 7 के तहत गोपनीयता की अनिवार्यताओं साथ ही ऊपर उल्लिखित निर्णयों का अनुवर्तन पालन करने में विफल रहा है। याचिका में किसी उचित कारण के दर्शाए बिना गोपनीय के रूप में मानी जाने वाली संबंधित सूचना शामिल है और प्रस्तुत जानकारी के सार को उचित रूप से समझने में विफल है। अतः हम अनुरोध करते हैं कि अगोपनीय सूचना को बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि डी एम ए आई अपनी रक्षा के अधिकारों का पूर्णतः प्रयोग कर सकें।

- iv. आवेदकों ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 और पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 6.5 के उल्लंघन में विभिन्न आर्थिक मानदंडों पर सूचना नहीं दी है। कुल भारतीय मांग व्यक्तिगत स्तर पर उत्पादन और बिक्रियों से संबंधित सूचना; अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन और बिक्रियों से संबंधित सूचना; और आवेदकों की लागत निर्धारण से संबंधित सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा अत्यधिक है क्योंकि याचिका के अगोपनीय सारांश उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
- v. विवरण ख में 3 वर्षों के लिए कच्ची सामग्री के लिए विवरण से संबंधित सूचना; फार्मेट ग I में उत्पादन की लागत का विवरण; फार्मेट ग II में व्यय का आवंटन और प्रभाजन; फार्मेट घ में उपयोगिता के खपत से संबंधित विवरण; और फार्मेट ड में बिक्री आय के पूर्ण विवरण को सूचीबद्ध रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है। कुछ अन्य विशेष सूचनाओं को भी गोपनीयता के अनधिकृत और अवैध दावों के नए निम्न मानकों को स्थापित करते हुए गोपनीय रखा गया है।
- vi. माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टलाईट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2003 (158) ई एल टी 673 (एस सी) के मामले में धारित किया है कि गोपनीयता स्वतः ही प्रदान नहीं की जानी थी बल्कि पूर्ण संवीक्षा पर आधारित होनी चाहिए थी। गोपनीय सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार द्वारा इसका सारांश उपलब्ध कराना चाहिए और जहां सारांश संभव नहीं है, उन्हें ऐसे कारणों का विवरण उपलब्ध कराना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावों का आकलन करना और यह निर्धारित करना भी जरूरी है कि क्या प्रश्नाधीन सूचना को गोपनीय रखा जा सकता है या नहीं। वर्तमान मामले में, गोपनीयता के दावे को सूचना जिससे गोपनीयता का दावा संबंधित है, पूरी तरह से मूल्यांकन के बिना प्रदान किया गया है।
- vii. डी एस 397 यूरोपियन समुदायों में डब्ल्यू टी ओ अपीलीय निकाय रिपोर्ट – चीन से विशिष्ट लौह या स्टील फास्टनर्स पर अंतिम पाटनरोधी उपायों में धारित करते हैं कि गोपनीयता का दावा करने वाले पक्षकार के लिए गोपनीयता के दावे के लिए सही कारण दर्शाना जरूरी है और प्राधिकारी द्वारा कथित “सही कारण” का उद्देश्यपरक रूप से आकलन करना और इसके अतिरिक्त यह निर्धारित करने के लिए पक्षकार के प्रदर्शन की जांच करने की जरूरत है कि क्या अनुरोध पर्याप्त रूप से पुष्ट था। सूचना की गोपनीयता उचित प्रक्रिया चिंताओं का कारण बनती है और ऐसी उचित प्रक्रिया के लिए अपने हितों की रक्षा करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने की जरूरत है। ऐसे अवसर को अपनी रक्षा करने की पक्षकार की क्षमता की शर्तों में पूर्ण होना चाहिए।
- viii. प्राधिकारी से तैयार गोपनीय पाठ के साथ याचिका के उचित अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है ताकि हितबद्ध पक्षकार अपने हितों की पूर्णतः और पूरी तरह से रक्षा कर और सर्वोत्तम तरीके से प्राधिकारी की सहायता करने में सक्षम हो सके।
- ix. याचिका का अगोपनीय पाठ उसमें अंतर्निहित आरोपों को उचित रूप से समझने की अनुमति नहीं देता। याचिका का अगोपनीय पाठ नियमावली के नियम 7 और दिनांक 9 दिसंबर, 2013 के ट्रेड नोटिस सं. 1/2013 में विनिर्दिष्ट अनिवार्यताओं का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है।
- x. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और एक अधूरी याचिका दायर की है। याचिका के भाग VI (लागत निर्धारण संबंधी सूचना) के प्रत्युत्तर में, घरेलू उद्योग ने कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। घरेलू उद्योग ने याचिका के भाग VI में उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर “संलग्न और बैलेंस शीट के अनुसार” दिया है। संलग्न फार्मेट क से ड तक में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है। याचिकाकर्त्ताओं ने हर चीज को *** के रूप में चिन्हित किया है और इसके पर्याप्त कारण उपलब्ध नहीं कराए हैं कि गोपनीयता का दावा क्यों किया गया था और विशिष्ट सूचना के लिए सारांशीकरण क्यों संभव नहीं था। याचिकाकर्त्ता द्वारा अपने दावे के लिए औचित्य दर्शाना जरूरी है किंतु वह ऐसा करने में असफल रहा है।
- xi. विचाराधीन उत्पाद के लिए लागत निर्धारण सूचना उपलब्ध कराई जानी होती है। कुछ प्रश्नों के प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्त्ता ने “बैलेंसशीट के अनुसार” उत्तर प्रस्तुत किया है। निरमा लिमिटेड और डी सी डब्ल्यू लिमिटेड जैसी बहु-व्यापार कंपनी में, बैलेंसशीट प्रत्येक खंड में विभिन्न उत्पादों के लिए समेकित होती हैं। ऐसी समेकित वित्तीय सूचना का आकलन करना और उसे विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध करना संभव नहीं है। तदनुसार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्त्ता ने पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई है जैसा कि आवेदन के तहत

अपेक्षित है। ऐसी सूचना महत्वपूर्ण है और याचिकाकर्ता से सूचना को या कम से कम अगोपनीय तरीके में दस्तावेजों का सारांशीकरण और सूचीबद्ध आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

22. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत प्रावधान इस प्रकार है:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

23. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर आवश्यकता के अनुसार, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को, गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सार्वजनिक फाइल के रूप में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया।

च. विविध अनुरोध

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

24. याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. जहां तक दिनांक 04.04.2018 के आदेश का संबंध है, उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया है और निर्णायक समीक्षा जांच इसके गुण-अवगुण के आधार पर शुरू करने का निदेश दिया। इस समीक्षा का प्रयोजन यह जांच करना है कि लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के क्या परिणाम रहे। प्राधिकारी को यह जांच करनी अपेक्षित है कि यदि घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो क्या लागू शुल्क को जारी रखना जरूरी होगा। घरेलू उद्योग अकेले सभी संगत सूचना उपलब्ध नहीं करा सकता। इस मामले में निर्यातकों ने यह कहते हुए निर्यातक प्रश्नावली उत्तर (ईक्यूआर) भाग-II दाखिल नहीं किया है कि उनसे कहा नहीं गया है। हम निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली उत्तर (ईक्यूआर) भाग-II दाखिल करने के लिए निदेश दें। निर्यातक ने नए निर्यातक प्रश्नावली फॉर्मेट के परिशिष्ट-I में यथा अपेक्षित निर्यात के आर्थिक मापदंडों पर सूचना प्रदान करने से आसानी से इंकार कर दिया है। इस प्रकार निर्यातक जानबूझकर सूचना को छिपा रहा है।
- ii. प्राधिकारी द्वारा एमटीआर अंतिम जांच परिणामों के निष्कर्षों को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और उसमें यह पाया गया कि जांच परिणाम अपर्याप्त थे और संगत मापदंडों पर विचार नहीं किया गया। याचिकाकर्ता प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा यथा प्रस्तुत वर्तमान मामले के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं का मूल्यांकन करें और उसके बाद यह निष्कर्ष निकालें कि पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है या नहीं। यद्यपि, यह स्वीकार किया गया है कि निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर) में घरेलू उद्योग पाटन और क्षति की संभावना के आधार पर समय विस्तार का

- अनुरोध कर रहा है, उसके लिए उसे प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य प्रदान करने आवश्यक होंगे, इसके लिए यह अनुरोध किया जाता है कि प्रतिवादी निर्यातकों को भी यह प्रमाणित करना चाहिए कि पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाने की अवस्था में पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है। निर्णायक समीक्षा जांच की प्रश्नावली भाग-II के तहत सूचना के आधार पर जब तक यह प्रमाणित नहीं करते कि पाटनरोधी शुल्कों को हटा लिए जाने की अवस्था में पाटन के जारी रहने, पाटन में तेजी आने अथवा पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है, इसे अन्यथा रखा जाना चाहिए।
- iii. प्राधिकारी अपनी स्थापित प्रथा के अनुसार कार्यवाही करेंगे। इसके अलावा, चूंकि क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में वर्तमान याचिका में दावा किया गया है, प्राधिकारी इसके पाए जाने पर कृपया मूल जांच परिणाम में लगाए गए शुल्कों में विस्तार करें। तथापि, यह उल्लेख किया गया है कि निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के भाग-II का उत्तर दाखिल नहीं किया है। यह स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले में असहयोग को प्रमाणित करता है।
- iv. याचिका अधूरी रहने के संबंध में यह विचार करने में काफी विलंब हुआ है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले ही सुनवाई कर ली है। यदि हितबद्ध पक्षकारों को कोई शिकायत है तो वे जांच प्रारंभ करने की अवस्था में उसे उठाए और हर हाल में सुनवाई से काफी समय पूर्व उठाए। हितबद्ध पक्षकारों को कार्यवाही की इतनी विलंब की अवस्था में ऐसे दावों को उठाकर जांच को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वैकल्पिक रूप से निर्दिष्ट प्राधिकारी को सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत सुनवाई तय करके अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए घरेलू उद्योग को आगे अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। कार्यवाहियों की इस अवस्था में ऐसे तर्क उठाना एक पक्षपात करने के प्रयास के अलावा कुछ भी नहीं है और इससे घरेलू उद्योग के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। याचिकाकर्ताओं ने निर्धारित फॉर्मेट में सभी संगत सूचना प्रदान कर दी है।
- v. याचिकाकर्ताओं के पास कानून के तहत अपने दावों को उठाने का हर अधिकार है। याचिकाकर्ताओं ने यह प्रस्तुत नहीं किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को जीएचसीएल अथवा टाटा केमिकल्स अथवा किसी अन्य पक्षकार से आंकड़े नहीं मांगने चाहिए। टाटा केमिकल्स की निरमा के साथ स्थिति की तुलना पूरी तरह से गलत है। वर्तमान जांच की अवधि के दौरान केन्या से आयात *** मी. टन थे, जो कुल आयातों का *** प्रतिशत होता है, भारत में मांग *** प्रतिशत है, टाटा केमिकल्स के उत्पादन का *** प्रतिशत है। इसके विपरीत, निरमा के संगत पक्षकार ने संगत अवधि के दौरान भारत को किसी सामग्री का निर्यात नहीं किया है। निरमा से पत्र, जिसमें उसके यूएस से संबद्ध उत्पादक द्वारा भारत को निर्यात किए जाने के संबंध में सूचना दी गई है, इन अनुरोधों के साथ संलग्न है। यह देखा जाएगा कि हितबद्ध पक्षकार अतुलनीय की तुलना कर रहे हैं।
- vi. नियमों के तहत यथानिर्दिष्ट आशंका मापदंडों में (क) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त व आसानी से निपटान योग्य अथवा एक अवश्यभावी पर्याप्त वृद्धि; (ख) भारतीय बाजारों में पाटित निर्यातों की पर्याप्त वृद्धि की संभावना दिखना; (ग) किसी अतिरिक्त निर्यात को समायोजित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखना। वर्तमान मामले में – (क) याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देशों में वर्तमान मांग आपूर्ति के बीच के अंतर के साक्ष्य प्रदान किए हैं। यह कहा जाता है कि जो क्षमता देश में निर्यातों की मांग से अधिक है, उसका आसानी से निपटान किया जा सकता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण तीसरे देश के निर्यात संबद्ध देशों द्वारा किए जा रहे हैं। यह देखा जाएगा कि अन्य देशों को किए जा रहे महत्वपूर्ण निर्यात भारत को किए गए निर्यात की कीमत से भी कम है। ये निर्यात भारत की ओर आने की भी संभावना है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा क्षमता में अवश्यभावी पर्याप्त वृद्धि दर्शाने वाले पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किए हैं, (ख) यह तथ्य कि काफी अधिक सरप्लस क्षमता है और क्षमता के विस्तार की योजना की गई है, सरप्लस और अतिरिक्त क्षमता से भारत में आयातों में वृद्धि होने की संभावना है, जो कि एक विकासशील बाजार है, (ग) याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न देशों में मांग-आपूर्ति के बीच के अंतर को दर्शाते हुए साक्ष्य भी प्रदान किए हैं। अतः ऐसी स्थिति में, जहां संबद्ध वस्तुओं की अधिक्यता है, भारत जैसा विकासशील बाजार एक अनुकूल बाजार बन जाता है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. टर्की खेद प्रकट करना चाहता है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय को पलट दिया, जिसने बार-बार संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी न रखने का निर्णय लिया है। हमें आशा है कि यह निर्णायक समीक्षा स्वतंत्र और निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार को बनाए रखने के लिए शीघ्र से शीघ्र समाप्त की जाए।
- ii. भारत टर्की का एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार है और द्विपक्षीय व्यापार अधिकतर भारत के पक्ष में है। वर्ष 2008 में टर्की ने भारत को 500 मिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया है जबकि टर्की का भारत को निर्यात 2.4 बिलियन रहा है। पिछले दशक में, टर्की का भारत को निर्यात केवल 40 प्रतिशत बढ़ा है जबकि भारत का टर्की को निर्यात लगभग तीन गुना बढ़ा है। वर्ष 2017 में टर्की और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा 6.9 बिलियन यूएस डॉलर रही। इन उपायों के जारी रहने से हमारे द्विपक्षीय व्यापार पर महत्वपूर्ण व्यापार-विचलन प्रभाव पड़ेगा और निःसन्देह टर्की पर व्यापार घाटा अधिक मात्रा में बढ़ेगा।
- iii. टर्किश स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अनुसार, टर्की का भारत को सोडा ऐश का निर्यात वर्ष 2013 में 14 मिलियन यूएस डॉलर से 9.5 प्रतिशत कम होकर वर्ष 2017 में 12.8 मिलियन यूएस डॉलर हो गया है। टर्की का निर्यात वर्ष 2016 में 2.1 मिलियन यूएस डॉलर के साथ सबसे कम रहा।
- iv. आवेदकों का यह दावा कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में जांच की अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई है लेकिन उनके द्वारा इस दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए अनुलग्नक- 1.2 में प्रदान किए गए आंकड़े भ्रामक हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजन से जांच की अवधि में अप्रैल, 2016 से सितंबर, 2017 तक की अवधि शामिल है। अतः पूर्व वित्तीय वर्षों की जांच की अवधि से इसकी तुलना असंगत है। डीजीसीआईएंडएस के आयात संबंधी आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा वर्ष 2014-15 से स्थिर रही है और क्षति की अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई है। इन आंकड़ों से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातों की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- v. टर्की और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडा ऐश" के आयातों के संबंध में मध्यावधिक समीक्षा जांच के दौरान जांच प्राधिकारी ने सोडा ऐश के भारतीय आयातकों के इन दावों को गलत करार दिया है कि संबद्ध देशों में अप्रयुक्त आसानी से निपटान योग्य क्षमताएं हैं। अब आवेदकों ने इस दावे की क्षति की आशंका के संबंध में विभिन्न तर्कों के आधार पर पुनरावृत्ति की है।
- vi. याचिकाकर्ताओं ने पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा जांच आरंभ करने के लिए शर्त को सिद्ध करने के लिए कोई उचित साक्ष्य नहीं दिया है।
- vii. रिकार्ड पर मौजूद तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध उत्पाद के बढ़ते आयातों को बढ़ाकर दिखाया है और जानबूझकर घरेलू उद्योग को क्षति दिखाई है।
- viii. याचिकाकर्ताओं के दावे प्रकाशित सूचना से उलट हैं और याचिकाकर्ताओं को क्षति दर्शाने के लिए मनगढ़ंत और मनमर्जी से तैयार किए गए प्रतीत होते हैं।
- ix. याचिकाकर्ता नियमावली के नियम 11 और तत्संबंधी अनुबंध-II के पैरा IV में सूचीबद्ध कुछ संगत आर्थिक कारकों और संसूचकों का मूल्यांकन करने में विफल रहा है। याचिका की व्याख्या में यूनिट कीमत, कुल लागत, निवेश, रोजगार और स्टॉक के संबंध में सूचीबद्ध आंकड़े स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए हैं और उनका विश्लेषण नहीं किया है जिसमें सार्थक विश्लेषण की कमी है। प्राधिकारी को पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.3 और संयुक्त राज्य सॉफ्टवुड लंबर, कनाडा, ग्वाटेमाला-सीमेंट-II और मैक्सिको-स्टील पाइप तथा ट्यूब में डब्ल्यूटीओ पैनेल द्वारा विनिर्धारित मानकों के अनुसार याचिका में साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की जांच करनी चाहिए थी।
- x. वर्तमान मामले में, महानिदेशक ने ऐसे मामले में जहां कहीं कोई क्षति नहीं थी अथवा क्षति होने की संभावना नहीं थी, जैसे नाइलोन फिलामेंट, ड्राईसेल बैट्रियों, विस्कोस फिलामेंट यार्न में हुआ, जांचों को शुरू करने से इंकार कर दिया अथवा समाप्त कर दिया।
- xi. इस मामले में पाटनरोधी उपायों को लागू करने से यह भारतीय घरेलू उद्योग और उसके डाउनस्ट्रीम उद्योगों के दीर्घकालिक और समग्र हित के अनुकूल नहीं होगा। रूस से संबद्ध वस्तुओं का कोई पाटन नहीं हुआ था और आयातित वस्तुओं के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई थी।

- xii. यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई जबकि इसके बावजूद पाटन के आरोप जारी रहे हैं।
- xiii. अनुबंध-II के पैरा (vii) के मानदंडों के अनुसार रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह सुझाव देता हो कि यदि शुल्कों को जारी नहीं रखा गया तो क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- xiv. पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे तीन मामले रहे हैं जिनमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पाया है कि कोई क्षति नहीं हुई है और क्षति की पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है – (i) चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और यूएसए के संबंध में दिनांक 22 जुलाई, 2017 के अंतिम जांच परिणामों के तहत एमटीआर, (ii) दिनांक 22 जुलाई, 2017 के अंतिम जांच परिणामों के तहत टर्की और रूस के संबंध में एमटीआर, और दिनांक 5 अप्रैल, 2018 के अंतिम जांच परिणाम के तहत टर्की और रूस के संबंध में निर्णायक समीक्षा आदेश।
- xv. क्षति की संभावना को प्रमाणित करने का दायित्व पूरी तरह से घरेलू उद्योग का है, जिसे वे बिना किसी विश्वसनीय साक्ष्य के प्रमाणित करने में विफल रहे।
- xvi. याचिकाकर्ताओं ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि जांच की अवधि के दौरान पर्याप्त मात्रा में पाटन हो रहा है और यह भी स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हो रही।
- xvii. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर) है जिनके साथ दो मध्यावधिक समीक्षाएं पहले समाप्त हो चुकी हैं। इस अवस्था में, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को, पाटन के बार-बार आरोप लगाने के बावजूद, कोई क्षति नहीं हुई है, निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर) आदेश, दिनांक 05.04.2018 के पैरा 4 के निष्कर्ष में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि घरेलू उद्योग लगाई गई पूंजी पर काफी लाभ और प्रतिफल अर्जित कर रहा है। यहां तक कि याचिका के अन्य क्षति मापदंड क्षति न होना दर्शाते हैं।
- xviii. विचारणीय पक्ष यह उत्पन्न होता है कि क्या क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। रिकार्ड में इस बात का सुझाव देने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं कि यदि शुल्कों को जारी नहीं रखा जाता तो क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- xix. चूंकि, वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11 के प्रावधान वर्तमान मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण के संदर्भ में संगत हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए भी यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करने से पाटन के होने, जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने और क्षति के जारी रहने और पुनरावृत्ति होने की संभावना है अथवा नहीं।
- xx. याचिकाकर्ताओं ने महत्वपूर्ण पाटन का आरोप लगाया है, जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने दिनांक 05.04.2018 के आदेश में स्वीकार किया है। तथापि, एचयूएल का निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि व्यक्तिगत सहयोगी संस्थाओं के उत्तरों का आकलन करें और तदनुसार यह निर्धारित करें कि क्या वास्तव में पाटन जारी रहा है अथवा क्या शुल्कों को समाप्त करने से पाटन की आगे पुनरावृत्ति होने की संभावना है। जहां तक क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने के विश्लेषण का संबंध है, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि घरेलू उद्योग स्पष्ट रूप से वर्तमान क्षति का सामना नहीं कर रहा है।
- xxi. एचयूएल का यह कहना है कि याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के बाद के सभी अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं जिनके कारण क्षति होने की संभावना के आरोप का किसी भी इच्छुक हितबद्ध पक्षकार द्वारा विश्लेषण नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने मौखिक सुनवाई से पूर्व दिनांक 24.07.2018 को एक पेपर बुक प्रस्तुत की है जो जांच की अवधि के उपरांत के डाटा को आयात की मात्रा तक ही सीमित करती है और यह घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना अथवा जारी रहने की संभावना अथवा क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना का निष्कर्ष के तौर पर निर्धारण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार, एचयूएल का निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि उसे अस्वीकार किया जाए और इस जांच पर तब तक आगे कार्यवाई न करें जब तक कि जांच की अवधि के बाद के सभी अपेक्षित आंकड़े याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध न करा दिए जाएं।
- xxii. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विस्कांस फिलामेंट यार्न के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा को अंतिम जांच परिणामों की दिनांक 20.04.2018 की अधिसूचना संख्या 15/16/2016/डीजीएडी में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह नोट किया कि क्षति की संभावना को प्रमाणित नहीं

किया जा सकता क्योंकि जांच की अवधि के उपरांत के आंकड़े प्रदान नहीं किए गए थे। इसमें आगे यह भी निर्धारित किया गया है कि घरेलू उद्योग निम्नलिखित कारणों से निरंतर क्षति का सामना करने के लिए दावा नहीं कर सका: प्रथमतः, जांच की अवधि के दौरान प्रमुख आर्थिक मापदंडों के संबंध में कोई क्षति नहीं हुई और द्वितीय, जांच की अवधि के उपरांत के कोई भी सत्यापन के योग्य साक्ष्य नहीं हैं। एचयूएल का यह कहना है कि ऐसे डाटा के बिना और जांच की अवधि के बाद के डाटा के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रदान न किए जाने पर वर्तमान को क्षति की संभावना न होने के कारण तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

- xxiii. याचिकाकर्ताओं ने पृष्ठ 24 पर अपनी याचिका के तहत प्रमाण प्रस्तुत करने का भार यह प्रमाणित करने के लिए निर्यातकों पर डालने का प्रयास किया है कि पाटन होने की संभावना नहीं है। तथापि, याचिकाकर्ताओं ने न तो पाटन और क्षति की संभावना को प्रमाणित किया है और न ही उन्होंने इसके लिए प्रमाणित करने योग्य और पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किए हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा साक्ष्य के भार के संबंध में दिए गए तर्क निराधार हैं और उनका कोई कानूनी आधार नहीं है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 (1ख) के तहत एक समीक्षा की जरूरत के समर्थन में सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए आवेदन का प्रावधान है। इस प्रकार का आवेदन प्रस्तुत करने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच में एक समीक्षा आरंभ करते हैं जिसके पूरा होने पर यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित शुल्कों को समाप्त करने पर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है तो वे पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करने की सिफारिश कर सकते हैं। नियम में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए यह दिखाना आवश्यक नहीं है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाते हैं तो क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है। रिलायंस के लिए अनिल रिशी बनाम गुरबक्सा सिंह मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार न्यायालय ने यह पाया है कि प्रमाण प्रस्तुत करने का दायित्व हमेशा आवेदन दाखिल करने वाले का होता है और प्रमाण प्रस्तुत करने का दायित्व अन्य पर नहीं डाला जा सकता। अतः एचयूएल का यह अनुरोध है कि याचिकाकर्ता प्रमाण प्रस्तुत करने के अपने दायित्व को अन्य हितबद्ध पक्षकारों पर नहीं डाल सकते। अन्य पक्षकारों को याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सूचना का विश्लेषण और उन पर टिप्पणियां करनी अपेक्षित होती हैं।
- xxiv. कतिपय रबड़ केमिकल्स निर्णायक समीक्षा जांच और सोडियम नाइट्राइट निर्णायक समीक्षा जांच में जारी जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संभावना के निर्धारण के लिए निम्नलिखित मापदंडों का विश्लेषण किया, प्रथम, संबद्ध आयातों की वृद्धि, जिसमें बढ़े हुए आयात की संभावना का उल्लेख किया गया है, दूसरे, एक संबद्ध देश में स्पेयर क्षमताओं का प्रदर्शन करने के साक्ष्य, जिन्हें यदि शुल्कों को हटाया जाता है तो भारत को भेजे जाने की संभावना है, तीसरे, साक्ष्य जो कीमतों में कमी/ रुकावट के प्रभाव की मौजूदगी को प्रमाणित करते हैं और चौथे, जांच की जा रही वस्तु की इवेंट्री के साक्ष्य। इसके अतिरिक्त, पीटीएफई के आयातों के संबंध में लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के संबंध में हाल ही की एक जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अन्य मापदंडों का भी विश्लेषण किया है, जैसे प्रथम, पूर्व जांचों में पाटन मार्जिन, दूसरे भारतीय बाजार की कीमतों में आकर्षकता, और तृसरे, संबंधित उत्पाद और भारतीय बाजार की कीमत संबंधी संवेदनशीलता के संदर्भ में घरेलू उद्योग की संवेदनशीलता। एचयूएल का यह कहना है कि वर्तमान जांच में याचिकाकर्ताओं ने यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त अथवा ठोस साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं कि शुल्क को बंद करने के कारण पाटित आयातों की क्षति की पुनरावृत्ति अथवा क्षति जारी रहेगी।
- xxv. यह प्रमाणित करने के लिए कि क्या वर्तमान में उत्पाद पाटित किए जा रहे हैं अथवा यदि पाटित आयातों में कोई वृद्धि हुई है तो जांच की अवधि के उपरांत के अधिप्रमाणित डाटा का विश्लेषण करना आवश्यक है, जिन्हें याचिकाकर्ताओं ने उपलब्ध नहीं कराया है। उपरोक्त अधिप्रमाणित डाटा के बिना, पर्याप्त रूप से बढ़े आयातों की संभावना का उपयुक्त निर्धारण नहीं हो सकता। उपरोक्त पर पूर्वाग्रह के बिना, चाहे याचिकाकर्ता के आंकड़े आयातों में पर्याप्त वृद्धि दर्शाते हैं, कथित क्षति और संबद्ध आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। अतः यहां तक कि यदि पाटन जारी रहने में कोई अभाव नहीं है तो क्षति जारी रहने में अभाव है, जिसका तात्पर्य यह है कि अब आगे पाटन और क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। सऊदी अरब और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कास्टिक सोडा" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की हाल की निर्णायक समीक्षा जांच में संबंधित प्राधिकारी ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है (अन्य के बीच) कि उनमें घरेलू उद्योग सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर बढ़े आयातों को सहन करने में समर्थ नहीं था और इसके बावजूद सकारात्मक रूप से निष्पादन किया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश नहीं करने का निर्णय लिया गया।

- xxvi. याचिका के पैरा 76 पर, याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि संबद्ध देशों से विदेशी उत्पादकों के पास भारी सरप्लस है और पर्याप्त उत्पादन क्षमता है, और यह कि ईटीआई सोडा जैसे उत्पादकों ने फरवरी, 2017 में अतिरिक्त क्षमता संस्थापित की है। एचयूएल ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य का गहन विश्लेषण करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के ध्यान में यह लाया है कि ऐसे तर्क वास्तव में मात्र अनुमान होते हैं और यह नहीं दर्शाते कि संबद्ध देशों में सरप्लस क्षमताएं मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क लगाते हुए कि ईटीआई सोडा ने फरवरी, 2017 में वर्तमान निदेशों के साथ *** मी. टन की अतिरिक्त क्षमता वृद्धि संस्थापित की है, उस साक्ष्य पर भरोसा किया है, ईटीआई सोडा प्लांट में मार्च, 2009 में एक आयोजन के साथ उत्पादन करना शुरू किया। हमारे संयंत्र अभी भी 1 मिलियन सोडा ऐश और 100 हजार टन सोडियम बाईकार्बोनेट का हर वर्ष उत्पादन करते हैं। फरवरी, 2017 में वर्तमान निदेशों के साथ 600 हजार टन की अतिरिक्त क्षमता वृद्धि को चालू करने की योजना बनाई गई थी। इससे यह स्पष्ट है कि यद्यपि विदेशी उत्पादकों ने सोडा ऐश और सोडियम बाईकार्बोनेट (गैर-विचाराधीन उत्पाद) के लिए अतिरिक्त क्षमता चालू करने की केवल योजना बनाई है, लेकिन इस बात के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि संबद्ध देशों में फ्री सरप्लस क्षमताएं मौजूद थीं। रूस के दूतावास ने दिनांक 25.07.2018 को हुई मौखिक सुनवाई में यह तर्क दिया कि रूस की क्षमताओं में वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा बढ़ा कर दर्शाई गई हैं और यह कि कोई भी बड़ी हुई क्षमताएं केवल मध्यवर्ती उत्पादों के लिए होती हैं न कि विचाराधीन उत्पाद के लिए।
- xxvii. चीन जन. गण., इंडोनेशिया, थाइलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यातित प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा, दिनांक 19.04.2018 की अधिसूचना संख्या 7/8/2017-डीजीएडी में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पाया कि मौजूदा सरप्लस क्षमताओं और क्षमता वर्धन का मूल्यांकन किया जाए ताकि भारतीय बाजार में विपथन की संभावना को तलाशा जा सके। यह निष्कर्ष कि ऐसा विपथन होने की संभावना है, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मौजूदा सरप्लस क्षमताओं और परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों की वृद्धि होने की संभावना के संबंध में कोई प्रमाणित किए जाने योग्य साक्ष्य और सूचना प्रदान किए बिना नहीं हो सकता। एचयूएल का पुनः यह कहना है कि एक निर्णायक समीक्षा में संभावना का विश्लेषण मौजूदा सरप्लस क्षमताओं और विचाराधीन उत्पाद, यदि है तो उसके लिए क्षमता वर्धन, निर्यात अभिमुखीकरण तथा विचाराधीन उत्पाद के लिए जांच की अवधि के उपरांत के डाटा इत्यादि के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसे याचिकाकर्ताओं ने प्रदान नहीं किया है। अतः याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों को अस्वीकार किया जाना चाहिए। इसके पूर्वाग्रह के बिना, यह मानते हुए कि संबद्ध देशों में सरप्लस क्षमताएं हैं, एचयूएल का अनुरोध है कि तथ्य ही अपने आप में सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कास्टिक सोडा" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा में संबंधित प्राधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के निष्कर्ष को बल नहीं देगा।
- xxviii. याचिकाकर्ताओं ने याचिका के पैरा 79 से 81 में यह तर्क दिया है कि टर्की के उत्पादक अपने उत्पादन का विस्तार कर रहे हैं और रूस से उत्पादकों के निर्यातों में उसकी स्थानीय बिक्रियों की तुलना में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। एचयूएल का यह कहना है कि इन दावों के लिए कोई प्रमाणित करने योग्य साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए हैं और इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उनके तर्कों को अस्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, टर्की के उत्पादकों ने दिनांक 25.07.2018 को मौखिक सुनवाई के दौरान यह अनुरोध किया कि उनका मुख्य फोकस बाजार इजिप्ट और यूरोपीय संघ है क्योंकि उनकी टर्की के साथ भौगोलिक समीपता है और भारत उनका मुख्य बाजार नहीं है। यह अनुरोध किया जाता है कि चूंकि भारत टर्की का मुख्य बाजार नहीं है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह देखा जाए कि भारत की बजाए अन्य बाजारों पर उनका ध्यान होने के कारण, टर्की के आयातों की वजह से घरेलू उद्योग को कथित पाटन अथवा कथित क्षति की पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं होगी। अतः एचयूएल का यह अनुरोध है कि चूंकि याचिकाकर्ता कोई पर्याप्त और सत्यापित करने योग्य साक्ष्य तथा सूचना प्रदान करने में विफल रहे हैं, अतः उनका मौजूदा क्षमताओं अथवा क्षमता वर्धन और निर्यात अभिमुखी होने के कारण क्षति की संभावना होने के संबंध में दावा पूरी तरह से नकार दिया जाना चाहिए।
- xxix. याचिकाकर्ताओं ने पैरा 1-3 के तहत उत्पाद के दायरे का वर्णन किया है और उसके लिए अनुरोध किए हैं। एचयूएल को इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। तथापि, यदि उत्पाद के दायरे के संबंध में कोई नई अथवा अतिरिक्त सूचना प्रदान किए जाने की स्थिति में उन पर टिप्पणियां करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

xxx. याचिकाकर्ताओं ने पैरा 4 के तहत समान वस्तु के संबंध में अनुरोध किए हैं। एचयूएल की उस पर कोई टिप्पणियां नहीं हैं। तथापि, यदि उत्पाद के दायरे के संबंध में कोई नई अथवा अतिरिक्त सूचना प्रदान किए जाने की स्थिति में उन पर टिप्पणियां करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

26. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में प्रावधान है:

(1) अधिनियम की धारा 9 क के उपबंध के अंतर्गत लगाया गया कोई पाटनरोधी शुल्क क्षति पहुंचाने वाले पाटन को समाप्त करने के लिए उस अवधि तक और उस सीमा तक लागू रहेगा।

(1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी जहां अपेक्षित हो, अपनी खुद की पहल पर या ऐसे किसी हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर जो ऐसी समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद उचित समयावधि बीत जाती है, किसी पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षा के उपरांत निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में उसकी समाप्ति हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश करेंगे जहां वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त या परिवर्तित कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं है।

(1 ख) उप नियम (1) या (1क) में किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत शुरू की गई कोई समीक्षा ऐसी समीक्षा की शुरुआत की तारीख से 12 माह से अनधिक अवधि के भीतर संपन्न की जाएगी।

(3) नियम 6, 7, 8, 9/10, 11, 16, 17, 18, 19 तथा 20 के उपबंध समीक्षा के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

27. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों संबंधी जांच अवधि के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, यह बताया गया है कि जांच अवधि के बाद के आंकड़े उपलब्ध सीमा तक प्रकटन विवरण में प्रकट किए गए थे और वर्तमान जांच परिणाम में उपलब्ध कराए गए हैं।
28. इस अनुरोध के संबंध में कि टर्की और रूस में अतिरिक्त क्षमता या क्षमता वृद्धि की मौजूदगी के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, यह समुक्ति की गई है कि इन दलीलों पर अंतिम जांच परिणामों में उचित स्थानों पर ध्यान दिया गया है।
29. प्रयोक्ता उद्योग के हित संबंधी अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य समान अवसर वाली प्रतिस्पर्धा सृजित करना है। यह प्रयोक्ता उद्योग के हित में है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों जो घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, से पर्याप्त संरक्षण दिया जाए।
30. पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना संबंधी मुद्दों का वर्तमान जांच परिणामों में समुचित स्थानों पर समाधान किया गया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

31. याचिकाकर्ताओं द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

- i. संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से भेजी जाती हैं। याचिकाकर्ताओं को किसी यानांतरण की जानकारी नहीं है। उद्योग में व्यापक रूप से यह ज्ञात है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी हैं जो अनेक देशों से वस्तुएं खरीदते हैं और उसके बाद भारत को निर्यात करते हैं।

- ii. घरेलू उद्योग ने रूस के बाजार के सूचना प्राप्त करने के प्रयासों के बाद आईएचएस केमिकल ग्लोबल सोडा ऐश में सूचित की गई कीमतों के अनुसार रूस के लिए कीमतों पर विचार किया है। ग्लोबल सोडा ऐश सेवा विश्वव्यापी आधार पर ऐतिहासिक और पूर्वानुमान कीमतों के स्रोत प्रदान करती है। इसकी डाटा के प्राधिकृत होने और लाभप्रदता के बारे में मान्यता और विश्वसनीयता है। चूंकि, जर्नल में उच्च और निम्न कीमतों का उल्लेख है, इसलिए घरेलू उद्योग ने औसत कीमत को स्वीकार किया है।
- iii. घरेलू उद्योग टर्की के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की कीमत की कोई सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ नहीं था। तथापि, भौगोलिक स्थान के संदर्भ में टर्की की रोमानिया से समीपता को देखते हुए रोमानिया और टर्की में कीमतों की उपलब्धता बिल्कुल तुलनात्मक है। यह अनुरोध किया जाता है कि रोमानिया में कीमतों पर टर्की में विचाराधीन उत्पाद की कीमत के लिए उपयुक्त आधार पर विचार किया जा सकता है। घरेलू उद्योग अप्रैल, 2016 से अप्रैल, 2017 की अवधि के लिए रोमानिया में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों के आधार पर टर्की में सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। याचिकाकर्ता मई, 2017 से सितंबर, 2017 तक की अवधि के लिए टर्की में प्रचलित वास्तविक कीमतें प्राप्त कर सके और तदनुसार उन पर विचार किया गया है।
- iv. निर्धारित सामान्य मूल्य चूंकि कारखाना बाह्य स्तर पर है, निर्यात कीमतों को निम्नलिखित व्ययों के लिए समायोजित किए जाने की जरूरत है, जिन्हें संबद्ध देशों से निर्यातकों ने भारत को सामग्री निर्यात करने के लिए खर्च किया है – समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, स्वदेशी यातायात, बंदरगाह व्यय। जब भी याचिकाकर्ता संगत साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकें, याचिकाकर्ताओं ने सबसे अधिक रुढ़ीवादी अनुमानों को अपनाया है और यह अनुरोध किया जाता है कि सभी कीमत समायोजनों को नकार किए जाने के बाद भी पाटन मार्जिन न्यूनतम से ऊपर है।
- v. याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि की गई तुलना की उचित तुलना पर विचार किया जाना चाहिए। कीमतें एक समान व्यापार स्तर को दर्शाती हैं। इसके अलावा, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत, दोनों को कारखाना बाह्य स्तर पर तय किया गया है। सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत उसी अवधि से संबंधित है। इस प्रकार से याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई तुलना में एक उचित तुलना शामिल है। उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि पर्याप्त भी है। अतः पाटनरोधी शुल्कों को लगाने के बाद भी पाटन जारी रहा है।
- vi. प्राधिकारी कृपया यह निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत संस्थाओं के उत्तरों का आकलन करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें कि यदि पाटन जारी रहता है अथवा समाप्त कर दिया जाता है तो क्या पुनरावृत्ति होगी। यह देखा जाएगा कि निर्यातक वस्तुओं का पाटन कर रहे हैं। यदि एमटीआर जांच में भी निर्धारित किया गया था। इसके अलावा, भारतीय बाजार में वर्तमान पाटन न होने की स्थिति में प्राधिकारी को पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना का निर्धारण करना है। यदि पाटन वर्तमान में नकारात्मक है तो उससे संभावना समाप्त होना स्थापित नहीं होता।
- vii. घरेलू उद्योग का प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह रूस के प्रतिभागियों को असहयोगी पक्षकारों के रूप में समझें और उनके द्वारा दाखिल की गई प्रश्नावली के उत्तरों को अस्वीकार करे क्योंकि यह स्वीकार्य तथ्य है कि उनके द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर बिल्कुल ऐसे समय दाखिल किए गए जब सार्वजनिक सुनवाई शुरू होने वाली थी, जिसमें उसका अगोपनीय अंश प्रदान नहीं किया गया। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चूंकि उन्होंने रूस के निर्यातकों द्वारा दाखिल उत्तर प्राप्त किए बिना इस सुनवाई में भाग लिया था, इसलिए सुनवाई अधूरी थी। याचिकाकर्ताओं का निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि कृपया प्रश्नावली उत्तर का अगोपनीय अंश (एनसीवी) उपलब्ध कराएं और उसके बाद सुनवाई तय करें। मौखिक सुनवाई भी तभी प्रभावी हो सकती है, जब बहस पूरी हो। तथापि, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता आवश्यक सूचना प्राप्त हुए बिना सुनवाई के लिए मजबूर हुए। अतः वर्तमान सुनवाई एक अप्रभावी सुनवाई थी और घरेलू उद्योग को संगत दस्तावेज प्राप्त न होने और अपने हितों का बचाव न कर पाने से गंभीर रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त होना पड़ा है। लिखित अनुरोध दाखिल करने का अवसर मौखिक सुनवाई की तरह नहीं है।

अन्य हितबद्ध द्वारा किए गए अनुरोध

32. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:
- i. सोडा सनायी ए.एस. ने पूरी जांच की अवधि के दौरान माननीय प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है और टर्की के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में जांच की अवधि में भारत को किए गए निर्यातों के लिए रिकार्ड पर अपने सभी प्रभावली उत्तर रखे हैं। यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं तो वर्तमान जांच में उनके पूर्ण सहयोग के कारण उत्पादक को व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान किया जाए।
 - ii. सोडा सनायी ए.एस. ने प्रभावली उत्तर दाखिल किया है और प्राधिकारी से अनुरोध है कि उसके द्वारा दाखिल किए गए डाटा के आधार पर सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन की गणना की जाए।
 - iii. याचिकाकर्ताओं ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन की गणना के संबंध में अनुरोध किए हैं। एक प्रयोक्ता के रूप में एचयूएल की इनके निर्धारण के संबंध में कोई टिप्पणियां नहीं हैं। तथापि, एचयूएल का निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वर्तमान जांच में सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा दाखिल सूचना के आधार पर इसकी गणना की जाए।
 - iv. याचिकाकर्ता अपनी याचिका में वर्तमान सूचना और आंकड़ों पर भरोसा करते हैं ताकि पाटन और क्षति का निर्धारण हो सके, लेकिन कई अवसरों पर ऐसे डाटा के स्रोत प्रदान करने में विफल रहते हैं। उदाहरण के लिए, कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की गणना निराधार भत्तों जैसे समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, कमीशन, बैंक प्रभारों, स्वदेशी मालभाड़ा के आधार पर की गई है। ऐसे डाटा के स्रोत के बिना डीएमएआई उसकी विश्वसनीयता का निर्धारण नहीं कर सकता और इसीलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि याचिकाकर्ताओं को सभी उपरोक्त भत्तों के स्रोत का विवरण बताने का निदेश दिया जाए, ऐसा न होने पर अज्ञात स्रोतों के डाटा को अस्वीकार किया जाए।
 - v. सचिव (राजस्व) ने भारत सरकार बनाम डार्स्टफ मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 2015 (322) ईएलटी 3 (एस सी) में उच्चतम न्यायालय ने सेसटेट की व्यवस्था की पुष्टि की है कि व्यापार जर्नल पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन से उपलब्ध तथ्य सर्वोत्तम निर्णय आकलन सिद्धांत पर होते हैं। वर्तमान समीक्षा में याचिकाकर्ताओं ने रूस के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण व्यापार जर्नल आईएचएस केमिकल ग्लोबल सोडा ऐश में उल्लिखित कीमतों के आधार पर निर्धारित किया है। माननीय न्यायालय की राज्य के आधार पर, रूस के लिए याचिका में निर्धारित सामान्य मूल्य को अस्वीकार किया जाए।
 - vi. याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि जांच की अवधि के दौरान टर्की में प्रचलित कीमत के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं थी और इसकी बजाए उसने रोमानिया में प्रचलित कीमतों पर भरोसा किया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि वे टर्की में कीमत से तुलनीय थी और टर्की के लिए सामान्य मूल्य की गणना की गई थी। इस संकल्पना का पूरी तरह से विरोध किया गया था क्योंकि किसी भी याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि उन्होंने रोमानिया के संबंध में डाटा कैसे प्राप्त किए और न ही किसी ने यह स्थापित किया कि रोमानिया से कीमतें क्यों टर्की में कीमतों से तुलनीय मानी जा सकीं। यह संकल्पना अधिनियम की धारा 9क (1) (ग) के प्रावधानों के अनुसार गलत है। इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि दोनों देशों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण केवल सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा दाखिल डाटा के आधार पर किया जाए। याचिका के अनुलग्नक- 3.2 में यह उल्लेख किया गया है कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना निम्नलिखित शीर्षों में व्यापार के उसी स्तर पर करने के लिए समायोजन किए गए हैं : समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बंदरगाह व्यय, स्वदेशी मालभाड़ा और बैंक प्रभार। तथापि, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह प्रकट नहीं किया गया कि इन समायोजनों का स्रोत क्या है और उनकी गणना किस प्रकार की गई थी। याचिका में कारखाना बाह्य कीमत का निर्धारण साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(2) और 5(3) का उल्लंघन है। यह कहा जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए याचिका में निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन गलत है और उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन उनके संबंधित डाटा के आधार पर होना चाहिए।

ज. प्राधिकारी द्वारा जांच

33. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक प्रश्नावली उत्तर टर्की और रूस से उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इसके संबंध में टिप्पणियां आगामी पैरा में दी गई हैं।

मैसर्स सोडा सनायी ए.एस., टर्की (उत्पादक/निर्यातक) के लिए सामान्य मूल्य

34. मैसर्स सोडा सनायी ए.एस. द्वारा दाखिल किए गए उत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की सीधी बिक्रियां की हैं। यह भी नोट किया गया था कि घरेलू बिक्रियां टर्की के संगत और असंगत ग्राहकों को की गई थी। तथापि, संगत ग्राहकों की कीमतें असंगत ग्राहकों की कीमतों से कम थी। इस प्रकार, इस कंपनी के लिए सामान्य मूल्य निकालने के लिए असंगत ग्राहकों की ही घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया था।
35. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत और विचाराधीन उत्पाद से संबंधित एस जी ए व्यय के संबंध में लाभकारी घरेलू बिक्री सौदों का निर्धारण करने के लिए सामान्य व्यापार परीक्षण किया। जहां लाभ कमाने वाले सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी सौदों पर विचार किया है और जहां लाभ अर्जित करने वाले सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं वहां केवल लाभ अर्जित करने वाली घरेलू बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के विचार किया गया है।
36. इस मामले में, सामान्य व्यापार परीक्षण के आधार पर असंगत ग्राहकों को सभी घरेलू बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है क्योंकि लाभ अर्जित करने वाली बिक्रियां 80 प्रतिशत से अधिक थीं। मैसर्स सोडा सनायी ए.एस. ने स्वदेशी मालभाड़ा, वेयरहाउस व्यय, हैंडलिंग और अन्य व्यय, ऋण लागत, रिबेट/छूट के लिए समायोजनों का दावा किया है और उसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई थी। तदनुसार, प्रतिभागी उत्पादक के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य मैसर्स सोडा सनायी ए.एस. के लिए *** यूएस डॉलर प्रति मी. टन निर्धारित किया गया है।

टर्की से सभी उत्पादकों/निर्यातकों का सामान्य मूल्य

37. टर्की से सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के संबंध में, जिन्हें असहयोगी माना गया है, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के तहत उपलब्ध तथ्यों के तहत सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य *** यूएस डॉलर प्रति मी. टन है।

मैसर्स ट्रेड हाउस लि. "बशकिरियन कैमिस्ट्री", रूस (उत्पादक/ निर्यातक) और उसकी संबद्ध कंपनी मैसर्स ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी "बेरेजिनीकी सोडा वर्क्स" (उत्पादक), रूस के लिए सामान्य मूल्य

38. उत्पादक द्वारा दाखिल किए गए उत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स ट्रेड हाउस लि. "बशकिरियन कैमिस्ट्री" मैसर्स ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी "बेरेजिनीकी सोडा वर्क्स" संगत उत्पादक हैं। मैसर्स ट्रेड हाउस लि. "बशकिरियन कैमिस्ट्री" मैसर्स ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी "बेरेजिनीकी सोडा वर्क्स" द्वारा दाखिल उत्तर में, विशेषकर उत्पादन की लागत के संबंध में काफी कमी है। तदनुसार, प्राधिकारी मैसर्स ट्रेड हाउस लि. "बशकिरियन कैमिस्ट्री" मैसर्स ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी "बेरेजिनीकी सोडा वर्क्स" द्वारा किए गए दावों के अनुसार उत्पादन की लागत को अस्वीकार करते हैं और इसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

मैसर्स पब्लिक स्टॉक कंपनी क्रीमिया सोडा प्लांट, रूस (उत्पादक/निर्यातक) के लिए सामान्य मूल्य

39. मैसर्स पब्लिक स्टॉक कंपनी क्रीमिया सोडा प्लांट द्वारा दाखिल किए गए उत्तर से यह नोट किया जाता है कि मैसर्स पब्लिक स्टॉक कंपनी क्रीमिया सोडा प्लांट संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक और निर्यातक है। मैसर्स पब्लिक स्टॉक कंपनी क्रीमिया सोडा प्लांट द्वारा दाखिल किए गए उत्तर में विशेषकर उत्पादक की लागत के संबंध में काफी कमी है। तदनुसार, मैसर्स पब्लिक स्टॉक कंपनी क्रीमिया सोडा प्लांट द्वारा किए गए दावों के अनुसार उत्पादन की लागत को अस्वीकार करते हैं और इसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

रूस से अन्य उत्पादकों/निर्यातकों का सामान्य मूल्य

40. रूस से अन्य सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के संबंध में, जिन्हें असहयोगी माना गया है, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (8) के तहत उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य *** यूएस डॉलर प्रति मी. टन है।

झ. निर्यात कीमत**मैसर्स सोडा सनायी ए.एस., टर्की (उत्पादक/निर्यातक) के लिए निर्यात मूल्य**

41. मैसर्स सोडा सनायी ए.एस. द्वारा दाखिल उत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स सोडा सनायी ए.एस. संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक और निर्यातक है। जांच की अवधि के दौरान, मैसर्स सोडा सनायी ए.एस. ने भारत को सीधे संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। स्वदेशी मालभाड़ा, ऋण लागत, हैंडलिंग व्यय, कमीशन, बीमा, विदेशी मालभाड़ा और विदेशी विनिमय हानि के लिए समायोजन के लिए उत्पादक/ निर्यातक द्वारा दावा किया गया है। स्वदेशी मालभाड़ा, ऋण लागत, हैंडलिंग व्यय, कमीशन, बीमा और विदेशी मालभाड़ा के संबंध में समायोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। तदनुसार, भारत को निर्यातों के लिए निर्धारित निवल निर्यात कीमत *** यूएस डॉलर प्रति मी. टन के रूप में निर्धारित की गई है।

मैसर्स ट्रेड हाउस लि. "बशकिरियन कैमिस्ट्री", रूस (उत्पादक/निर्यातक) और उसकी संबद्ध कंपनी मैसर्स ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी "बेरेजिनीकी सोडा वर्क्स" (उत्पादक), रूस के लिए निर्यात कीमत

42. उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा दाखिल उत्तर से, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स ट्रेड हाउस लि. "बशकिरियन कैमिस्ट्री" मैसर्स ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी "बेरेजिनीकी सोडा वर्क्स" संगत उत्पादक हैं और उन्होंने जांच की अवधि के दौरान मैसर्स ट्रेड हाउस लि. "बशकिरियन कैमिस्ट्री" के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। स्वदेशी मालभाड़ा और विदेशी मालभाड़ा के लिए समायोजन के लिए उत्पादक/निर्यातक द्वारा दावा किया गया है और इसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। तदनुसार, भारत को निर्यातों के लिए निर्धारित की गई निवल निर्यात कीमत *** यूएस डॉलर प्रति मी. टन है।

मैसर्स पब्लिक स्टॉक कंपनी क्रीमिया सोडा प्लांट, रूस (उत्पादक/ निर्यातक) के लिए निर्यात कीमत

43. मैसर्स पब्लिक स्टॉक कंपनी क्रीमिया सोडा प्लांट द्वारा दाखिल किए गए उत्तर से यह नोट किया जाता है कि यह कंपनी संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक और निर्यातक है। यह भी नोट किया जाता है कि मैसर्स पब्लिक स्टॉक कंपनी क्रीमिया सोडा प्लांट ने एक संगत कंपनी के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है जिसने कि निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है। मैसर्स पब्लिक स्टॉक कंपनी क्रीमिया सोडा प्लांट द्वारा दाखिल किए गए निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में विशेषकर उत्पादन की लागत के संबंध में काफी कमियां हैं। संगत व्यापारी से सूचना के अभाव में और मैसर्स पब्लिक स्टॉक कंपनी क्रीमिया सोडा प्लांट द्वारा दाखिल किए गए कमी से संबंधित उत्तर को देखते हुए प्राधिकारी मैसर्स पब्लिक स्टॉक कंपनी क्रीमिया सोडा प्लांट द्वारा दाखिल किए गए उत्तरों को अस्वीकार करते हैं और इसकी बजाए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित करते हैं।

टर्की से असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

44. प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर टर्की से असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। तदनुसार, टर्की से निर्यातों के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

रूस से असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

45. प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रूस से असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। तदनुसार, रूस से निर्यातों के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

ज. संबद्ध देशों में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण

46. उपरोक्त सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध वस्तुओं के सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन को इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

क्रम सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	सीएनवी/ एनवी (यूएस डॉलर/मी. टन)	निवल निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/मी. टन)	पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/मी. टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
1.	टर्की	सोडा सनायी ए.एस.	सोडा सनायी ए.एस.	***	***	***	***	30-35%
2.	टर्की	कोई अन्य	कोई अन्य	***	***	***	***	45-50%

3.	रूस	ट्रेड हाउस लि. «बशकीरियन कैमिस्ट्री»	ट्रेड हाउस लि. «बशकीरियन कैमिस्ट्री»	***	***	***	***	55-60%
4.	रूस	ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी “बेरिजिनीका सोडा वर्क्स”	ट्रेड हाउस लि. «बशकीरियन कैमिस्ट्री»	***	***	***	***	55-60%
5.	रूस	कोई अन्य	कोई अन्य	***	***	***	***	75-80%

ट. क्षति निर्धारण के लिए कार्यपद्धति और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

47. इस संबंध में, याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में यह प्रावधान है कि समान वस्तु के घरेलू उत्पादन के संबंध में पाटित वस्तुओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा जब उपलब्ध डाटा से उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादकों की बिक्रियों और लाभों जैसे मानदंडों के आधार पर उस उत्पादन की अलग पहचान होती है। यदि उस उत्पादन की ऐसी अलग पहचान संभव नहीं है तो पाटित आयातों के प्रभावों का सबसे समीपवर्ती समूह अथवा उत्पादों की रेंज के अनुसार उत्पादन की जांच करके मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है जिसमें समान उत्पाद शामिल हैं जिसके लिए आवश्यक सूचना प्रदान की जा सकती है। भाग लेने वाली कंपनियां बहु उत्पाद की वाली कंपनियां हैं और समान वस्तु के संबंध में व्यावहारिकता के अनुसार और पृथक उपलब्धता के अनुसार संगत सूचना प्रदान की है। तथापि, ऐसी स्थितियों में, जहां समान वस्तु के संबंध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि उस सूचना की पृथक पहचान तर्कसंगत रूप से उपलब्ध नहीं है तो नजदीकी समूह अथवा उत्पादों की रेंज के संबंध में सूचना प्रदान की गई है जिसमें समान वस्तु शामिल है और उसके लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध है और अनुबंध-II के प्रावधानों के अनुरूप सूचना प्रदान की जा सकती है।
- याचिकाकर्ताओं ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के रूप में परिभाषित किया है। घरेलू वस्तुओं की मांग/ खपत में प्रस्तावित जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में 2015-16 तक गिरावट आई है। तथापि, प्रस्तावित जांच की अवधि में इसमें निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में आयात आधार वर्ष की तुलना में अधिक थे और क्षति की अवधि में तो सबसे उच्च स्तर पर थे। घरेलू उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में भी 2015-16 तक गिरावट आई है और उसके बाद प्रस्तावित जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
- प्रस्तावित जांच की अवधि में आयात कीमत में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जिससे यह पता चलता है कि आयात से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही थी और पाटनरोधी शुल्क न होने पर घरेलू बिक्री कीमतों में आगे भी कटौती होगी। मालभाड़ा लागत संबद्ध वस्तुओं की उत्पाद लागत का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। सोडा ऐश के भारतीय उत्पादक गुजरात में स्थिति हैं, लेकिन बिक्रियां पूरे भारत में की जाती हैं। संबद्ध वस्तुएं भी तुलनात्मक रूप से कम कीमत के उत्पाद हैं। इस प्रकार, उत्पाद की बिक्री कीमत से तुलना करने पर मालभाड़ा लागत का प्रभाव उत्पाद के प्रति मी. टन बहुत ही आकलित किया गया है। इसे देखते हुए यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना में केवल मालभाड़ा लागतों को शामिल करने के बाद आयातों की पहुँच कीमत से की जानी चाहिए। इसके अलावा, जबकि घरेलू मालभाड़ा बढ़ रहा है, समुद्री मालभाड़ा कीमतें घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रही हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों से, भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण कीमत कटौती हो रही है। तथापि, यह नियम यह नहीं बताता कि कैसे निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निर्धारित करना चाहिए कि भारत में समान उत्पाद की कीमत से तुलना करने पर पाटित आयातों से महत्वपूर्ण कीमत कटौती हो रही है। यद्यपि, निर्दिष्ट प्राधिकारी की वर्तमान प्रथा बंदरगाह स्तर पर आयातों की पहुँच कीमत और कारखाना बाह्य स्तर पर आयातों की पहुँच कीमत और कारखाना बाह्य

स्तर पर घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण करने के लिए है, याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि कीमत कटौती के निर्धारण के लिए कोई एक कार्यप्रणाली नहीं है। इस अवस्था में, याचिकाकर्ताओं ने घरेलू उत्पाद पर उनके द्वारा भुगतान किए गए कारखाना बाह्य व्यय को शामिल किया है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ये मालभाड़े की पूरी कीमत को नहीं दर्शाते। पाटनरोधी नियम उचित तुलना के सिद्धांत के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान करते हैं और स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति दर्शाते हैं जहां पर कारखाना बाह्य स्तर से अलग स्तर पर तुलना की गई हो। निर्दिष्ट प्राधिकारी से भारत सरकार द्वारा डब्ल्यूटीओ में परिचालित कागजात को ध्यान में रखने का अनुरोध है जिसमें भारत सरकार ने यह कहा है कि पाटित आयात की सावधि कीमत को लागत, बीमा और मालभाड़ा अथवा सीमा शुल्क बाह्य क्षेत्र अथवा आयात की पुनर्विक्री कीमत अथवा ग्राहक को प्रदान की गई कीमत, जैसे किसी स्तर पर आयात कीमत के अर्थ से लिया जाएगा, बशर्ते कि उप पैरा 1.1 के तहत समान उत्पाद की कीमत अथवा उप पैरा 1.2 के तहत लक्ष्य कीमत के साथ तुलना क्षति मार्जिन के निकालने के प्रयोजन से केवल एक तुलनीय स्तर पर की गई है। यदि यह भारत सरकार की स्थिति है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि घरेलू उद्योग को इसे झेलने दिया जाए और यह आशा है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी 146 डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के समक्ष भारत के तर्क को स्वीकार नहीं करेगा।

iv. याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि तीन प्रकार के मालभाड़े हो सकते हैं – (क) कारखाने से डिपो तक का मालभाड़ा, जो व्यय में शामिल है और उद्योग द्वारा वहन किया जाता है, (ख) भुगतान किया गया और वसूला गया मालभाड़ा (जिसमें विक्रेता मालभाड़े के लिए व्यवस्था करता है और उसके लिए भुगतान करता है लेकिन बाद में विक्रेता द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाती है और (ग) क्रेता द्वारा भुगतान किया गया मालभाड़ा (जिसमें परिवहन के लिए व्यवस्था की जाती है लेकिन उसके लिए प्रभारों का भुगतान केवल क्रेता द्वारा किया जाता है)। याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि कारखाने से डिपो तक के मालभाड़े को निकालने का कोई कारण नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है बल्कि यह व्ययों का भाग है जो लेखा बहियों से सत्यापित किया जा सकता है और ये केवल वस्तुओं के लिए एक विस्तारित फैक्ट्री गेट तक ले जाने के लिए किया गया व्यय मात्र है। घरेलू उद्योग ने भारत और यूक्रेन के मूल के पोर्टेशियम परमैंग्रेट के संबंध में इसी का संदर्भ दिया है जिसमें कि निर्यातक फैक्ट्री से डिपो तक की परिवहन लागत के भाड़े की मांग की थी और उसे यह व्यवस्था देते हुए अस्वीकार कर दिया गया था कि संयंत्र और डिपो उसी आर्थिक और कानूनी संस्था का हिस्सा है। मामले का सामान्य पाटन करने से ही यह स्पष्ट है कि यदि माल को फैक्ट्री से डिपो तक भेजा जाता है तो माल को इंटेंट्री का भाग माना जाता है। घरेलू उद्योग की निर्दिष्ट प्राधिकारी से आबकारी प्राधिकारी साथ चर्चा की मांग करने की मंशा नहीं है ताकि वे कारखाना बाह्य कीमतों के रूप में विचार करें। घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि डिपो कीमतों को एनआईपी की गणना और बिक्री कीमत के प्रयोजन से कारखाना बाह्य कीमतों के रूप में माना जाए।

v. याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि कीमत कटौती को ऐसे आयात सौदों पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए जिनकी आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। याचिकाकर्ताओं की चिन्ता क्षतिकारी आयातों के लिए है न कि गैर-क्षतिकारी आयातों के लिए। ब्राजील से मैलिएबल फैस आयरन ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग के संबंध में पाटनरोधी शुल्क पर इसी के मामले में यह देखा जा सकता है कि – (क) अनुच्छेद 3.2 के तहत संबंधित उत्पाद और समान उत्पाद से संबंधित हर सौदे की जांच के आधार पर एक सिंगल मार्जिन कटौती प्रमाणित करने के लिए कोई अपेक्षा नहीं है, (ख) एक ऐसी अपेक्षा, जिसमें किसी जांच प्राधिकारी का कीमत कटौती विश्लेषण एक ऐसी कार्यप्रणाली के आधार पर हो कि ऑफसेट कटौती कीमतें और "ओवरकटिंग" कीमतें जांच प्राधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकालने के परिणामस्वरूप होगी कि जब कोई कीमत कटौती मौजूद नहीं है तो वास्तव में उसमें अनेक विचारणीय बिक्रियां हो सकती हैं, जो कीमतों में कटौती करती हों, (ग) कीमत कटौती की मात्रा का घरेलू उद्योग पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा जो परिवर्तनों के कारण होगा, कटौती कीमतों पर बिक्रियां और ऐसी बिक्रियों से कीमत कटौती की मात्रा। कीमत कटौती की बिक्रियों की संख्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे घरेलू उद्योग को बिक्रियों की हानि की संभावित संख्या के लिए एक सूचक प्राप्त होगा। ऐसी बिक्रियों की कटौती का मार्जिन यहां तक संगत है कि गैर-कीमत संवेदी उत्पादों में कम मात्रा में कीमत कटौती के संबंध में खरीददार की निर्णय लेने में कोई निर्णायक भूमिका नहीं होती और (घ) सभी बिक्रियों, चाहे वे कीमतों में कटौती की है अथवा नहीं, के औसत मार्जिन की गणना, किसी घरेलू उद्योग पर कीमत कटौती के प्रभाव का

आकलन करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी तरीके नहीं हो सकता क्योंकि इससे इन दो प्रकारों की जांच करने के लिए जांच प्राधिकारी की स्वतंत्र योग्यता सीमित हो जाती है।

- vi. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत की तुलना से यह पता चलता है कि वर्ष 2016-17 तक उत्पादन की लागत में गिरावट आई थी और उसके बाद प्रस्तावित जांच अवधि के अंतिम छः महीनों में वृद्धि हो गई, जबकि बिक्री कीमत में 2015-16 तक की वृद्धि हुई और तब प्रस्तावित जांच की अवधि में गिरावट आई। इस प्रकार, आयातों में प्रस्तावित जांच की अवधि के अंतिम छः माह के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों पर दमनकारी प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क मामले को समाप्त कर दिया जाएगा तो पाटन से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर आगे दमनकारी/ गिरावट का प्रभाव पड़ेगा। प्रस्तावित जांच की अवधि में आयात की कीमत में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। जबकि उत्पादन की लागत में पूरे विश्व में वृद्धि हुई है, क्योंकि टर्की के उत्पादक प्राकृतिक सोडा ऐश से संबद्ध हैं, आयात कीमत में 2015-16 और एच-1, 2017-18 के बीच करीब 25 प्रतिशत (***) रुपए प्रति मी. टन) तक गिरावट आई है, आयात की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिसमें 2016-17 की तुलना में आयातों में 370 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई गई है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में निरपेक्ष संदर्भ में और भारत में उत्पादन व खपत के संदर्भ में प्रस्तावित जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर दमनकारी/ गिरावट का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है।
- vii. प्रोफार्मा IV-क (भाग-II) में इन मापदंडों के संबंध में याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के निष्पादन से, यह देखा जा सकता है कि (क) याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग ने देश में बढ़ती मांग को देखते हुए प्रस्तावित क्षति की अवधि के दौरान अपनी क्षमताओं में वृद्धि की है, (ख) घरेलू उद्योग के उत्पादन में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, लेकिन यह पाटन न होने पर जो वृद्धि होती, उससे कम है। ऐसी परिस्थितियों में पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होगी, (ग) याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की क्षमता के उपयोग में 2014-15 में सुधार आया है लेकिन उसके बाद जांच की अवधि तक गिरावट आई है, (घ) याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों की मात्रा में प्रस्तावित जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, जबकि क्षमता में वृद्धि *** प्रतिशत, उत्पादन में वृद्धि *** प्रतिशत और बिक्रियों में वृद्धि *** प्रतिशत हुई है। यह विचार करते हुए कि आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है, यह संभावना है कि आयातित वस्तुओं की मांग में पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पर्याप्त वृद्धि होगी, (ङ) पाटनरोधी शुल्क 2012 में लगाए गए थे। उद्योग को 2011-12 में नुकसान हो रहा था और 2013-14 तक लाभ और आरओआई प्राप्त करने का स्तर कम रहा। पाटनरोधी शुल्क लग जाने के बाद घरेलू उद्योग की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आया और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों ने यह पाया कि क्षमता के विस्तार के लिए बाजार निवेश के लिए व्यवहार्य है। मौजूदा और नए उत्पादकों द्वारा भारत में महत्वपूर्ण क्षमताएं जोड़ी गई हैं। एक याचिकाकर्ता निरमा ने प्रस्तावित जांच की अवधि के दौरान *** मी. टन क्षमता जोड़ी है जबकि जीएचसीएल ने *** मी. टन तक क्षमता जोड़ी है। अब घरेलू उद्योग के संरक्षण की अधिक जरूरत है।
- viii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2015-16 तक सुधार आया है। वर्ष 2016-17 में लाभप्रदता में गिरावट आई है। लगाई गई पूंजी पर नकदी प्रवाह और प्रतिफल में भी 2015-16 तक वृद्धि हुई थी और उसके बाद प्रस्तावित जांच की अवधि में गिरावट आई। कीमत मापदंडों ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर सुधार दर्शाया है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से लाभ में गिरावट आएगी। घरेलू उद्योग को 2013-14 तक कम स्तर पर लाभ और आरओआई प्राप्त हो रहा था। क्षति की अवधि के दौरान लाभ और आरओआई में वृद्धि हुई, लेकिन विगत वर्ष की तुलना में प्रस्तावित जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई। पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जिसके कारण घरेलू उद्योग को इन मापदंडों में और भी गिरावट का सामना करना पड़ा जिसमें लाभ में तर्कसंगत स्तर पर गिरावट आई। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के विस्तार के प्रश्न पर विचार करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया देश में इन क्षमताओं की संस्थापना पर संभव प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करें। इन निवेशों में तर्कसंगत रूप से व्यावहारिक होने के लिए *** रुपए प्रति मी. टन का न्यूनतम तर्कसंगत प्रतिफल अपेक्षित है। इस आवश्यक प्रतिफल के लिए घरेलू उद्योग द्वारा क्षति की अवधि के दौरान अर्जित औसत प्रतिफल काफी कम था। यदि वे इन लाभों को अर्जित करना जारी रखेंगे तो आने वाले समय में नए निवेश होंगे जिनसे परिसंपत्तियों का कार्यकाल भी बढ़ेगा। इस अवस्था में पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने से इन निवेशों को गंभीर नुकसान

होगा। मैसर्स घड़ी *** करोड़ रुपए के निवेश पर *** मी. टन की क्षमता उत्पादन का एक नया ग्रीन प्लांट लगा रहा है। इन नए निवेशों की व्यवहार्यता दांव पर है।

- ix. क्षमता में वृद्धि होने के बावजूद व्याज लागत और मूल्यहास लागत में गिरावट आई है, अतः क्षमता में वृद्धि लाभों में गिरावट के लिए कारण नहीं है। लाभों में गिरावट आई है क्योंकि टर्की से आयात कीमत में गिरावट आई है और टर्की से ऐसे पाटित आयातों में वृद्धि हुई है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद घरेलू उद्योग पर आयातों के दमनकारी प्रभाव पड़ने शुरू हो गए हैं। यह पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की संभावित स्थिति को दर्शाता है, जहां घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में महत्वपूर्ण गिरावट आएगी। फोरम ऑफ एंटीलिंक फाइबर मैनुफैक्चर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामला का हवाला देना आवश्यक है जिसमें कि माननीय न्यायाधिकरण ने लाभों के संबंध और महत्व समुचित रूप से उल्लेख किया है। याचिकाकर्ताओं ने नए संयंत्रों की पृथक लाभप्रदता का निर्धारण किया है जिनकी संगत सूचना गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई है। यह देखा जाएगा कि नए संयंत्र की लाभप्रदता पुराने संयंत्र की तुलना में पर्याप्त रूप से कम है। अतः यदि घरेलू उद्योग ने अच्छा लाभ कमाया है तो वह केवल इस तथ्य के कारण से है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेश काफी कम मूल्य पर हैं। जहां तक नए निवेशों का संबंध है, घरेलू उद्योग को बहुत ही कम आरओआई प्राप्त होने की संभावना है, यदि घरेलू उद्योग कीमत और लागत संरचनाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखता है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के बाद घरेलू उद्योग को इन कीमतों को कम करना पड़ेगा जिससे आरओआई में और भी गिरावट आएगी।
- x. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का बाजार अंश 2015-16 तक बढ़ा था और प्रस्तावित जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई थी, जबकि याचिकाकर्ताओं ने अपनी क्षमताओं में वृद्धि की है। दूसरी ओर आयातों के बाजार अंश में 2015-16 तक गिरावट आई है और प्रस्तावित जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने पर घरेलू उद्योग को अपने बाजार अंश का घाटा होने की संभावना है। इसके अलावा, संबद्ध देशों में क्षमताओं के विस्तार के साथ इन देशों के घरेलू अंश में पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शानी शुरू कर दी है। आवेदक उत्पादकों का बाजार अंश लगभग उतना ही रहा जबकि अन्य भारतीय उत्पादकों ने गिरावट दर्शाई।
- xi. याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि रोजगार के मापदंड, मजदूरी और उत्पादकता अन्य मापदंडों पर निर्भर करते हैं और इनसे घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रभाव का पता नहीं चलता। मजदूरी में क्षति की अवधि में सुधार दिखाई दिया है। तथापि, ये संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन पर पूर्णतया निर्भर करते हैं क्योंकि ये देश में कई कानूनी अपेक्षाओं और अन्य कारोबारी बाध्यताओं से संचालित होते हैं।
- xii. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की औसत इन्वेंट्री में प्रस्तावित जांच की अवधि में बहुत ही महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- xiii. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का विकास उत्पादन, घरेलू बिक्रियों की मात्रा के संदर्भ में सकारात्मक था, तथापि, लाभों और आरओसीई के संदर्भ में विकास सकारात्मक था और प्रस्तावित जांच की अवधि में नकारात्मक हो गया। याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग पाटन के प्रभावों से केवल लागू पाटनरोधी शुल्कों के कारण उबर रहा है।
- xiv. यद्यपि, घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क की संरक्षण छत्रछाया के तहत वर्तमान क्षति की अवधि के दौरान निवेश किए हैं, लेकिन यह संभव है कि पूंजीगत निवेश जुटाने के लिए उनकी योग्यता पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- xv. पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद, संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा पाटित की जा रही हैं। यदि शुल्कों को हटा लिया गया तो पाटन में तेजी आएगी और घरेलू उद्योग को क्षति का कारक होगी।
- xvi. पाटन करने वाले देशों से आयात कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धा, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक, जिनसे घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं, का एक विश्लेषण यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों और अन्य देशों से संबद्ध उत्पादों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से कम है जिससे भारतीय बाजार में गंभीर कीमत कटौती हो रही है। अतः यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए जिम्मेदार कारकों में केवल उत्पाद की आयात कीमतें और घरेलू उद्योग की

उत्पादन लागत है, क्योंकि आयात कीमतें घरेलू कीमतों और लागतों से काफी कम हैं, इसलिए, घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों में वृद्धि करने से रोकती है।

- xvii. दोनों ही संबद्ध देशों से पाटन का मार्जिन महत्वपूर्ण और सकारात्मक है। घरेलू उद्योग यह समझता है कि टर्की के उत्पादकों को आवधिक प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होने का लाभ प्राप्त है और इसलिए उनकी उत्पादन की लागत भारत में प्रयुक्त सिंथेटिक सामग्रियों की तुलना में कम है। तथापि, इसके बाद भी टर्की के निर्यातक पाटन प्रक्रियाओं का सहारा ले रहे हैं क्योंकि वे भारत को उनके सामान्य मूल्य से काफी कम कीमत पर निर्यात कर रहे हैं जिनसे आयातों में भारी वृद्धि हुई है। उत्पादन की कम लागत होना किसी भी तरह से संबद्ध निर्यातकों को यह हक नहीं देता कि अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं में शामिल हों। टर्की में प्रकाशित कीमतें भारत को निर्यात कीमत से अधिक हैं। टर्की में उत्पादक घरेलू बाजार में अधिक कीमतों पर बिक्री कर रहे हैं बल्कि कम कीमतों पर निर्यात भी कर रहे हैं, ताकि बढ़ते भारतीय बाजार में बाजार अंश प्राप्त कर सकें और अपनी क्षमता विस्तार का उपयोग कर सकें।
- xviii. डाटा और विश्लेषण यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में 2015-16 तक सुधार हुआ है और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई है। यद्यपि, निरपेक्ष निष्पादन बुरे स्तर पर नहीं था, पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के कारण क्षति में तेजी आने पर घरेलू उद्योग की स्थिति बिल्कुल ही नाजुक और कमजोर है।
- xix. बिक्री, उत्पादन और बाजार अंश में वृद्धि केवल क्षति न होने को दर्शाता है न कि क्षति की संभावना न होने को। घरेलू उद्योग पाटन जारी न रहने के चलते उत्पादन और बिक्री अधिक कर सकता था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि क्षमताओं में वृद्धि होने के कारण क्षमता के उपयोग में गिरावट आई है, लेकिन संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण बाजार अंश हासिल करने और संस्थापित क्षमताओं निरर्थक किया है।
- xx. याचिकाकर्ताओं ने क्षति जारी रहने का दावा नहीं किया है। जहां तक घरेलू उद्योग की कीमतों को देश में पाटित आयातों की मौजूदगी के बाद घटाए नहीं जाने के संबंध में किए गए तर्कों का संबंध है, घरेलू उद्योग का यह कहना है कि कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से काफी कम हैं। कथित महत्वपूर्ण आरओआई केवल इस तथ्य के कारण से है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेश काफी कम करके बताए गए हैं। इस प्रकार से यह अधिक आरओआई का मामला नहीं है बल्कि कार्यप्रणाली की अनुपयुक्तता का है। जहां तक सीएनवी के लिए 5 प्रतिशत लाभ का संबंध है, यह विचार किए जाने की जरूरत है कि यह कोई कानून नहीं है बल्कि वास्तविक लाभ के लिए बनावटीपन है और जब वास्तविक लाभ उपलब्ध नहीं हों तो बेहतर उपलब्ध सूचना के सिद्धांत के तहत प्रयोग में लाया जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही है, इसमें इस तर्क के लिए कोई आधार नहीं है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए 5 प्रतिशत लाभ एक उपयुक्त लाभ है। याचिकाकर्ता बेड लिनेन के मामले में डब्ल्यूटीओ के मामले का हवाला देते हैं, जहां अपील निकाय ने पैनल के निष्कर्ष को पलट दिया कि अनुच्छेद 2.2.2(ii) की एक व्याख्या, जिसके तहत बिक्रियां सामान्य व्यापार प्रक्रिया में नहीं, निर्मित सामान्य मूल्य की गणना में प्रयुक्त किए जाने वाले लाभ के निर्धारण से बाहर की गई है, की अनुमति है। अपील निकाय ने इस बात पर जोर दिया कि इसकी बजाए, वह खर्च की गई और अन्य निर्यातकों व उत्पादकों द्वारा प्राप्त वास्तविक राशि का उल्लेख करे और यह निष्कर्ष दिया कि इस व्याख्या को देखते हुए, भारित औसत की गणना में समस्त वास्तविक धनराशि शामिल की जानी है, चाहे उल्लिखित बिक्रियां सामान्य व्यापार अवधि के दौरान हुई अथवा नहीं। इस प्रकार से विचाराधीन उत्पाद के लिए लाभ पर वास्तविक आधार पर विचार किया जाना है न कि उत्पादन की लागत संबंधी कुछ बनावटी प्रतिशतता के आधार पर।
- xxi. यह आश्चर्यजनक है कि हितवद्ध पक्षकार यह तर्क दे रहे हैं कि उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क का दुरुपयोग किया है। वास्तव में, यह तर्क निर्दिष्ट प्राधिकारी को केवल भावनात्मक पूर्वाग्रह की ओर ले जाने के लिए है। यदि उपभोक्ता उद्योग की लाभप्रदता की जांच की जाए तो यह देखा जाएगा कि अधिकांश खपत संबंधी घटकों में उसने महत्वपूर्ण सुधार दर्शाया है। इसके अलावा, यदि घरेलू उद्योग पर वर्तमान मूल्य पर विचार किया जाए तो उद्योग की लाभप्रदता तर्कसंगत लाभ बेंचमार्क से कम है। यह उच्च लाभ अथवा आरओआई का मामला नहीं है। यह आरओआई के निर्धारण के लिए अनुपयुक्त कार्यप्रणाली का मामला है। यदि भारतीय बाजारों में कीमतों की तुलना अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों से की जाए तो यह देखा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतें वास्तव में भारतीय बाजार में प्रचलित कीमतों से अधिक हैं। उपभोक्ता लागत जुटाने के संबंध में आरोप भी बिना किसी सबूत के हैं। यदि सोडा ऐश की वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं और यदि उपभोक्ता

वैश्विक रूप से अधिक भुगतान कर रहे हैं तो बिना किसी विधिवक और तथ्यात्मक आधार के यह तर्क है कि भारत में कीमतें चुन-चुनकर बढ़ाई गई हैं। इन सबके बावजूद, घरेलू उद्योग उचित संरक्षण की ओर देख रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभों के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षमता विस्तार किए गए हैं। घरेलू उद्योग उचित कीमत के आयातों के खिलाफ नहीं हैं। निर्यातकों को ऐसी सामान्य कीमत पर निर्यात करने के लिए छूट है, जिस पर वे अपने घरेलू बाजार में बिक्री कर रहे हैं। यदि घरेलू उद्योग उसके बाद क्षति का सामना करता है तो पाटनरोधी शुल्क घरेलू बाजार की मदद नहीं कर सकते। तथापि, यदि आयात ऐसी कीमतों से कम पर हो रहे हैं, तो उपभोक्ता यह तर्क नहीं दे सकते कि वे पाटित कीमतों पर सामग्री चाहते हैं।

- xxii. घरेलू उद्योग को पाटन के बावजूद कोई क्षति नहीं हुई क्योंकि पाटनरोधी शुल्क लगाया हुआ है। घरेलू उद्योग को क्षति होगी, यदि उसे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद आयातों की कीमतों की तुलनी करनी है।
- xxiii. डाटा और विश्लेषण यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में 2015-16 तक सुधार आया है और उसके बाद जांच की अवधि में मामूली गिरावट आई है। यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा में वृद्धि हुई है क्योंकि संबद्ध वस्तुओं की पहुँच कीमतों में वृद्धि हुई है। चूंकि, जांच की अवधि में आयात की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है, पहुँच कीमत में कमी आई है, यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाते हैं तो आयात की मात्रा और पहुँच कीमत की संभावित प्रवृत्ति दर्शाई है। वर्तमान शुल्कों की मौजूदगी के बावजूद देश में पाटित वस्तुओं की मौजूदगी है और उनसे घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को शामिल करने अथवा शामिल किए बिना, कटौती हो रही है। यद्यपि, निरपेक्ष निष्पादन सामग्री क्षति को नहीं दर्शाते, लेकिन घरेलू उद्योग की स्थिति पाटनरोधी शुल्क समाप्त न होने की अवस्था में नाजुक और कमजोर है।
- xxiv. जांच की अवधि से पूर्व की तीन वर्षों की अवधि और जांच की अवधि घरेलू उद्योग पर अनुचित व्यापार के क्षतिकारी प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए शामिल की गई है। विश्लेषण में उस प्रवृत्ति का अध्ययन शामिल है, जो जांच की अवधि के दौरान गठित किया गया न कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक की तुलना से पूर्व/आयात की मात्रा में जांच की अवधि में वृद्धि में सहायता के लिए 2015-16 तक कमी आई है। आयातों में वृद्धि के साथ ही आयात की कीमतों में वृद्धि हुई है, जो उत्पादन की लागत में किसी कमी के बिना हुई है। विशेष रूप से, टर्की से आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के आगे आयात में वृद्धि होने की संभावना है। पहुँच कीमतों के कारण से दमन/ गिरावट न होने के मामले पर यह कहना है कि यद्यपि आतों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर ऐसे प्रभाव पहले से ही पड़ने शुरू हो गए हैं जो कि जांच की अवधि के अंतिम छः माह से दिखाई देने लगे हैं, संभावना के विश्लेषण के लिए, प्राधिकारी को संभावित दमन/ गिरावट के प्रभावों पर विचार करने की जरूरत है न कि वास्तविक प्रभाव की। यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने दिया जाता है तो घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को तत्काल घटाने पर मजबूर होगा और उसके बाद आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर दमनकारी/ गिरावट का प्रभाव पड़ेगा।
- xxv. विभिन्न हितधारक इस बात पर सहमत हैं कि घरेलू उद्योग का परिवहन लागत को शामिल करने का दावा काफी तर्कसंगत है। मौजूदा प्रक्रिया का तर्क पुनः त्रुटिपूर्ण है। सबसे पहले तो, निर्दिष्ट प्राधिकारी को मूल तथा प्रथम अंतिम समीक्षा जांच दोनों में व्हाइट सीमेंट के मामले में वास्तव में कीमत कटौती और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए मालभाड़े पर विचार किया है। इसके अलावा, यह निर्दिष्ट प्राधिकारी की स्थिति है कि वर्तमान एनआईपी कानूनी कोडीकृत प्रक्रिया के अलावा कुछ नहीं है। इन सबसे ऊपर, नियम एनआईपी पर रुक जाता है और घरेलू उद्योग का तर्क क्षति मार्जिन के संबंध में है। ऐसा कोई कानूनी नहीं है जो यह कहता हो कि क्षति मार्जिन एनआईपी और कारखाना बाह्य स्तरों पर आयातों की पहुँच कीमत के बीच का अंतर होगा। वर्तमान में निदेशालय की प्रक्रिया कारोबारी वास्तविकताओं को नहीं पहचानती।
- xxvi. याचिकाकर्ता जांच की अवधि के बाद के डाटा प्रदान करने के इच्छुक हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया इस पर निर्णय लें और उसके बाद घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के बाद के डाटा प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें। यदि ऐसे डाटा की कीमत के दमन/गिरावट में भी शामिल करना है तो घरेलू उद्योग को डाटा प्रदान करने में व्यापक कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा, ऐसे जांच की अवधि के निष्पादन को मात्र घरेलू उद्योग के निष्पादन तक सीमित नहीं किया जा सकता। निर्यातकों को इस पक्ष के डाटा भी प्रदान करने चाहिए।

- xxvii. घरेलू उद्योग ने पहले ही इस तथ्य को स्थापित करते हुए पर्याप्त साक्ष्य प्रदान कर दिए हैं कि उत्पादकों द्वारा क्षमताओं में वृद्धि की गई है। घरेलू उद्योग ने अन्य साक्ष्य भी प्रकट किए हैं, जो इस तथ्य को दर्शाते हैं कि क्षमताओं में वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के उपरांत क्षमताओं को शुरू करने के साथ ही आयातों में वृद्धि होना, घरेलू उद्योग द्वारा पूर्व में किए गए अनुरोधों को सही होने को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है।
- xxviii. घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि केवल यह कहना कि "भारत एक प्रमुख बाजार नहीं है", यह साबित नहीं करता कि चालू शुल्कों को समाप्त करने से क्षति के जारी रहने/ पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है। घरेलू उद्योग विस्तृत रूप से तिमाही-वार जांच की अवधि के पश्चात के आयात संबंधी डाटा संलग्न कर रहा है। यह दोनों संबद्ध देशों से आयातों की प्रवृत्ति का साक्ष्य होगा। रूस के आयातों से पूरी क्षति अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि का मार्ग दिखाया गया है जबकि टर्की के आयातों में जांच की अवधि में व्यापक वृद्धि दिखाने के पहले 2015-16 तक गिरावट दिखाई गई है। इसके अलावा, संबद्ध निर्यातकों के क्षमता विस्तार की योजना में अनुकूल बाजार अपेक्षित है, जैसे भारतीय बाजार एक विकसित हो रहा बाजार है। टर्की का सोडा ऐश का पाटन भी न केवल टर्की से क्षति की संभावना की पुष्टि करता है बल्कि यूरोपीय संघ से भी संभावना की पुष्टि करता है – (क) टर्की के निर्यातक यूरोपीय रूप में भारतीय बाजार से कम कीमत पर बिक्री कर रहे हैं और वे उसे भारतीय बाजार में भेजने से नहीं रुकेंगे, (ख) टर्की के निर्यातकों ने यूरोपीय उत्पादकों को विस्थापित किया है, जो बदले में भारतीय उत्पादकों को विस्थापित करने का प्रयत्न कर सकते हैं।
- xxix. यदि टर्की की तीसरे देशों को निर्यात कीमत भारत को निर्यात कीमत से काफी कम है तो यह प्रमाणित होता है कि ये मात्रा भारतीय बाजार में चली जाएगी। ऐसा कोई साक्ष्य रिकार्ड में नहीं लाया गया है, जो यह दर्शाता हो कि टर्की के उत्पादक यूरोपीय बाजार को कुछ मान्य/ मध्यम/ भावनात्मक अथवा दीर्घावधिक अनुबंध से निर्यात कर रहे हैं। यदि टर्की से यूरोप को निर्यात कारोबारी स्थितियों में हो रहे हैं तो पाटनरोदी शुल्क समाप्त करने से न्यूनतम भी हो सकता है, वह यह कि टर्की में उत्पादकों को भारत में, उत्पादन को न केवल बढ़ाकर बल्कि तीसरे देश के निर्यातों की ओर भेजकर भी अपने निर्यातों को बढ़ाएं।
- xxx. घरेलू उद्योग के घटक सिंगल उत्पाद कंपनियां न होकर विविध उत्पाद कंपनियां हैं। प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट पूरी कंपनी के लिए है न कि केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए। तथापि, यह निर्दिष्ट प्राधिकारी को गुमराह करने के लिए है और पूरी तरह से चुनिंदा है। प्रतिवादी पक्षकार ने इसी पृष्ठ का उल्लेख कम लागत आयातों से भविष्य की हानियों के लिए किया है जो प्रतिवादी पक्ष द्वारा दुर्भावना से छोड़ दिया गया है।
- xxxii. कथित गलत/अधूरे डाटा आधार वर्ष के लिए संचित कटौती स्तर के अलावा कुछ नहीं है और इसीलिए आधार वर्ष के लिए रूस से आयातों के अभाव में यह स्पष्ट है कि यह केवल निर्यातक संबद्ध देश टर्की के कटौती स्तर को ही दर्शाएगा। जहां तक आरओआई/ नकद लाभ न होने के संबंध में उठाए गए मुद्दे का संबंध है, यह कहना है कि अपेक्षित सूचना कारोबारी संवेदनशीलता से जुड़ी है और उसका प्रकटीकरण प्रतिद्वंदियों को फायदा पहुंचाएगा।
- xxxiii. घरेलू उद्योग ने क्षति जारी रहने का दावा किया है। घरेलू उद्योग मौजूद पाटनरोधी शुल्क के तथ्य के कारण सकारात्मक कटौती के बावजूद प्रभावित नहीं है। इसके अलावा, प्रदान की गई सूचना से यह देखा जाएगा कि उत्पादन की लागत 2016-17 तक कम हुई है और उसके बाद वर्तमान जांच की अवधि के अंतिम 6 माह में वृद्धि हुई है, जबकि बिक्री कीमत में 2015-16 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई है। अतः आयातों से जांच की अवधि के अंतिम 6 माह के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों पर गिरावट का प्रभाव आना शुरू हो गया।
- xxxiv. वर्तमान मामला क्षति जारी रहने का नहीं बल्कि एक ऐसा मामला है, जहां तथ्य स्पष्ट रूप से पाटन में तेजी आने और पाटनरोधी शुल्क समाप्त न होने पर क्षति जारी रहने को दर्शाते हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि क्षमता का उपयोग करने में क्षमताओं में वृद्धि होने के कारण गिरावट आई है। इसकी बजाए इसके पाटन संबद्ध आयातों के कारण बाजार प्राप्त करने और संस्थापित क्षमताओं के निरर्थक करने में बल मिला है।
- xxxv. घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि और घरेलू बिक्रियों में वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग की औसत इवेंट्री में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह क्षति जांच अवधि में लगभग दोगुनी हुई है। घरेलू उद्योग के संबंध में जो सही हो सकता है, उसे संबद्ध निर्यातकों द्वारा हथिया लिया गया है, जैसा कि जांच की अवधि में आयातों की मात्रा में

अचानक हुई वृद्धि और संबद्ध आयातों की पहुँच कीमतों में गिरावट से देखा जा सकता है। यह तर्क देना कि औसत स्टॉक का कोई अर्थ नहीं है इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। नियमों में भी इस प्रभाव के संबंध में कुछ उल्लेख नहीं है।

- xxxv. वर्तमान मामला पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना के मूल आधार पर पाटनरोधी शुल्क के विस्तार का है। अतः वर्तमान मात्रा पाटित आयातों के संभावित प्रभाव को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान आयातों की मात्रा अभी भी पाटित कीमतों पर है। अतः पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करने से तेज हो रहे पाटन और आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए निवेदन :-

48. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने नीचे दिए अनुसार निवेदन किया है:

- (i) तुर्की के सोडा ऐश निर्यातों के लिए भारत मुख्य बाजार नहीं है। इसके विपरीत, भौगोलिक दृष्टि से निकट बाजार और इटली, मिस्र और स्पेन जैसे व्यापार साझीदार तुर्की के लिए मुख्य गंतव्य स्थल हैं। तुर्की और ई.यू. के बीच में सीमा शुल्क संबंधी संयोजन तथा आस-पास के देशों के साथ एफ.टी.ए. के नेटवर्क का आभार, जिसकी वजह से तुर्की से इटली, मिस्र और स्पेन के निर्यात वर्ष 2017 के उत्पाद के समस्त निर्यातों का क्रमशः 16.4 प्रतिशत, 12.3 प्रतिशत और 9.7 प्रतिशत हुए जबकि भारत का हिस्सा केवल 3.8 प्रतिशत था।
- (ii) विगत 5 वर्षों में तुर्की ने सौ से अधिक देशों के लिए सोडा ऐश का निर्यात किया है, लेकिन यह भारत में ही पाटनरोधी उपायों का सामना कर रहा है। यह स्पष्ट है कि तुर्की के सोडा ऐश के निर्यातक पूर्णरूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापार करते हैं।
- (iii) पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.1 में यह अपेक्षा है कि पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव एवं ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के बारे में क्षति का निर्धारण सकारात्मक प्रभाव के आधार पर हो। शिकायत में आयात संबंधी आंकड़े साफ-साफ यह दर्शाते हैं कि तुर्की से सोडा ऐश आयातों में वर्ष 2013 से पीओआई तक (वार्षिक) मात्रा के संदर्भ में 45 प्रतिशत की गिरावट हुई। इसी प्रकार, संबद्ध देशों से आयातों में 16 प्रतिशत गिरावट हुई। इसी अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में 18.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यह आंकड़े यह साबित करते हैं कि आयातों में पूर्णतः अथवा घरेलू उद्योग के उत्पादन के संदर्भ में पर्याप्त रूप से बढ़ोतरी नहीं हुई है।
- (iv) शिकायत के अनुसार, घरेलू उद्योग का लाभ वर्ष 2013 से घरेलू प्रचालनों से लगभग तीन गुना हुआ और बाजार हिस्से, बिक्री, उत्पादन क्षमता, निवेश पर लाभ, उत्पादकता लाभ/हानि के संदर्भ में सकारात्मक प्रवृत्ति है। तुर्की का यह यकीन है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। क्षति विश्लेषण के संबंध में तुर्की यह उम्मीद करता है कि भारतीय प्राधिकारी पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.2 तथा भारत के संबंधित कानूनों एवं प्रथाओं के अनुरूप कार्य करें। तुर्की का यह अनुरोध है कि भारतीय प्राधिकारी जारी निर्णायक समीक्षा को यथा संभव शीघ्र समाप्त करें तथा किन्हीं उपायों को जारी न रखें। तुर्की डब्ल्यूटीओ की न्यायिक व्यवस्था के तहत कार्यवाही का घनिष्ठ रूप से पालन कर रहा है और इसके अधिकारों का सुरक्षित रखता है।
- (v) आवेदक का यह दावा है कि रूस के निर्यातकों बशकीर सोडा कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमताओं में ***% की बढ़ोतरी की है, यह गलत है। वस्तुतः आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बशकीर सोडा कंपनी ने नए कार्बोनेटिंग टावर को चालू किया और इस टावर की क्षमता में ***% तक बढ़ोतरी हुई। इसके परिणामस्वरूप कंपनी की उत्पादन क्षमताओं में नगण्य बढ़ोतरी हुई। रूस के उद्योग के आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। इस आंकड़े से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2015 से जांच प्राधिकारी को क्षति होने का कोई खतरा न होने पर रूस के उत्पादकों की क्षमताओं में नगण्य बढ़ोतरी हुई है। घरेलू मांग की आपूर्ति करने के लिए सोडा ऐश के उत्पादन की मात्रा में हल्की सी बढ़ोतरी हुई है। यह सूचित किया है कि रूस की कंपनियां घरेलू उन्मुख विपणन नीति को अभी आगे बढ़ा रही हैं।

- (vi) रूस में उत्पादन क्षमताओं में पर्याप्त बढ़ोतरी के बारे में आवेदक के दावे को असंगत एवं पक्षपातपूर्ण मानते हुए हम जांच प्राधिकारी से कृपया यह कहना चाहते हैं कि वे तुर्की में उत्पादन क्षमताओं के संबंध में आवेदक के दावे की जांच करें।
- (vii) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में कमी, भारतीय बाजार में बढ़ती हुई मांग के साथ-साथ संबद्ध देशों में उत्पादन क्षमताओं में अपर्याप्त बढ़ोतरी और भारत में घरेलू उद्योग का विकास क्षति की पुनरावृत्ति न होने को दिखा रहे हैं। हम उपायों को जारी रखे बिना समीक्षा को समाप्त करने के लिए जांच प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं।
- (viii) याचिकाकर्ताओं ने अपने लिखित निवेदनों में यह स्वीकार किया है कि संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क ने अपने आशयित प्रयोजन को पूरा किया है और वे क्षमताओं में बढ़ोतरी कर सके हैं। सउदी अरब और अमरीका से कास्टिक सोडा की निर्णायकसमीक्षा में प्राधिकारी ने समान तथ्यों के आधार पर इन देशों पर पाटनरोधी शुल्क जारी न रखने की सिफारिश की। घरेलू उद्योग (सकारात्मक आर्थिक मापदण्डों के संदर्भ में) सामान्य मूल्य से कम आयातों में कथित बढ़ोतरी को सहन कर रहा है और इस प्रकार, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह निर्णय करने का अनुरोध है कि याचिकाकर्ताओं के लिए पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति अथवा जारी रखने की कोई संभावना नहीं है।
- (ix) सोडा सानायी यह निवेदन करता है कि याचिकाकर्ताओं को हुई कथित क्षति और संबद्ध आयातों के बीच में कोई कारणात्मक संबंध नहीं है- क्योंकि बिक्रियों की मात्रा, कीमत, बाजार हिस्से के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के निष्पादन में सम्पूर्ण क्षति अवधि के दौरान पर्याप्त सुधार हुआ है।
- (x) आयात में पर्याप्त रूप से बढ़ोतरी होने की संभावना के बारे में प्रमाणित बाद के ऐसे पीओआई आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद में ही निर्धारण किया जा सकता है जो याचिकाकर्ताओं ने याचिका में उपलब्ध नहीं कराए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कीमत ह्रास/न्यूनीकरण के बारे में कोई बाद के पीओआई आंकड़े न तो उपलब्ध कराए हैं और न ही इस बारे में इसने कोई प्रमाणित निवेदन किए हैं।
- (xi) वर्ष 2015-16 से पीओआई तक पहुंच मूल्य में कथित कमी के बावजूद याचिकाकर्ताओं का विक्रय मूल्य इस अवधि (और अधिकांश क्षति अवधि) के दौरान स्थिर रहा है। याचिकाकर्ताओं का विक्रय मूल्य आधार वर्ष की तुलना में क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- (xii) संबद्ध देशों में स्वेच्छा से प्रयोज्य क्षमताओं का याचिकाकर्ता के आरोप केवल निराधार कल्पना है। सोडा सानायी का क्षमता उपयोग 95 प्रतिशत है, यह इस बात का प्रमाणित करता है कि तुर्की के उत्पादकों के पास तुर्की में न तो स्वेच्छा से प्रयोज्य क्षमताएं होती हैं अथवा न ही अधिशेष क्षमताएं हैं, जिनका वे शुल्क समाप्त होने की स्थिति में भारत के लिए उपयोग कर सकें।
- (xiii) घरेलू उद्योग यह प्रमाणित करने में असमर्थ रहा है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर देने की स्थिति में पाटन और क्षति को जारी अथवा पुनरावृत्ति की संभावना को दर्शाने के लिए अधिशेष क्षमताएं हैं और मौजूदा क्षमता में बढ़ोतरी करने के प्रमाण हैं।
- (xiv) याचिकाकर्ताओं ने यह प्रमाणित करने के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया है कि संबद्ध देशों में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है। पैराग्राफ सं. 80 में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया प्रमाण पीओआई के केवल एक भाग से ही संबंधित है और इस तरह यह क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना अथवा जारी का प्रभावी विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- (xv) मौखिक सुनवाई के दौरान तुर्की के उत्पादकों के द्वारा दिए गए निवेदनों से निर्दिष्ट प्राधिकारी यह नोट कर सकते हैं कि उनके प्रमुख निर्यात बाजार मिस्र और ईयू हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह प्रमाणित करने के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए हैं कि तुर्की के उत्पादक भारत की ओर निर्यातोन्मुख हैं।
- (xvi) आयातों के प्रति कीमत संबंधी आकर्षण के बारे में याचिकाकर्ताओं के दावे ठीक नहीं हैं, याचिका के अनुसार अन्य देशों के लिए तुर्की की निर्यात कीमतें भारत के लिए उसकी कीमत की अपेक्षा पहले से ही काफी कम हैं। यदि शुल्क भी समाप्त हो जाते हैं तो भी इस बात की कोई संभावना नहीं है कि भारत के लिए तुर्की की निर्यात कीमतें कम हो जाएंगी।

- (xvii) याचिका के अनुसार तुर्की के मुख्य बाजार मिस्र और सउदी अरब हैं और रूस के मुख्य बाजार कजाकिस्तान, बेलारूस और यूक्रेन हैं तथा इन देशों को निर्यात सार्थक एवं गैर पाटित कीमतों पर होता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में पाटनरोधी शुल्क होने अथवा समाप्त होने के बावजूद तुर्की और रूस के मुख्य बाजार यथा उपरोक्त रहेंगे। वर्तमान वास्तविक मैट्रिक्स (आधार) में संभावित विश्लेषण करते समय अन्य देशों के लिए संबद्ध देशों से निर्यात असंगत हैं।
- (xviii) वर्तमान मामले में यूरोप, पाकिस्तान और चीन गणराज्य जैसे गैर-संबद्ध देशों में क्षमता विस्तार अप्रासंगिक है। पूर्व जांच में पाटन मार्जिन वर्तमान निर्णायक समीक्षा का मूल प्रश्न नहीं है।
- (xix) पीओआई के बाद की अवधि में कम कीमत पर बेचने के संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। संबद्ध देशों में माल सूची स्तरों के संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
- (xx) लिखित अधिकांश प्रमाणों को अलग करने के बाद शुल्क जारी रखने के लिए याचिकाकर्ता माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध कर रहे हैं जो न केवल पाटनरोधी नियमावली का उल्लंघन है अपितु स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है।
- (xxi) यदि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, तो पाटनरोधी नियमावली के तहत यथा निर्धारित कम शुल्क नियम को लागू करने का अनुरोध है।
- (xxii) घरेलू उद्योग का औसत लाभ पीओआई के दौरान बिक्री लागत का ***% है जो पाटनरोधी जांच में सामान्य मूल्य निकालते समय महानिदेशक के द्वारा अनुमत लाभ से काफी अधिक (अर्थात् ***%) है। याचिकाकर्ताओं के द्वारा नियोजित पूंजी पर लाभ पीओआई के दौरान एनएफए का ***% है जबकि सभी पाटनरोधी मामलों में एनआईपी की गणना करते समय महानिदेशक ***% लाभ की अनुमति देते हैं। इसलिए, घरेलू उद्योग का कोई क्षति नहीं है और इस प्रकार इसको जारी रखने का प्रश्न नहीं होता है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए कोई विशेष/अपवादात्मक परिस्थितियां आवश्यक नहीं होती हैं।
- (xxiii) वर्ष 2013 से 2017 तक संबद्ध देशों से आयातों का बढ़ने का कारण पाटन नहीं है, अपितु अनुप्रवाह उद्योग के विकास पर चलते हुए भारतीय बाजार की मांगों का बढ़ना है। यह देखा जा सकता है कि आधार वर्ष 2013-14 से पीओआई (ए) के दौरान मांग 100 से बढ़कर 117 हुई है। इसके विपरीत, संबद्ध देशों से आयातों में 17 प्रतिशत की गिरावट हुई है जो आधार वर्ष के 100 के मुकाबले पीओआई (ए) के दौरान 83 हुआ है।
- (xxiv) रूस से आयातों की मात्रा बहुत कम है यह पीओआई के दौरान कुल मांग का केवल ***% है जो एक अपर्याप्त हिस्सा बनता है। ऐसे सांकेतिक भाग से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है। संबद्ध देशों के उत्पादकों का पाटन का इरादा नहीं होता है और न ही उन्होंने भारत के लिए निर्यात बढ़ाने के लिए एक तरीके के रूप में पाटन का उपयोग किया है।
- (xxv) याचिका का प्रपत्र IV यह दर्शाता है कि घरेलू बाजार में बिक्री की लागत और विक्रय मूल्य के बीच में कोई परस्पर संबंध नहीं है। आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि बिक्रियों की लागत में 15 प्रतिशत की कमी हुई है जो वर्ष 2013-14 में 100 थी और पीओआई के दौरान कम होकर 83 हुई है। बिक्रियों की लागत में गिरावट आने से घरेलू उद्योग ने तदनुसार विक्रय मूल्यों में कमी नहीं की थी, अपितु इसे बढ़ाता रहा। विक्रय मूल्य आधार वर्ष के 100 से बढ़कर पीओआई के दौरान 107 हो गया है। इससे पीओआई के दौरान उनकी लाभप्रदता अधिक हुई है। अतः कीमत ह्रास/न्यूनीकरण नहीं हुआ है। महानिदेशक से इसकी गहन जांच करने का अनुरोध है।
- (xxvi) पाटन और क्षति के बीच में कारणात्मक संबंध में स्थापित करने के लिए कम कीमत पर बेचना एक महत्वपूर्ण मापदण्ड होता है, लेकिन यह निर्धारण करने के लिए आधार प्रदान नहीं करता है और इसे अलग से नहीं देखना चाहिए। घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन के संदर्भ में यह देखना होगा कि क्या इससे हानियां हो रही हैं। याचिका के अनुसार, क्षति अवधि के दौरान रूस से सस्ती कीमत पर बेचना सकारात्मक है। वर्तमान मामले में, सस्ता बेचने के बावजूद घरेलू उद्योग के अपने निष्पादन में सुधार हुआ है। अतः वर्तमान में जांच में कम कीमत पर बेचने की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

- (xxvii) पी ओ आई के दौरान क्षमता और उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। क्षमता में बढोत्तरी करने पर बल देने के बजाय याचिकाकर्ताओं के द्वारा कुशल एवं प्रभावी क्षमता उपयोग पर बल देना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने क्षमता न बढ़ायी होती तो पी ओ आई के दौरान उनका क्षमता उपयोग ***% तक बढ़ना चाहिए और इष्टतम स्तर प्राप्त कर लेना चाहिए।
- (xxviii) जो कुछ वे उत्पादन कर रहे हैं उसको बेचने की क्षमता याचिकाकर्ता में है। आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में पीओआई के दौरान याचिकाकर्ताओं की बिक्री मात्रा ** एमटी से बढ़कर ** एमटी हुई है। क्षति अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के निर्यातों में काफी गिरावट हुई है और फिर पीओआई के दौरान अचानक वृद्धि की है। निर्यातों में कमी होने से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। याचिकाकर्ताओं के समग्र निष्पादन में सुधार हुआ है।
- (xxix) औसत स्टॉक के अलग से नहीं देखना चाहिए। इसको बिक्री और उत्पादन के संदर्भ में देखना होगा।
- (xxx) याचिकाकर्ताओं के बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान बढोत्तरी हुई और संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में कमी हुई है। वृहद बाजार हिस्से को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों ने कब्जे में कर रखा है। रूस से आयात कुल मांग का केवल ** % है। आयातों के ऐसे नगण्य हिस्से से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।
- (xxxi) आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी सुधार हुआ है। आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में पीओआई के दौरान पीबीआईटी में भी 270 तक सुधार हुआ है।
- (xxxii) आधार वर्ष में आरओसीई 100 था जो पीओआई के दौरान बढ़कर 167 हो गया है। महानिदेशक ने ऐसे बहुत से मामलों को समाप्त कर दिया है जिनमें घरेलू उद्योग अधिक लाभ अर्जित कर रहा था अथवा एनआईपी से अधिक कीमत पर अपने उत्पादों को बेच रहा था जैसे चीन जनवादी गणराज्य और वियतनाम से 27 सितंबर, 2016 के अंतिम निर्णयों में एए ड्राई सैल बैटरियां, 24 मई, 2011 के मध्यावधि समीक्षा अंतिम निर्णय में चीन से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, 9 फरवरी, 2012 के मध्यावधि समीक्षा अंतिम निर्णय में कोरिया जनवादी गणराज्य से फिनाइल, दिनांक 25 अगस्त, 2005 के अंतिम निर्णय में चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया जनवादी गणराज्य और यूक्रेन से साइट्रिक एसिड और दिनांक 27 जून, 2005 के अंतिम निर्णय में इण्डोनेशिया और थाइलैण्ड से जिप्सम प्लास्टर बोर्ड।
- (xxxiii) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं (कैप्टिव सहित) की कुल मांग में 17 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई है, जबकि भारतीय प्रयोक्ता उद्योग की मांग के अनुरूप कुल मांग (कैप्टिव को छोड़कर) 15 प्रतिशत बढ़ी है। दूसरी तरफ, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों में 17 प्रतिशत तक काफी कमी हुई है।
- (xxxiv) संबद्ध वस्तुओं की मांग (कैप्टिव को छोड़कर) वर्ष 2013-14 में *** एमटी थी जो पीओआई(ए) में बढ़कर *** एमटी हो गई। मांग में वृद्धि के अनुरूप घरेलू उद्योग ने अपनी वार्षिक क्षमता 37 प्रतिशत बढ़ाई है जो वर्ष 2013-14 में *** एमटी से बढ़कर पीओआई(ए) में *** एमटी हो गई। उत्पादन में भी 18 प्रतिशत बढोत्तरी हुई जो वर्ष 2013-14 में *** एमटी से बढ़कर पीओआई (ए) में *** एमटी हो गया। इसी प्रकार, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां 16 प्रतिशत बढ़ीं, जो वर्ष 2013-14 में *** एमटी से बढ़कर पीओआई (ए) में *** एमटी हो गयीं। मांग, उत्पादन और बिक्रियों में वर्ष दर वर्ष बढोत्तरी होने से घरेलू उद्योग ने निकट भविष्य में अपनी वार्षिक क्षमताओं में *** लाख टन बढ़ाने के लिए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हुए। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निष्पादन और उनकी भावी योजनाएं पाटन से हुई क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना न होने को दर्शाती है।
- (xxxv) संबद्ध देशों से आयातों के समग्र बाजार हिस्से में कमी हुई है जो वर्ष 2013-14 के 2.27 प्रतिशत से कम होकर पीओआई(ए) के दौरान 1.65 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में घरेलू उद्योग के लाभ में बढोत्तरी हुई जो वर्ष 2013-14 के 100 सूचकांक से बढ़कर पीओआई(ए) के दौरान 341 सूचकांक हो गया। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभों में 241 सूचकांक तक तेजी से बढोत्तरी हुई। क्षति अवधि के दौरान यह समग्र ***% हिस्से को भी बनाए रख सका था, जबकि अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में हल्की सी कमी हुई जो वर्ष 2013-14 में ***% से कम होकर पीओआई(ए) में ***% हुआ। यह इस बात को दर्शाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाते हैं तो क्षति होने की कोई संभावना नहीं है।

- (xxxvi) वर्ष 2013-14 में क्षमता उपयोग ***% था जो पीओआई(ए) के दौरान ***% कम हो गया। किसी उद्योग में इस बात की यथोचित संभावना होती है कि जब क्षमताओं में पर्याप्त बढ़ोतरी होती है तो ऐसी क्षमताओं का तत्काल उपयोग कराया नहीं जा सकता है। क्षमता उपयोग में कमी होना क्षति अवधि के दौरान 37 प्रतिशत तक क्षमताओं में अचानक बढ़ोतरी का स्वाभाविक परिणाम होता है। इसके अलावा, संबद्ध वस्तुओं के आयातों में क्षति अवधि के दौरान 17 प्रतिशत तक ज्यादा तेजी से कमी हुई है। अतः संबद्ध वस्तुओं के आयातों से घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग कोई कमी नहीं हुई थी। उद्योग के स्रोतों के अनुसार घरेलू उद्योग वर्ष 2018 के दौरान पूरी क्षमता पर कार्य कर रहा है और वार्षिक क्षमताओं में अन्य *** टन की बढ़ोतरी करेगा। अतिरिक्त क्षमताओं से भारतीय बाजार के काफी बड़े हिस्से को कब्जे में ले सकेगा।
- (xxxvii) वार्षिक क्षमता और उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद, घरेलू उद्योग अपने स्टॉक का अच्छी तरह से बनाए रखने में समर्थ रहा है। यद्यपि वर्ष 2013-14 का 100 सूचकांक वर्ष 2014-15 में 74 सूचकांक तक गिर गया था, परन्तु वर्ष 2014-15 की अवधि में स्टॉक 127 सूचकांक तक बढ़ा और पीओआई(ए) के दौरान 129 सूचकांक तक सीमान्त बढ़ोतरी हुई। निर्यात सूचकांक वर्ष 2013-14 में 100 था जो वर्ष 2014-15 में 36 तक गिर गया और वर्ष 2015-16 में 17 सूचकांक तक गिर गया। इससे पहले पीओआई(ए) के दौरान इसमें 159 सूचकांक तक तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिससे स्टॉक में और बढ़ोतरी होने से रोकने में घरेलू उद्योग को मदद मिली है।
- (xxxviii) यद्यपि समग्र रोजगार का सूचकांक वर्ष 2013-14 में 100 से गिरकर पीओआई(ए) में 85 सूचकांक हो गया था, परन्तु भुगतान किए गए वेतन इसी अवधि के दौरान 100 से तेजी से बढ़कर 133 सूचकांक हो गए। रोचक बात यह है कि अधिक वेतनों के बावजूद लाभों में बढ़ोतरी हो रही थी, क्योंकि घरेलू उद्योग के लाभ वर्ष 2013-14 का सूचकांक 100 से बढ़कर 341 सूचकांक तक पहुंच गया था। यह इस बात को सशक्त ढंग से दर्शाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाते हैं तो क्षति को जारी रखने अथवा पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है।
- (xxxix) घरेलू उद्योग की क्षमता में बढ़ोतरी हुई जो वर्ष 2013-14 में 100 सूचकांक से बढ़कर पीओआई में 137 सूचकांक हो गई। साथ ही, इसी अवधि में नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई और इसका सूचकांक 100 से बढ़कर 162 हो गया। आरओसीई भी 100 से बढ़कर 167 सूचकांक हो गया। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के द्वारा अर्जित आरओसीई पर आयातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ है।
- (xi) जब संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक की अवधि में सूचकांक 100 से घटकर 79 हो गया, तब लाभों में 231 सूचकांक की बढ़ोतरी हुई और पीबीआईटी का भी सूचकांक बढ़कर 183 हो गया। संबद्ध वस्तुओं के आयातों का सूचकांक घटकर 41 हो गया और लाभों में 364 सूचकांक की तेजी से बढ़ोतरी हुई जबकि पीबीआईटी सूचकांक बढ़कर 287 हो गया।
- (xli) घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत 100 सूचकांक से घटकर वर्ष 2013-14 से पीओआई तक 85 सूचकांक हो गई, जबकि घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य इसी अवधि में 100 सूचकांक से बढ़कर 107 सूचकांक हो गया।
- (xlii) घरेलू उद्योग प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की वजह से सस्ती कीमत पर बेचने का दावा करता है तथा सस्ती कीमत पर बेचने की समग्र सीमा 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच है। तथापि, सस्ती कीमत पर बेचने से घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं हुआ है।
- (xliii) ट्रक एंड बस टायर्स मामले में माननीय सीईएसटीएटी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने का खण्डन इस आधार पर किया था कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के क्षति संबंधी निष्कर्षों में त्रुटि थी और उनका मत यह था कि यदि वास्तव में, कीमत में कटौती होती है और सस्ती कीमत पर बिक्री की जाती है, जैसा डी.ए. के द्वारा निर्धारित है, तब घरेलू उद्योग बिक्रियों में ऐसी बढ़ोतरी को दर्शाने की अपेक्षा उसकी बिक्री की मात्रा को बनाए रखना बहुत ही कठिन होगा। वर्तमान मामले में, संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में बढ़ोतरी होने से संपूर्ण क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में बढ़ोतरी हुई। कीमत में कथित कटौती होने के बावजूद भारत में इसकी बिक्रियां बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योग व्यवस्था करता है, केवल यह तथ्य क्षति न होने तथा क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की कोई संभावना न होने को दर्शाता है।
- (xliv) नियोजित पूंजी पर ***% लाभ के बारे में घरेलू उद्योग का दावा गैर-कानूनी है, क्योंकि इण्डियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2004(170) ईएलटी 144 (ट्रि-डेल) के मामले में माननीय सेस्टेट

के निर्णय के संदर्भ में मानदण्ड लाभ की ऐतिहासिक दर पर विचार करने के बारे में है। ***% आरओसीई को स्वीकार करना चाहिए, घरेलू उद्योग के इस अप्रमाणित अनुरोध के बारे में कोई तर्क नहीं दिया है और इसे निरस्त कर देना चाहिए तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा वैश्विक और भारत में सोडा ऐश उद्योग के द्वारा लाभ प्राप्त आरओसीई की जांच करनी चाहिए और केवल तभी इस मामले के लिए उचित आरओसीई को स्वीकार करना चाहिए।

- (xiv) याचिकाकर्ताओं को हुई किसी कथित क्षति का संबद्ध देशों से आयातों के बारे में पूर्णतः परस्पर संबंध नहीं होता है। यह निवेदन है कि जब संबद्ध आयातों से वर्ष 2015-16 से पीओआई तक कथित बढ़ोतरी हुई हो, तब याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री और बिक्री मूल्यों में बढ़ोतरी करके वर्ष 2015-16 से पीओआई तक आयातों में कथित बढ़ोतरी होने से याचिकाकर्ता के निष्पादन में सुधार हुआ था। एचयूएल स्वीकार करते हुए यह निवेदन करता है कि आयातों में पूर्णतः अथवा सापेक्ष तौर पर कथित बढ़ोतरी होने की वजह से क्षति अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं को कोई क्षति नहीं हुई है।
- (xlv) तथापि, याचिका के पैरा 51 में याचिकाकर्ताओं ने यह सूचित किया है कि पाटनरोधी शुल्क की मात्रा कम होने की वजह से आयातों में बढ़ोतरी हुई थी। पाटनरोधी शुल्क की वजह से पर्याप्त सुरक्षा मिली है, याचिकाकर्ता को इसे स्वीकार करने के संदर्भ में तथा भारतीय बाजार में सुधार लाने में उन्हें सहायता मिली है, यह तथ्य यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतः पर्याप्त है कि शुल्क पर्याप्त थे। इसके बजाए बढ़ते हुए आयातों को बढ़ती हुई मांग के साथ जोड़ा जा सकता है जिसको घरेलू उद्योग पूरा करने में असमर्थ दिखता है। तदनुसार एचयूएल इस संबंध में याचिकाकर्ता के निवेदन को निरस्त करने के लिए डीए से अनुरोध करता है।
- (xlvii) पैरा 16 और पैरा 18 से 25 के द्वारा याचिकाकर्ताओं ने निश्चयपूर्वक यह कहा है कि वर्तमान बाजार हिस्सा कोई महत्व नहीं रखता है और यदि वर्तमान शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो बाजार हिस्से पर आयातों के संभावित प्रभाव महत्वपूर्ण है। एचयूएल यह निवेदन करता है कि एसएसआर जांच में किसी क्षति अथवा संभावित क्षति का विश्लेषण करते समय घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से का निर्धारण करना अनिवार्य बन जाता है। अतः इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के द्वारा किए गए निवेदनों को निरस्त कर देना चाहिए। एचयूएल यह निवेदन करता है कि यदि याचिकाकर्ताओं को संबद्ध आयातों की वजह से कथित क्षति हो रही थी, तो उन्हें बाजार हिस्से में गिरावट होने तथा संबद्ध देशों से आयातों के लिए बाजार हिस्से में कथित बढ़ोतरी का भी सामना होना चाहिए। तथापि, वर्तमान मामले में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान याचिकाकर्ताओं के बाजार हिस्सों में 1.49 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि दूसरी ओर, इसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में कमी हुई थी। अतः संबद्ध आयातों से याचिकाकर्ताओं के बाजार हिस्से पर प्रभाव नहीं पड़ा है।
- (xlviii) संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य से याचिकाकर्ताओं के विक्रय मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ा है और न ही इससे कीमत ह्रास/न्यूनीकरण नहीं पड़ा है। वर्ष 2015-16 से पीओआई तक पहुंच मूल्य में कमी होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं का विक्रय मूल्य इसी अवधि (और अधिकांश क्षति अवधि) के दौरान स्थिर रहा है। याचिकाकर्ताओं का विक्रय मूल्य आधार वर्ष की तुलना में क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- (xlix) याचिका के पैरा 53 से पैरा 55 तक याचिकाकर्ताओं ने निश्चयपूर्वक यह कहा है कि पहुंच मूल्य विक्रय मूल्य से कम है और इस प्रकार आयातों की वजह से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी। पैरा 26 से 48 के द्वारा याचिकाकर्ताओं ने अपनी-अपनी याचिकाओं में निश्चयपूर्वक यह कहा है कि कीमत के कम होने तथा क्षति मार्जिन की निष्पक्ष तुलना करने के लिए दुलाई संबंधी खर्चों / माल भाड़े को जोड़ने के बाद में ही विक्रय मूल्य की तुलना पहुंच मूल्य के साथ करनी चाहिए। याचिका के पैरा 53 में याचिकाकर्ताओं ने यह सूचित किया है कि याचिकाकर्ताओं ने अपना क्षति विश्लेषण करते समय घरेलू उत्पाद पर याचिकाकर्ताओं के द्वारा भुगतान किए गए कारखानागत बाद के खर्चों को उन्होंने जोड़ दिया है। एचयूएल यह निवेदन करता है कि कहे गए प्रकथन त्रुटिपूर्ण हैं और ये कारखानागत स्तर पर विक्रय मूल्य और पहुंच मूल्य की तुलना करने की निर्दिष्ट प्राधिकारी की विगत प्रथा के विपरीत है और इसलिए डीए के द्वारा इसे निरस्त कर देना चाहिए। सर्वसम्मति से, डीए की विगत प्रथा के आधार पर सांकेतिक प्रत्यक्ष विक्रय मूल्य / एनआईपी तथा संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य का निर्धारण आयात स्थल पर किया जाता है। एनआईपी का निर्धारण

पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। इसका निर्धारण करने में, डीए संबद्ध उत्पाद पर आरओसीई की 22 प्रतिशत दर की अनुमति देता है। इसके अलावा, चूंकि पहुंच मूल्य के बारे में आयात स्थल पर विचार किया जाता है, इसलिए कीमतों की स्पष्ट तुलना सुनिश्चित करने के लिए कारखानागत स्तर पर एनआईपी की भी गणना की जाती है। याचिकाकर्ता विक्रय मूल्य और पहुंच मूल्य के बीच तुलना करने से पूर्व डीए को विगत प्रथा को समाप्त करने तथा कारखानागत बाद के खर्चों / दुलाई लागत / माल भाड़े को जोड़ने के लिए डीए से अनुरोध करने के लिए याचिकाकर्ता सही नहीं है।

- (i) पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II(iv) के अनुसार विभिन्न आर्थिक कारकों का विश्लेषण करके कथित पाटित आयातों के प्रभाव का आकलन करना अनिवार्य है। याचिकाकर्ताओं ने पृष्ठ 18 पर अपनी याचिका के द्वारा यह स्वीकार किया है कि क्षति अवधि और पीओआई के दौरान उत्पादन, बिक्री मात्रा सहित आर्थिक मापदण्डों सभी ने सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शायी है।
- (ii) घरेलू बिक्री मात्रा और मूल्य संबंधी आंकड़े क्षति अवधि और पीओआई के दौरान यह दर्शाते हुए धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं कि संबद्ध आयातों को ध्यान में न रखते हुए घरेलू उद्योग का निष्पादन लाभप्रद रहा है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं का उत्पादन भी क्षति अवधि के दौरान बढ़ा है।
- (iii) आधार वर्ष से पीओआई तक याचिकाकर्ताओं का प्रति यूनिट लाभ 193 प्वाइंट तक बढ़ा है। उनका कर पूर्व लाभ भी आधार वर्ष से पीओआई में 170 प्वाइंट तक बढ़ा है, जबकि कंपनी के द्वारा चालू की गई नई क्षमताओं की वजह से प्रति यूनिट लाभ में कमी होने के बावजूद एक याचिकाकर्ता, नामतः नीरमा लि० (उनकी वर्ष 2016-17 की वार्षिकी रिपोर्ट के द्वारा) पूर्ण अवधियों में लाभों में बढ़ोतरी को देखा है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका के पैरा 58 में एक नए संयंत्र की लाभप्रदता का अलग से निर्धारण किया है और उन्होंने यह सूचित किया है कि यह कम है। एचयूएल यह निवेदन करता है कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा निर्दिष्ट संयंत्र एक नया संयंत्र है। यह सुनिश्चित है कि याचिकाकर्ताओं को कुछ उत्पादन खर्च और ऊपरी व्यय आदि करने होंगे, परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद के बारे में घरेलू उद्योग का कीमत ढांचा प्रभावित होगा और उससे लाभप्रदता और नए संयंत्र के निवेश पर लाभ प्रभावित होगा। अतः जब याचिकाकर्ताओं ने पाटनरोधी शुल्क से वसूली और विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग की प्रत्याशा में अपनी क्षमताओं का उचित रूप से विस्तार किया है और नए संयंत्र के बारे में कम लाभ हुए हों, तो यह अब आयातों के लिए सबसे कम आत्मकृत क्षति के लिए सुरक्षा प्राप्त करने के रूप में नहीं हो सकती है।
- (liii) अतः एचयूएल यह निवेदन करता है कि घरेलू उद्योग को स्पष्टतः कोई क्षति नहीं हो रही है और जो क्षति समाप्त हो गई थी, उसे जारी रखना संभव नहीं है। इसलिए, क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में केवल विश्लेषण किया जाना रहता है।
- (liv) याचिकाकर्ताओं ने अपनी वार्षिकी रिपोर्टों में अपनी कथित क्षति के कारणों की पहचान की है जो संबद्ध देशों से आयातों के लिए शामिल नहीं हैं। एक याचिकाकर्ता डीसीडब्ल्यू लि० ने वर्ष 2016-17 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 4 के द्वारा यह सूचित किया है कि आयातों से कोई खतरा नहीं था और कंपनी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने की सामर्थ्य थी। इसके अलावा, पृष्ठ 3 पर उन्होंने सूचित किया है कि उसके सोडा ऐश डिवीजन के बंद हो जाने की वजह से पूर्व वर्ष की तुलना में ***% तक कारोबार में हानि हुई थी। अतः यह अर्थ निकालना अतर्कसंगत होगा कि संबद्ध आयातों से राजस्व में परिणामी हानि हो सकती है।
- (lv) निम्नलिखित दृष्टांतों में याचिकाकर्ता पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे हैं अथवा उन्होंने असंगत सूचना और आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। याचिका के पृष्ठ 36 पर याचिकाकर्ताओं ने तुर्की और रूस से आयातों से कीमत में हुई कटौती के बारे में गणनाएं उपलब्ध करायी हैं। उन्होंने वर्ष 2013-14 की अवधि के लिए रूस से विचाराधीन उत्पाद की कीमत में कोई कटौती न होने की गणना की है, जबकि दोनों देशों से इसी अवधि की कीमत कटौती 10 से 20 प्रतिशत होने की सूचना दी गई है। अतः याचिकाकर्ताओं के द्वारा की गई गणनाएं पूर्णतः त्रुटिपूर्ण हैं और इसलिए इनको पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने अपने क्षति विश्लेषण में निवेश पर लाभ और नकद लाभों पर भरोसा किया है, लेकिन इसके बारे में प्रपत्र iv-ए में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं करा सके हैं। यदि उक्त सूचना उपलब्ध न हो तो अन्य हितबद्ध पक्षकार इसका प्रभावी विश्लेषण नहीं कर सकते हैं।

- (lvi) एचयूएल यह निवेदन करता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को वर्तमान जांच तत्काल समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रथमतः घरेलू उद्योग के आंकड़े अपूर्ण और अपर्याप्त हैं, दूसरे लगातार क्षति नहीं हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग को उसके महत्वपूर्ण आर्थिक मापदण्डों के अनुसार पीओआई के दौरान कोई क्षति नहीं हुई है और याचिकाकर्ताओं के द्वारा पीओआई के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, और तीसरे घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है अथवा क्षति होने की संभावना नहीं है। तथापि, किसी प्रकार की हुई क्षति केवल आत्मकृत है और अकुशलता की वजह से हुई है और संबद्ध देशों के आयातों से यह क्षति नहीं हो सकती है।
- (lvii) याचिका के पैरा 17 के द्वारा, याचिकाकर्ताओं ने निश्चयपूर्वक यह कहा है कि मै० नीरमा नामक एक याचिकाकर्ता और जीएचसीएल ने मांग में बढ़ोतरी होने की प्रत्याशा में पर्याप्त क्षमता विस्तार किया है। पैरा 16 में याचिकाकर्ताओं ने यह स्वीकार किया है कि क्षति न होने की वजह से वे ऐसा विस्तार करने के लिए सक्षम हो गए हैं। जब याचिकाकर्ताओं ने स्वयं अपनी इच्छा से क्षति के न होने अथवा मांग में बढ़ोतरी महसूस होने की वजह से क्षमताएं बढ़ायी हों तब यह स्पष्ट प्रभाव होता कि लागू किए जाने वाले शुल्कों को ज्यादा आवश्यकता नहीं है। पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य याचिकाकर्ताओं को उनके भावी निवेशों के लिए एक सुरक्षा कवर प्रदान करना नहीं होता है। ईयू, ईरान, इण्डोनेशिया और जापान में अथवा वहां से निर्यात किए "मेलामाइन" के आयातों से संबंधित एसएसआर जांच सं. 7/14/2017-डीजीएडी, दिनांक 19.02.2018 में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह नोट किया कि जो भावी उत्पादन योजनाएं भावी क्षमता विस्तारों के अनुरूप अभी शुरू की जानी हैं, उनको जारी एसएसआर में जोड़ा नहीं जा सकता है। तदनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त पूर्व निर्णय को ध्यान में रख सकता है तथा इस संबंध में याचिकाकर्ता के प्रकथनों को निरस्त कर सकता है।
- (lviii) पैरा 16 और पैरा 18 से 25 के द्वारा याचिकाकर्ताओं ने प्रबल ढंग से कहा है कि पांच शीर्ष उपभोक्ताओं की बिक्री मात्रा को ध्यान में रखते हुए बिक्रियों में कमी आयी है और संबद्ध वस्तुओं की बिक्रियां कम हैं। एचयूएल यह निवेदन करता है कि क्षति विश्लेषण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की कुल बिक्रियों पर आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए और न कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा यथा प्रस्तावित पांच शीर्ष उपभोक्ताओं के लिए की गई घरेलू बिक्रियों पर विचार करना चाहिए। यह दोहराया जाता है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं की बिक्रियां क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है, इसलिए उपरोक्त प्रकथन कहीं नहीं ठहरता है और प्रत्यक्षतः याचिकाकर्ताओं को कोई क्षति नहीं है।
- (lix) उत्पादन और खपत के लिए आयातों के संबंध में, एचयूएल यह निवेदन करता है कि उत्पादन और मांग/खपत के संदर्भ में आयातों में पीओआई में गिरावट हुई है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को कथित क्षति नहीं है। उत्पादन के संदर्भ में आयातों में आधार वर्ष की तुलना में न केवल ***% तक पीओआई में गिरावट हुई। अपितु, वर्ष 2014-15 की तुलना में भी ***% तक गिरावट हुई। इसके अलावा, आधार वर्ष की तुलना में मांग/खपत के संदर्भ में आयातों में पीओआई के दौरान गिरावट हुई।
- (lx) पैरा 16 और 18 से 25 के द्वारा याचिकाकर्ताओं ने प्रबल ढंग से यह कहा है कि तुर्की और रूस के उत्पादक यह वचन दे सकते हैं कि उनके निर्यातों की मात्रा सीमित रहेगी, बशर्ते याचिकाकर्ता पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने के लिए उनके अनुरोध पर कार्यवाही न करने पर विचार करेंगे। एचयूएल यह निवेदन करता है कि क्षति अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं के काफी अच्छे ढंग से कार्य करने की वजह से कोई क्षति नहीं है अथवा क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है। अतः याचिकाकर्ताओं के निष्पादन की वजह से पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने की आवश्यकता न होने पर संबद्ध देशों के द्वारा मात्रा संबंधी वचन देने का प्रश्न प्रथमतः नहीं उठता है। इस संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के द्वारा किए गए निवेदनों को निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा निरस्त कर दिया जाना चाहिए।
- (lxi) पैरा 26-48 के द्वारा याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में प्रबल ढंग से यह कहा है कि जिन आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम है, उन आयात लेन-देनों पर विचार करने के बाद कीमत में कटौती करने के बारे में निर्धारण करना चाहिए। एचयूएल यह निवेदन करता है कि यहां प्रकथन त्रुटिपूर्ण और डीके की विगत प्रथा के विपरीत है। याचिकाकर्ताओं का प्रस्ताव कुछ नहीं है और यह कार्य इस एकमत से अनुचित तथा पाटनरोधी करार का उल्लंघन करने वाला माना गया है। जापान और कतर में अथवा वहां से निर्यात किये कास्टिक सोडा के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में घरेलू उद्योग का एक ऐसा ही प्रस्ताव निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा निरस्त कर दिया गया था और उन्होंने यह नोट किया था कि

डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर विचार करते हुए कटौती करने संबंधी गणना की जाएगी और न कि चुनिंदा लेन देनों पर विचार करने के बाद गणना की जाएगी। अतः डीए से अनुरोध है कि वे इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के प्रकथन को तदनुसार निरस्त कर दें।

- (Ixii) गैर-संबद्ध देशों में क्षमता विस्तार के बारे में अपने लिखित निवेदनों के पृष्ठ 33 से 35 पर याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया था। एचयूएल यह निवेदन करता है कि संबद्ध देशों से आयातों की वजह से घरेलू उद्योग को पाटन अथवा क्षति जारी रखने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के लिए यह अप्रासांगिक है और इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के प्रकथनों को डीए के द्वारा निरस्त कर दिया जाना चाहिए।
- (Ixiii) यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर देने से क्षति की पुनरावृत्ति होगी, इस बात की जांच करते समय पीओआई और पीओआई के बाद में कम कीमत पर बेचने की प्रासंगिकता के बारे में याचिकाकर्ताओं ने पैराग्राफ 95 से 102 में निवेदन किए हैं। याचिकाकर्ताओं ने विशेष तौर पर यह कहा है कि पैरा 95 में यथा निर्दिष्ट एक स्थिति चाहे अनुकूल हो, तो भी डीए के द्वारा निर्णय लेना चाहिए कि शुल्क समाप्त कर देने से क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। एचयूएल यह निवेदन करता है कि इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के प्रकथन आधारहीन हैं। यह सुनिश्चित है कि संभावना का निर्धारण एक समग्र निर्धारण होता है, यह कार्य विगत में डीए के द्वारा समान रूप से कायम रखा कार्य होता है। प्रबल रूप से लिखित अधिकांश प्रभाव को न मंजूर करने के बाद में याचिकाकर्ता शुल्क जारी रखने के लिए डीए से अनुरोध कर रहे हैं, जो न केवल पाटनरोधी नियमावली का उल्लंघन है, अपितु स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। अतः इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के प्रकथनों को निरस्त कर दिया जाना चाहिए।
- (Ixiv) घरेलू उद्योग का भाग न बनने वाले अन्य घरेलू उत्पादकों के निष्पादन और उत्पादन मापदण्ड की जांच करने का प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है। ईसी फास्टनर्स (चीन) के मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय ने यह निर्णय दिया था कि जांच प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होता है कि घरेलू उद्योग का निरूपण करते समय विकृति का वस्तुतः कोई जोखिम नहीं है।
- (Ixv) यूनाइटेड स्टेट्स से बायलर उत्पादों पर पाटनरोधी और समतुल्य शुल्क उपाय के संबंध में चीन के एक डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह नोट किया कि किसी जांच प्राधिकारी को इसकी क्षति के निर्धारण में अन्य घरेलू उत्पादकों की स्थिति की उपेक्षा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। वर्तमान मामले में अन्य घरेलू उत्पादन को बाहर कर देने से तस्वीर पूरी तरह से विकृत हो जाती है, विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कई विजातीय कारकों की वजह से आवेदन उद्योग को हानि हो रही है।
- (Ixvi) घरेलू उद्योग की अपेक्षा भारत में अन्य उत्पादक काफी अच्छा कार्य रहे हैं और देश में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करने में टाटा केमिकल्स और जीएचसीएल जैसे उत्पादक एक वृहद भूमिका निभा रहे हैं। पोलिस्टर स्टेपल फाइबर मामले में जैसा देखा गया है, भारत में अन्य उत्पादक मांग के बड़े हिस्से को संभालते हैं और संबद्ध वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
- (Ixvii) भारत में संबद्ध वस्तुओं के विक्रय मूल्य घरेलू उत्पादकों के द्वारा निर्धारित कीमतों से शासित होते हैं। पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत 15 प्रतिशत कम हुई, घरेलू उत्पादकों का विक्रय मूल्य लगभग 7 प्रतिशत बढ़ा। उत्पादन में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि क्षमता उपयोग में सीमांत कमी हुई है। यह केवल घरेलू उद्योग की क्षमताओं में बढ़ोतरी के कारण हुआ है।
- (Ixviii) सोडा ऐश उद्योग आयातित कच्चे माल पर कम निर्भर है, क्योंकि यह भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अतः कच्चे माल की वजह से घरेलू उद्योग की लागत पर प्रभाव नहीं पड़ता है।
- (Ixix) सोडा ऐश उद्योग को रूपए का मूल्य बढ़ने से स्थानीय कच्चे माल और आयात समान मूल्यन का लाभ मिलना जारी रहेगा। यह व्यावहारिक भी है कि वर्ष 2016 से रूपया प्रति अमरीकी डालर आईएनआर 65 से अधिक रहा है, जो स्पष्ट तौर पर रत्तीभर संदेह से परे है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने का कोई कारण नहीं है।
- (Ixx) प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के पैरा (vii) के साथ पठित नीरमा लि० बनाम भारत संघ, दिनांक 23.02.2017 के आदेश में यथा निर्धारित संभावित विश्लेषण के प्रयोजन के लिए क्षति के खतरे संबंधी मापदंडों की जांच कर सकते हैं।

- (lxxi) संबद्ध वस्तुओं के आयात आधार वर्ष में 62,103 एमटी थे, जो पीओआई(ए) में घटकर 51,668 एमटी हो गए हैं।
- (lxxii) घरेलू उद्योग के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण वर्तमान क्षमताओं के बारे में है और न कि उन्मुक्त रूप से प्रयोज्य अथवा बढ़ी हुई क्षमताओं के बारे में हैं। याचिकाकर्ताओं को निस्संदेह रूप से यह सुनिश्चित करना होता है कि निर्यातकों की ऐसी क्षमताओं का उनके गृह देश अथवा अन्य निर्यात बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है और भारत की ओर उनको मोड़ने की संभावना है। केवल अधिक अथवा निष्क्रिय क्षमताओं के होने से अभिप्रायः घरेलू उद्योग के पाटन अथवा क्षति सन्निकट होने से नहीं होता है। विश्व में अन्य क्षमताओं के होने के बावजूद घरेलू उद्योग बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। घरेलू उद्योग अधिशेष क्षमता के मामले को स्थापित करने में असमर्थ रहा है।
- (lxxiii) घरेलू उद्योग कीमत ह्रास/न्यूनीकरण के मामले को प्रमाणित करने में असमर्थ रहा है।
- (lxxiv) घरेलू उद्योग की सामान सूचियों पर किसी प्रभाव को दर्शाने के लिए याचिका में कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं है।
- (lxxv) समग्र कीमत कटौती के अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए सकारात्मक कीमत कटौती वाले लेन देनों पर ही विचार किया जाना चाहिए, घरेलू उद्योग का यह दावा आधारहीन है और इनमें कोई तर्क नहीं है। घरेलू उद्योग के द्वारा दर्शायी गई डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट एक अलग संदर्भ में है और यह किसी मामले में कीमत कटौती संबंधी विश्लेषण करने की किसी विशेष पद्धति को सुनिश्चित नहीं करती है। इसीलिए, एक समग्र आधार पर कीमत कटौती संबंधी विश्लेषण करने के लिए इसकी समनुरूप प्रथा का पालन करने हेतु प्राधिकारी पूरी तरह से न्यायसंगत होंगे।
- (lxxvi) क्षति मार्जिन का निर्धारण करने में माल भाड़े को शामिल करना चाहिए, घरेलू उद्योग का यह दावा सुदृढ़ आर्थिक तर्क से हट कर है। प्राधिकारी का समनुरूप कार्य सुदृढ़ आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है कि तुलना प्रथम स्थल पर की जानी चाहिए जहां से आयातित वस्तुएं और घरेलू उत्पादित वस्तुएं देश की वाणिज्य की मुख्य धारा में आती हैं और जो वास्तविक उपभोग के लिए पहले उपलब्ध होती हैं।
- (lxxvii) कम शुल्क नियम पर भारत के दस्तावेज का संदर्भ ठीक समझा न गया और भ्रामक है। भारत का दस्तावेज कम शुल्क नियम के प्रयोग के लिए भी डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों को समझाने के संदर्भ में था। यह सुझाव देना शरारतपूर्ण होगा कि भारत का यह सुझाव था कि उपभोग के समीपस्थ स्थल पर तुलना की जानी चाहिए। वस्तुतः भारत का कार्य ऐसे प्रथम स्थल पर तुलना करने के लिए है जहां पर वस्तुएं उपभोक्ता को उपलब्ध होती हैं।
- (lxxviii) यह नोट करना भी प्रासंगिक है कि डब्ल्यूटीओ में उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था, उसके काफी बाद में अनुबंध-III लागू किया गया था। इसलिए यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि न केवल कानूनी प्रावधान क्षति मार्जिन की गणनाओं के लिए माल भाड़े को शामिल करने की अनुमति नहीं देते हैं, अपितु खपत के स्थल पर तुलना करने का भारत का इरादा भी नहीं है।
- (lxxix) घरेलू उद्योग को कथित क्षति पहुंचाने के अन्य कारक हैं, जिनके बारे में सूचना याचिका से गायब है, जैसे घरेलू उत्पादकों में बाजार संबंधी प्रतिस्पर्धा की सूचना, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा काफी मात्रा में उत्पादन न करना, संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ताओं में अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात करने की प्रवृत्ति।

प्राधिकारी द्वारा जांच

49. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों का ध्यान रखा है।
50. क्षति विश्लेषण में एक कारक के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए भाड़े पर विचार के लिए घरेलू उद्योग के तर्क के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एन आई पी का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के संबंध में किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति के मार्जिन के निर्धारण के लिए एन आई पी और पहुंच मूल्य के बीच तुलना प्राधिकारी की सतत् प्रथा के अनुसार उसी स्तर पर की गई है।

51. प्राधिकारी द्वारा इसके अंतर्गत की गई क्षति का विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

संचयी आकलन

52. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II पैरा (iii) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद का आयात एक ही समय में पाटनरोधी जांच के अधीन रखा जा रहा है, निर्दिष्ट प्राधिकारी संचयी रूप से इस प्रकार के आयातों के प्रभाव का आकलन करेंगे, यदि यह निर्धारण किया जाता हो कि :
- प्रत्येक देश से आयातों की तुलना में स्थापित पाटन का मार्जिन दो प्रतिशत से अधिक है जिसे निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया हो और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान उत्पाद के आयात का तीन प्रतिशत है और जहां अलग अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम हो, सामूहिक रूप से ये आयात समान वस्तु के आयात के सात से अधिक होता है; और
 - आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन आयात की गई वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त हो।
53. इस संबंध में प्राधिकारी, यह मानते हैं कि :
- संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से पाटन का मार्जिन उपर्युक्त निर्धारित सीमाओं से अधिक है;
 - संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा निर्धारित सीमाओं से अधिक है;
 - विभिन्न संबद्ध देशों से और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु समान वस्तु हैं।
 - आयात किए गए और घरेलू उत्पाद का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है और घरेलू उत्पाद तथा आयात किए गए उत्पाद के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा है।
54. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी इसे उपर्युक्त मानते हैं कि आयात किए गए उत्पाद और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धाओं की स्थितियों के आलोक में घरेलू उद्योग पर टर्की और रूस से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभावों का संचयी रूप से आकलन किया जाये।
55. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II जिसमें (क) समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव एवं (ख) इस प्रकार के आयातों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव, दोनों की वस्तुपरक जांच का प्रावधान है। जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कि पाटित के कीमत प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली इस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती।
56. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लेख है :
- "संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"*
57. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच के लिए प्राधिकारी ने आगे ऐसे सूचकांकों पर विचार किया है जिसका उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का आकार और मार्जिन आदि की स्थिति पर उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध II (iv) के अनुसार प्रभाव पड़ता हो।
58. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(क)(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पूर्व में समाप्त नहीं किया गया हो, का इस प्रकार से लगाये जाने की तिथि से पांच वर्षों के समाप्त होने पर प्रभाव नहीं

पड़ेगा बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार किसी समीक्षा में इस राय पर पहुंचती हो कि इस प्रकार के शुल्क को समाप्त किए जाने के कारण संभवतः पाटन और क्षति को जारी रखे जाने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है, यह समय समय पर, इस प्रकार के आरोपण की अवधि को अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा सकता है और इस प्रकार की आगे की अवधि ऐसे बढ़ाये जाने के आदेश की तिथि से आरंभ होगी।

59. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन और क्षति की संभावना की पहलुओं की जांच करने की कार्यवाही करने के पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो की जांच करने की कार्यवाही करते हैं।

मांग और बाजार हिस्सा

60. संबद्ध वस्तुओं की घरेलू खपत/ मांग का आकलन करने के प्रयोजन से, घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री की मात्रा को भारत में कुल आयातों में जोड़ दिया गया है और उसे नीचे सारांश के रूप में दिया गया है:

विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि (क)
भारत में मांग – कैप्टिव सहित					
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	111	122
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	105	110
कुल घरेलू बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	107	115
आयात – संबंधित देश	मी. ट.	62,355	49,071	25,674	51,668
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	41	83
आयात – अन्य देश	मी. ट.	506,611	674,148	607,588	628,901
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	133	120	124
कुल मांग	मी. ट.	2,833,341	3,024,370	3,059,141	3,279,345
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	108	116
मांग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
संपूर्ण रूप में भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
संबद्ध देश	%	2.2%	1.6%	0.8%	1.6%
अन्य देश	%	17.9%	22.3%	19.9%	19.2%

61. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि (क) के दौरान मांग में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान मांग में वृद्धि 16 प्रतिशत थी। घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई जबकि संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि (क) के दौरान मांग में संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा 1.6 प्रतिशत था, जबकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 34 प्रतिशत था और कुल मिलाकर भारतीय उत्पादकों का उसी अवधि में 79 प्रतिशत बाजार हिस्सा था।

ठ. पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

आयात की मात्रा और बाजार हिस्सा

62. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त किए गए आयात संबंधी आंकड़ों पर विचार किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है :

विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि	जांच की अवधि (क)
टर्की	मी. ट.	62,355	42,114	16,325	51,181	34,121
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	68	26	-	55
रूस	मी. ट.	0	6,957	9349	26,321	17,547
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	-	100	134	-	252
संबद्ध देश	मी. ट.	62,355	49,071	25,674	77,502	51,668
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	79	41	-	83
अन्य देश	मी. ट.	506,611	674,148	607,588	943,351	628,901
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	133	120	-	124
कुल आयात	मी. ट.	568,965	723,219	633,261	1,020,853	680,568
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	127	111	-	120
टर्की	%	11%	6%	3%	5%	5%
रूस	%	0%	1%	1%	3%	3%
संबद्ध देश	%	11%	7%	4%	8%	8%
अन्य देश	%	89%	93%	96%	92%	92%
कुल	%	100%	100%	100%	100%	100%

63. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों में आधार वर्ष में 62,355 मी. ट. से जांच की अवधि (क) में 51,688 मी. ट. तक स्वतंत्र रूप में गिरावट आई है। टर्की से आयात आधार वर्ष में 62355 एम टी से घटकर पी ओ आई (ए) में 34121 एम.टी. हो गया। यद्यपि, रूस से आयात पी ओ आई (ए) में बढ़कर 17547 एम टी हो गए हैं, परंतु ये आयात भारत में संबद्ध वस्तु के कुल आयातों का मात्र 3 प्रतिशत हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पी ओ आई (ए) के दौरान मांग में संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा केवल 1.6 प्रतिशत रहा था।

ड. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

64. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में कीमतों का न्यूनीकरण होता अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण और कीमत पर दबाव,

यदि कोई हो, के संबंध में जांच की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) और क्षति-रहित कीमत (एन आई पी) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

पाटित आयातों का कीमत पर दबाव और न्यूनीकरण संबंधी प्रभाव

65. पाटित आयातों का कीमत पर दबाव और कीमत न्यूनीकरण प्रभाव की भी जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति और पहुंच मूल्य के संबंध में की गई है।

विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	14,729	16,508	18,394	14,808
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	125	101
बिक्री की लागत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	83	85
बिक्री की कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	109	107

66. उपर्युक्त सूचना से, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत में आधार वर्ष के दौरान 14,729 प्रति मी. ट. की जांच की अवधि के दौरान 14,808 रु. प्रति मी. ट. तक वृद्धि हुई है जबकि क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में गिरावट आई है, घरेलू उद्योग की बिक्री की कीमत में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और यह संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के बहुत अधिक थी।

कीमत में कटौती

67. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण करते समय, घरेलू उद्योग द्वारा दी जा रही छूट, बट्टे और कमीशन तथा भुगतान किए गए केंद्रीय उत्पाद में कटौती की गई है। आयातों की पहुंच कीमत को जी सी सी आई एंड एस के आंकड़ों में सूचित किए गए अनुसार संबद्ध देशों से सी आई एफ कीमतों में 1 प्रतिशत पहुंच प्रभार और लागू मूल सीमा शुल्क और शिक्षा उपकर को जोड़कर परिकलित किया गया है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि कीमत में कटौती के निर्धारण के लिए भाड़े को शामिल किया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निवल बिक्री प्राप्ति और पहुंच मूल्य के बीच तुलना कीमत में कटौती के निर्धारण के लिए प्राधिकारी की सतत प्रथा के अनुसार उसी स्तर पर किया गया है।

विवरण	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
टर्की					
आयातों की पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	14,729	16,548	19,572	14,946
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	% रेंज	15-20%	10-15%	0-5%	20-25%
रूस					
आयातों की पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	-	16,548	16337	14,540

निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	% रेंज	-	10-15%	15-20%	25-30%
संपूर्ण रूप में संबद्ध देश					
आयातों की पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	14,729	16,508	18,394	14,808
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	% रेंज	15-20%	15-20%	5-10%	20-25%

68. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान, पाटित आयातों की कीमत में कटौती संबंधी प्रभाव संबद्ध देशों में से प्रत्येक के संबंध में सकारात्मक है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों और पाटन तथा क्षति की संभावना या पुनरावृत्ति के संबंध में आगे पैराग्राफों में स्थिति की समग्र समझ के लिए और विश्लेषण किया है।

ढ. घरेलू उद्योग के अन्य आर्थिक मानदंडों की जांच

उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता और उपयोग

69. उत्पादन, क्षमता और क्षमता के उपयोग का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है :

विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि (क)
संस्थापित क्षमता	मी. ट.	1,111,000	1,111,000	1,236,000	1,524,000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	111	137
उत्पादन	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	110	118
क्षमता का उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	99	86
घरेलू बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	111	122
मांग	मी. ट.	2,833,341	3,024,370	3,059,141	3,279,345
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	108	116

70. उपर्युक्त सूचना से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता में जांच की अवधि (क) सहित क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। उत्पादों और बिक्री दोनों में क्षमताओं में वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि के अनुरूप आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि (क) के दौरान वृद्धि हुई है। क्षमता का उपयोग 2013-14 से 2015-16 तक प्रायः एक जैसी रही परंतु जांच की अवधि (क) के दौरान इसमें गिरावट आई।

माल सूची

71. माल सूची के संबंध में आंकड़े नीचे दिए गए अनुसार हैं :

विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि (क)
प्रारंभिक	मी. ट.	***	***	***	***
अंतिम	मी. ट.	***	***	***	***
औसत	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	127	129

72. यह नोट किया जाता है कि औसत माल सूची में 2013-14 से 2014-15 तक गिरावट आई लेकिन बाद की अवधि में 2015-16 में 127 सूचीबद्ध बिन्दुओं की वृद्धि हुई। उसके बाद पी ओ आई (ए) के दौरान क्षमता में भारी वृद्धि के बावजूद औसत मालसूची में केवल 2 सूचीबद्ध बिन्दुओं तक की वृद्धि हुई।

लाभ और नकदी के प्रवाह पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

73. लाभ/ हानि और नकदी के प्रवाह के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि लाभ, कर पूर्व लाभ और व्याज के संबंध में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि (क)
बिक्री की लागत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	83	85
बिक्री की कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	109	107
लाभ/ हानि	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	229	325	293
लाभ/ हानि	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	231	364	341
पी बी आई टी	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	183	287	270
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	189	292	277
निवेश पर लाभ	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	188	282	171

रोजगार, मजदूरी एवं उत्पादकता

74. रोजगार, मजदूरी और लाभप्रदता के संबंध में आंकड़े नीचे दिए गए अनुसार हैं :

विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	पी ओ आई (क)
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	101	85
मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	125	133

75. यह नोट किया जाता है कि 2013-14 से 2015-16 तक कर्मचारियों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई थी लेकिन जांच की अवधि (क) के दौरान उसमें गिरावट आई। क्षति की समग्र अवधि के दौरान मजदूरी में वृद्धि हुई है।

पाटन का आकार

76. पाटन मार्जिन से संबंधित उपर्युक्त भाग से यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटन मार्जिन जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक और बहुत अधिक है। तथापि, इसका याचिकाकर्ताओं के आर्थिक मापदंडों पर कोई दिखाई देने वाला प्रभाव नहीं पड़ा था।

वृद्धि

77. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का विकास जांच की अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री, लाभ, कर और व्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ में सुधार के संबंध में सकारात्मक थी।

निधि जुटाने की क्षमता

78. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2015-16 और जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अपनी क्षमता में वृद्धि की है। घरेलू उद्योग ने वर्तमान में पर्याप्त पूंजी निवेश किया है और क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए आगे और निवेश किये जाने की योजना बनाई है। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि पूंजी निवेश उगाहने की उनकी क्षमता पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव नहीं पड़ा है।

ण. क्षति और क्षति मार्जिन का आकार

79. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत जिसका निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है, की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देशों से निर्यातों की पहुंच मूल्य से की गई है। इस प्रकार से निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दिया गया है :

देश	उत्पादक	निर्यातक	एन आई पी यू एस डालर/ मी. ट.	पहुंच मूल्य एस डालर/ मी. ट.	क्षति मार्जिन एस डालर/ मी. ट.	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन % रेंज
तुर्की	सोडा सनायी ए. एस.	सोडा सनायी ए. एस.	***	***	***	***	5-10%
तुर्की	अन्य कोई	अन्य कोई	***	***	***	***	5-10%
रूस	ट्रेड हाउस लिमि. «बाशकिरियन केमिस्ट्री»	ट्रेड हाउस लिमि. «बाशकिरियन केमिस्ट्री»	***	***	***	***	5-10%
रूस	ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी «बेरेजनिगी	ट्रेड हाउस लिमि. «बाशकिरियन	***	***	***	***	5-10%

	सोडा वर्क्स	केमिस्ट्री»					
रूस	अन्य कोई	अन्य कोई	***	***	***	***	10-15%

त. वास्तविक क्षति संबंधी निष्कर्ष

80. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री की मात्रा, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर लाभ और माल सूची के मामले में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में यह भी स्वीकार किया है कि इसे क्षति की जांच की अवधि के दौरान क्षति नहीं हो रही थी। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और यह क्षमता में वृद्धि से जुड़ी लागत के बावजूद बिक्री लागत से काफी अधिक रही है।

थ. अन्य ज्ञात कारक एवं कारणात्मक संबंध

81. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की क्षति, मात्रा और कीमत संबंधित प्रभावों के मौजूद होने के संबंध में जांच करने के बाद, कीमत में कटौती और कीमत ह्रास एवं कीमत न्यूनीकरण के प्रभाव, पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत और पाटनरोधी करार के अंतर्गत अन्य सांकेतिक मानदंडों की जांच प्राधिकारी द्वारा यह देखने के लिए की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति में अंशदान कर सकता है, नीचे दिए गए अनुसार है :

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा बहुत अधिक रही है।

ख. मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। इसके विपरीत संबद्ध वस्तुओं के लिए समग्र मांग में जांच की अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

ग. प्रौद्योगिकी का विकास

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक परिवर्तनों, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी, को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

घ. विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं तथा उनके बीच प्रतिस्पर्धा

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं का निर्यात रूप से आयात किया जा सकता है। घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का प्रमुख उत्पादक है और यह पर्याप्त घरेलू उत्पादन और बिक्री का कारण है। इसके अलावा, सिवाय इस बात के कि यह बाजार अर्थव्यवस्था में स्पष्ट रूप से होता है, घरेलू उत्पादकों के बीच कोई दृष्टिगोचर प्रतियोगिता नहीं है।

ङ. घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन :

नीचे दी गई तालिका घरेलू उद्योग के उनके द्वारा किये गये निर्यातों के संबंध में कार्य निष्पादन का सारांश प्रस्तुत करता है।

विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि (क)
निर्यात	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	36	17	159

82. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि (क) के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है। निर्यात बाजारों में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन से भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के प्राधिकारी द्वारा किये गये आकलन पर प्रभाव नहीं पड़ा है। प्राधिकारी ने केवल घरेलू विक्री से संबंधित सूचना के आधार पर अपना आकलन किया है। घरेलू विक्री के आधार पर क्षति को अलग कर दिया गया है तथा उसकी जांच उस सीमा तक की गई है जिस सीमा तक यह संभव था।

83. उपर्युक्त विश्लेषण से, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि न तो सूचीबद्ध ज्ञात मानदंड और न ही उपर्युक्त में विश्लेषण किये गये अन्य कारक घरेलू उद्योग को कोई सतत् क्षति दर्शाता है। घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

द. क्षति के जारी रहने अथवा इसके फिर से होने की संभावना

84. समीक्षा जांच में प्राधिकारी को इस बात का निर्धारण करना है कि क्या संबद्ध वस्तु पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहा है अथवा इसके प्रवेश करने की संभावना है और यह भी क्या घरेलू उद्योग को क्षति संभवतः इन पाटित आयातों के कारण, यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, फिर से होने की संभावना है। प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 11 पैरा (vii) के संबंध में वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों पर विचार करते हुए पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना की जांच कर रहा है, जिसमें नीचे दिए गए अनुसार उल्लेख है :

“वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों के आधार पर और न कि केवल आरोपों, अनुमानों अथवा दूर की संभावना के आधार पर होगा। परिस्थितियों में बदलाव जिससे ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसमें पाटन से क्षति पहुंचेगी, स्पष्ट रूप से प्रत्याशित और आसन्न होनी चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे के होने के संबंध में निर्धारण करने में, निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ साथ ऐसे कारकों पर विचार करेगा जैसे :

क. भारत में पाटित आयातों में वृद्धि का अधिकतम दर जो पर्याप्त रूप से बड़े हुए आयात की संभावना को दर्शाता हो;

ख. किसी अतिरिक्त निर्यातों को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर विचार करते हुए भारतीय बाजारों को पर्याप्त रूप से बड़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना को दर्शाते हुए निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त रूप से स्वतंत्र रूप से विक्री योग्य अथवा आसन्न, वास्तविक वृद्धि;

ग. क्या आयात उन कीमतों पर हो रहा है जिनका घरेलू कीमतों पर पर्याप्त न्यूनकारी अथवा दबावकारी प्रभाव पड़ेगा और जिससे संभवतः आगे आयातों के लिए मांग में वृद्धि होगी;

घ. उस वस्तु जिसकी जांच की जा रही है, का माल भंडार।”

याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया अनुरोध

85. याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

i. निर्णायक समीक्षा के मामले में यह आवश्यक है कि याचिका दायर करने वाले घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन की संभावना का पता लगाया जाये। इस प्रकार से, निम्नलिखित पहलुओं की जांच किये जाने की आवश्यकता है – (क) क्या पाटन और/ अथवा क्षति जारी है और यदि ऐसा है तो क्या पाटनरोधी शुल्क के समाप्त किये जाने की स्थिति में इसके जारी रहने की संभावना है; (ख) यदि पाटन और/ अथवा क्षति जारी नहीं रही तब क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटन फिर से होगा।

ii. पाटनरोधी नियमावली में किसी अंतिम निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन अथवा क्षति की संभावना की जांच के लिए कोई विशिष्ट पद्धति का निर्धारण नहीं किया गया है। हालांकि, यदि जांच की अवधि की तुलना में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों के संबंध में सकारात्मक पाटन मार्जिन होता हो, तब यह संभव है कि पाटन जारी रहेगा और उसके फलस्वरूप लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने देने की स्थिति में परिणामी क्षति होगी। पाटन और क्षति के जारी न रहने की स्थिति में, पाटन और क्षति के फिर से होने की संभावना को देखे जाने की आवश्यकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि याचिका दायर करने वाले घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किये जाने की स्थिति में हो सकता है।

- iii. मूल जांच के दौरान डी ए ने टर्की और रूस के लिए क्रमशः 55-65 प्रतिशत और 65-75 प्रतिशत का पाटन मार्जिन निर्धारित किया। परिणामस्वरूप पहली समीक्षा जांच में संबद्ध देशों के लिए मार्जिन 25-35 प्रतिशत पाया गया था। उत्तरवर्ती समीक्षा जांच में मार्जिन दोनों संबद्ध देशों के लिए 25-35 प्रतिशत के समान स्तर पर रहा था।
- iv. संबद्ध देशों से आयातों को पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटित किया जाना जारी रहेगा और इसके कारण संभवतः घरेलू उद्योग को क्षति होगी। यह निम्नलिखित – आयात किये गये उत्पादों और घरेलू उत्पाद की कीमतों में वर्तमान और संभावित अंतर के बहुत अधिक होने से सिद्ध हो गया है और इस कारण से आयातों के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना है; बहुत अधिक कीमत अंतर और आयातों में परिणामी संभावित वृद्धि के कारण घरेलू कीमतों पर बहुत अधिक न्यूनकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है; संबद्ध निर्यातक बहुत अधिक मात्रा में निर्यात रूप से बिक्री योग्य क्षमता धारण कर रहे हैं जो किसी अतिरिक्त कदमों को अवशोषित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर भारतीय बाजारों में पर्याप्त रूप से बड़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना को दर्शाते हैं। पाटनरोधी शुल्क विस्तृत निर्धारण के बाद लगाया गया था कि उस उत्पादन के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही थी। घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन ने पाटनरोधी शुल्क के लगाये जाने के बाद सुधारना आरंभ किया है परंतु जांच की अवधि में इसमें गिरावट होना शुरू हो गया है। किसी भी मामले में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को सतत क्षति का न होना पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की आवश्यकता को दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि घरेलू उद्योग को विगत में हुई क्षति पाटन, कार्य निष्पादन में सुधार के कारण हुआ था अथवा क्षति का अभाव पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने का एक स्वाभाविक परिणाम है। इस कारण से निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस निष्कर्ष पर पहुंचना ही चाहिये कि घरेलू उद्योग को क्षति यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तब जारी रहने अथवा इसके फिर से होने की संभावना नहीं है।
- v. संबद्ध देशों से आयातों में 2015-16 तक गिरावट होने के बाद जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। क्योंकि टर्की से आयात जांच की अवधि में सबसे अधिक है। इसके अलावा, जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयातों में उछाल हुआ था। पाटित कीमतों पर आयातों में वृद्धि यह दर्शाती है कि आयात के पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटित कीमत पर पर्याप्त मात्रा में होने की संभावना है। वार्षिक आधार पर जांच की अवधि के लिए आयात 51,668 मी. ट. थी और केवल एक तिमाही (पहली तिमाही 2017-18) में जांच की अवधि के बाद आयात 52,658 मी. ट. है और इस प्रकार से इसमें 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार से, केवल टर्की से आयातों की संभावना संबद्ध देशों के औचित्य पूर्ण बाजार को लेने के लिए पर्याप्त है और इससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।
- vi. क्षति की अवधि के दौरान आयातों का इस कारण से घरेलू उद्योग पर न्यूनकारी अथवा दबावकारी प्रभाव नहीं पड़ा था कि पाटनरोधी शुल्क लागू था और टर्की की नई क्षमताओं का व्यापारीकरण नहीं किया गया था। हालांकि, आयात की कीमतों में पर्याप्त रूप से गिरावट शुरू हो गई है और यह घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबावकारी प्रभाव के साथ शुरू हुआ है जैसे ही टर्की की नई क्षमताओं का व्यापारीकरण शुरू हुआ है। यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाये तब घरेलू उद्योग इन कीमतों में प्रायः तत्काल रूप से कटौती करने के लिए बाध्य हो जायेगा। इस प्रकार से पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर बहुत अधिक न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा।
- vii. संबद्ध देशों में निर्यातकों के पास भारतीय मांग से बहुत अधिक क्षमताएं हैं। संबद्ध विदेशी उत्पादकों के पास विशाल मात्रा में अतिरिक्त और पर्याप्त उत्पादन क्षमताएं हैं। टर्की की न्यून लागत वाली नई 3 मिलियन मी. ट. क्षमता ने पहले ही आंशिक रूप से उत्पादन शुरू दिया है और शेष शीघ्र ही शुरू हो जायेगी। ई टी आई सौदे ने फरवरी 2017 में चल रहे निवेशों के साथ 6 लाख मी. ट. की अतिरिक्त क्षमता संस्थापित की है। साइनर ग्रुप, जिसका ई टी आई सोडा एक हिस्सा भी है, ने अपनी सहायक कंपनी कजन सोडा के माध्यम से 2.5 मिलियन मी. ट. डेंश सोडा एश का उत्पादन करने के लिए अंकारा के उत्तर पश्चिम में स्थित एक नया संयंत्र स्थापित किया है। आई एच एस बाजार 2017 वर्ल्ड सोडा एश रिपोर्ट के अनुसार टर्की में मांग आपूर्ति का अंतर 2.1 मिलियन मी. ट. है। इसके अलावा, टर्की की खपत में वृद्धि में गिरावट आ रही है जबकि इसके उत्पादन में वृद्धि प्रत्येक तिमाही में स्थिर रहता है जो निकट भविष्य में मांग आपूर्ति के अंतर में और अधिक वृद्धि हो दर्शाता है।

- viii. बशकिर सोडा कंपनी जो रूस के प्रमुख सोडा एश उत्पादकों में एक है, अर्थात् जो घरेलू सोडा एश का 65 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है, में व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण हुआ है और इसमें आगे 50 प्रतिशत तक क्षमताओं में वृद्धि हुई है।
- ix. टर्की के उत्पादक इस तथ्य के बावजूद अपने उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं कि टर्की में मांग और आपूर्ति में बहुत अधिक अंतर मौजूद है क्योंकि उनका उत्पादन देश में खपत की तुलना में बहुत अधिक है। विस्तार का कारण निर्यातों में वृद्धि करना है। अनुसंधान यह भी दर्शाता है कि रूस में उत्पादक एक वैश्विक बाजार की मांग को पूरा करते हैं। रूस के उत्पादकों की बिक्री भूगोल यूरोप, सी आई एस देश, एशिया, लेटिन अमेरिका और मध्य पूर्व को उनके उत्पाद के लिए बाजार के रूप में दर्शाता है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से विभिन्न अन्य देशों में निर्यात की मात्रा और मूल्य का विश्लेषण भी किया है और यह देखा है कि उनके द्वारा किये गये अधिकांश निर्यात पर्याप्त रूप से पाटित और प्रतिकारक दोनों कीमतों पर हो रहे हैं। क्षमताओं के वैश्विक विस्तार से आगे सकारात्मक मांग के साथ घरेलू बाजार में बढ़े हुए आयातों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। इसके अलावा, वैश्विक रूप से मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है जो यह दर्शाता है कि निर्यात मांग में अपनी सतत वृद्धि को देखते हुए भारतीय बाजार की ओर परिवर्तित हो जाने की संभावना है।
- x. यद्यपि वर्तमान जांच का संबंध टर्की और रूस है, फिर भी वैश्विक अतिरिक्त क्षमताओं और क्षमता में वृद्धि संगत हो जाती है जहां कहीं भी घरेलू बाजार की मांग क्षमताओं से कम है, अन्य बाजारों में भी क्षमता के विस्तार पर विचार करना संगत है। पाकिस्तान के निर्यातक भी क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह क्षमता विस्तार निर्यात बाजारों की मांग को पूरा करती है। याचिकाकर्त्ता पाकिस्तान में मांग और आपूर्ति में अंतर की सूचना जिसे आई एच एस केमिकल वीक में दिया गया है, प्राप्त करने में सक्षम है, जो यह दर्शाता है कि आई सी आई पाकिस्तान ओलंपिया केमिकल के साथ साथ विस्तार योजनाओं में प्रवेश कर रहा है। आई एच एस आंकड़े यह दर्शाते हैं कि पाकिस्तान के बाजार में आवश्यकता से अधिक आपूर्ति की गई है।
- xi. चीन की भी क्षमता में विस्तार किये जाने की योजना इस तथ्य के बावजूद है कि उसके पास बहुत अधिक अतिरिक्त क्षमता मौजूद है और यह दर्शाता है कि चीन के उत्पादक इस प्रकार के व्यापक क्षमता विस्तार को नहीं कर सकते हैं, जब उनके पास पहले से ही भारी मात्रा में अतिरिक्त क्षमताएं हैं और इस प्रकार से वे अनेक देशों में उत्पादकों की तुलना में निम्नतर लागतों का लाभ उठाते हुए व्यापक वैश्विक बाजार में निर्यात करने की लालसा को छोड़कर इन निवेशों के लिए किसी तर्क से इन्कार नहीं कर सकते हैं।
- xii. टर्की से आयातों की वर्तमान मात्रा स्पष्ट रूप से इस बात का साक्ष्य है कि निर्यातक वास्तव में इस तथ्य में विश्वास करने में घरेलू उद्योग को भ्रमित कर रहे हैं कि आयातों में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी। रूस और टर्की की सरकार और निर्यातक एक लिखित आश्वासन दे सकता है कि निर्यातों की मात्रा वर्तमान जांच की अवधि में दर्ज की गई मात्राओं से अधिक नहीं होगी बल्कि यदि निर्यातक अपने निर्यातों को उस सीमा तक बढ़ाना चाहते हैं जिस सीमा तक टर्की के उत्पादक ने पहले ही जून 2018 तक बढ़ा लिया है और जिस सीमा को वे दिसंबर 2018 तक बढ़ाये जाने की आशा करते हैं, याचिकाकर्त्ता यह अनुरोध करता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने के बाद आयातों में अचानक वृद्धि होगी। याचिकाकर्त्ता ने उनके द्वारा किये गये आयातों और इन वस्तुओं के 5 शीर्ष उपभोक्ताओं को अपनी बिक्री मात्राओं के संबंध में सूचना इकट्ठी की है। यह देखा जायेगा कि घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री *** मी. ट. से गिरकर लगभग *** मी. ट. से कम हो गई है। यह हानि अपने आप में बाजार की हानि के पूर्व संकेत को परिलक्षित करता है जो घरेलू उद्योग को, यदि वर्तमान शुल्क को समाप्त होने दिया जाये, तब होना अवश्यभावी है।
- xiii. पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत में कटौती सकारात्मक और पर्याप्त है। यह स्पष्ट है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को इस अपरिपक्व चरण में वापस ले लिया जाता है तब इन आयातों के कारण कीमतों में बहुत अधिक कटौती होगी, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
- xiv. भारतीय बाजार कीमत के आधार पर खरीद करने का निर्णय लेने वाले उपभोक्ताओं के साथ बहुत अधिक कीमत संवेदनशील है। संबद्ध देशों से कम कीमत पर आयातों की उपलब्धता के कारण इस प्रकार से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। घरेलू उद्योग का जोखिम इस बात से संबंधित है कि क्या यह उद्योग लगाये गये पाटनरोधी शुल्क को रद्द किये जाने की स्थिति में वास्तविक क्षति की स्थिति में होगा। समय से

पूर्व के चरण में वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग के पास या तो पाटनरोधी शुल्क की राशि में कटौती पर बिक्री की कीमत का निर्धारण करने अथवा बिक्री की मात्रा को क्षति पहुंचाने का विकल्प होगा। दोनों मामलों में घरेलू उद्योग को हानि होगी। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को वापस लिये जाने की स्थिति में और यदि घरेलू उद्योग आयात कीमतों पर बिक्री करने के लिए बाध्य हो तब घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में बहुत अधिक गिरावट होगी। निवेश पर लाभ और नकद लाभ में भी बहुत अधिक गिरावट होगी। इस कारण से पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने का इस बाजार में कीमतों पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संबद्ध देशों में इन उत्पादकों के पास उपलब्ध माल सूची का स्तर का पता घरेलू उद्योग द्वारा नहीं लगाया जा सका। हालांकि, उन उत्पादकों के पास उसकी पर्याप्त उपलब्ध क्षमता को देखते हुए उचित रूप से यह माना जा सकता है कि विदेशी उत्पादक बहुत कम अवधि में उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

- xv. संबद्ध निर्यातकों को उनकी सूचना के आधार पर यह सिद्ध करना चाहिए कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में यह संभव नहीं है कि पाटन जारी रहेगा, इसमें और अधिक वृद्धि होगी अथवा यह फिर से होगा।
- xvi. अनेक समीक्षा जांचों में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से संभवतः घरेलू उद्योग को क्षति फिर से होगी। इस उद्देश्य से, निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित जांच करें - क) क्या जांच की अवधि के दौरान भारत में निर्यातों के संबंध में कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन सकारात्मक है; ख) क्या जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान भारत में निर्यातों के संबंध में कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन सकारात्मक है; ग) क्या जांच की अवधि के दौरान विभिन्न तीसरे देशों के संबंध में कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन सकारात्मक है; घ) क्या जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान विभिन्न तीसरे देशों के संबंध में कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन सकारात्मक है; ङ) जांच की अवधि के दौरान तीसरे देशों में निर्यातों की मात्रा जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और भारत में निर्यात कीमत से कम कीमत पर हुई थी और क्या निर्यातों की ऐसी मात्रा भारतीय मांग के संबंध में बहुत अधिक है। केवल ऐसी स्थिति में जहां निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उपर्युक्त सभी स्थितियों में कीमत में कटौती नकारात्मक है, निर्दिष्ट प्राधिकारी यह मान सकते हैं कि भारतीय बाजार विदेशी उत्पादकों के लिए आकर्षक नहीं है और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने के बाद और अधिक पाटन होने की संभावना नहीं है। अन्य प्रकार से निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह मानना चाहिए कि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग को क्षति के फिर से होने की संभावना है। जब क्षति मार्जिन के सिद्धांत को अनेक जांचों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा लागू किया गया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी अब इस सिद्धांत को लागू नहीं कर सकते हैं जहां तक क्षति के मार्जिन का संबंध है। हालांकि, कीमत में कटौती के सिद्धांत को उसी उद्देश्य से लागू किये जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी द्वारा विगत जांचों में किये गये संगत निर्धारण जिनमें क्षति के मार्जिन के उक्त सिद्धांत को लागू किया गया है - चीन की तार्पेई अथवा वहां से निर्यात किए गए ऐसीटोन के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क के संबंध में एम टी आर जांच है; कोरिया जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये फिनोल के आयात के संबंध में एम टी आर जांच है, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये फिनोल के आयातों के संबंध में लगाये गये पाटनरोधी शुल्क की एम टी आर है; चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये डकटाइल आयरन पाईप के आयातों के संबंध में अंतिम निर्णायक जांच है; चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये ज़िंक ओक्साइड के आयात पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क की अंतिम निर्णायक समीक्षा में अंतिम जांच परिणाम है; सिंगापुर के मूल के अथवा से निर्यात किये गये पोप्रोपीलिन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की अंतिम निर्णायक समीक्षा जांच है और यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर और यू एस ए के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये ऐसीटोन के आयातों के संबंध में लगाये गये पाटनरोधी शुल्क की अंतिम निर्णायक समीक्षा है।
- xvii. मूल जांच में कारणात्मक संबंध को पहले ही सिद्ध किया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति के पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में जारी रहने अथवा फिर से होने की संभावना है। पूर्व के अनुरोधों से यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने के कारण घरेलू उद्योग को गहन क्षति होने की संभावना है - (क) मात्रा का प्रभाव : कीमत में कटौती - > आयात की गई सामग्री को उपभोक्ताओं द्वारा पसंद किया जाना -> घरेलू उद्योग को बिक्री की हानि होना

-> माल सूची में वृद्धि होना -> उत्पादन में गिरावट -> क्षमता के उपयोग में गिरावट होना; (ख) कीमत का प्रभाव : कीमत में कटौती -> घरेलू उद्योग को कीमत में वृद्धि करने से रोका गया -> लाभप्रदता में गिरावट आई -> उत्पाद में अर्जित सकल लाभ में गिरावट -> नकद लाभ में गिरावट -> नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट।

- xviii. उसको देखते हुए, घरेलू उद्योग को क्षति मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटित आयातों से उत्पन्न होने की संभावना है। घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि (क) विचाराधीन उत्पाद का निर्यात भारत में संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर किया गया है। पाटन के संबद्ध देशों से और अधिक होने की संभावना है; (ख) घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना है; और (ग) पाटनरोधी शुल्क को आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
- ix. हितबद्ध पक्षकार ए आई जी एम एफ के तर्क का आशय यह है कि क्षति के जारी रहने के निर्धारण के लिए संगत मानदंड भी क्षति की संभावना के निर्धारण के लिए संगत हैं। इस प्रकार के अनुमान के लिए कोई कानूनी और तथ्यात्मक आधार नहीं है। इसके विपरीत वास्तविक क्षति अथवा शपथ क्षति के लिए संगत मानदंड क्षति के खतरे अथवा उसके फिर से होने के लिए संगत मानदंडों से अलग हैं। इस कारण से क्षति के फिर से होने की संभावना का निर्धारण करने के लिए सतत क्षति के मानदंडों पर विचार करना उचित नहीं है। यदि मानदंडों में संभावित गिरावट पर क्षति के फिर से होने की संभावना के निर्धारण के लिए एक मानदंड के रूप में विचार किया जाना अपेक्षित है तब विगत आंकड़े पूर्ण रूप से असंगत हो जाते हैं और प्राधिकारी को बाद की अवधि के लिए संभावित आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। प्राथमिक मानदंड जो अंतिम निर्णायक समीक्षा जांच में विश्लेषण का आधार बनता है, घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का विश्लेषण है। अन्य हितबद्ध पक्षकार इस तथ्य को समझ पाने में असफल रहे हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क का इच्छित प्रभाव पड़ा होता, तब घरेलू उद्योग को कोई स्पष्ट वर्तमान क्षति नहीं होगी, घरेलू उद्योग की स्थिति पाटनरोधी शुल्क के संरक्षणात्मक व्यवस्था के दौरान सुधर जाने की आशा है। वर्तमान जांच में, घरेलू उद्योग इस तथ्य पर सहमत है कि घरेलू उद्योग की विभिन्न मानदंडों में सुधार हुआ है लेकिन वह मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने का परिणाम है। इसके अलावा, इन मानदंडों ने आयातों में वृद्धि के साथ जांच की अवधि में गिरावट को दर्शाना शुरू कर दिया है। जबकि पूर्ण मानदंड वास्तविक क्षति को नहीं दर्शाएंगे फिर भी उद्योग की स्थिति बहुत अधिक नाजुक है। हालांकि, चूंकि यह एक अंतिम निर्णायक समीक्षा जांच है जिसे प्राथमिक रूप से देखा जाना है और वह मौजूदा शुल्कों को समाप्त किए जाने/ निरस्त किए जाने के मामले में घरेलू उद्योग को पाटन/ क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।
- xx. यह तर्क कि यदि घरेलू उद्योग पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करता है तो आयात निश्चित रूप से और कम होगा, में कोई दम नहीं है। स्थापित स्थिति की मांग और आपूर्ति में अंतर इस देश में पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है, के पूर्वाग्रह के बिना याचिकाकर्ता यह अनुरोध करते हैं कि केवल *** मी. ट. इस देश में कथित मांग आपूर्ति अंतर है जबकि संबद्ध देशों और अन्य देशों जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है, से आयात इस अंतर जो मौजूद है, से लगभग 6 गुणा अधिक है। घरेलू उद्योग तभी निर्यात करता है जब इसे एक अनुकूल बाजार मिलता है। क्षमता में वृद्धि जो बढ़ती हुई मांग को देखते हुए की गई थी पर विचार करने के बाद, घरेलू उद्योग बिक्री की मात्रा प्राप्त करने में सक्षम नहीं था जो अधिकार पूर्वक उनका होना चाहिए था। क्षति की जांच के आधार वर्ष से 2015-16 तक, संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में गिरावट आई परंतु जांच की अवधि में उसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई। इसके अलावा, चूंकि यह एक अंतिम निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयातों के परिचालन को निर्यातकों से संभावित व्यवहार की जांच करने के लिए भी देखा जा सकता है। पाटित कीमतों पर आयातों में वृद्धि इस तथ्य को दर्शाता है कि इन आयातों से पाटनरोधी शुल्क के समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटित कीमत पर बहुत अधिक मात्रा में प्रवेश करने की संभावना है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

86. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- i. याचिकाकर्ता संभावना के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं और वे इस संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य के साथ भी प्राधिकारी को आपूर्ति करने में असफल रहे हैं। जांच को आरंभ किये जाने की मांग करते समय संगत मानदंडों के संबंध में साक्ष्य अवश्य होना चाहिए।
- ii. पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना और पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। पाटित आयातों में कथित वृद्धि का याचिकाकर्ताओं के उत्पादन, क्षमता का उपयोग और घरेलू बिक्री पर प्रभाव नहीं पड़ा है। जैसा कि पूर्व में दर्शाया गया, कीमत में किसी कथित कटौती का घरेलू उद्योग के वित्तीय कार्य निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- iii. भारतीय उद्योग ने वार्षिक क्षमता का *** लाख टन के करीब वृद्धि की है और *** लाख टन की वार्षिक क्षमता को आगे बढ़ाये जाने की योजना है जिसे दिनांक 14.12.2018 के अंतिम जांच परिणामों में रिकार्ड किया गया है। घरेलू उद्योग की मजबूत उपस्थिति भारत में संबद्ध देशों में किसी अतिरिक्त क्षमताओं के प्रवाह को बाधित नहीं करेगी।
- iv. यदि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए कीमत में कटौती का कोई वास्तविक हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता तब घरेलू उद्योग अपनी घरेलू बिक्री को बनाये नहीं रख पाती अथवा उसमें वृद्धि नहीं कर पाती। केवल यह तथ्य की घरेलू उद्योग ने कीमत में कथित कटौती के बावजूद अपनी घरेलू बिक्री का विस्तार कर पाया यह दर्शाता है कि क्षति नहीं हुई थी और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की कोई संभावना नहीं है।
- v. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में क्षति की अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई जबकि लाभप्रदता में कथित पाटन के बावजूद आधार वर्ष 2013-14 से तुलना किये जाने पर जांच की अवधि के दौरान तीन गुणा से अधिक वृद्धि हुई। रिकार्ड में आंकड़े यह नहीं दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग क्षति के अवधि के दौरान अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य था।
- vi. संबद्ध वस्तुओं की आयातों में गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त क्षमताओं को संस्थापित किया और उस पर अच्छा लाभ प्राप्त किया। नियोजित पूंजी पर लाभ 2013-14 में 100 सूचीबद्ध अंक से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 167 सूचीबद्ध अंक हो गया।
- vii. रिकार्ड में साक्ष्य इस तथ्य को दर्शाता है कि मांग में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग में कथित पाटन के बावजूद क्षमताओं में वृद्धि की, अपने उत्पादन, घरेलू बिक्री और लाभप्रदता में वृद्धि की। यह एक प्रवृत्ति है जो उस स्थिति में भी जारी रहेगी जब पाटनरोधी शुल्क का समय समाप्त हो जायेगा। इसके अलावा, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाये तब ग्राहक आयात को अपनाना शुरू करेंगे।
- viii. घरेलू उद्योग की स्थिति में आपवादित रूप से सुधार हुआ है और अब आगे संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त सभी को देखते हुए, इस समीक्षा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग को क्षति की किसी संभावना को उत्पन्न करने वाली पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना को दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है।
- ix. एच यू एल का यह अनुरोध है कि वर्तमान मामले में क्षति की संभावना के लिए एक कारण के रूप में कीमत आकर्षकता को नहीं माना जा सकता है। तीन देशों में और भारत में टर्की के निर्यातों के बीच कीमत में अंतर बहुत अधिक है जिसके कारण पाटनरोधी शुल्क के मौजूद होने अथवा उसके न होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरे देशों में टर्की की निर्यात कीमतें वर्तमान में लगाये गये पाटनरोधी शुल्क को शामिल करने के बाद भी भारत में इसकी कीमत की तुलना में बहुत कम कीमतों पर पहले से ही हो रहा है। यदि भारत का बाजार कीमत के मामले में आकर्षक है, तब इन तथ्यों की क्या शुल्कों को समाप्त होने दिया जाये अथवा नहीं, पर ध्यान दिये बिना भारत में टर्की के निर्यातों में पहले से ही बहुत अधिक वृद्धि होनी चाहिए थी। हालांकि, भारत में निर्यात में इस प्रकार की वृद्धि को नहीं देखा गया है यद्यपि टर्की के उत्पादक पाटनरोधी शुल्कों को खपाने के बाद भी भारत में बिक्री करने पर बहुत अधिक लाभप्रद कीमतें प्राप्त कर सकते हैं। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि यद्यपि शुल्कों समाप्त होने दिया जाता फिर भी टर्की, से उत्पादकों के लिए कीमत आकर्षकता में कोई अधिक परिवर्तन नहीं होता जिसके द्वारा भारत में पाटित आयातों में अचानक वृद्धि की कोई संभावना है।

- x. इसके अलावा, याचिकाकर्त्ताओं ने अपने लिखित अनुरोधों के पृष्ठ संख्या 33 और 45 – 46 के माध्यम से पाटित कीमतों पर तीसरे देशों में संबद्ध देशों द्वारा किये गये निर्यातों और भारत में तीसरे देशों को निर्यात को परिवर्त्ती किये जाने की संभावना के संबंध में अनुरोध किया है। एच यू एल का यह अनुरोध है कि याचिकाकर्त्ताओं द्वारा उनकी याचिका में पृष्ठ संख्या 81 – 87 के द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों से, यह देखा जा सकता है कि टर्की का मुख्य बाजार इटली, मिस्र और सउदी अरब है तथा रूस का प्रमुख बाजार कजाकिस्तान, बेलरस और यूक्रेन है। यह भी देखा जा सकता है कि इन देशों में न केवल आयात बहुत अधिक है बल्कि पाटित कीमतों पर भी “नहीं” हो रहा है (विशेष रूप से भारत में निर्यात कीमत से अधिक कीमत पर)। अतः, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने अथवा उसके मौजूद रहने के बावजूद टर्की और रूस का मुख्य बाजार ऊपर में दिये गये बाजार ही रहेंगे। इस कारण से तीसरे देशों में संबद्ध देशों से निर्यात वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स में संभावना का विश्लेषण करते समय संगत नहीं होता है।
- xi. याचिकाकर्त्ताओं ने कीमत न्यूनीकरण/ उस पर दबाव के संबंध में जांच की अवधि के बाद की किसी अवधि से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये हैं और न ही इसने उसके संबंध में कोई पुष्टि किया हुआ अनुरोध किया है। हालांकि, एच यू एल ने विस्तृत अनुरोध प्रस्तुत किये हैं जो इस बात का साक्ष्य है कि कोई कीमत न्यूनीकरण/ उस पर दबाव जांच की अवधि के दौरान नहीं हुआ है। इस प्रकार से एच यू एल का यह अनुरोध है कि याचिकाकर्त्ताओं की न्यूनकारी अथवा दबावकारी बिक्री कीमत को संबद्ध आयातों की कीमत जिसका कथित प्रभाव बहुत अधिक होना चाहिए था, को वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स में गैर मौजूद प्रभाव के विपरीत नहीं माना जा सकता है।
- xii. याचिकाकर्त्ताओं ने संबद्ध देशों में माल सूची के स्तर के संबंध में जांच की अवधि के बाद की अवधि से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये हैं और न ही उन्होंने उसके संबंध में कोई पुष्टि किया हुआ अनुरोध किया है।
- xiii. इस याचिका के पैरा 75 के माध्यम से, याचिकाकर्त्ताओं ने यह उल्लेख किया था कि पूर्व के जांचों में घरेलू बाजार ने विचाराधीन उत्पाद का बहुत अधिक पाटन हुआ था। हालांकि, यह अनुरोध किया जाता है कि पूर्व की जांचों में पाटन का होना मात्र अंतिम निर्णायक समीक्षा का मुख्य विषय नहीं है और भारत में पाटित आयातों में वृद्धि का स्पष्ट साक्ष्य होना चाहिए। याचिकाकर्त्ता संबद्ध देशों के आयातों के पाटन के फिर से होने अथवा उसके जारी रहने की संभावना जिसे पूर्व की जांचों में उजागर किया गया है, को निर्णायक रूप से सिद्ध करने में असफल रहे हैं। यदि सतत पाटित आयातों की संभावना को मान भी लिया जाये (लेकिन नहीं माना गया), तब भी यह स्पष्ट है कि क्षति की अवधि में पाटन का याचिकाकर्त्ताओं के कार्य निष्पादन से पूर्ण रूप से कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- xiv. वर्तमान में कोई पाटन नहीं हुआ है और न ही भविष्य में पाटन की कोई संभावना है। वर्तमान क्षति का न होना एक मजबूत संकेतक है कि इस क्षति के फिर से होने की संभावना नहीं है। वर्तमान अंतिम समीक्षाओं में प्राधिकारी की यह मत रहा है कि पाटन का मौजूद रहना भी पर्याप्त नहीं है जब उससे घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई हो। वही स्थिति हाल में समाप्त विभिन्न जांचों जिसमें दिनांक 10.01.2018 के निर्णायक समीक्षा अंतिम जांचों में जापान और कतर से कास्टिक सोडा और दिनांक 05.01.2018 के निर्णायक समीक्षा अंतिम जांचों में चीन जन. गण., चीन ताईपेई, मलेशिया, इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड और कोरिया जन. गण. से नायलॉन फिलामेंट यार्न शामिल है, से उत्पन्न होती है।
- xv. उपर्युक्त को देखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि याचिकाकर्त्ता पाटनरोधी शुल्कों के न होने की स्थिति में क्षति की किसी संभावना को दर्शा पाने में असफल रहे हैं। याचिकाकर्त्ताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण उन्हें कोई क्षति नहीं हुई है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

87. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ॥ (vii) के संबंध में वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना की जांच की है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ॥ के नियम (vii) के अंतर्गत संभावना के पहलुओं पर विचार करते समय, प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित कारणों पर विचार किया है।

1. वर्तमान में सतत् आयात

88. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान और क्षति की बाद की अवधि के दौरान भी संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का विश्लेषण किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा ने आधार वर्ष में 62,355 मी. ट. से जांच की अवधि (क) के दौरान 51,668 मी. ट. तक गिरावट दर्ज की। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हालांकि संबद्ध देशों से आयात ने जांच की अवधि के बाद की अवधि (अक्टूबर 2017 से सितंबर, 2018) में 2,20,791 मी. ट. तक वृद्धि हुई है। जैसा पूर्ववर्ती खंडों में सिद्ध हुआ है, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई के दौरान उत्पादन, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और मालसूची की दृष्टि से सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में भी यह माना है कि इससे क्षति जांच अवधि के दौरान क्षति नहीं हो रही थी। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और क्षमता में वृद्धि से जुड़ी लागत के बावजूद वह बिक्री लागत से अधिक रही है। वर्तमान पाटन के बावजूद घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं के आयातों से कोई क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा संबद्ध आयात पी ओ आई (ए) के दौरान भारत में कुल आयात का केवल 1.6 प्रतिशत थे। यह सभी कारक दर्शाते हैं कि पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना वर्तमान मामले में साबित नहीं होती है।

2. अतिरिक्त क्षमताएं

89. वास्तविक क्षति के खतरे का पता लगाने के लिए इस मानदंड में भारतीय बाजार में बिक्री के योग्य मात्रा को परिवर्तित किये जाने की संभावना की तलाश करने के लिए मौजूदा अतिरिक्त क्षमताओं और क्षमता वृद्धि, यदि कोई हो का मूल्यांकन अपेक्षित है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों को पहले से ही बहुत अधिक अतिरिक्त क्षमताओं का सामना करना पड़ रहा है और यह कि ये उत्पादक अनेक देशों में इस उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के मामले में कीमतों से कम कीमत पर निर्यात किया जा रहा है और इस प्रकार से पाटनरोधी शुल्क को वापस लिये जाने की स्थिति में भारत में इन निर्यातों को परिवर्तित किये जाने की संभावना दर्शा रहा है।
90. जबकि भाग लेने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने मौजूदा अतिरिक्त क्षमताओं के संबंध में कोई साक्ष्य और सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, घरेलू उद्योग ने आई एच एस कैमिकल जर्नल से सूचना और संबद्ध देशों में सोडा एश के निर्माण के संबंध में आंकड़े/ विवरण अर्थात् मौजूदा क्षमता, मौजूदा उत्पादन, उपयोग न की गई क्षमता, क्षमता विस्तार, निवेश आदि उपलब्ध कराते हुए संबद्ध देशों में कुछ उत्पादकों की वार्षिक रिपोर्ट से उद्धरण प्रस्तुत किये हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों में क्षमता का विस्तार हुआ है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध करायी गयी आई एच एस कैमिकल रिपोर्ट का उद्धरण यह दर्शाता है कि टर्की में उत्पादक वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए जुलाई 2018 से दिसंबर 2019 तक लगभग 25 लाख मी. ट. क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं। तथापि, यह सिद्ध नहीं हुआ है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो संबद्ध देशों में ऐसी किसी कथित अतिरिक्त क्षमता को भारत में भेजा जाएगा।

3. कीमत आकर्षकता

91. घरेलू उद्योग ने शेष विश्व को टर्की द्वारा निर्यातों के संबंध में टर्की सीमा शुल्क आंकड़े उपलब्ध कराये हैं। डब्ल्यू टी ए के आंकड़े जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, जांच की अवधि के लिए, टर्की से शेष विश्व को डब्ल्यू टी ए निर्यात आंकड़े (नीचे भारतीय कीमत निर्यात के संबंध में समग्र और अलग अलग किये गये आंकड़े) नीचे दिए गए हैं :

शेष विश्व को निर्यात – मात्रा	इकाई	जांच की अवधि वार्षिकीकृत	जांच की अवधि वार्षिकीकृत (डब्ल्यू टी ए के आंकड़ों के अनुसार)	जांच की अवधि के बाद की अवधि (अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018)
कुल	मी. ट.	1,393,227	16,06,891	26,60,570
भारत की तुलना में कम कीमत	मी. ट.	900,547	10,64,490	20,97,451
भारत की तुलना में अधिक कीमत		492,680	5,42,401	563,119
शेष विश्व को निर्यात – कीमत				

कुल	डालर/ मी. ट.	181	180	176
भारत की तुलना में कम कीमत	डालर/ मी. ट.	170	171	171
भारत की तुलना में अधिक कीमत	डालर/ मी. ट.	200	199	193

92. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि टर्की से विश्व को निर्यात में जांच की अवधि की तुलना में जांच की अवधि के बाद की अवधि (अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018) में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उन्होंने अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के दौरान टर्की से विश्व को निर्यात 13,93,227 मी. ट. हुआ जिसमें जांच की अवधि के बाद की अवधि में 26,60,570 मी. ट. तक वृद्धि हुई। इसके अलावा उन्होंने यह दावा किया है कि शेष विश्व को बहुत अधिक निर्यात उस कीमत पर किया गया है जो भारत में औसत कीमत से कम है और यह कि शेष विश्व को टर्की द्वारा किये गये निर्यात का 26,60,570 मी. ट. में से, 20,97,451 मी. ट. अर्थात् निर्यात का लगभग 79 प्रतिशत उस कीमत पर किया गया है जो औसत कीमत जिस पर भारत में इन वस्तुओं का निर्यात किया गया है, से कम है। देश में कोई मांग जांच की अवधि में 32,79,345 मी. ट. तक है।

4. कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण

93. यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में जांच की अवधि की तुलना में जांच की अवधि के बाद की अवधि में (अक्टूबर, 2017 से मार्च 2018) 11 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जबकि उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में केवल 3 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। तथापि, यह भी नहीं देखा गया है कि पी ओ आई के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उसकी बिक्री लागत से काफी अधिक रही है।

5. माल सूची का स्तर

94. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास उपलब्ध माल सूची के स्तर का पर्याप्त सहयोग न किये जाने को देखते हुए पता नहीं लगाया जा सका।

6. वर्तमान मार्जिन का स्तर

95. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मूल जांच में पाटन मार्जिन सकारात्मक था। वर्तमान समीक्षा जांच में, संबद्ध देशों से आयातों के लिए जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक है।
96. हालांकि, सभी मानदंडों का समग्र आकलन किए जाने के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है तब पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की कोई संभावना नहीं है।

प. प्रकटन पश्चात् टिप्पणियां

याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया अनुरोध

97. याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- प्राधिकारी द्वारा भेजे गए पत्रों का अगोपनीय पाठ, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों और अनुरोधों की प्रति और सामान्य मूल्य को प्रकट किया जाए ताकि वे सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचने में सक्षम हो सकें।
- संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में 0.8 प्रतिशत तक कमी आई और तब फिर जांच की अवधि में इसमें 1.6 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। जांच की अवधि की बाद की अवधि में आयातों में वृद्धि के साथ, बाजार हिस्से में आगे और वृद्धि हुई है।
- आयात की मात्राओं में 2015-16 तक गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि में इसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई। आयातों में लगभग 100 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। इसके अलावा, टर्की में अतिरिक्त क्षमताओं का प्रचालन शुरू होने के बाद जांच की अवधि की बाद की अवधि में आयातों में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई।

- iv. संबद्ध आयात जांच की अवधि के पिछले छः महीनों के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। यदि क्षति के अवधि की तुलना में समग्र आधार पर कोई दबाव/ ह्रास नहीं हुआ हो तब यह तथ्य कि आयातों ने दबावकारी/ ह्रासकारी प्रभाव डालना आरंभ कर दिया है। इस बात का स्पष्ट रूप से द्योतक है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता यह अनुरोध करते हैं कि जांच की अवधि के अंत की स्थिति विशेष रूप से जब जांच की अवधि की बाद की अवधि में यह प्रवृत्ति बदतर स्थिति को दर्शाती हो, समग्र स्थिति की तुलना में और अधिक महत्वपूर्ण है।
- v. जबकि घरेलू उद्योग की क्षमता में 37 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, उत्पादन में केवल 18 प्रतिशत तक वृद्धि हुई और बिक्री में केवल 16 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।
- vi. यद्यपि घरेलू उद्योग लाभ अर्जित कर रहा है फिर भी विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। लाभ 2016-17 की तुलना में जांच की अवधि के पिछले छः महीनों में लगभग 50 प्रतिशत तक कम हुई। जांच की अवधि के अंत की स्थिति विशेष रूप से जब जांच की अवधि की बाद की अवधि में बदतर स्थिति को दर्शाता हो, समग्र स्थिति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है।
- vii. यद्यपि वर्तमान में कोई क्षति नहीं हुई है फिर भी घरेलू उद्योग का जांच की अवधि के भीतर कार्य निष्पादन घरेलू उद्योग की नाजुकता को दर्शाता है जो संभावना के निर्धारण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और संगत मानदंड है।
- viii. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास उपलब्ध माल भंडार के स्तर के संबंध में, प्रतिकूल अनुमान पर्याप्त सहयोग के अभाव को देखते हुए इन निर्यातकों के विरुद्ध निकाला जाना अपेक्षित है।
- ix. यदि माल भंडार का स्तर निम्न भी हो तो वह वास्तविक नहीं है क्योंकि टर्की के उत्पादक भारतीय मांग का लगभग 81 प्रतिशत निर्यात तीसरे देशों से बाजारों में अपेक्षाकृत कम कीमत पर कर रहे हैं और यह मात्रा क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त है।
- x. प्राधिकारी ने सही रूप में यह माना है कि याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत आधार की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इस प्रकार से ये याचिकाकर्ता पात्र घरेलू उद्योग बनते हैं।
- xi. प्राधिकारी ने सही रूप में घरेलू उद्योग के गोपनीयता संबंधी दावों को स्वीकार किया है। हालांकि, याचिकाकर्ता यह विश्वास करते हैं कि विदेशी उत्पादकों ने अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया है।
- xii. टर्की से असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के संबंध में, पाटन मार्जिन बहुत अधिक है। टर्की और रूस से निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन में मूल जांच और मध्यावधि समीक्षा जांच की तुलना में वृद्धि हुई है। इन उत्पादकों द्वारा पाटन वास्तव में और अधिक हुआ है।
- xiii. घरेलू उद्योग इस तथ्य को पुनः दोहराता है कि दुलाई लागत/ भाड़े की लागत पर विचार निम्नलिखित कारणों से कीमत में कटौती और क्षति के मार्जिन की जांच करते समय किया जाना चाहिए :
 - क) दुलाई की लागत संबद्ध वस्तुओं के मामले में उत्पादन की लागत का एक बहुत बड़ा वास्तविक हिस्सा होता है क्योंकि उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात में (कच्चे माल की उपलब्धता के कारण) होता है जबकि बिक्री पूरे भारत में की जानी होती है।
 - ख) संबद्ध वस्तु तुलनात्मक रूप से निम्नतर कीमत उत्पाद है। इस प्रकार से इस उत्पाद की प्रति मी. ट. दुलाई लागत का आपतन इस उत्पाद की बिक्री कीमत से तुलना किये जाने पर बहुत अधिक हो जाती है।
 - ग) भाड़े के मुद्दे को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से क्षति रहित कीमत से गलत ढंग से जोड़ा जा रहा है। यह क्षति मार्जिन के लिए उचित तुलना का एक मुद्दा है।
- xiv. मांग में क्षति की जांच की समग्र अवधि में धीरे धीरे वृद्धि हुई है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में वृद्धि का अनुमान लगाते हुए घरेलू उद्योग ने क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि की है।
- xv. आयात कीमत में जांच की वर्तमान अवधि में बहुत अधिक गिरावट आई है जबकि उत्पादन की लागत में वैश्विक रूप से वृद्धि हुई। चूंकि आयात की कीमत 2017-18 की पहली छमाही में कम हुई, आयात की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई जो 2016-17 की तुलना में आयातों में 370 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।

- xvi. उन क्षमताओं जिनका व्यापारीकरण टर्की के उत्पादकों द्वारा किया गया है, के प्रकार को देखते हुए शेष क्षमताओं जिनका व्यापार भविष्य में किया जायेगा, को देखते हुए आयात की मात्रा में आगे और वृद्धि होगी।
- xvii. संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। फिर भी, जिसे देखा जाना है वह वर्तमान शुल्क को समाप्त होने दिए जाने की स्थिति में बाजार हिस्से पर आयातों का संभावित प्रभाव है।
- xviii. प्राधिकारी कृपया केवल उन लेन देन पर विचार करें जो वास्तव में कीमत में कटौती की जांच करते समय घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही थी क्योंकि केवल वही वास्तविक कटौती की सीमा को दर्शायेगा।
- xix. घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत में 2016-17 तक कमी आई और तब बाद में वर्तमान क्षति की अवधि के पिछले छः में इसमें वृद्धि हुई जबकि बिक्री की कीमत में 2015-16 तक वृद्धि हुई और तब उसके बाद जांच की अवधि में इसमें कमी आई। आयात की कीमतों में भी जांच की अवधि के पिछले छः महीनों में कमी आई है। इस प्रकार से आयातों का जांच की अवधि के पिछले छः महीने के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी प्रभाव पड़ना आरंभ हो गया है।
- xx. जबकि 3,225 करोड़ रुपए का निवेश पहले ही किया जा चुका है, 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आगे किए जाने की योजना बनाई जा रही है। क्षति का विश्लेषण करते समय इन निवेशों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित रूप से समाप्त होने के प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए। शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में इन निवेशों पर संभावित प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में प्रतिकूल होगा।
- xxi. व्याज और ह्रास लागतों में क्षमता में वृद्धि के बावजूद कमी आई है। इस प्रकार से क्षमता में वृद्धि लाभों में गिरावट का कारण नहीं है। टर्की से आयात कीमतों में गिरावट और टर्की से इस प्रकार के पाटित आयातों में वृद्धि के कारण लाभ में कमी आई है।
- xxii. इस प्रकार से, यदि घरेलू उद्योग ने अच्छा लाभ अर्जित किया है तो वह केवल इस कारण से है कि घरेलू उद्योग द्वारा निवेश किया गया है। जहां तक नये निवेशों का प्रश्न है घरेलू उद्योग संभवतः उस स्थिति में निवेश में पर मामूली लाभ प्राप्त करेगा जब घरेलू उद्योग कीमत के वर्तमान स्तर और लागत ढांचों को बनाये रखे। हालांकि, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने के बाद की अवधि में, घरेलू उद्योग संभवतः इन कीमतों में कटौती करेगा जिसके फलस्वरूप निवेश पर लाभ में और अधिक कमी आयेगी।
- xxiii. संबद्ध देशों में क्षमताओं के विस्तार के साथ, इन देशों के बाजार हिस्से में बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाना शुरू कर दिया है यद्यपि पाटनरोधी शुल्क मौजूद है। याचिकाकर्ताओं का बाजार हिस्सा लगभग वही रहा है जबकि अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट देखी गयी है।
- xxiv. याचिका दायर करने वाले घरेलू उद्योग का औसत माल भंडार जांच की अवधि में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा है और यह लगभग दुगना हो गया है।
- xxv. यद्यपि क्षति की अवधि में मजदूरी ने सुधार दर्शाया है, रोजगार और मजदूरी संबद्ध वस्तुओं के कार्य निष्पादन पर ही निर्भर नहीं हैं। वे घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रतिकूल प्रभावों को नहीं दर्शाते हैं क्योंकि इन कारकों को कंपनी और अर्थव्यवस्था के समग्र प्रचालनों द्वारा शासित किया जाता है।
- xxvi. उत्पादन और घरेलू बिक्री की मात्रा के संबंध में घरेलू उद्योग का विकास सकारात्मक था। हालांकि, लाभ और निवेश पर आय के संबंध में विकास केवल 2015-16 तक सकारात्मक था और यह जांच की अवधि में नकारात्मक हो गया।
- xxvii. प्राधिकारी द्वारा विश्लेषण किये गये मानदंड क्षति के फिर से होने और पाटन के जारी रहने की संभावना को स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है जिसे नीचे देखा जा सकता है :
- क) संबद्ध आयातों की मात्रा जांच की अवधि में 51,668 मी. ट. (वार्षिकीकृत) से बढ़कर जांच की अवधि की बाद की अवधि में 2,20,791 मी. ट. तक हो गया है इसका आशय यह है कि इसमें 327 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।
- ख) रूस और टर्की में उत्पादकों की क्षमता का बहुत अधिक विस्तार हुआ है।

- ग) टर्की के उत्पादक भारतीय मांग का लगभग 81 प्रतिशत निर्यात तीसरे देशों के बाजार में कमतर कीमत पर कर रहे हैं। यदि इस मात्रा को भारत में उन कीमतों पर भी परिवर्तित किया जाता है जिस पर टर्की भारत में इन वस्तुओं का निर्यात वर्तमान में कर रहा है, घरेलू उद्योग को हानि होगी।
- घ) घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में जांच की अवधि की तुलना में जांच की अवधि की बाद की अवधि में (अक्टूबर 2017 से मार्च 2018) में 11 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जबकि उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की कीमत में केवल 3 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। इस प्रकार से आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासकारी और न्यूनीकरण प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है।
- ङ) संबद्ध देशों से तीसरे देशों में अधिकांश निर्यात बहुत अधिक मात्रा में पाटित और क्षति कारक दोनों कीमतों पर होता है।
- च) क्षमताओं में वैश्विक विस्तार से आगे सकारात्मक मांग के साथ घरेलू बाजार में बड़े हुए आयात होने का खतरा पैदा हो रहा है। इसके अलावा, वैश्विक रूप से मांग और आपूर्ति में विशाल अंतर होता है जो यह दर्शाता है कि ये निर्यात संभवतः भारतीय बाजार में इसकी सतत बढ़ती हुई मांग को देखते हुए परिवर्तित हो जायेंगे।
- छ) पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत में कटौती सकारात्मक और अधिक है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि यदि पाटनरोधी शुल्कों को इस अपरिपक्व चरण में वापस ले लिया जाता है तब इन आयातों के कारण कीमत में बहुत अधिक कटौती होगी जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
- ज) भारतीय बाजार अत्यधिक रूप से कीमत संवेदनशील है। इस बाजार में संबद्ध देशों से इस प्रकार से कम कीमत पर आयातों की उपलब्धता के कारण निश्चित रूप से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- झ) ऐसी स्थिति में जहां संबद्ध देशों से विश्व के शेष देशों में विचाराधीन उत्पाद का बहुत अधिक निर्यात घरेलू उद्योग की बिक्री की कीमत और भारत में संबद्ध देशों से निर्यात कीमत से कम पर होता है, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या भारत में इन निम्न कीमत पर आयातों के परिवर्तन के कारण पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने के बाद की स्थिति में घरेलू उद्योग को संभवतः क्षति होगी।
- xxviii. निर्यातक अत्यधिक रूप से निर्यात उन्मुख हैं। इसके अलावा, विश्व में मांग और आपूर्ति में अंतर है जिसके कारण आगे सकारात्मक मांग के साथ घरेलू बाजार में बड़े हुए आयातों का खतरा उत्पन्न हो रहा है।
- xxix. यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाता है तब और अधिक गहन आयातों की निश्चित रूप से संभावना है।
- xxx. पाटनरोधी शुल्क को यू एस डालर/ मी. ट. के रूप में व्यक्त किये गये पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा के रूप में ही लगाया जाना चाहिए।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

98. निम्नलिखित अनुरोध अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये हैं :

- i. यू एन कॉमट्रेड सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार, जांच की अवधि (अप्रैल 2016 – सितंबर 2017) के दौरान भारत में रूस के संघ से सोडा ऐश का निर्यात उस अवधि के दौरान भारत द्वारा आयात किये गये कुल सोडा ऐश का केवल 2.8 प्रतिशत था। रूस के संघ से इस प्रकार की निम्न आयात मात्रा को पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.8 के प्रावधानों के अनुसार नगण्य के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि रूस के संघ से ये आयात भारत में सोडा ऐश के आयातों की कुल मात्रा का 3 प्रतिशत से अधिक नहीं था। इस प्रकार के निम्न आयातों को पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.1 के प्रावधानों के अंतर्गत पाटित किये गये के रूप में माना नहीं जा सकता है।

- ii. रूस का संघ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के अंतर्गत घरेलू उद्योग को क्षति न किये जाने के बारे में जांच करने वाला निकाय के मत का समर्थन करता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत के घरेलू उद्योग का उत्पादन और आर्थिक सांकेतिकों की स्थायी सकारात्मक गतिशीलता है।
- iii. 2014 से 2017 (जांच की अवधि सहित) की अवधि के दौरान, इस उद्योग की स्थिति में सुधार आया है। रूस के उद्योग का यह विश्वास है कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.4 और 3.5 के प्रावधानों के अंतर्गत घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- iv. घरेलू उद्योग को किसी प्रकार के पाटन और फिर से आरंभ किये गये क्षति के खतरे के संबंध में साक्ष्य का अभाव है। इस प्रकार से पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क को तत्काल रद्द कर दिया जाना चाहिए।
- v. रूस के संघ से आयात किये गये वस्तुओं और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.4 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के घरेलू उद्योग को अनुमानित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि रूस के संघ से उत्पन्न होने वाले वस्तुओं के आयात की मात्रा जांच की अवधि के दौरान बहुत कम थी अर्थात् यह भारत में सोडा ऐश के आयातों की कुल मात्रा का 2.8 प्रतिशत था। इसके अलावा, क्षति के अवधि के दौरान तथा 2014-15 एवं 2015-16 में भी भारत की घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2013-14 के समान संकेतकों की तुलना में दोगुना से ज्यादा अधिक थी जो भारत के घरेलू उद्योग को क्षति न होने की पुष्टि करता है और यह वर्तमान पाटनरोधी उपाय को निरस्त किये जाने की स्थिति में फिर से आरंभ हुई क्षति के अनुमान का खंडन करता है।
- vi. उपर्युक्त पर विचार करते हुए, रूस के संघ के विरुद्ध पाटनरोधी उपाय को पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.1 के प्रावधानों के अनुसार रद्द किया जाना चाहिए।
- vii. यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग ने आंशिक और अव्यवस्थित तरीके से जांच की अवधि की बाद की अवधि के लिए रिकार्ड पर आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों को सोडा सानायी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को एक समन्वित तरीके से उपलब्ध नहीं कराया गया है। महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध न कराया जाना सभी आवश्यक तथ्यों को प्रकट करने के दायित्व के विरुद्ध है और साथ ही यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन भी है। यह निरमा लिमि. बनाम संघ सरकार, 2017 (358) ई एल टी 0146 गुजरात में माननीय उच्च न्यायालय गुजरात द्वारा दिये गये निर्णय का स्पष्ट उल्लंघन है।
- viii. जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों का उपयोग आंशिक रूप से और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में किया गया है। जांच की अवधि की बाद की अवधि के लिए केवल आयात की मात्रा को प्रकट किया गया है लेकिन जांच की अवधि की बाद की अवधि के लिए याचिकाकर्ताओं की लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और अन्य प्रमुख कार्य निष्पादन मानदंडों के संबंध में कोई सूचना नहीं है।
- ix. याचिकाकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि पाटन और क्षति के उस स्थिति में जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है जब पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया गया। प्रकटन विवरण में रूस से पाटित आयातों के कारण क्षति के फिर से होने की संभावना के संबंध में कोई वास्तविक सूचना नहीं दी गई है। प्राधिकारी को रूस के विरुद्ध इस शुल्क को समाप्त होने देना चाहिए।
- x. यह स्पष्ट नहीं है कि क्या प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की है कि जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान आयातों में अचानक उछाल क्यों हुआ था, विशेषकर जब ये शुल्क लागू थे। घरेलू उद्योग पर आयातों में इस वृद्धि के प्रभाव का कोई विश्लेषण नहीं है। इस बात का भी कोई विश्लेषण नहीं है कि जांच की अवधि की बाद की अवधि में आयातों की बढ़ी हुई मात्रा पाटित कीमतों पर थी।
- xi. रिकार्ड पर दिये गये आंकड़ों के अनुसार इन याचिकाकर्ताओं के कार्य निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। हुई कथित क्षति और संबद्ध आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- xii. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे सोडा सानायी सहित इन हितबद्ध पक्षकारों को अगोपनीय रूप में आई एच एस केमिकल रिपोर्ट उपलब्ध करायें। जुलाई 2018 से दिसंबर 2019 के अधिकांश भाग के लिए टर्की में विस्तार की जा रही क्षमताएं एक अनुमान है और न कि जांच की अवधि

- अथवा जांच की अवधि की बाद की अवधि से संबंधित मौजूदा क्षमताएं अथवा आंकड़े हैं। अतिरिक्त क्षमता के मौजूद रहने अथवा क्षमताओं के विस्तार का केवल पूर्वानुमान लगाने का यह अभिप्राय नहीं होता है कि अतिरिक्त क्षमताओं का उपयोग भारत में निर्यात किये जाने के लिए किया जायेगा।
- xiii. बाजार का स्वतंत्र विश्लेषण भी इस तथ्य को इंगित करता है कि टर्की में किसी अतिरिक्त क्षमता के प्रभाव को संभवतः तेजी से बढ़ती हुई मांग के द्वारा निष्प्रभावी बनाया जायेगा।
- xiv. टर्की का तीसरे देशों और भारत में निर्यातों के बीच कीमत में अंतर बहुत अधिक है इसके कारण पाटनरोधी शुल्क के मौजूद रहने अथवा उसके न रहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा कि याचिका के पृष्ठ संख्या 84 से देखा जा सकता है, तीसरे देशों में टर्की की निर्यात कीमतें वर्तमान में लगाये गये पाटनरोधी शुल्क को शामिल करने के बाद भी भारत में इसकी कीमत की तुलना में पहले से ही बहुत कम है।
- xv. याचिकाकर्ता कीमत ह्रास, कीमत पर न्यूनीकरण और माल भंडार के स्तर के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। प्राधिकारी ने कीमत न्यूनीकरण अथवा दबाव का निर्धारण करने के लिए संगत कारकों के वास्ते जांच की अवधि की बाद की अवधि के आंकड़ों/ प्रवृत्ति के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। हितवद्ध पक्षकारों को उस पर सार्थक टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए अवसर से वंचित किया गया है।
- xvi. यदि यह भी मान लिया जाये कि सतत रूप से पाटन हुआ है तब भी घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति अथवा सतत रूप से क्षति नहीं हुई है – इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि यदि पाटन जारी भी रहता है तब भी घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होगी।
- xvii. जी एच सी एल और रोहित सरफेक्टेंट को छोड़कर, निरमा और टाटा केमिकल्स ने भी विचाराधीन उत्पाद के लिए अपनी क्षमताओं में बहुत अधिक विस्तार आरंभ किये हैं। यदि पाटित किये गये आयातों से क्षति के फिर से होने की गंभीर संभावना हो तब विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में बहुत अधिक पूंजी निवेश करना स्व-विचार के प्रतिकूल प्रतीत होता है। यह स्पष्ट रूप से इस तथ्य का द्योतक है कि घरेलू उद्योग भारत में विकास कर रहा है और निकट भविष्य में पाटित आयातों से क्षति के फिर से होने की कोई संभावना अथवा खतरा नहीं है।
- xviii. प्रकटन विवरण के अनुच्छेद सं. 31 में मैसर्स सोडा सानायी ए. एस., टर्की (उत्पादक/ निर्यातक) के लिए सामान्य मूल्य के संबंध में, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि इसने सामान्य मूल्य को तय करने के लिए असंबंधित ग्राहकों को की गई बिक्री पर ही विचार किया है। प्राधिकारी ने यह नोट किया कि संबंधित ग्राहकों की कीमतें उन कीमतों की तुलना में कम थी जो असंबंधित ग्राहकों की थी। इसके उत्तर में सोडा सानायी यह अनुरोध करते हैं कि यदि संबंधित ग्राहकों की कीमते असंबंधित ग्राहकों की कीमतों की तुलना में कम भी हैं तो इस प्रकार के संबंधित ग्राहकों को बिक्री व्यापार के सामान्य प्रतिक्रिया में की गई है। इस कारण से प्राधिकारी को सामान्य मूल्य को परिचालित करते समय सोडा सानायी द्वारा दायर किये गये प्रश्नावली के उत्तर के प्रशिष्ट 4क और 4ख (गोपनीय) में रिपोर्ट किये गये अनुसार टर्की के घरेलू बाजार में संबंधित/ संबद्ध तथा असंबंधित/ असंबद्ध ग्राहकों दोनों को की गई बिक्री पर अवश्य विचार करना चाहिए।
- xix. उत्पादन की लागत पर और “पाटन मार्जिन गणना - सोडा सानायी – टर्की” के गोपनीय पाठ में लाभप्रद बिक्री के संबंध में प्राधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में, सोडा सानायी का यह अनुरोध है कि यह उससे सहमत है। तदनुसार, उसे अंतिम जांच परिणामों में रिकार्ड किया जाये।
- xx. परिशिष्ट 4क और 4ख में सोडा सानायी द्वारा किये गये कारखाना पश्चात् खर्च के दावों के भाग (घरेलू बिक्री का व्यौरा) के रूप में विदेशी विनिमय लाभ/ हानि और बिलिंग समायोजन के संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी ने उन दावों पर विचार नहीं किया है जिन्हें सोडा सानायी द्वारा किया गया था। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे सोडा सानायी द्वारा किये गये उक्त खर्च के दावों पर विचार करें और तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण करें।
- xxi. निर्यात कीमत का निर्धारण करते समय, प्रकटन विवरण के अनुच्छेद सं. 38 के अनुसार, प्राधिकारी ने अंतर्देशीय भाड़े, ऋण लागत, रख-रखाव संबंधी खर्च, कमीशन, बीमा और विदेशी भाड़े के प्रति ही

समायोजन किया है और विदेशी विनिमय से संबंधित लाभ/ हानि को अस्वीकार किया है। सोडा सानायी प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे इन समायोजनों को करते समय विदेशी विनिमय से लाभ/ हानि पर विचार करें और तदनुसार निर्यात कीमत का फिर निर्धारण करें।

- xxii. सोडा सानायी का यह अनुरोध है कि प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दोनों रूपों अर्थात् सोडा ऐश घना और सोडा ऐश हल्का के लिए बिक्री और लागतों को मिलाकर पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है। इस संबंध में सोडा सानायी का यह अनुरोध है कि इसने जांच की अवधि के दौरान भारत में केवल सोडा ऐश घना का निर्यात किया है जबकि इसने अपने घरेलू उद्योग बाजार में सोडा ऐश घना और सोडा ऐश हल्का दोनों की बिक्री की है। इसके अलावा, सोडा सानायी का यह अनुरोध है कि इसने विचाराधीन उत्पाद के दोनों ग्रेडों के लिए पृथक् रूप से बिक्री और लागत हेतु इन आंकड़ों को उपलब्ध कराया है। यह नोट किया जा सकता है कि विचाराधीन उत्पाद के दोनों ग्रेडों के बीच कीमत में काफी अंतर है। उसको देखते हुए प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे केवल इन कीमतों की उचित तुलना के उद्देश्य से सोडा ऐश घना की घरेलू बिक्री के आधार पर सोडा सानायी के लिए पाटन के मार्जिन का निर्धारण करें।
- xxiii. प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये गोपनीय सामान्य मूल्य गणना के अनुसार यह देखा जा सकता है कि प्राधिकारी ने 0.31 यू एस डालर प्रति टी एल तक टी एल (टर्किश लिरा) की औसत विनिमय दर पर विचार किया है। इस संबंध में सोडा सानायी यह अनुरोध करता है कि टर्किश लिरा में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक उतार चढ़ाव आया है और जांच की समग्र अवधि के लिए औसत विनिमय दर पर विचार करना सोडा सानायी द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक कीमतों की उचित तस्वीर पेश नहीं करती है। उसको देखते हुए प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे भारत में निर्यात और घरेलू बिक्री दोनों के लिए प्रत्येक लेन देन के वास्ते दैनिक विनिमय दर पर विचार करें।
- xxiv. सोडा सानायी प्रकटन विवरण के अनुच्छेद सं. 77 पर प्राधिकारी द्वारा की गई इस टिप्पणी से सहमत है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में उत्पादन, बिक्री की मात्रा, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और माल भंडार में सुधार आया है। तदनुसार, सोडा सानायी प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वे अपने अंतिम जांच परिणामों के द्वारा उसे रिकार्ड करें।
- xxv. प्राधिकारी से यह निष्कर्ष निकाले जाने का अनुरोध किया जाता है कि आकलन की गई अवधि में कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है; और अगर कोई क्षति हुई है तो वह अपने ही कारण से हुई है; सतत क्षति नहीं हुई है, रिकार्ड पर इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है जो यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाये तब पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना सिद्ध करता हो और तदनुसार प्राधिकारी कृपया इस जांच को समाप्त कर दें। यदि शुल्क को जारी रखा ही जाये तब कमतर शुल्क के नियम को उचित रूप से पालन किया जाना चाहिए।
- xxvi. गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में, व्यापार उपचार महा निदेशालय ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच आरंभ की। एतद् द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि उसी स्थिति, जांच की उसी अवधि के साथ, प्राधिकारी के निर्णय की पूर्ण रूप से उपेक्षा नहीं की जा सकती है। प्राधिकारी की पूर्व की जांच वर्तमान जांच में भरोसा किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है और पाटनरोधी शुल्क ने अपने उद्देश्य को पूरा किया है।
- xxvii. संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है। घरेलू उद्योग का औसत लाभ जांच की अवधि के दौरान बिक्री की लागत का 41 प्रतिशत था जो पाटनरोधी जांच में सामान्य मूल्य को तय करते समय महा निदेशक द्वारा अनुमति दी गई बिक्री की लागत से काफी अधिक (अर्थात् 5 प्रतिशत) था। जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता का नियोजित पूंजी पर लाभ एन एफ ए का 29 प्रतिशत है जबकि सभी पाटनरोधी मामलों में क्षति रहित कीमत की गणना करते समय महा निदेशक 22 प्रतिशत की अनुमति देते हैं। इस कारण से घरेलू उद्योग को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है और इस प्रकार से इसके जारी रहने का प्रश्न नहीं उठता है।

- xxviii. एतद् द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क प्रकृति से स्थाई नहीं है और इस मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता के अनुरूप कोई विशेष/ आपवादिक परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं। इस प्रकार से उपर्युक्त को देखते हुए, पाटनरोधी शुल्क को जारी नहीं रखा जायेगा और वर्तमान जांच को उन्हीं आधारों पर समाप्त किया जाना चाहिए।
- xxix. प्रकटन विवरण से, यह स्पष्ट है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई थी और इस प्रकार से वर्तमान जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।
- xxx. वर्तमान जांच के संबंध में दिनांक 8 फरवरी, 2019 के वर्तमान प्रकटन विवरण में प्रकट किये गये तथ्यों से चीन जन. गण., यूरोपीय यूनियन, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, उक्रेन और यू एस ए के संबंध में दिनांक 14 दिसंबर, 2018 की निर्णायक समीक्षा अंतिम जांच परिणामों में सिद्ध किये गये तथ्यों का एक तुलनात्मक विश्लेषण यह सिद्ध करता है कि पाटनरोधी शुल्क को जारी नहीं रखा जाना चाहिए और इस जांच को उस आधार पर समाप्त किया जाना चाहिए।
- xxxi. पिछले तीन वर्षों में कई अवसरों पर, महा निदेशक ने यह पाया है कि टर्की और रूस से सोडा ऐश के आयातों और चीन जन. गण., यूरोपीय यूनियन, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, उक्रेन और यू एस ए से सोडा ऐश के आयातों के कारण क्षति के फिर से होने की कोई संभावना नहीं है और कोई क्षति नहीं हुई है। सभी विभिन्न अंतिम जांच परिणामों और वर्तमान प्रकटन विवरण पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग बहुत अधिक लाभ कमा रहा है जिसे उनकी वार्षिक रिपोर्टों में और उपर्युक्त अंतिम जांच परिणामों के अनुसार दर्शाया गया है।
- xxxii. संयुक्त स्टॉक कंपनी << बक्शिर सोडा कंपनी ने अपनी क्षमता में 50 प्रतिशत तक वृद्धि >> नहीं की है जिसका दावा याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया है। संयुक्त स्टॉक कंपनी << बक्शिर सोडा कंपनी >> और ओ जे एस सी अधिक दर पर कार्य करता है और निकट भविष्य में क्षमताओं का विस्तार करने की आगे कोई योजना नहीं है। ट्रेड हाउस लिमि. << बक्शिर की सोडा कंपनी >> रूस की सी आई एस बाजार में 90 प्रतिशत सोडा ऐश की बिक्री करता है और इसके पास निर्यात का विस्तार किये जाने के लिए अतिरिक्त मात्राएं और संसाधन नहीं हैं।
- xxxiii. नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत लाभ का आधार वर्ष 1987 में बनाया गया था जब ब्याज दर और कॉरपोरेट कर जैसे सभी मानदंड अलग अलग थे, जिन्हें वर्ष 2018 में 30 वर्षों के बाद उचित के रूप में नहीं माना जा सकता है। 1987 में ब्याज की दर लगभग 18 प्रतिशत थी और कॉरपोरेट कर 40 प्रतिशत था, अब दोनों लगभग 10 प्रतिशत ब्याज दर और कॉरपोरेट कर (30 प्रतिशत) में कमी आई है। इस कारण से यह अनुरोध किया जाता है कि डी जी टी आर क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत लाभ को लागू कर घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण दे रहा है। ब्रिज स्टोन टायर मैनिफेक्चरिंग एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2011 (270) ई एल टी 696 (ट्राइ-डेल.) में, माननीय सेस्टेट ने यह टिप्पणी की है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत लाभ की प्रथा सही नहीं थी क्योंकि लाभ के इस प्रकार के उच्च दर को मानते हुए क्षति रहित कीमत की गणना करना कम कीमत पर बिक्री की एक अतिशयोक्ति पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है। यूरोपीय यूनियन की प्रथा यह सिद्ध करती है कि घरेलू उद्योग किसी जांच प्राधिकारी द्वारा अनुमति दिए गए लाभ के मार्जिन की वह राशि होनी चाहिए जो घरेलू उद्योग पाटित आयातों के न होने की स्थिति में प्रतिस्पर्धा के सामान्य स्थितियों के अंतर्गत तार्किक रूप से भरोसा कर सके। कुछ काल्पनिक विचारों के आधार पर 22 प्रतिशत लाभ मार्जिन का अपनाना पूर्ण रूप से अतार्किक है और उसे उचित के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- xxxiv. मैसर्स सेंट गोबेन इण्डिया प्रा. लिमि. इस देश में सोडा ऐश के प्रमुख प्रयोक्ताओं में एक है। टर्की और रूस से सोडा ऐश के आयातों पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क न्यायोचित नहीं है और इसे यथाशीघ्र वापस लिया जाना चाहिए।

- xxxv. याचिकाकर्ताओं ने जानबूझ कर इस याचिका में लाभप्रद भारतीय उत्पादकों को शामिल किया है। मूल जांच में, चार भारतीय उत्पादक घरेलू उद्योग थे परंतु वर्तमान निर्णायक समीक्षा में केवल दो भारतीय उत्पादक घरेलू उद्योग के रूप में हैं।
- xxxvi. इन याचिकाकर्ताओं ने इस तर्क के आधार पर घरेलू उद्योग पर जानबूझ कर टाटा केमिकल को शामिल नहीं किया है कि टाटा केमिकल का केन्या में एक संबंधित उत्पादक है। उसी तर्क को मैसर्स निरमा लिमि., जो इन याचिकाकर्ताओं में से एक है, पर लागू किया जाना चाहिए क्योंकि इसका एक संबंधित उत्पादक यू एस ए में है।
- xxxvii. घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि उसे संबद्ध देश से कथित पाटित आयातों के कारण क्षति नहीं हो रही है। इस तथ्य का उल्लेख प्रकट विवरण में भी किया गया है।
- xxxviii. प्राधिकारी का दिनांक 05.04.2018 का आदेश स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को नियोजित पूंजी पर 58 प्रतिशत (निरमा लिमि. द्वारा) और लगभग 29 प्रतिशत तक बहुत अधिक लाभ हो रहा है। इसके अलावा, रिकार्ड पर उपलब्ध सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने यह उल्लेख किया कि घरेलू उद्योग को क्षति की कोई संभावना नहीं है। प्राधिकारी की उक्त टिप्पणी अभी भी सही है क्योंकि पाटनरोधी शुल्कों को वापस लिये जाने के बाद भी घरेलू उत्पादकों को किसी क्षति की कोई संभावना नहीं है जो प्रकटन विवरण से स्पष्ट है।
- xxxix. यह एक ज्ञात तथ्य है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत घरेलू उत्पादकों द्वारा तय की गई कीमतों द्वारा शासित किया जाता है। जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में 15 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, घरेलू उत्पादकों की बिक्री कीमत में जांच की अवधि के दौरान लगभग 7 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।
- xl. घरेलू उद्योग के उत्पादन में 18 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। जबकि क्षमता के उपयोग में आंशिक रूप से कमी आई है, वह घरेलू उद्योग की क्षमताओं में वृद्धि के आधार पर ही है।
- xli. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में 16 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, कैप्टिव अंतरण में 70 प्रतिशत तक वृद्धि हुई और घरेलू बिक्री के मूल्य में 25 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।
- xlii. घरेलू उद्योग की लाभ प्रति इकाई में 193 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। कुल लाभ में 241 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। जी एफ ए के आधार पर निवेश पर आय में 41 प्रतिशत तक वृद्धि हुई और एन एफ ए आधार पर निवेश पर लाभ में 62 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर लाभ में 67 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में मांग में समग्र वृद्धि के बावजूद कमी आई।
- xliii. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सोडा ऐश आयात किये गये कच्चे माल पर बिलकुल निर्भर नहीं है अथवा बहुत कम निर्भर है। वास्तव में, जबकि घरेलू उत्पादकों को बड़े हुए पहुंच मूल्य के मामले में अवमूल्यन किये गये रुपए का लाभ मिलता है, इस तथ्य के कारण उनकी लागतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि घरेलू उत्पादक कच्चे माल का उपयोग कर रहे हैं जो स्वयं भारत में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है।
- xliv. इसे पुनः दोहराया जाता है कि सोडा ऐश उद्योग रुपए के बड़े हुए मूल्य के साथ आयात समानता कीमत निर्धारण और स्थानीय कच्चे माल का लाभ अर्जित करना जारी रखेगा। यह एक वास्तविकता भी है कि रुपया 2016 से 65 रुपए प्रति यू एस डालर से ऊपर रहा है जो स्पष्ट रूप से बिना किसी संदेह के यह सिद्ध करता है कि पाटनरोधी शुल्कों को सतत् रूप से लगाये जाने के लिए कोई कारण नहीं है।
- xlv. प्राधिकारी को वर्तमान समीक्षा में संभावना की जांच के उद्देश्य से वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों की जांच करनी चाहिए। यह निरमा लिमि. बनाम भारतीय संघ में माननीय गुजराज उच्च न्यायालय के दिनांक 23.02.2017 के निर्णय के अनुरूप है।
- xlvi. संबद्ध वस्तुओं के आयातों में आधार वर्ष में 62,103 मी. ट. से जांच अवधि (वार्षिकीकृत) में 51,668 मी. ट. तक कमी आई है। यद्यपि प्रकटन विवरण में इस बात का उल्लेख है कि जांच की अवधि की बाद की अवधि में आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है, उसे अलग रूप में नहीं देखा जा सकता है बल्कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि के आलोक में देखा जाना है। यह एक ज्ञात स्थिति है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग

में विगत में बहुत अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। इस स्टीक कारण है कि क्यों घरेलू उद्योग क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि करता रहा।

- xlvi. निष्क्रिय क्षमता अथवा अतिरिक्त क्षमता के मौजूद होने मात्र से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को पाटन अथवा क्षति की संभावना आसन्न है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि घरेलू उद्योग स्वीकार्य तौर पर विश्व के किसी अन्य स्थान पर क्षमताओं के मौजूद रहने के बावजूद अच्छा कार्य कर रहा है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग अतिरिक्त क्षमता के संबंध में इस मामले को सिद्ध करने में असफल रहा है।
- xlvi. यह याचिका माल भंडार के संबंध में कोई दावा नहीं करता है और कोई वास्तविक तथ्य उसे सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को पाटन के फिर से होने और परिणामी क्षति की कोई संभावना नहीं है।
- xlix. ऑल इण्डिया ग्लास मैनीफैक्चर्स फेडरेशन ("ए आई जी एम एफ") इस जांच में उत्तर देने वाला एक हितबद्ध पक्षकार है और इसके अनुरोधों को अंतिम जांच परिणामों में रिकार्ड किया जाना चाहिए और जांच की जानी चाहिए
- i. याचिकाकर्ता नियम 2(ख) के अंतर्गत आधार की आवश्यकता को केवल तकनीकी तौर पर संतुष्ट करते हैं। हालांकि, केवल दो उत्पादकों के क्षति संबंधी आंकड़े पूर्ण रूप से क्षति की जांच और संभावना की जांच को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और उसे गुप्त रूप से हानि पहुंचाते हैं। जी एच सी एल जैसे वृहत लाभप्रद उत्पादकों को इस याचिका में शामिल नहीं किया गया है जिसने क्षति संबंधी सूचना को विदूषित कर दिया है। यह याचिका अपने वास्तविक अभिप्राय से नियम 2(ख) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका और इस प्रकार से क्षति की जांच जर्मनी और इटली से एल सी वी पर पाटनरोधी शुल्क – रूस में डब्ल्यू टी ओ द्वारा निर्धारित आवश्यक मानदंड को पूरा नहीं करता है।
- ii. ए आई जी एम एफ प्राधिकारी से यह नियम बनाने का अनुरोध करता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े सोडा ऐश से संबंधित घरेलू उद्योग की वास्तविक आर्थिक स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथापरिकल्पित घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के लिए आधार नहीं है।
- iii. चूंकि क्षति संबंधी विभिन्न मानदंडों पर घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन बहुत मजबूत है, पाटन संबंधी आंकड़ों का कोई परिणामी प्रभाव नहीं होता है।
- liii. संबद्ध देशों से आयातों में इन वर्षों के दौरान बहुत अधिक कमी आई जबकि आयातों की पहुंच कीमत में कमी नहीं आई। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि भारत में अधिक मात्रा में निर्यात करने के लिए किसी भी साधन के रूप में पाटन को नहीं माना गया था।
- liv. यदि निर्यातकों के पास निर्यात योग्य कोई अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होती जिसे मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किये जाने की स्थिति में भारत में पूर्वानुमान के तौर पर परिवर्तित किया जायेगा, क्षति के अवधि के दौरान आयातों की स्थिति बिलकुल अलग हुई होती। इस प्रकार की प्रवृत्ति आयात की प्रवृत्ति में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती, यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लागू है और इस तर्क पर प्राधिकारी द्वारा कृपया विचार किया जाए। इसके साथ ही भारत में जांच की अवधि की बाद की अवधि में आयातों को प्रकटन विवरण में समान नहीं दिया गया है न ही उस पर विचार किया गया है।
- iv. आधार वर्ष की तुलना में क्षमता उपयोग में मामूली गिरावट को क्षति के अवधि के दौरान किये गये बहुत अधिक क्षमतावर्धनों पर विचार करते हुए देखा जाना चाहिए। वास्तव में, आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बहुत अधिक मात्रा में अर्थात् लगभग 10,687 मी. ट. तक कमी आई जबकि पहुंच कीमत स्थिर रही। घरेलू उद्योग की एन एस आर में इन वर्षों में वृद्धि हुई जबकि सी ओ पी में बहुत मात्रा में कमी आई जिसके फलस्वरूप बहुत अधिक लाभ हुआ। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को मजबूत कीमत निर्धारण अधिकार मिल रहे हैं और वास्तव में कीमत निर्धारण संबंधी व्यवहार बहुत अधिक एकाधिकारवादी है। इस प्रकार से इन आयातों से घरेलू उद्योग को कीमत अथवा मात्रा के मामले में किसी प्रतिकूल प्रथा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यह तब है जब पाटन मार्जिन के सकारात्मक होने का दावा किया जाता है। कीमत में सकारात्मक कटौती केवल कागज पर है और इस प्रकार की

सकारात्मक कीमत में कटौती घरेलू उद्योग द्वारा वसूली गई बहुत अधिक कीमत का परिणाम है। प्राधिकारी इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आयातों की पहुंच कीमत से घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा और न ही यदि शुल्कों को समाप्त होने दिया जाये तब भविष्य में इस प्रकार के आयातों से क्षति होने की कोई संभावना है।

- lvi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता आधार वर्ष में 100 आधार अंक से बढ़कर जांच की अवधि में 293 अंक हो गई और नियोजित पूंजी पर लाभ आधार वर्ष में 100 आधार अंकों से बढ़कर जांच की अवधि में 177 अंक तक पहुंच गई। इस प्रकार की वृद्धि को उल्लेखनीय विकास के रूप में देखा जाना चाहिए। वास्तव में, डी एम एफ के संबंध में हाल के एक ताजे मामले में प्राधिकारी ने यह पाया कि जब लाभप्रदता आधार वर्ष में 100 अंक से बढ़कर जांच की अवधि में नियोजित पूंजी पर 6 प्रतिशत लाभ की तुलना में कम लाभ के साथ जांच की अवधि में 15 अंकों तक पहुंच गयी तब कोई शुल्क लगाये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में तथ्यों में शुल्क को जारी रखना स्पष्ट रूप से आवश्यक नहीं है जब इस प्रकार के मानदंडों को लागू किया जाये।
- lvii. यद्यपि घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नियोजित पूंजी पर लाभ में प्रवृत्ति रेखा पर पिछले वर्षों में कमी आई, नियोजित पूंजी पर वास्तविक लाभ का प्रतिशत अभी भी बहुत अधिक बना हुआ है, जिसके कारण प्रवृत्ति में गिरावट भ्रामक और निर्थक हो गयी है। प्राधिकारी क्षति रहित कीमत के उद्देश्य से नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत लाभ की अनुमति देता है और हमारी समझ में, घरेलू उद्योग 25 से 35 प्रतिशत तक नियोजित पूंजी पर औसत लाभ अर्जित कर रहा है। नियोजित पूंजी पर लाभ का यह स्तर और लाभ मार्जिन स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभों के स्तरों को दर्शाता है। घरेलू उद्योग किसी प्रकार से आगे क्षति होने की संभावना नहीं है।
- lviii. याचिकाकर्ता ने यह कहने के लिए डब्ल्यू टी ए के आंकड़ों पर विश्वास किया है कि टर्की से निर्यात की क्षमता बहुत अधिक है परंतु ये दावे दोषपूर्ण हैं। याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि टर्की से शेष विश्व को निर्यात जांच की अवधि की बाद की अवधि में दोगुना हो गया है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उस कीमत पर हुआ है जो भारत की तुलना में कम है। हालांकि, यह नोट किए जाने की आवश्यकता है कि जब टर्की स्वयं याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार जांच की अवधि में 13 लाख मी. ट. से अधिक निर्यात कर रहा था तब भारत में उनके निर्यात में आधार वर्ष में 62,000 मी. ट. के स्तर से कम होकर लगभग 34,000 मी. ट. के स्तर तक पहुंच गया और पहुंच कीमतों में भी आधार वर्ष की तुलना में लगभग 2 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। इस प्रकार से भारत में टर्की का निर्यात जब वे 13 लाख टन का निर्यात कर रहे थे, कीमत में वृद्धि के साथ सतत रूप से कम हो रही थी। यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता का यह दावा कि टर्की के बड़े हुए निर्यात की संभावना है, में कोई सच्चाई नहीं है। टर्की के निर्यातकों को अन्य स्थान पर अपेक्षाकृत बड़े अनुकूल बाजार में मिलते हैं जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि टर्की से निर्यात में बहुत अधिक मात्रा में कमी आई और ये कीमतें बढ़ रही थीं। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने भारत में टर्की से जांच की अवधि की बाद की अवधि में किये गये निर्यात की जानकारी नहीं दी है। साथ ही घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन जिसे डी सी डब्ल्यू (याचिकाकर्ता) और अन्य कंपनियों के प्रकाशित व्यौरे से देखा जा सकता है, स्पष्ट रूप से जांच की अवधि की बाद की अवधि में भी प्रबल कार्य निष्पादन को दर्शाते हैं। घरेलू उद्योग पर जांच की अवधि की बाद की अवधि में भी आयातों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है जो निर्णायक रूप से शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में भी क्षति की किसी संभावना को इन्कार करता है। ए आई जी एम एफ प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वे संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश न करें।
- lix. डिटर्जेंट मैनिफैक्चर्स एसो. ऑफ इण्डिया (डी एम ए आई) प्रकटन विवरण के अनुच्छेद 63 में प्राधिकारी का तथ्य अन्वेषण से सहमत है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान कम हुई। इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी इस परिणाम पर पहुंचने में सही हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी क्षति की अवधि के दौरान भी वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत के बिना बढ़ी और यह जांच की अवधि के दौरान बढ़ना जारी रहा जिसका उल्लेख हमारे द्वारा हमारे पूर्व के अनुरोधों में किया गया है और उसे पुनः बाद के अनुच्छेदों में स्पष्ट किया गया है।

- ix. संबद्ध वस्तुओं के आयातों में कमी आई यद्यपि भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग और आपूर्ति में बहुत बड़ा अंतर था। घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत 100 सूचकांक इकाईयों से कम होकर क्षति की अवधि के दौरान 85 सूचकांक इकाई तक पहुंच गया। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में क्षति के अवधि के दौरान 100 सूचकांक इकाईयों से बढ़कर 107 सूचकांक इकाईयों तक पहुंच गयी। रिकार्ड में दिए गए आंकड़े यह नहीं दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग क्षति की अवधि के दौरान अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य था। वास्तव में, प्रकटन विवरण से हम यह समझते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत संबद्ध वस्तुओं के आयातों के पहुंच मूल्य तथा घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना में बहुत अधिक थी। इसके फलस्वरूप, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में आधार वर्ष 2013-14 से तुलना किये जाने पर जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान लगभग तीन गुना वृद्धि हुई। प्रकटन विवरण के पैरा 90 में घरेलू उद्योग का यह दावा सही नहीं है कि जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान बिक्री की इसकी लागत में 11 प्रतिशत तक वृद्धि हुई बल्कि बिक्री की कीमत में केवल 3 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान बिक्री की लागत के लिए 11 प्रतिशत तक बढ़ना संभव नहीं है। इसके अलावा, हम यह अनुरोध करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में जांच की अवधि की बाद की अवधि में बल्कि 10 प्रतिशत से अधिक तक वृद्धि हुई। इस संबंध में एक विस्तृत नोट गोपनीय एक्जिबिट 1 के रूप में संलग्न किया गया है। हम अनुरोध करते हैं कि किसी पाटनरोधी शुल्क के फलस्वरूप भारत में तैयार वस्तुओं अर्थात् डिटर्जेंट के आयातों में वृद्धि होगी और उसके माध्यम से घरेलू डिटर्जेंट उद्योग पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ेगा।
- ixi. घरेलू उद्योग यह भी सिद्ध नहीं कर पाया कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया होता तो उपभोक्ता संबद्ध वस्तुओं का आयात करना शुरू कर देते। संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ता डिटर्जेंट और ग्लास उद्योग में भी हैं जो व्यापक स्तर पर इन संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जांच की अवधि और जांच की अवधि की बाद के अवधि के दौरान सतत् रूप से यू एस डालर की तुलना में भारतीय रुपए का अवमूल्यन होने के साथ, यह संबद्ध वस्तुओं का आयात करने के लिए अधिकाधिक महंगा हो गया था। भारत में प्रयोक्ता उद्योग इन संबद्ध वस्तुओं के स्थानीय आपूर्ति पर विश्वास करना और संबद्ध वस्तुओं का आयात करना जारी रखेंगे जब आपूर्ति में कमी हुई हो।
- ixii. हम यह समझते हैं कि प्रकटन विवरण के अनुच्छेद 87 में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में अतिरिक्त क्षमताओं के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विश्वास किया है जो आई एच एस केमिकल जर्नल से लिये गये आंकड़ों के आधार पर है। प्रकटन विवरण के अनुच्छेद 88 और 89 में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने टर्की से शेष विश्व में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों की मात्रा और कीमतों के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विश्वास किया है जो विश्व व्यापार एटलस ("डब्ल्यू टी ए") से लिये गये आंकड़ों के आधार पर है। हम अनुरोध करते हैं कि यह दृष्टिकोण सचिव (राजस्व), भारत सरकार बनाम डायस्टफस एसो. ऑफ इण्डिया 2015 (322) ई एल टी 3 (एस सी) में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुरूप नहीं है। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय सस्टेट के फैसले की पुष्टि की थी कि ट्रेड जर्नल पर पाटनरोधी जांचों में भरोसा नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में हम यह अनुरोध करते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस मामले में आई एच एस केमिकल जर्नल और डब्ल्यू टी ए के आधार पर सूचना को नहीं मानना चाहिए।
- ixiii. हम निर्दिष्ट प्राधिकारी का ध्यान माननीय सस्टेट द्वारा ट्रक और बस टायर मामले में दिए गए फैसले की ओर आकर्षित करना चाहेंगे। इस मामले में माननीय सस्टेट ने इस आधार पर पाटनरोधी शुल्क को लगाया जाना रद्द किया था कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के क्षति संबंधी जांच परिणामों में खामियां थीं।
- ixiv. वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में क्षति के अवधि की तुलना में 115 सूचकांकों तक वृद्धि हुई। यदि दावे किये गये कीमत में कटौती का कोई वास्तविक हानिकारक प्रभाव पड़ता तब याचिकाकर्ता अपनी घरेलू उद्योग बिक्री को बनाये रखने अथवा उनमें वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुए होते। केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता कथित कीमत कटौती के बावजूद भारत में अपनी बिक्री का विस्तार करने में सक्षम हो पाये, क्षति के न होने को दर्शाता है।

- lxv. हम यह अनुरोध करते हैं कि यदि अंतिम जांच परिणामों के पहले किसी चरण में, निर्दिष्ट प्राधिकारी दिनांक 8 फरवरी, 2019 के प्रकटन विवरण में किसी अन्य टिप्पणी अथवा संरचित सामान्य मूल्य, कारखानागत निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन तय करने के लिए पद्धति, क्षति रहित कीमत, पहुंच मूल्य, कम कीमत पर बिक्री/ क्षति मार्जिन, कीमत में कटौती, कीमत पर ह्रास, कीमत में न्यूनीकरण, घरेलू उद्योग के मात्रा के प्रभावों और कीमत के प्रभावों के संबंध में कोई मानदंड, क्षति का निर्धारण, कारणात्मक संबंध की जांच, संभावना का निर्धारण सहित परंतु वहीं तक सीमित नहीं वर्तमान प्रकटन विवरण में प्रकट किए गए विचाराधीन आवश्यक तथ्यों में संशोधन करते हैं, डी एम ए आई निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसरण में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों में इस प्रकार के परिवर्तनों के बारे में सूचना दें और इसके साथ ही विचाराधीन इस प्रकार के बदले हुए आवश्यक तथ्यों पर टिप्पणी करने के लिए एक अवसर भी प्रदान करें।

प्राधिकारी द्वारा जांच

99. प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों की जांच नीचे दिए गए अनुसार की गई है :

- i. प्रकटन विवरण के संबंध में रूस के संघ से प्राप्त टिप्पणियों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि उसे प्रकटन विवरण में दिए गए समय सीमा के बाद प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया था। हालांकि, प्राधिकारी ने इसके संबंध में एक उदार दृष्टिकोण अपनाया है और रूस के संघ के टिप्पणियों की जांच की है।
- ii. इस अनुरोध के संबंध में की क्षति की अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के कारण कीमत पर कोई दबाव अथवा कीमत में ह्रास नहीं हुआ था, यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने आयातों के पहुंच मूल्य में पाटनरोधी शुल्क को जोड़े बिना इस प्रकार का विश्लेषण किया था और उसके बावजूद कीमत पर कोई दबाव अथवा कीमत में ह्रास नहीं पाया था।
- iii. इस अनुरोध के संबंध में की घरेलू उद्योग के अनुरोधों पर उचित विचार किया जाना चाहिए था, यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है और वर्तमान जांच परिणामों में उपयुक्त स्थानों पर उनका निवारण किया है।
- iv. इस अनुरोध के संबंध में की दुलाई लागत पर विचार क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-111 के अनुसार क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है और क्षति रहित कीमत एवं क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए पहुंच मूल्य के बीच तुलना इस निदेशालय की सतत् प्रथा के अनुसार व्यापार के उसी स्तर पर किया गया है।
- v. इस अनुरोध के संबंध में कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों में जांच की अवधि की बाद की अवधि में वृद्धि हुई है और पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में इसमें और वृद्धि होगी, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों का विश्लेषण पाटित आयातों के कारण क्षति को नहीं दर्शाता है। इसके अलावा, यह सिद्ध नहीं किया गया है कि यदि संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया होता तब पाटित आयातों के कारण क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।
- vi. इस अनुरोध के संबंध में कि कीमत में कटौती संबद्ध देशों के लिए सकारात्मक और अधिक है यह देखा गया है कि निर्णायक समीक्षा में, कीमत में कटौती एकमात्र निर्धारक कारक नहीं है। प्राधिकारी ने सुव्यवस्थित तरीके से मात्रा संबंधी प्रभावों और कीमत संबंधी प्रभावों के लिए घरेलू उद्योग के सभी संगत आर्थिक मानदंडों की जांच की है तथा इस मामले में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की जांच की है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि याचिकाकर्ताओं ने लाभ, नियोजित पूंजी पर लाभ, क्षमता का विस्तार, उत्पादन और बिक्री के संबंध में जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान वित्तीय रूप से अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया है। कीमत पर ह्रास और कीमत में न्यूनीकरण का अभाव है। याचिकाकर्ता यह सिद्ध कर पाने में सक्षम नहीं हुए हैं कि पाटन के कारण क्षति हुई है अथवा यह कि संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। वास्तव में, निरमा, जी एच सी एल और अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा नई क्षमताएं

बढ़ाई गई है/ बढ़ाई जा रही है जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने आगे यह मान लिया है कि क्षमता में वृद्धि की योजना इस चरण में बनाई जा रही है क्योंकि इस उत्पाद के लिए भारतीय बाजार अर्थक्षम रहा है। याचिकाकर्ताओं की नियोजित पूंजी लाभ क्षमता विस्तार में खर्च की गई गई बहुत अधिक लागत के बावजूद अत्यधिक रहा है।

- vii. इस अनुरोध के संबंध में की प्राधिकारी ने पाटन और क्षति की संभावना अथवा उसके फिर से होने के संबंध में पर्याप्त विश्लेषण नहीं किया है। यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणामों के उपयुक्त स्थानों पर इस संबंध में विस्तृत विश्लेषण किया है।
- viii. इस अनुरोध के संबंध में की प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार करना चाहिए। यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने इस प्रकार के अनुरोधों को रिकार्ड किया है और उसकी जांच वर्तमान जांच परिणामों में उपयुक्त स्थानों पर की है।
- ix. इस अनुरोध के संबंध में कि हितबद्ध पक्षकारों को जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों के साथ उपलब्ध नहीं कराया गया है, यह देखा गया है कि डी जी टी आर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, हितबद्ध पक्षकार जांच की अवधि की बाद की अवधि से संबंधित आयात आंकड़ों के लिए अनुरोध कर सकते हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की अवधि की बाद की अवधि से संबंधित आयात आंकड़ों को प्राप्त करने के संबंध में प्राधिकारी से सम्पर्क नहीं किया है।

न. निष्कर्ष और सिफारिशें

100. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने के बाद और उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों और विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी नीचे दिए गए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं :
 - i. घरेलू उद्योग के वित्तीय और आर्थिक मापदंड (मात्रा और कीमत दोनों) स्थाई हैं और उसमें गिरावट नहीं देखी जा रही है जिसके कारण पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना अपेक्षित हो।
 - ii. याचिकाकर्ताओं ने लाभ, नियोजित पूंजी पर लाभ, क्षमता का विस्तार, उत्पादन और बिक्री के मामले में जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान आर्थिक रूप से बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया है।
 - iii. कीमत पर कोई ह्रास अथवा कीमत में न्यूनीकरण नहीं हुआ था।
 - iv. याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं हो पाये हैं कि पाटन के कारण क्षति की अवधि के दौरान क्षति हुई।
 - v. याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं हो पाये हैं कि पाटन के कारण क्षति हो रही है और यह कि संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।
 - vi. पाटनरोधी शुल्क को वापस लिये जाने पर क्षति के फिर से होने की संभावना के संबंध में इन याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये कारकों को जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की कीमत संबंधी प्रवृत्तियों और कीमत प्राप्ति के द्वारा समर्थन नहीं किया गया है।
 - vii. इन याचिकाकर्ताओं के कार्य निष्पादन में सुधार के कारण, निरमा (घरेलू उद्योग के संघटकों में से एक) और अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा नई क्षमताएं या तो बढ़ाई गई हैं अथवा बढ़ाई जा रही हैं।
 - viii. इन याचिकाकर्ताओं का नियोजित पूंजी पर लाभ क्षमता विस्तार में अत्यधिक लागत के बावजूद अधिक रहा है।
101. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना आवश्यक नहीं है और एतद् द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क को आगे न बढ़ाने की सिफारिश करते हैं।

प. आगे की प्रक्रिया

102. इस अधिसूचना के विरुद्ध अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और मैसर्स जिंदल पोली फिल्म लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, डब्ल्यू. पी. (सिविल) सं. 8202/2017 में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के निर्णय के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधीकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2019

FINAL FINDINGS

Subject: Sunset review anti-dumping investigation concerning imports of ‘Soda Ash’, originating in or exported from Turkey and Russia.

A. BACKGROUND OF THE CASE

- F. No. 7/4/2018-DGAD.**—1. Whereas, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), had issued final findings vide Notification No. 14/3/2011-DGAD dated 9th February 2013, recommending imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of “Soda Ash” (hereinafter referred to as the subject goods, or product under consideration or Disodium Carbonate), originating in or exported from Turkey and Russia (hereinafter referred to as the subject countries). The definitive anti-dumping duties were accordingly imposed by the Central Government vide Notification No. 08/2013 – Customs (ADD) dated 18th April 2013.
2. And whereas, the Authority conducted a mid-term review investigation under Rule 23 and the Authority vide final findings dated the 22nd July, 2017 revoked the anti-dumping dumping duties levied on subject goods from subject countries.
3. And whereas final findings dated the 22nd July, 2017 was challenged before the Hon’ble High Court of Gujarat in Special Civil Applications No.14203,14205 and 14207 of 2017 and the High Court vide its order dated the 31st July, 2017 restrained Union of India from acting upon the MTR final findings order dated 22.7.2017.
4. And whereas the Central Government vide Notification No. 51/2017-Customs (ADD) dated 18th October, 2017 rescinded customs notification No. 08/2013–Customs (ADD) dated 18th April 2013, and stated that such recession shall remain in abeyance subject to the final order of the Hon’ble High Court of Gujarat in Special Civil Applications Nos. 14203, 14205 and 14207 of 2017.
5. And whereas, a petition was jointly filed by M/s Nirma Ltd and M/s DCW Ltd (hereinafter referred to as ‘petitioners’) in accordance with the Act and the Rules, seeking initiation of sunset review of the anti-dumping duty in force on import of “Soda Ash” for extending the duties for a further period of five years, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury of the subject goods originating in or exported from Turkey and Russia.
6. And whereas, based on examination of the petition filed by the Domestic Industry, the Authority came to the conclusion that there was no need to initiate the Sunset Review concerning imports of Soda Ash

originating in or exported from Turkey and Russia and accordingly, speaking order dated 5th April 2018 was issued intimating the decision of the Authority on Sunset Review petition.

7. And whereas against the said speaking order, the Domestic Industry filed Special Civil Applications No. 5798 of 2018 and 5808 of 2018 before the Hon'ble High Court of Gujarat at Ahmedabad. The extracts of directions dated 12.04.2018 from Hon'ble High Court are reproduced as under:—

“Pending admission and final hearing of this Petition, this Hon'ble Court be pleased to direct the Respondent No.2 to initiate Sunset Review investigation under the provisions of Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules on or before 16.04.2018 and further direct the

Respondent No.1 to issue an appropriate notification in terms of 2nd proviso to Section 9A(5) of the Act for extension/continuation of the Duty imposed by way of Customs Notification dated 18.04.2013 for a period not exceeding 1 year pending the outcome of Sunset Review before the expiry of the period of original notification, that is, on or before 17.04.2018.”

8. Pursuant to the above stated orders of the Hon'ble High Court of Gujarat, the Designated Authority initiated the present sunset review in accordance with section 9A (5) of the Custom Tariff Amendment) Act read with Rule 23 of Antidumping Rules vide Initiation Notification F.No. 7/4/2018-DGAD dated 16th April 2018.
9. The present sunset review however was subject to the outcome in the Special Civil Applications No. 5798 of 2018 and 5808 of 2018 and that in the Special Civil Applications Nos. 14203, 14205 and 14207 of 2017, all pending before the Hon'ble High Court of Gujarat.
10. The Hon'ble High Court of Gujarat vide its order dated 11.06.2018 set aside the final findings passed in the mid-term review and accordingly the anti-dumping duties imposed on import of Soda Ash from Turkey and Russia was allowed to continue for full term of five years. Accordingly, the present Sunset review does not suffer from any legal infirmity.

B. PROCEDURE

11. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - i. The Authority sent copies of the initiation notification dated 16th April, 2018 to the embassies of the subject countries in India, known exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, and the domestic producers, as per available information. The known interested parties were requested to file the questionnaire responses and make their views known in writing within the prescribed time-limit.
 - ii. Copies of letters and questionnaires sent to the exporters were also sent to embassies of the subject countries along with a list of known exporters/ producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond within the prescribed time.
 - iii. Copy of the non-confidential version of the application filed on behalf of the applicants was made available to the known exporters, domestic producers and the embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
 - iv. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the SSR to the following known producers/exporters in the subject countries and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4) of the Rules:

Soda Sanayii A.S. Turkey

TurkiyeSiseVe Cam Fabrikalari A.S.

Is Kuleleri, Kule – 334330 4, Levent Istanbul Turkiye

ETI Soda, Ciner Group, Pasalimani Cad No.4, Uskudar 34674, Istanbul Turkey
SASS SODA ASH SALES & SERVICES M. Tolmachevskiy per. 10 Office 7, 8 119017 Moscow Russia
JSC Bashkirian Chemistry 8, B PoluyaroslavsiyPereulok, Moscow, 105 120, Russia

- v. In response to the initiation of the subject investigation, following producers/ exporters from Turkey and Russia had responded by filing questionnaire response and made submissions:
- Soda Sanayii A.S., Turkey
 - M/s Trade House Ltd (Bashkirian Chemistry), Russian Federation
 - M/s Open Joint Stock Company “Berezniki Soda Works”, Russian Federation
 - M/s Public Stock Company, Crimea Soda Plant, Republic of Crimea, Russian Federation
- vi. Questionnaires were sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

Gujarat Guardian Ltd, Village- Kondh, Valia Road, Plant Sate Highway No.13, Ankleshwar, Bharuch 393001
Float Glass India Ltd., T-7, Midc, Industrial Area, Taloja, Maharashtra
Hindustan National Glass & Ind. Ltd., Rishra, West Bengal
Procter & Gamble Hygiene & HealthCare, Mandideep Plnt L&C-MFG, Plot No.182, Mandideep, Madhya Pradesh
Advatecg Industries Pvt Ltd, Dhanali, Village –Dhanali, Al-Kadi Distrcit, Mahesana, Gujarat
U.P. Glass Manufacturer,Syndicate, 14-Monapuram, Near Ganesh Nagar, Firozabad-283203, U.P.
Fena (P) Ltd, A-237, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-20
Pollachi Chamber of Commerce & Industry, RP Complex, IInd floor, 14, Balagopalapuram Street, Pollachi-642001
Power Soap Ltd, 62-B, North Boag Road, T.Nagar, Chennai – 600017
Alembic Glass Industries Ltd, Alembic Road, Baroda (Vadodara), Gujarat
Deepak Nitrite Ltd, 4/12, Chemical Complex,GIDC, Nanfessari, Baroda (Vadodara), Gujarat
Hindustan Uniliver Ltd., Party Address Dakshina Building, 8th Floor, Plot No-2 Sector-11, CBD Belapur, Navi Mumbai
Albright Morarji & Pandit Ltd, Ambernath, Dist. Thane, Maharashtra
Saint-Gobain Glass India, Head Office and Plant: A-1 SIPCOT Industrial Park, Sriperumbudur-602105, Kanchipuram District – Tamil Nadu
Asahi India Glass Ltd., 5th Floor, Tower-B, Global Business Park, Mehrauli-Gurgaon Road, Gurgaon-122002(India)

Shree Union Organics P Ltd, BS-3, Apeejay. 130, Bombay Samachar Marg, Mumbai-23
Vasundhara Rasayan Ltd, C-104, MIDC Industrial Area, Mahed, Dist. Raigad, Maharashtra
Shantinath Detergents Pvt Ltd, P-15, Kalakar Street, Kolkata-700007
Advance Home & Personal Care Ltd, Advance Surfactants India Ltd, 511/2/1, Village Rajokri, New Delhi-38
S. Kumar Detergent P. Ltd, Plot No.34, Sector-2, Industrial Area, Pithampur-454775 Distt Dhar, M.P.
Hind Silicates Pvt Ltd., 3A, Auckland Place, 5th floor, Kolkata-17
P & J Cretechem (P) Ltd, 318, Swapnalok, 92/93, SD Road, Secunderabad-500003, AP, India
J.J. Patel Industries, Gondal Road, B/H Rajkamal Petrol Pump, Vavdi, Rajkot-360004
Modern Glass Industries, Coal Siding Road, S.N. Road, Firozabad-283203
Sandeep Organics Pvt Ltd., 104, Nain Krupa, 118/122, Kazi Syeed, Street, Masjid Bunder (West), Vadgadi, Mumbai - 400003
Alembic Glass Industries Ltd., Alembic Road, Baroda(Vadodara) Gujarat
Rohit Surfactants(P) Ltd., 117/H-2/202, Pandu Nagar, Kanpur-05
BDJ Glass Industries Pvt. Ltd, 1 Kyd Street, Place Court, 1 st Floor, Suite-14-A, Kolkata-700016
Jagatjit Industries Ltd., Plot No.78, Sector-18, Institutional Area, Gurgaon-122001
Haldyn Glass Gujarat Ltd., 9, Gayatri Commercial Complex, Behind Mittal Industrial Estate No.5, Andheri Kurla Road, Marol Naka, Andheri(E), Mumbai-400059
Hipolin Limited, Madhuban”, 4 th Floor, Ellisbridge, Ahmedabad-380006
Modern Glass Industries, Coal Siding Road, S.N. Road, Firozabad-283203
Detergent Manufacturers, Association (Delhi Region), 148, New Okhla Industrial Complex-1, New Delhi-110020
Mauli Exports, Plot No.97-98, Sector – 25, Part-II, Industrial Area, HUDA, Panipat – 132 104, Haryana
M/s Chempex International, 393/III/6 Bazer, Bikanerian, Katra, Ahluwalia, Amritsar, Punjab
Tata Chemicals Ltd., Leela Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai -59
M/s Tuticorin Alkali Chemicals and Fertilizers Ltd., 534, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 18
AGI Glasspac, Glass factory Road, Moti Nagar, Post Box. 1930,Shanth Nagar, Hyderabad – 500 018
Power Soaps Ltd., A-8, 1st Main Road, Ambattur Industrial Estate Chennai – 600 058
Hindcon Chemicals (P) Ltd., 62/B, Braunfled Row, 1st floor, Calcutta – 700 027
Empire Industries Ltd., Empire House, 414, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 13

vii. In response to the above notification, following importers/users filed importer questionnaire response and made submissions.

a. Hindustan Unilever Limited

viii. Initiation notification was also sent to the following associations:

Detergent Manufacturers Association (Delhi Region)
Indian Chemical Merchants & Manufacturers Association
Bulk Drug Manufacturers Association(India)
Indian Glass Manufacturers' Association
The Dyers & Chemical Merchants Association
All India Glass Manufacturers Federation
Alkali Manufacturers Association of India
Indian Soap & Toiletries Maker's Association

- ix. The following parties also made submissions during the course of this investigation:
- i. Domestic industry – M/s Nirma Ltd. and M/s DCW Ltd.
 - ii. Ministry of Trade, Republic of Turkey
 - iii. The Trade Representation, Russian Federation
 - iv. Soda Sanayii A.S., Turkey
 - v. JSC Bashkirian Chemistry, Russian Federation
 - vi. PJSC Soda Crimea Plant, Republic of Crimea, Russian Federation
 - vii. Detergent Manufacturers Association of India
 - viii. Indian Glass Manufacturers' Association
 - ix. Hindustan Unilever Ltd.
 - x. Saint Gobain India Pvt. Ltd.
- x. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- xi. Investigation was carried out for the period starting from 1st April, 2016 to 30th September, 2017 (POI). However, injury examination was conducted for a period from 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the POI. Post-POI period considered for analysis is 1 October 2017 to 30 September 2018.
- xii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange for details of imports of subject goods for the past three years in addition to the period of investigation and post-POI. The Authority has, therefore, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis.
- xiii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry. The Non-Injurious Price (NIP) has been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure III to the AD Rules.
- xiv. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, judgment of Gujarat High Court the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 25th July, 2018. The parties, which presented their views in the oral hearing, were

requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

- xv. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xvi. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded the final findings on the basis of available facts.
- xvii. The Authority disclosed essential facts under consideration to all parties vide disclosure statement dated the 8th February, 2019. Adequate time was given to all parties to submit their comments on the disclosure statement. Submissions of all parties on the disclosure statement have been recorded and examined at appropriate places in the present findings
- xviii. ***represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules.
- xix. The average exchange rate of 1US\$ = Rs 65.67 prevailing during the POI has been adopted by the Authority

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

12. The Product under Consideration (PUC) in the original investigation as well as in the present sunset review is 'Soda Ash'. In the original investigation the PUC was defined as under:

"i. The product under consideration in the present investigation is Disodium Carbonate, also known as Soda Ash having chemical formula Na_2CO_3 . Soda Ash is produced in two forms - Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is bulk density. It can be produced through synthetic route and natural route, known as dissolution process. The present investigation includes all types and forms of Soda Ash.

ii. Soda Ash is an essential ingredient in the manufacture of detergents, soaps, cleaning compounds, sodium-based chemicals, float glass, container and specialty glasses, silicates and other industrial chemicals. It is also widely used in textiles, paper, metallurgical industries and desalination plants. Soda Ash is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act under subheading No. 2836.20. The customs classification is, however, indicative only and is not binding on the scope of the present investigation."

13. None of the importers, consumers, exporters, domestic industry and other interested parties have made any objection with regard to the scope of the product under consideration and like article. In view of the above, the scope of the product under consideration in the present review investigation remains the same as that in the original investigation.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Submissions made by the Petitioners

14. The following submissions have been made by the Petitioners with regard to standing and scope of the domestic industry:
- i. The production of the participating companies constitutes a major proportion of the total domestic production. Further, petitioner companies are eligible domestic producers. Thus, the participating companies constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.

- ii. Related exporter of Nirma has not exported goods in the POI. Further, as regards the claims raised hereinabove on the constitution of the domestic industry, the same have not been addressed to it in written submission filed earlier. Standing is not a mandatory requirement in a SSR investigation, Rule 23, dealing with reviews, specifically excludes Rule 5. Furthermore, in the present case where the Petitioners have admittedly claimed a case of no injury, there appears to be no reason to require analysis of data relating to continued injury to the domestic industry. Thus, there is no basis to seek data of the other producers. Without prejudice, the production of the petitioning companies constitutes a major proportion in the Indian production and therefore the Petitioners cannot be denied relief only because other producers have not provided relevant information.

Submissions made by other interested parties

15. The following submissions have been made by other interested parties with regard to standing of the domestic industry:
 - i. In para 32 of their Petition, the Petitioners have averred that M/S Nirma Ltd has a related producer outside India and that there were no exports made by the said related producer to India during the POI. HUL submits that the DA should examine if the related producer has in fact, not exported the PUC during the POI to India, to render Nirma an eligible domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules.
 - ii. At para 28 of the Petition, Petitioners have also stated that there are other domestic producers including M/s GHCL, Tata Chemicals Ltd., Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers Ltd of the PUC in India. However, they have also stated that GHCL has imported the PUC and that Tata Chemicals is ineligible in view of the original investigation. There appears to be no evidence supporting such claim. GHCL has historically been part of the domestic industry in previous iterations of the present investigation. HUL requests the DA to call for appropriate information from GHCL and assess whether its imports truly disqualify it from being considered domestic industry. HUL further submits that the mere existence of imports does not automatically render a domestic producer ineligible under Rule 2(b) of the AD Rules. An analysis of GHCL's Annual Report shows that their Soda Ash division is performing exceptionally, with their profits having increased by *** and capacity utilization going over ****%.
 - iii. The exclusion of Tata Chemicals is not permissible in law and is illegal. The discretion to include or exclude an importer of the subject goods or a party related to an importer or exporter of the subject goods rests with the Authority. While the domestic industry has excluded Tata Chemicals from the scope of the domestic industry on the basis that it has a related producer in Kenya, it has adopted a completely opposite approach while taking M/s Nirma, who have a related producer in USA, as part of the domestic industry. By excluding Tata Chemicals from the scope of the domestic industry, the petitioners have denied the Authority the opportunity to exercise discretion under Rule 2(b).
 - iv. For the aforementioned reasons, the petitioner failed to provide sufficient information required for the initiation of a sunset review in terms of Rule 23(1)(B) of the Rules. The Authority is requested to terminate the review on this ground alone.

Examination by the Authority

16. The Authority notes that Rule 2(b) of the AD Rules read as follows:

“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or

are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers”.

17. Rule 2(b) of the AD Rules provides that domestic producers which are related to the exporters or importers or which are themselves importers of the allegedly dumped articles may be excluded when determining the domestic industry in certain situations. The Authority is of the considered view that the use of the word 'may' in Rule 2(b) suggests that the two types of producers in question, i.e. related producers and producers importing the dumped product, are not automatically excluded from being part of the domestic industry. It has accordingly been the consistent practice that exclusion of such producers is decided on a case-to-case basis, by taking into consideration all the legal and economic aspects involved.
18. The Authority notes that in the original investigation also some of the domestic producers were involved in imports of subject goods from the subject countries or were related to the exporters/importers of subject goods from the subject countries. In the final findings of the original investigation, the Authority has clearly dealt with domestic industry and its standing. In the original investigation, the Authority had considered GHCL, Nirma Ltd and DCW Limited as “domestic industry”, in accordance the requirements of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the AD Rules. The present review petition has been jointly filed by Nirma Ltd and DCW Limited.
19. For the purpose of present review, the Authority notes that DCW Limited has neither imported the subject goods from subject countries nor is related to either importer or exporter of subject goods. Further, Nirma Ltd has not imported the subject goods during the injury period. It is alleged that Nirma Ltd has a related producer in USA that was involved in exporting the subject goods to India. The Authority observes that Nirma Ltd's related producer is based at USA and not in the subject country. Authority further notes that Nirma has neither imported subject goods from the subject country nor is related to any importer. It is thus held that Nirma Ltd and DCW Limited qualify as domestic industry in terms of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the AD Rules.

E. CONFIDENTIALITY

Submissions made by Petitioners

20. Following submissions have been made by the Petitioners:

As regards the claims of excessive confidentiality claimed in section VI, the domestic industry submits that the same contains information of the basic costing of the domestic industry and the disclosure of actual information with regard to the domestic industry can jeopardize the future business of the product. It is surprising to see that the exporter has raised this issue when the exporter has not filed the NCV of response at all.

Submissions made by other interested parties

21. Following submissions have been made by other interested parties:

- i. Petitioners have claimed confidentiality on several information and data in the Petition, which significantly impairs the ability of Detergent Manufacturers Association of India (DMAI) to defend their interests in so far as essential facts are unknown to them. In particular, the Petitioner had failed to provide a good cause for claiming confidentiality on certain essential facts, as required by Rule 7 of the AD Rules and Article 6.5 of the AD Agreement. It is submitted that information relating to export sales volume, captive consumption, inventory and employment should be reported as per actuals as this information cannot be considered confidential due to the fact that its disclosure neither gives DMAI a significant competitive advantage nor does it adversely affect the Petitioners significantly.
- ii. As per the requirements enshrined in Rule 7 of the AD Rules and Trade Notice 1/2013, the non-confidential version of the Petition is required to contain an indexation and/or a summary of the

confidential data. Further, the non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. Paragraph (vi) of the Trade Notice 1/2013 explicitly states that any submission made without a meaningful non-confidential version on confidentiality shall not be taken on record by the Designated Authority. The WTO Panel in Argentina – Ceramic Tiles while examining whether the authorities were allowed to rely on confidential information in their determination, considered that the purpose of the non-confidential summaries is to inform the interested parties so as to enable them to defend their interests. The Designated Authority cannot treat information as confidential merely at a request for confidentiality by the party providing the information. In the *Sterlite Industries (India) Pvt. Ltd. v Designated Authority*, 2003 (158) ELT 673, the Hon'ble Supreme Court held that confidentiality under Rule 7 should not be automatically assumed. The party submitting such information required to provide a non-confidential summary. In the event that a party chooses not to furnish the same, they are required to submit a statement of reasons explaining why such summarization cannot be provided. The Court also observed that not making relevant material available to the other side handicapped their ability to file an effective appeal. This view of the Court was later confirmed in the *Union of India & Anr. v Meghmani Organics Ltd. & Others* case.

- iii. The non-confidential version of the Petition fails to adhere to the confidentiality requirements under Rule 7, Trade Notice 1/2013 as well as the abovementioned judgements. The Petition contains information regarded as confidential without any good cause being shown and fails to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted. Thus, we request that the non – confidential information be made available without delay so that DMAI can fully exercise their rights of defence.
- iv. The applicants have kept information on several economic parameters in violation of Rule 7 of the Anti-dumping Rules, 1995 and Article 6.5 of the Anti-dumping Agreement. The claim of confidentiality is excessive with respect to information relating to total Indian demand; information pertaining to the production and sales at individual level; information pertaining to the production and sales of other Indian producers; and information pertaining to costing of the applicants, as non-confidential summaries have not been provided in the petition.
- v. Information pertaining to statement for raw material for 3 years in Statement B; statement of cost of production in Format CI; allocation of and apportionment of expenditure in Format CII; statement of consumption of utilities in Format D; and statement of sales realisation in Format E can all be provided in indexed form. Certain other information has also been kept confidential setting new low standards of unwarranted and illegal claims of confidentiality.
- vi. The Hon'ble Supreme Court held in *Sterlite Industries (India) Ltd. v. Designated Authority*, 2003 (158) ELT 673 (SC) that confidentiality was not to be granted automatically and should be based on thorough scrutiny. Party providing confidential information should provide a summary of the same and where summary is not possible, provide a statement of reasons as to why summarisation is not possible. The Authority is also required to evaluate the claims of confidentiality and determine whether the information in question can be kept confidential or not. In the present case, the claim for confidentiality has been granted without a thorough evaluation of the information to which the confidentiality claim pertains.
- vii. The WTO Appellate Body Report in DS 397 European Communities – Definitive Anti-dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China held that it is for the party claiming confidentiality to show good cause for claiming confidentiality and the authority needs to objectively assess the “good cause” alleged and further scrutinise the party's showing in order to determine whether the request was sufficiently substantiated. Confidentiality of information leads

to due process concerns and such due process requires adequate opportunity to interested parties for the defence of their interests. Such opportunity must be meaningful in terms of a party's ability to defend itself.

- viii. The Authority is requested to provide proper non-confidential versions of the petition with the confidential text redacted so as to enable interested parties to defend their interests fully and completely and to assist the Authority in the best manner.
- ix. The non-confidential version of the petition does not allow for a reasonable understanding of the allegations contained therein. The non-confidential version of the petition clearly violates the requirements specified in Rule 7 of the Rules and Trade Notice No. 1/2013 dated December 9, 2013.
- x. The domestic industry has claimed excessive confidentiality and filed an incomplete petition. In response to Section-VI (Costing Information) of the petition, the domestic industry has not furnished any information at all. The domestic industry has replied to all questions raised in Part VI of the petition "enclosed and as per balance sheet". Nothing has been provided in enclosed formats A to E. Petitioners have marked everything as *** and have not provided sufficient reasons as to why confidentiality was claimed and why summarisation was not possible for certain information. The petitioner is required to show justification for its claim but has failed to do so.
- xi. The costing information is to be provided for the product under consideration. In response to the few questions, the petitioner has submitted "As per balance sheet". In a multi business company like Nirma Limited and DCW Limited, the balance sheets are consolidated for various products in each segment. It is not possible to assess such consolidated financial information and link the same to the product under consideration. Accordingly, it is evident that the petitioner has not provided complete information as required under the application. Such information is crucial, and the petitioner should be requested to provide the information or at least a summary of documents and indexed data in non-confidential manner.

Examination by the Authority

22. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the AD Rules provides as follows:⁹³

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed

on confidential basis. The Authority made available the non-confidential versions of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

Submissions made by the Petitioners

24. Following miscellaneous submissions have been made by the Petitioners:

- i. With regard to the order dated 4/4/18, the High Court has overruled the same and directed initiation of SSR investigation on its own merit. The purpose of this review is to examine what has been the result of the ADD imposed. The Authority needs to examine if the duty in force needs to continue in case there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry. The Domestic Industry cannot alone provide all relevant information. The exporters in this case have not filed EQR Part-II stating that they have not been asked to. We request the DA to direct the exporters to file EQR Part-II. The exporter has conveniently ignored to give information on the economic parameters of the exporter as required under Appendix 1 of the new exporter questionnaire format. Thus, the exporter is mischievously hiding information.
- ii. The MTR final findings concluded by the Authority were challenged in the High Court of Gujarat, and the same held that the findings were inappropriate and does not consider relevant parameters. The petitioners request the Authority to appreciate the various crucial aspects of the present case as presented by the domestic industry and thereafter conclude whether or not there is likelihood of recurrence of dumping and injury. While it is accepted that in SSR the domestic industry pleading extension on the ground of likelihood of dumping and injury needs to provide evidence establishing the same, it is submitted that the responding exporters must also establish that dumping is unlikely to continue or recur in the event of cessation of ADD. Unless the exporters establish on the basis of information under SRR questionnaire Part II that dumping is unlikely to continue, intensify or recur in the event of cessation of ADD, it must be held otherwise.
- iii. The Authority will proceed as per its established practice. Further, since the present petition claims likelihood of recurrence of injury, the Authority upon finding the same, may kindly extend the duties as levied in the original findings. It is however pointed out that the exporters have not filed responses to EQ-Part-II, clearly establishing them as non-cooperative in the present case.
- iv. It is too belated to raise averments related to incompleteness of petition, considering that the DA has already held hearing. If the interested parties had any such grievance, they should have pointed out the same at the stage of initiation and in any case much before the hearing. The interested parties should not be allowed to colour the investigations by raising such claims at such belated stage of the proceedings. Alternatively, the DA may kindly allow further opportunity to the Domestic Industry to present its case by fixing public or personal hearing. Raising such arguments at this stage of the proceedings is nothing but an attempt to create a bias and cause prejudice to the rights of the domestic industry. Petitioners have provided all relevant information as per the prescribed formats.
- v. The Petitioners have every right to lodge their claims consistent with law. The Petitioners have not submitted that the DA should not call data from GHCL or Tata Chemicals or any other parties. The comparison of Tata Chemicals situation with Nirma is totally misplaced. Imports from Kenya during the present POI were ***MT constituting *** % of total imports, *** % of demand in India and *** % of Tata Chemicals' production. As opposed to this, the related party of Nirma has not exported any material to India during relevant period. Letter from Nirma giving therein information with regard to exports by its US affiliated producer to India is enclosed with these submissions. It would be seen that the interested parties are comparing the incomparable.

- vi. Threat parameters as laid down under Rules are – a) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter; b) indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets; c) taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports. In the present case – a) petitioners have submitted with evidence the present demand supply gap in subject countries. It is submitted that capacity which is more than the demand in the country of exports is a freely disposable capacity. Further, significant third country exports are being made by the subject countries. It would be seen that significant exports are being made to other countries at prices lower than that to India. These exports are also likely to be diverted to India. Further, the Petitioners have provided adequate evidence showing imminent substantial increase in capacity by the producers in subject countries; b) the fact that there is significant surplus capacity and capacity expansions planned, the surplus and additional capacity is likely to increase imports into India which has a growing market; c) Petitioners have also provided evidence showing demand-supply gap in various countries. Therefore, in a situation where there is a surplus of subject goods, any market such as India with growing market becomes a favourable market.

Submissions made by other interested parties

25. Following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:

- i. Turkey wants to express regret that the High Court of Gujarat overturned the decision of the Designated Authority which repeatedly decided not to continue the anti-dumping duty imposed on imports of the subject goods. We expect this sunset review to be terminated as soon as possible for the sake of maintenance of free and fair bilateral trade.
- ii. India is an important trading partner of Turkey and bilateral trade is largely in favour of India. In 2008, Turkish exports to India amounted to USD 500 million while India's exports to Turkey amounted to USD 2.4 billion. In the last decade, Turkey's exports to India increased only by 40%, while India's exports to Turkey almost tripled. In 2017, the bilateral trade volume between Turkey and India stood at USD 6.9 billion. Continuation of measures will have significant trade-diverting effects on our bilateral trade and will undoubtedly scale up the trade deficit against Turkey to higher levels.
- iii. According to Turkish Statistical Institute, Turkey's soda ash exports to India decreased by 9.5% from USD 14 million in 2013 to USD 12.8 million in 2017. Turkey's exports hit the lowest point with USD 2.1 million in 2016.
- iv. Applicants' claim that volume of imports from subject countries has increased significantly in the POI but data provided by them in Annexure 1.2 in support of this claim is misleading. POI for the purpose of the present investigation covers the period April 2016 until September 2017. Therefore, it is irrelevant to compare POI with previous financial years. DGCI&S import statistics clearly indicate that the volume of imports from subject countries have remained stable since 2014-15 and declined during the injury period. This data clearly reveals that volume of imports from subject countries have declined during the injury period.
- v. During the mid-term review investigation concerning imports of 'Soda Ash' originating in or exported from Turkey and Russia, the investigating authority refuted the claim of Indian producers of soda ash that there are unutilized freely disposable capacities in subject countries. Now applicants repeat this claim as a ground for their line of arguments about threat of injury.
- vi. The petitioners have not brought about any substantive evidence to prove the condition for initiation of the sunset review of anti-dumping investigation.
- vii. The facts on the record reveal that the petitioners have exaggerated the increased imports of the

subject product, and deliberately invented injury to the domestic industry.

- viii. The claims of the petitioners are contrary to the published information and appear to be concocted and fabricated to show injury to the petitioners.
- ix. The petitioner failed to evaluate some of the relevant economic factors and indices listed in Rule 11 of the Rules and para IV of Annexure II thereof. Indexed data on unit price, total costs, investments, employment and stocks are not explicitly provided and analysed in the narrative of the petition, which lacks a meaningful analysis. The authority should have examined the accuracy and adequacy of the evidence in the petition in terms of Article 5.3 of the Anti-dumping Agreement and standards laid down by WTO panels in United States – Softwood Lumber from Canada, Guatemala – Cement II and Mexico – Steel Pipes and Tubes.
- x. In recent cases, the Director General has either declined initiation or terminated the investigations where there was no injury or likelihood of injury, for example, in Nylon Filament Yarn, Dry Cell Batteries, Viscose Filament Yarn.
- xi. Applying anti-dumping measures in this case will be inconsistent with the long-term and overall interests of the Indian domestic industry and its downstream industries. There was no dumping of the subject goods from Russia and imported goods did not cause any injury to the domestic industry.
- xii. It is clear that there is no injury to the domestic industry even though there is continued allegation of dumping.
- xiii. As per the parameters of paragraph (vii) of Annexure II, there is no evidence on record to suggest that there is a likelihood of recurrence of injury if duties are discontinued.
- xiv. Over the last three years, there have been three instances where the Hon'ble Designated Authority has found that there is no injury, and no likelihood of recurrence of injury: i) MTR on China PR, the EU, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA vide final findings dated 22 July 2017; ii) MTR on Turkey and Russia vide final findings dated 22 July 2017; and iii) SSR order on Turkey and Russia vide final findings dated 5 April 2018.
- xv. The onus to establish likelihood falls squarely on the domestic industry, which they have failed to establish with any reliable evidence whatsoever.
- xvi. The petitioners have themselves admitted that substantial dumping is taking place during the period of investigation and further admitted that the domestic industry is not suffering any injury during the period of investigation.
- xvii. The present investigation is a sunset review (SSR), with two mid-term reviews that had been concluded earlier. At this stage, it is clear that there is no injury to the domestic industry, despite continued allegations of dumping. The finding at para 4 of the SSR Order dated 05/04/18 clearly shows that the domestic industry is earning high profits and return on capital employed. Even the other injury parameters from the Petition indicate an absence of injury.
- xviii. The question that arises for consideration is therefore whether there is a likelihood of recurrence of injury. There appears to be no evidence on record to suggest that there is a likelihood of recurrence of injury if duties are discontinued.
- xix. The present investigation being a sunset review, the requirements of Rule 23 of the AD Rules as well as Article 11 of the AD Agreement are relevant in terms of the analysis to be conducted by the DA in the present case. The same require the DA to determine whether or not the expiry of anti-dumping duties is likely to lead to: continuation or recurrence of dumping; and continuation and recurrence of injury.

- xx. The Petitioners have alleged significant dumping, which the DA admitted in its order dated 05/04/2018. However, HUL requests the DA to assess the responses of the individual cooperating entities and accordingly determine whether there has in fact been a continuation of dumping or whether the expiry of duties is likely to lead to a recurrence of dumping. With regards to the analysis for likelihood of continuation or recurrence of injury is concerned, it is important to note that the domestic industry is clearly not suffering present injury.
- xxi. HUL submits that the Petitioner has not provided all requisite post POI data, due to which the alleged likelihood of injury cannot be analyzed by any interested parties. The Petitioners submitted a paper book dated 24/07/18, prior to the oral hearings, which limits post-POI data to import volume, and the same is not sufficient to conclusively determine the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry. Thus, HUL requests the DA to reject the same and not proceed with the investigation unless and until all the requisite post-POI data is made available by the Petitioners.
- xxii. In the Final Findings of the Sunset Review of Anti-dumping investigation concerning imports of Viscose Filament Yarn originating in or exported from China PR, Notification No. 15/16/2016/DGAD dated 20/04/18, the DA noted that the likelihood of injury cannot be established as the post POI data was not provided. It further determined that the domestic industry could not claim to suffer continued injury due to the following reasons: first, no injury suffered with respect to the major economic parameters during the POI, and second, no verifiable post-POI evidence. HUL submits that without such data, and with no iota of evidence provided by the Petitioners for the Post POI data, the present investigation should be terminated immediately due to the absence of likelihood of injury.
- xxiii. Vide their petition at page no. 24, the Petitioners have attempted to shift the burden of proof on the exporters to prove that dumping is unlikely to occur. However, the Petitioners have neither established a likelihood of dumping and injury, nor have they provided verifiable and sufficient evidence on the same. The averments made by the Petitioners with respect to the burden of proof are unfounded and have no legal basis. Rule 23 (1B) of the AD Rules requires an applicant to provide positive information substantiating the need for a review. Once such application is submitted, the DA initiates a review investigation, at the completion of which it may recommend for the expiry of anti-dumping duty, if the DA comes to a conclusion that injury to the Domestic Industry is not likely to continue or recur on removal of anti-dumping duties. The rule does not require the other interested parties to show that if anti-dumping duty is removed, there is no likelihood of continuation or recurrence of injury. Reliance is placed on the Hon'ble Supreme Court's decision in the *Anil Rishi v Gurbaksha Singh* case, where the Court held that the onus of proof is always on the party filing an application and the onus of proof could not be shifted. HUL thus submits that the Petitioners cannot shift their burden of proof on the other interested parties. The other parties are required to analyse and comment on the information relied upon by the Petitioners.
- xxiv. In its findings issued in *Certain Rubber Chemicals* Sunset Review, as well as the *Sodium Nitrite* Sunset Review, the DA analysed the following parameters for determining likelihood: first, an increase of subject imports indicating a likelihood of increased importation; second, evidence to demonstrate spare capacities in a subject country which are likely to be diverted to India if duties are removed; third, evidence that proves the existence of depressing/suppressing effect; and fourth, evidence on inventories of the article being investigated. Additionally, in a recent investigation relating to the SSR of the Anti-Dumping Duty in force concerning imports of PTFE, the DA has also analysed other parameters such as, first, dumping margins in previous investigations; second, price attractiveness of the Indian Market; and third, the vulnerability of the

domestic industry in terms of price sensitivity of the concerned product and Indian market. HUL submits that the Petitioners in the present submission have not provided concrete or sufficient evidence for proving that discontinuation of duty would lead to recurrence or continuation of injury on account of dumped imports.

- xxv. To establish whether the product is currently being dumped, or if there is an increase in dumped imports, it is pertinent to analyse the authenticated post-POI data which the Petitioners have not provided. Without the abovementioned authenticated data, the likelihood of substantially increased importation cannot be appropriately determined. Without prejudice to the aforementioned, even if the Petitioners' data reflects a significant rate of increase in imports, there is no causal link between the alleged injury suffered by them and the subject imports. Therefore, even if there is no absence of continued dumping, there is an absence of continued injury, which implies that there is no longer a causal link between dumping and injury. In the recent SSR of Anti-dumping investigation concerning imports of 'Caustic Soda' originating in or exported from Saudi Arabia and USA, the concerned authority took into consideration the fact (amongst the others) that the domestic industry therein was able to withstand the increased imports below normal value and have performed positively despite the same, consequently deciding not to recommend continuation of anti-dumping duty.
- xxvi. At para 76 of the Petition, the Petitioners aver that foreign producers from subject countries are holding huge surpluses and significant production capacities and that certain foreign producers such as ETI Soda have installed additional capacity in Feb, 2017. HUL, having closely analysed the evidence provided by the Petitioners, brings to the notice of the DA that such averments are in fact mere conjectures and do not show that there are existing surplus capacities in Subject Countries. For example, the Petitioners while averring that ETI Soda has installed additional capacity increase of *** MT with on-going investments in Feb 2017 has relied on evidence that reads as "ETI Soda plants started to produce with a ceremony in March 2009. Our plants still produce 1 million ton of soda ash and 100 thousand tons of Sodium Bicarbonate every year. It was planned to commission the additional capacity increase of 600 thousand tons with on-going investments in February, 2017." From the same, it is clear that while foreign producers have merely planned to commission additional capacity for soda ash and sodium bicarbonate (non-PUC), there is no iota of evidence that there were existing free surplus capacities in the Subject Countries. The submissions made by the Russian Embassy at the oral hearing on 25/07/2018, averred that the increase in Russian capacities is exaggerated by the domestic industry and that any increased capacities are only for the intermediate products and not the PUC.
- xxvii. In the SSR of anti-dumping duty imposed on imports of *Plain Gypsum Plaster Boards*, originating in or exported from China PR, Indonesia, Thailand and UAE, Notification No. 7/8/2017 – DGAD, dated 19/04/18, the DA held that an evaluation of existing surplus capacities and capacity addition must be measured in order to explore the possibility of diversion to Indian market. The conclusion that such diversion is likely cannot be reached without the interested parties providing any verifiable evidence and information with regard to existing surplus capacities and consequent likelihood/possibility of increased dumped exports to Indian market. HUL reiterates that the likelihood analysis in a sunset review is ought to be made on the basis of existing surplus capacities and capacity addition for PUC, if any, export orientation and the post-POI data etc. for PUC, which the Petitioners have not provided. Hence, the averments made by the Petitioners should be rejected. Without prejudice, even assuming that there were existing surplus capacities in the Subject Countries, HUL submits that the fact in itself would not give rise to the conclusion of likelihood of continuation or recurrence of injury based on an observation made by the concerned authority in the SSR of Anti-Dumping Investigation concerning imports of 'Caustic Soda'

originating in or exported from Saudi Arabia and USA.

- xxviii. The Petitioners have at paras 79 to 81 of the Petition averred that Turkish producers are expanding their production and Russian producers' exports are gradually increasing in comparison to its local sales. HUL submits that no verifiable evidence has been provided for these claims, and as such their averments should be rejected by the DA. Furthermore, Turkish producers, during the oral hearing on 25/7/18, made submissions that their main focus markets are Egypt and the EU markets due to their geographical proximity with Turkey, and India is not their main market. It is submitted that since India is not the main market of Turkey, it may be noted by the DA that there would be no likelihood of recurrence of dumping or alleged injury to the domestic industry on account of Turkish imports due to their focus on markets other than India. Thus, HUL submits that since the Petitioners have failed to provide any sufficient and verifiable evidence and information, its claims regarding the likelihood of injury due to existing capacities or capacity addition and export orientation should be completely disregarded.
- xxix. Petitioners vide paras 1-3 have described the product scope and made submissions with respect to the same. HUL has no comments on the same. However, it reserves its right to comment in the event new or additional information is submitted with respect to the product scope.
- xxx. Petitioners vide para 4 have made submissions with respect to the like article. HUL has no comments on the same. However, it reserves its right to comment in the event new or additional information is submitted with respect to the product scope.

EXAMINATION OF THE AUTHORITY

26. Rule 23 of the AD Rules states as follows:

(1) Any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.

(1A) The Designated Authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the Designated Authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.

(1B) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or (1A), any definitive anti-dumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the Designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

(2) Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding twelve months from the date of initiation of such review.

(3) The provisions of rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall be mutatis mutandis applicable in the case of review.

27. As regards the submission that post-POI data on economic parameters of the domestic industry was not made available, it is observed that post-POI data to the extent available, was disclosed in the disclosure statement and is made available in the present final findings.
28. As regards the submission that there is no evidence regarding existence of surplus capacities or capacity additions in Turkey and Russia, it is observed that these contentions have been addressed at appropriate

places in the final findings.

29. As regards the submission on interest of user industry, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is to create a level-playing field. It is in the interest of user industry that the domestic industry is given adequate protection from dumped imports that cause injury to the domestic industry.
30. Issues regarding dumping, injury, causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury have been addressed at appropriate places in the present final findings.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

Submissions made by the Petitioners

31. The submissions made by the Petitioners with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
 - i. Subject goods are shipped from subject countries. The petitioner is not aware of any transshipment. It is widely known in the industry that there are some international traders who buy goods from several countries and then exported to India.
 - ii. Domestic industry has considered prices for Russia as per prices reported in IHS Chemical Global Soda Ash, after efforts at getting information for the Russian market. The Global Soda Ash service provides source of historical and forecasted pricing on a worldwide basis. It has recognition and reliability about the authenticity and usefulness of the data. Since the journal mentions high and low prices, domestic industry has adopted average price.
 - iii. Domestic industry was not able to get any information/evidence of price of subject goods in the domestic market of Turkey. However, given proximity of Turkey to Romania in terms of geographical location, availability of prices in Romania and Turkey are quite comparable. It is submitted that the prices in Romania can be considered appropriate basis for the price of the product under consideration in Turkey. The domestic industry has determined normal value in Turkey on the basis of prices of the product under consideration in Romania for the period April 2016 to April 2017. Petitioners could get actual prices prevailing in Turkey for the period of May 2017 to September 2017 and the same has been considered accordingly.
 - iv. Normal value determined being at ex-factory level, the export prices are required to be adjusted for the following expenses, which the exporter from subject countries have incurred for exporting the material to India – ocean freight, marine insurance, commission, inland transportation, port expenses. Wherever the Petitioners could not get relevant evidence, the Petitioners have adopted the most conservative estimates and submit that the dumping margin are significantly beyond de-minimus even if all price adjustments are ignored.
 - v. Petitioners submit that the comparison made must be considered fair comparison. The prices represent the same level of trade. Further, both the normal value and export price have been determined at ex-factory level. Both the normal value and export price pertain to the same period. Thus, the comparison made by the Petitioners constitutes a fair comparison. It may be seen from the above that the dumping margins are not only above de-minimus but also substantial. Thus, dumping has continued despite imposition of anti-dumping duties.
 - vi. The Authority may kindly do the needful regarding the assessment of responses of individual entities in order to determine if there has been continuation of dumping or if expiry will lead to recurrence. It will be seen that the exporters are dumping the goods. The same was determined even in the MTR investigation. Further, in a situation of absence of current dumping in the Indian market, the Authority is required to determine the likelihood of recurrence of dumping. Even if dumping is currently negative, the same ipso facto does not establish absence of likelihood.

- vii. The domestic industry requests the Authority to consider the Russian respondents as non-cooperative parties and reject the questionnaire responses filed by them as it is an admitted fact that the questionnaire responses were filed by them just before the public hearing was due to take place, without even providing a non-confidential version of the same. Notwithstanding above, the Petitioners submit that since they attended this hearing without access to the response filed by the Russian exporters, the hearing was not complete. The Petitioners request the Designated Authority to kindly make available the NCV of the questionnaire response and thereafter fix a hearing. Oral hearing can be effective only when pleadings are complete. However, in the instant case, the Petitioners were forced to the hearing without access to the essential information. As such, the present hearing was an ineffective hearing and the domestic industry is severely prejudiced by not getting access to relevant documents and defending its interests. The opportunity to file written submissions is not the same as oral hearing.

Submissions made by the other interested parties

32. The submissions made by other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
- i. Soda Sanayii A.S. has been cooperating with the Hon'ble Authority over the course of the entire investigation and has placed its complete questionnaire response on record for the exports made to India in the POI in respect of the subject goods originating in or exported from Turkey. If the Authority recommends anti-dumping duty, an individual dumping margin may be accorded to the producer herein due to its complete cooperation in the present investigation.
 - ii. Soda Sanayii A.S. has filed the questionnaire response and requests the Authority to calculate normal value, export price and dumping margin based on the data filed by it.
 - iii. Petitioners have made submissions with respect to the computation of normal value, export price and dumping margin. As a user, HUL does not have any comments on determination of these. However, HUL humbly requests the DA to calculate the same based on the information filed by the cooperating producers/exporters in the present investigation.
 - iv. The Petitioners rely on certain information and data in their Petition in order to determine dumping and injury, but fail, on several instances, to provide the sources of such data. For example, the ex-factory export price has been calculated on the basis of unsubstantiated allowances such as ocean freight, marine insurance, port expenses, commission, bank charges and inland freight. Without any source for such data, DMAI cannot determine the credibility of the same, and as such the Designated Authority is requested to direct the Petitioners to disclose the source of all the above-mentioned allowances, failing which, the data with unknown sources should be disregarded.
 - v. In the Secretary (Revenue), GOI v Dyestuffs Manufacturers Association of India, 2015 (322) ELT 3 (SC), the Supreme Court confirmed the CESTAT's ruling that trade journals cannot be relied upon as facts available for the purposes of determining normal value on best judgement assessment principle. In the present review, the Petitioners have determined normal value for Russia based on the prices mentioned in the trade journal IHS Chemical Global Soda Ash. Based on the Hon'ble Court's opinion, the normal value determined in the Petition for Russia should be disregarded.
 - vi. The Petitioners have contended that information regarding the price prevailing in Turkey during the POI was unavailable and have instead relied on the prices prevailing in Romania in order to contend that the same were comparable to prices in Turkey and calculated the normal value for Turkey. This approach is strongly objected to as neither have the Petitioners explained how they obtained the data relating to Romania, nor established why the prices in Romania could be treated

comparable to prices in Turkey. This approach is incorrect in terms of Section 9A(1)(c) of the Act. The Designated Authority is thus requested to determine the normal values for both the countries only on the basis of the data filed by cooperating producers/exporters.

- vii. Annex 3.2 of the Petition mentions that adjustments have been made in order to compare the normal value and the export price at the same level of trade in the following heads: ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight and bank charges. However, the source of these adjustments and how they were computed have not been disclosed by the Petitioners, despite this information being non-confidential in nature. The determination of the ex-factory export price in the Petition is unsupported by evidence and violates Rule 5(2) & 5(3) of the AD Rules. It is submitted that the dumping margins determined in the Petition for the subject countries are incorrect and should be rejected. Dumping margins for cooperating producers/exporters should be based on their respective data.

H. EXAMINATION BY AUTHORITY

33. The Authority notes that exporter's questionnaire responses have been submitted by producers/exporters from Turkey and Russia. Observations regarding the same are given in the subsequent paragraphs.

Normal value for M/s. Soda Sanayii A.S. , Turkey (Producer/Exporter)

34. From the response filed by M/s. Soda Sanayii A.S., the Authority notes that the company has made direct sales of the product under consideration in the domestic market during the POI. It was also noted that domestic sales were made to related as well as unrelated customers in Turkey. However, the prices to related customers were lower than the prices to unrelated customers. Thus, domestic sales to unrelated customers only have been considered for arriving at the normal value for this company.
35. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production and SGA expenses concerning the product under consideration. Where profit making transactions are more than 80%, the Authority considers all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in case, profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value.
36. In this case, based on the ordinary course of trade test, all domestic sales to unrelated customers have been taken for determination of normal value, since the profitable sales were more than 80%. M/s. Soda Sanayii A.S. has claimed adjustments for inland transportation, warehousing expenses, handling and other expenses, credit cost, rebate/discount and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, normal value at ex-factory level for the participating producer has been determined as USD *** per MT for M/s. Soda Sanayii A.S.

Normal value of All other Producers/Exporters from Turkey

37. In respect of all other producers/exporters from Turkey who are treated to be non-cooperative, the Authority has determined normal value as per facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. The normal value so determined is USD *** per MT.

Normal Value for M/s. Trade House Ltd «Bashkirian Chemistry», Russia (Producer/Exporter) along with its related company M/s. Open Joint Stock Company «Berezniki Soda Works» (Producer), Russia

38. From the response filed by producers, the Authority notes that M/s. Trade House Ltd «Bashkirian Chemistry» and M/s. Open Joint Stock Company «Berezniki Soda Works» are related producers. The responses filed by M/s. Trade House Ltd «Bashkirian Chemistry» and M/s. Open Joint Stock Company «Berezniki Soda Works» are grossly deficient particularly with respect to the cost of production. Accordingly, the Authority rejects the cost of production as claimed by M/s. Trade House Ltd.

«Bashkirian Chemistry» and M/s. Open Joint Stock Company “Berezniki Soda Works” and instead determines the normal value on the basis of facts available and the same is shown in the dumping margin table below.

Normal Value for M/s Public Stock Company Crimea Soda Plant, Russia (Producer/Exporter)

39. From the response filed by M/s Public Stock Company Crimea Soda Plant, it is noted that M/s Public Stock Company Crimea Soda Plant is a producer as well as exporter of the subject goods. The response filed by M/s Public Stock Company Crimea Soda Plant is grossly deficient particularly with respect to the cost of production. Accordingly, the Authority rejects the cost of production as claimed M/s Public Stock Company Crimea Soda Plant and instead determines the normal value on the basis of facts available and the same is shown in dumping margin table below.

Normal value of other Producers/Exporters from Russia

40. In respect of all other producers/exporters from Russia who are treated to be non-cooperative, the Authority has determined normal value and export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. The normal value so determined is USD *** per MT.

I. EXPORT PRICE

Export price for M/s. Soda Sanayii A.S., Turkey (Producer/Exporter)

41. From the response filed by M/s. Soda Sanayii A.S., the Authority notes that M/s. Soda Sanayii A.S. is a producer as well as exporter of the subject goods. During the POI, M/s. Soda Sanayii A.S. has exported subject goods to India directly. Adjustments towards inland freight, credit cost, handling expenses, commission, insurance, overseas freight and foreign exchange loss have been claimed by the producer/exporter. Adjustments towards inland freight, credit cost, handling expenses, commission, insurance and overseas freight have been allowed by the Authority. Accordingly, the net export price determined for exports to India has been determined as USD *** per MT.

Export price for M/s. Trade House Ltd «Bashkirian Chemistry», Russia (Producer/Exporter) alongwith its related company M/s. Open Joint Stock Company “Berezniki Soda Works”, Russia (Producer)

42. From the response filed by the producers/exporters, the Authority notes that M/s. Trade House Ltd «Bashkirian Chemistry» and M/s. Open Joint Stock Company “Berezniki Soda Works” are related producers and have exported the subject goods to India during the POI through M/s. Trade House Ltd «Bashkirian Chemistry». Adjustments towards inland freight and overseas freight have been claimed by the producer/exporter and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, the net export price determined for exports to India is USD *** per MT.

Export price for M/s Public Stock Company Crimea Soda Plant, Russia (Producer/Exporter)

43. From the response filed by M/s Public Stock Company Crimea Soda Plant, it is noted that this company is a producer as well as exporter of the subject goods. It is further noted that M/s Public Stock Company Crimea Soda Plant has exported the subject goods to the Indian customers through a related company which has not filed the exporter’s questionnaire response. The exporter’s questionnaire response filed by M/s Public Stock Company Crimea Soda Plant is grossly deficient particularly with respect to cost of production. In the absence of information from related trader as well as the grossly deficient response filed by M/s Public Stock Company Crimea Soda Plant, the Authority is not in a position to determine the export price for the above-mentioned producer. Accordingly, the Authority rejects the response filed by M/s Public Stock Company Crimea Soda Plant and instead determines the export price on the basis of facts available.

Export Price for non-cooperating producers/exporters from Turkey

44. The Authority has determined the export price for non-cooperating producers/exporters from Turkey

based on facts available. Accordingly, net export price at ex-factory level for exports from the Turkey is as shown in the dumping margin table below.

Export Price for non-cooperating producers/exporters from Russia

45. The Authority has determined the export price for non-cooperating producers/exporters from Russia on the basis of facts available. Accordingly, net export price at ex-factory level for exports from the Russia is as shown in the dumping margin table below.

J. Determination of dumping margin for producers and exporters in the subject countries

46. Considering the normal value and export price as above, the dumping margins for all producers/exporters of the subject goods from the subject countries is determined as below:

S. No.	Country	Producer	Exporter	CNV/NV (USD/MT)	Net Export Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range)
6.	Turkey	Soda Sanayii A.S.	Soda Sanayii A.S.	***	***	***	***	30-35%
7.	Turkey	Any other	Any other	***	***	***	***	45-50%
8.	Russia	Trade House Ltd «Bashkirian Chemistry»	Trade House Ltd «Bashkirian Chemistry»	***	***	***	***	55-60%
9.	Russia	Open Joint Stock Company "Berezniki Soda Works"	Trade House Ltd «Bashkirian Chemistry»	***	***	***	***	55-60%
10.	Russia	Any other	Any other	***	***	***	***	75-80%

K. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

Submissions made by the Petitioners

47. Following are the submissions made by the Petitioners in this regard:

- Para (iv) of Annexure II to the AD rules provides that the effect of the dumped imports shall be assessed in relation to the domestic production of the like article when available data permits the separate identification of that production on the basis of such criteria as the production process, producers' sales and profits. If such separate identification of that production is not possible, the effects of the dumped imports are required to be assessed by the examination of the production to the narrowest group or range of products, which includes the like product, for which necessary information can be provided. Participating companies are multiproduct companies and have provided relevant information in respect of like article to the extent feasible and separately available. However, in those situations where the information is not separately available in respect of the like article, because separate identification of that information is not reasonably available, information has been provided in respect of the narrowest group or range of products, which includes the like article and for which the necessary information is available and can be provided in consonance with the provisions of Annexure II.
- The Petitioners have defined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales and imports from all sources. The demand/apparent consumption of the

Subject Goods increased over the proposed injury period. The volume of dumped imports from the subject countries declined till 2015-16. However, the same increased significantly in the proposed POI in absolute terms. Imports in the period of investigation were higher than base year and were at highest level in the injury period. Imports related to domestic production and consumption also declined till 2015-16 and increased thereafter in the proposed POI.

- iii. The import price has declined significantly in the proposed POI. The landed price of imports from subject countries is below the selling price of the petitioning domestic industry, which indicates that the imports were undercutting the domestic prices and would further undercut the domestic selling prices in absence of anti-dumping duty. Transportation cost forms a very substantial portion of the cost of production in case of subject goods. Indian producers of Soda Ash are located in Gujarat, but the sales have to be made all over India. Subject goods are also a comparatively lower price product. Thus, the incidence of transportation cost per MT of the product works out very substantial when compared with the selling price of the product. In view of the same, it is submitted that the selling price of the domestic industry should be compared with the landed price of imports only after adding the transportation costs. Further, whereas the domestic freight is increasing, the ocean freight prices are crashing threatening further injury to the domestic industry. The AD Rules requires the DA to determine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India. The rule, however, does not provide how the DA should determine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India. While the present practice of the DA is to determine landed price of imports at the port level and net sales realization of the domestic industry at ex-factory level, petitioners submit that there is no one methodology for determining price undercutting. At this stage, the Petitioners have added the post ex-factory expenses paid by them on the domestic product. It is clarified, however, that these do not represent full value of freight. The AD rules make a specific provision with regard to the principle of fair comparison and clearly envisage a situation where comparison may have to be done at level other than ex-factory level. The DA is requested to take into account the paper circulated by the Govt. of India at the WTO wherein the Govt. of India has stated that the term “price of dumped import” shall be interpreted as meaning import prices at any level such as cost, insurance, and freight, or ex-customs area or resale price to the importer or delivered price to the customer, provided that the comparisons with the price of the like product under subpara 1.1, or with the target price under subpara 1.2 for the purpose of arriving at the injury margin are made only at a comparable level. If this is the position of the Govt. of India, it would be unfortunate if the Domestic Industry is made to suffer and it is expected that the DA would not accept what India is contending before 146 WTO member countries.
- iv. Petitioners further submit that there can be three types of freights – a) freight from the factory to the depot as booked in the expenses and borne by the industry; b) freight paid and recovered (wherein the seller makes arrangement for freight and pays for the same but eventually the same is reimbursed by the seller) and; c) freight paid by the buyer (wherein an arrangement for transportation is made but the charges for the same are paid by the buyer only). Petitioners submit that there can be no reason for excluding freight expense from the factory to the depot as these are nothing but part of expenses, verifiable from the books of accounts and are merely expenses incurred for transportation of goods to an extended factory gate. The Domestic Industry refers to the decision of the EC in relation to Potassium Permanganate originating in India and Ukraine, wherein the exporter sought allowance of transportation cost from the factory to depot and the same was rejected, holding that the plant and the depot are part of the same economic and legal entity. From a simple reading of the case, it is evident that if the

goods are transferred from the factory to the depot then the goods are to be considered as a part of the inventory. The domestic industry has no issues with the DA wishing to consult the excise authority as to what they consider as ex-factory prices. The domestic industry requests that the depot prices be considered as ex-factory prices for the purpose of calculation of the NIP and selling price.

- v. Petitioners submit that price undercutting should be determined only considering those import transactions whose landed price of imports is below selling price of the domestic industry. Petitioners' concern is against injurious imports, and not against non-injurious imports. From the WTO report in the matter of EC – ADD on Malleable Case Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil, it can be seen that – a) there is no requirement under Article 3.2 to establish one single margin of undercutting on the basis of an examination of every transaction involving the product concerned and the like product; b) a requirement that an investigating authority must base its price undercutting analysis on a methodology that offset undercutting prices with “overcutting” prices would have the result of requiring the investigating authority to conclude that no price undercutting existed when, in fact, there might be a considerable number of sales at undercutting prices, having an adverse effect on the Domestic Industry; c) the extent to which price undercutting would have an impact on a domestic industry would be a function of two variables, the number of sales at undercutting prices and the extent of the undercutting by such sales. The number of sales at undercutting prices is particularly important, because it would provide an indicator of the likely number of sales lost by the domestic industry. The margin of undercutting of such sales is relevant to the extent that in non-price sensitive products a small margin of undercutting may not play a decisive role in purchasers' decision making; and d) the calculation of an average margin of undercutting for all sales, whether or not at undercutting prices, might not be the most effective manner to assess the impact of price undercutting on a domestic industry, as it limits the ability of the investigating authority independently to examine these two variables.
- vi. Comparison of cost of production and selling price of the petitioning domestic industry shows that cost of production declined till 2016-17 and then increased thereafter in the last six months of the proposed investigation period; whereas selling price increased till 2015-16 and then declined thereafter in the proposed POI. Thus, imports have started having suppressing effect on the prices of the domestic industry during the last six months of the proposed POI. Should the present ADD cease, the dumping would cause further suppressing/depressing effect on the prices of the Domestic Industry in the market. The import price has declined significantly in the proposed POI. While the cost of production increased globally, since the Turkish producers are on natural soda ash, the import price declined by about 25% (Rs. *** per MT) between 2015-16 and H1, 2017-18. As the import price declined in H1, 2017-18, the import volumes increased significantly, showing 370% increase in imports as compared to 2016-17. The volume of dumped imports from the subject countries has increased, both in absolute terms, as well as in relation to production and consumption in India in the proposed POI. Further, imports are undercutting the prices of the Domestic Industry and have started having suppressing/depressing effect on the prices of the domestic industry in the market.
- vii. From the performance of the petitioning domestic industry in respect of these parameters in Proforma IV-A (Part II), it can be seen that, (a) petitioning domestic industry has increased their capacity over the proposed injury period in view of the increasing demand in the country; (b) Production of domestic industry has increased over the injury period, but is lower than what it could have been in the absence of dumping. Under such circumstances, cessation of ADD shall lead to recurrence of injury to domestic industry; (c) the capacity utilization of the petitioning

domestic industry improved in 2014-15 but declined thereafter till the investigation period; (d) the domestic sales volume of the petitioning domestic industry has increased over the proposed injury period. Whereas capacity increased by **%, production increased only by **% and sales by **%. Considering that the imports are undercutting the domestic selling price, it is likely that the demand for the imported goods would increase substantially, in the event of cessation of ADD; (e) ADD got levied in 2012. Industry was incurring losses in 2011-12 and was earning low level of profits and ROI until 2013-14. After imposition of ADD, the situation of the domestic industry gradually improved and consequently constituents of domestic industry and other producers felt that the market is viable to invest in capacity expansions. Significant capacities have been added in India by existing as well as new producers. One of the petitioners, Nirma, has added capacity by ** MT during the proposed investigation period, whereas GHCL has added capacity by ** MT. There is enhanced need for protecting the domestic industry now.

- viii. Profitability of the Domestic Industry has improved up to 2015-16. The profitability declined in 2016-17 and thereafter further in 2017-18. Cash flow and return on capital employed also increased till 2015-16 and thereafter declined in the proposed POI. Price parameters showed improvement as a result of imposition of ADD. However, cessation of ADD would lead to decline in profits. Domestic Industry was making low level of profits and ROI until 2013-14. The profits and ROI have increased over the period of injury but declined in the proposed POI as compared to the previous year. Cessation of ADD will lead to significant increase in dumped imports leading to further decline in these parameters of the domestic industry, with profits falling below reasonable levels. While considering the question of extension of present ADD, the DA may kindly consider the possible adverse impact on establishment of these capacities in the country. These investments require a minimum reasonable return of Rs. ** per MT in order to be reasonably viable. As against this necessary return, the average return earned by the Domestic Industry over the injury period was much lower. Should they continue to earn these profits, the fresh investments will be recovered over a period that exceeds even the life of the assets. Possible cessation of ADD at this stage shall imply serious injury to these investments. MS Gharhi is coming up with a new green plant of a production capacity of ** MT at an investment of Rs. ** crores. Viability of these fresh investments are clearly at stake.
- ix. Interest cost and depreciation cost have declined despite increases in capacity, thus increase in capacity is not the reason for decline in profits. Profits have declined because of decline in import price from Turkey and increase in such dumped imports from Turkey. Thus, despite imposition of ADD, imports have started having suppressing effect on the Domestic Industry. This indicates the likely situation of cessation of ADD, where profitability will decline significantly for the domestic industry. It is pertinent to refer to the case of Forum of Acrylic Fibre Manufacturers v DA, wherein the Hon'ble Tribunal appropriately dealt with the relevance and importance of profits. The Petitioners have determined separate profitability of the new plant, relevant information of which has been provided on confidential basis. It would be seen that profitability of the new plant is considerably lower as compared to that of an old plant. Thus, if the Domestic Industry has earned good profits, the same is only because of the fact that the investments made by the domestic industry are largely depreciated. As far as new investments are concerned, the domestic industry is likely to achieve a meagre ROI if the domestic industry maintains the current level of price and cost structures. However, post cessation of ADD, the domestic industry is likely to reduce these prices, leading to further decline in ROI.
- x. Market share of the petitioning domestic industry increased till 2015-16 and declined in the proposed POI even when the Petitioners have enhanced their capacities. Market share of

- imports, on the other hand, declined till 2015-16 and has increased in the proposed POI. In the event of cessation of ADD, the domestic industry is likely to lose its market share. Further, with expansion of capacities in the subject countries, the market share of these countries has started showing increasing trend, in the presence of ADD. The market share of the applicant producers remained about the same while that of the other Indian producers show a decline.
- xi. Petitioners submit that parameters of employment, wages and productivity are dependent on other parameters and do not reflect the impact of dumping on the domestic industry. Wages have shown improvement in the injury period. However, these are solely dependent on the subject goods performance, as they are governed by several legislative requirements in the country, and other business compulsions.
 - xii. The average inventory of the petitioning domestic industry has increased very significantly in the proposed POI.
 - xiii. The growth of the petitioning domestic industry in terms of production, domestic sales volume was positive, however, growth in terms of profits and ROCE was positive and became negative in the proposed POI. The petitioning domestic industry is recovering from the effects of dumping, solely due to the anti-dumping duties in force.
 - xiv. While the domestic industry has made investments over the present injury period under the protective umbrella of ADD, it is likely that their ability to raise capital investment is adversely impacted by the cessation of ADD.
 - xv. Despite ADD, the subject goods are being dumped by exporters from the subject countries. If the duties cease, the dumping would intensify and cause injury to the domestic industry.
 - xvi. An analysis of the import prices from dumping countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market would show that the landed value of concerned products from Subject Countries and other countries attracting is below the selling price of the domestic industry, causing severe price undercutting in the Indian Market. It is thus evident that the only factor responsible for the domestic industry prices are the import prices of the product and the cost of production of the domestic industry, the import prices are much lower than the domestic prices and costs and therefore prevent the domestic industry from increasing their prices.
 - xvii. Margin of dumping from both the subject countries is significant and positive. The domestic industry understands that Turkish producers are blessed with the advantage of having immense natural resources and so their cost of production is less compared to the synthetic materials used in India. However, even then the Turkish exporters are resorting to dumping practices as they are exporting to India at prices much below their normal value which is leading to a surge in imports. Having lower cost of production does in no way entitle the subject exporters to indulge in unfair trade practices. The published prices in Turkey are higher than the export price to India. The producers in Turkey are selling at higher prices in their domestic market but exporting at lower prices in order to gain market share in the growing Indian market to utilize their capacity expansions.
 - xviii. Data and analysis show that performance of the domestic industry improved till 2015-16 and declined thereafter in the proposed POI. While absolute performance was not at bad levels, the situation of the domestic industry is clearly fragile, and vulnerable to intensified injury due to the cessation of ADD.

- xix. The increase in sales, production and market share only implies absence of injury, but not the absence of likelihood of injury. The domestic industry could have produced and sold more in the absence of continued dumping. Hence, it cannot be said that the capacity utilization declined due to addition of capacities but because of the dumped imports from the subject countries gaining market and making the installed capacities redundant.
- xx. Petitioners have not claimed continued injury. As regards the contentions raised on the prices of the domestic industry not being reduced despite the presence of the dumped imports in the country, the domestic industry submits that the prices are much below the selling prices of the domestic industry. Allegedly significant ROI is only because of the fact that the investments made by the Domestic Industry are highly depreciated. Thus, it is not a case of high ROI, but that of inappropriateness of methodology. As regards 5% profit considered for CNV, it needs to be considered that the same is not a law, but surrogate for actual profit and is applied under principles of best available information when actual profits are not available. Such being the case, there is no basis of the argument that the 5% profit for determination of normal value is an appropriate profit. The Petitioners refer to the case of WTO in the matter of bed linen, where the Appellate Body reversed the Panel's conclusion that an interpretation of Article 2.2.2(ii) under which sales not in the ordinary course of trade are excluded from the determination of the profit amount to be used in the calculation of a constructed normal value is permissible. The Appellate Body emphasized that instead, it refers to actual amounts incurred and realized by other exporters and producers, and concluded that in light of this wording, in the calculation of weighted average all of the actual amounts have to be included, regardless of whether the underlying sales were made in the ordinary course of trade or not. Thus, the profit for the PUC is required to be considered on actual basis and not as some surrogate percentage on cost of production.
- xxi. It is surprising that the interested parties are contending that the industry has misused the ADD. In fact, the argument has been advanced only to emotionally bias the DA. If profitability of the consumer industry is examined it would be seen that in majority consumption segments, it has shown significant improvement. Further, if the domestic industry is considered at present value, then the profitability of the industry is way below the reasonable profits benchmark. It is not a case of high profits or ROI. It is a case of inappropriate methodology to determine ROI. If the prices in Indian markets are compared with the prices in the international market, it would be seen that the prices prevailing in the international market are in fact higher than the prices prevailing in the Indian market. The allegation with regard to raising of consumers' cost are also without any substance. If globally prices of Soda Ash have gone up and if consumers globally are paying higher prices, it is without any legal and factual basis to contend that the prices are selectively increasing in India. Above all, the domestic industry is looking only for fair protection. Significant capacity expansions have been undertaken through the profits earned by the domestic industry. The domestic industry is not against fair price imports. The exporters are free to export at normal price at which they have been selling in their home market. If the domestic industry thereafter suffers, ADD cannot support the Domestic industry. However, if imports are occurring below such prices, the consumers cannot plead that they want the material at dumped prices.
- xxii. There is no injury to the domestic industry despite dumping as the ADD is in place. The domestic industry will suffer injury if it has to match the prices of imports after cessation of anti-dumping duty.
- xxiii. Data and analysis show that performance of the domestic industry improved till 2015-16 and then declined marginally thereafter in the POI. It can be seen that as the import volumes of the

- subject goods from the subject countries decreased, as the landed prices of the subject goods increased. As the import volumes surged in the POI, the landed prices decreased, indicating the likely trend of import volumes as well as landing prices if the ADD is ceased. Despite existence of current duties, there is a presence of the dumped goods in the country and the same are undercutting the selling prices of the domestic industry, with or without factoring in the existing ADD. While the absolute performance may not show material injury, the situation of the domestic industry is fragile, and vulnerable to injury in the event that ADD ceases to operate.
- xxiv. A period of three years prior to the POI and the POI itself are taken for analysing the injurious effects of unfair trade upon the domestic industry. The analysis involves a study of the trend that has formed during the investigation period and not just an end point to end point comparison. Import volumes decreased till 2015-16 only to surge back up in the POI. The increase in imports is coupled with a decrease in import prices, without any decline in cost of production. Imports, in particular, from Turkey have increased significantly. Cessation of ADD is likely to increase imports further. On the issue of landed prices not having caused price suppression/depression, it is submitted that while imports have already started having such effects on the prices of the domestic industry, as evident from the last six months of the POI, for likelihood analysis, the authority is required to consider likely suppressing/depressing effects and not actual effect. In case the ADD is allowed to cease the domestic industry would be forced to reduce their price almost immediately, and the imports then would be having suppressing/depressing effect on the prices of the Domestic Industry.
- xxv. Various stakeholders agree that the claim of the Domestic Industry to add transportation costs has significant rationality. The argument of existing practice is again flawed. First of all, the DA has in fact considered freight for determining price undercutting and injury margin in the matter of white cement case both in original and first SSR investigations. Further, it is DA's position that the present NIP law is nothing but codified practice. Above all, the rule stops at NIP and the domestic industry's argument is on injury margin. There is no law which says that injury margin shall only be the difference between the NIP and landed price of imports at ex-factory levels. The present practice of the Directorate does not recognize business realities.
- xxvi. The Petitioners are willing to provide post POI data. The DA may kindly decide and thereafter give adequate time to the domestic industry to provide post-POI data. If such data needs to include price depression/suppression as well, the domestic industry is required to undertake elaborate exercise in providing the data. Further, such POI performance cannot be limited to merely domestic industry performance. Exporters must also provide data from their side.
- xxvii. The domestic industry has already provided adequate evidences establishing the fact that there has been an addition of capacities by the producers. The domestic industry has disclosed further evidence which cement the fact that there has been addition of capacities. The surge in imports in the post-POI with the commencement of capacities clearly establishes correctness of the submissions earlier made by the domestic industry.
- xxviii. The domestic industry submits that mere statements of 'India not being a major market' do not evidence that there is no likelihood of the continuation/recurrence of injury in case of cessation of the current duties. The domestic industry is enclosing detailed quarter-wise post-POI import data. The same would evidence the movement trend of imports from both the subject countries. Russian imports have shown a continual growth path throughout the injury investigation period whereas the Turkish imports showed a decline till 2015-16 before explosively surging in the POI. Furthermore, capacity expansion plans for subject exporters require favourable markets, such as the growing Indian market. Turkey's dumping of soda ash also establishes likelihood of injury not only from Turkey, but also from EU – a) admittedly, Turkish exporters are selling in

- the EU at prices lower than the Indian market and shall not hesitate to divert the same to the Indian market; b) Turkish exporters have displaced the European producers, who in turn may move forward to displace the Indian producers.
- xxix. If Turkish export prices to third countries are much lower than export price to India, at the least, it establishes that these volumes will get diverted to Indian Market. No evidence has been brought on record to show that Turkish producers are exporting to European markets out of some affiliation/medium/emotion or long-term contracts. If exports from Turkey to Europe are happening due to business situations, the minimum that will happen from cessation of ADD is that Turkish producers will enhance their exports to India further by not only enhancing production, but also diverting third country exports.
- xxx. The constituents of the domestic industry are multi-product companies rather than single product companies. The annual reports published are for the companies as a whole, and not for the PUC alone. However, the extracts as referred are an attempt to mislead the DA and are extremely selective. The very same pages referred by the responding party also refer to the threat in future by low cost imports, which has been maliciously left out by the responding party.
- xxxi. The alleged inaccurate/incomplete data is nothing but just cumulative undercutting levels for the base year and hence in the absence of the imports from Russia for the base year it is but obvious that the same would only show the undercutting levels of the only exporting subject country Turkey. As regards the issue raised on absence of ROI/cash profit, it is submitted that the sought information is of highly business sensitive nature and disclosure would put competitors at an advantage.
- xxxii. Domestic Industry has not claimed continued injury. The domestic industry is not affected despite positive undercutting because of the fact of anti-dumping duty in existence. Further, it would be seen from the information provided that cost of production declined till 2016-17 and then increased thereafter in the last six months of the present investigation period; whereas selling price increased till 2015-16 and then declined thereafter in POI. Thus, imports have started having suppressing effect on the prices of the domestic industry during the last six months of the POI.
- xxxiii. Current case is not of continued injury but a case where the facts clearly indicate intensification of dumping and recurrence of material injury in the event of cessation of ADD. Hence, it cannot be said that the capacity utilization declined because of addition of capacities. Rather, it did, because of the dumped subject imports gaining market and making the installed capacities redundant.
- xxxiv. Despite increase in production and domestic sales by the domestic industry, the average inventory of the domestic industry has increased significantly. It has almost doubled in the injury investigation period. What rightfully belonged to the domestic industry is being captured by the subject exporters as can be seen from the sudden rise in import volumes in the POI along with the declining landed prices of the subject imports. The averments that average stock has no meaning is without legal basis. Rules have not stated anything to this effect.
- xxxv. The present case is for extension of ADD based on the grounds of likelihood of recurrence of dumping and injury. Thus, current volume is not sufficient to determine the likely effect of dumped imports. The present volume of imports is still at dumped prices. Thus, cessation of anti-dumping duty is likely to lead to intensified dumping and significant increase in imports.

Submissions made by the other interested parties

48. The other interested parties have submitted as under:

- i. India is not the main market for Turkey's soda ash exports. On the contrary, geographically close markets and trade partners such as Italy, Egypt and Spain are the main destinations for Turkey. Thanks to the customs union between Turkey and the EU as well as its network of FTAs with the surrounding countries, exports from Turkey to Italy, Egypt and Spain constituted 16.4%, 12.3% and 9.7%, respectively of all exports of the product concerned in 2017 while India's share was only 3.8%.
- ii. In the last 5 years, Turkey has exported soda ash to over a hundred countries, but it is facing anti-dumping measures only in India. It is evident that Turkish soda ash exporters trade fairly in international markets.
- iii. Article 3.1 of the Anti-dumping Agreement requires that determination of injury be based on positive evidence regarding volume of the dumped imports and the effects of dumped imports on prices in the domestic market for like products, and consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The import statistics in the complaint clearly shows that soda ash imports from Turkey decreased by 45% in terms of quantity from 2013 to POI (Annualised). Similarly, imports from subject countries decreased by 16%. In the same period, production of the domestic industry increased by 18.2%. These figures prove that there is no significant increase of imports either in absolute terms or relative to production of the domestic industry.
- iv. According to the complaint, the domestic industry almost tripled its profit from the domestic operations since 2013 and there are positive trends in terms of market share, sales, production capacity, return on investments, productivity, profit/loss. Turkey believes that there is no injury to the domestic industry. Regarding injury analysis, Turkey expects the Indian authority to act in line with Article 3.2 of the Anti-dumping Agreement as well as India's related laws and practices. Turkey requests the Indian authority to terminate the ongoing sunset review as soon as possible and not to continue any measures. Turkey is closely following the proceeding and reserves its rights under WTO jurisprudence.
- v. Applicants' claim that Russian exporter Bashkir Soda Company enhanced its production capacities by ***% is false. Indeed, in the frame of modernization program Bashkir Soda Company put into operation new carbonating tower and capacity of this tower enhanced by ***%. As a result, the production capacities of the company have increased insignificantly. Data on Russian industry has been provided. It is evident from this data that since 2015, when the investigating authority found no threat of injury, Russian producers' capacities have increased insignificantly. Volume of soda ash production has slightly increased in order to supply domestic demand. It is indicated that Russian companies are still pursuing domestic-oriented marketing policy.
- vi. Given the irrelevant and biased nature of applicants' claim about substantial increase in production capacities in Russia, we kindly ask the investigating authority to verify the applicants' claim in regard to production capacities in Turkey.
- vii. The decrease in volume of imports from subject countries during the injury period, insignificant increase of production capacities in subject countries along with increasing demand in the Indian market and growth of domestic industry in India are indicating the absence of recurrence of injury. We request the investigating authority to terminate the review without continuation of measures.

- viii. The petitioners have admitted in their written submissions that anti-dumping duty on the subject goods has served its intended purpose and enabled them to expand capacities. In the sunset review of Caustic Soda from Saudi Arabia and USA, the Authority in similar facts recommended not to continue anti-dumping duty on these countries. The domestic industry has been able to withstand the alleged increase in imports below normal value (in terms of positive economic parameters) and hence, the Hon'ble Designated Authority is requested to conclude that there is no likelihood of recurrence or continuation of dumping and injury to the Petitioners.
- ix. Soda Sanayii submits that there is no causal link between the alleged injury suffered by the Petitioners and the subject imports – as the Petitioners' performance in terms of sales volume, value, market share has improved significantly throughout injury period.
- x. The likelihood of substantially increased importation can only be determined after analysing authenticated post-POI data, which the Petitioners have not provided in the Petition. Petitioners have not provided any post-POI data on price suppression/ depression, nor has it made any substantiated submissions with respect to the same.
- xi. Despite the alleged decline in the landed price from 2015-16 to the POI, the selling price of the Petitioners has remained stable during the same period (and most of the injury period). The selling price of the Petitioners shows a positive trend throughout the injury period in comparison to the base year.
- xii. The Petitioners' allegations of freely disposable capacities in the subject countries is mere conjecture. Capacity utilisation of Soda Sanayii is 95%, evidencing that the Turkish producers do not have existing freely disposable or surplus capacities in Turkey, which they could utilise towards India in the event of cessation of duty.
- xiii. The domestic industry has failed to substantiate that there are existing surplus capacities and evidence of capacity addition to demonstrate likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event the anti-dumping duty is discontinued.
- xiv. The Petitioners have provided no evidence to substantiate that there is demand-supply gap in the subject countries. The evidence relied upon by the Petitioners at paragraph no. 80 pertains to only a portion of the POI, hence not sufficient to conduct an effective analysis of likelihood of recurrence or continuation of injury.
- xv. The Designated Authority may take note of the submissions made by the Turkish producers during the oral hearing that their main export markets are Egypt and the EU. The Petitioners have not provided any evidence to substantiate that Turkish producers have export orientation towards India.
- xvi. The Petitioners' contentions regarding price attractiveness of imports is without merit. As per the petition, Turkey's export prices to third countries are already much lower than its price to India. Even if duties expire, there is no likelihood that Turkey's export prices to India would fall.
- xvii. As per petition, the main markets of Turkey are Egypt and Saudi Arabia, and the main markets of Russia are Kazakhstan, Belarus and Ukraine, and exports to these countries are significant as well as at non-dumped prices. Hence, it can be concluded that the main markets of Turkey and Russia would remain as above despite the existence or cessation of the anti-dumping duty in India. Exports from subject countries to third countries are irrelevant while making a likelihood analysis in the present factual matrix.

- xviii. Capacity expansions in non-subject countries like Europe, Pakistan and China PR are irrelevant in the present case. Dumping margins in previous investigation is not the crux of the present sunset review.
- xix. No evidence has been provided regarding price undercutting in post-POI period. No evidence has been provided regarding inventory levels in the subject countries.
- xx. Petitioners are requesting the Hon'ble Designated Authority to continue duties after discarding a majority of the evidence on record, which is not only in violation of the AD Rules, but also the principles of natural justice.
- xxi. If the Hon'ble Designated Authority recommends anti-dumping duty in the review, it is requested to apply lesser-duty rule as laid down under the AD Rules.
- xxii. The average profit of the domestic industry is ***% of cost of sales during the POI, which is way above the one (i.e. ***) permitted by the Director General while constructing normal value in an anti-dumping investigation. The return on capital employed of petitioners is ***% of NFA during the POI whereas the Director General allows ***% while computing NIP in all anti-dumping cases. Therefore, there is no existence of injury to the domestic industry and thus question of its continuation does not arise. There does not exist any special/exceptional circumstances calling for continuance of anti-dumping duty on the subject goods from the subject countries.
- xxiii. The reason for the increase of imports from the subject countries from 2013 to 2017 is not dumping, but the growth of the Indian market demands following the development of downstream industry. It may be seen that the demand has increased to 117 from 100 during the base year 2013-14 to the POI(A). To the contrary, imports from the subject countries have declined by 17% from 100 in the base year to 83 during the POI (A).
- xxiv. The quantum of imports from Russia is very less, only ***% of the total demand during the POI constituting an insignificant share. Such nominal share cannot cause injury to the domestic industry. The producers from the subject countries have no intention of dumping nor have they used dumping as a method to increase exports to India.
- xxv. Proforma IVA of the petition shows that there is no correlation between cost of sales and selling price in domestic market. From the data, it is evident that the cost of sales has decreased by 15%, from 100 during 2013-14 to 85 during the POI. With the decrease in cost of sales, the domestic industry did not decrease the selling prices accordingly rather kept on increasing the same. The selling price has increased from 100 during the base year to 107 during the POI. This has resulted in high profitability to them during the POI. So, there is no price depression and price suppression. The Director General is requested to critically examine the same.
- xxvi. Price undercutting is an important parameter to establish causal relationship between dumping and injury, but it does not provide the basis for determination and should not be seen in isolation. It has to be seen in light of overall performance of the domestic industry, whether it is resulting in losses. As per petition, price undercutting from Russia is positive during the injury period. In the present case, despite price undercutting, domestic industry has improved its performance. Hence, price undercutting has no relevance in the present investigation.
- xxvii. Capacity and production increased substantially during the POI. Rather than focusing on increasing the capacity, the petitioners should have focused on efficient and effective capacity utilisation. Had the petitioners not increased the capacity, its capacity utilisation must have increased to ***% during the POI and achieved optimum level.

- xxviii. Petitioner is able to sell whatever they are producing. The sales volume of the petitioners has increased from *** MT to *** MT during the POI as compared to base year 2013-14. Petitioners' exports have substantially declined during the injury period and then registered sudden growth during the POI. The decline in exports might have caused injury to the domestic industry. Overall performance of the petitioners has improved.
- xxix. Average stock should not be seen in isolation. It shall be seen in relation with sales and production.
- xxx. Market share of petitioners increased during the injury period and that of the subject countries declined. Major market share has been captured by the domestic industry and other Indian producers. Imports from Russia is only ***% of the total demand. Such negligible share of imports cannot cause injury to the domestic industry.
- xxxi. Profitability of the domestic industry has improved substantially during the POI as compared to the base year 2013-14. Total profit of the company has increased from 100 during the base year 2013-14 to 341 during the POI. The PBIT has also improved to 270 during the POI as compared to base year, 2013-14.
- xxxii. ROCE has increased from 100 in the base year to 167 during the POI. The Director General has terminated many cases wherein the domestic industry was earning huge profits or selling its products at price above NIP, such as, AA Dry Cell Batteries from China PR and Vietnam in the final findings dated 27th September 2016; Hydrofluoric Acid from China in the mid-term review final findings dated 24th May 2011; Phenol from Korea RP in the mid-term review final findings dated 9th February 2012; Citric Acid from China PR, Korea RP and Ukraine in the final findings dated 25th August 2005; and Gypsum Plaster Board from Indonesia and Thailand in the final findings dated 27th June 2005.
- xxxiii. Total demand for subject goods (including captive) has increased by 17% during the injury period, while total demand (excluding captive) has risen by 15%, in line with requirement of the Indian user industry. On the other hand, imports of the subject goods declined significantly by 17% during the injury period.
- xxxiv. Demand (excluding captive) for the subject goods increased from *** MT in 2013-14 to *** MT in the POI(A), an overall increase of 15%. In line with the growth of demand, the domestic industry increased its annual capacity by 37% from *** MT in 2013-14 to *** MT in the POI(A). Production also increased by 18% from *** MT in 2013-14 to *** MT in the POI(A). Similarly, domestic industry's domestic sales increased by 16 % from ***MT in 2013-14 to ***MT in the POI(A). With year-on-year increase in demand, production and sales, the domestic industry feels encouraged to invest in enhancing its annual capacities by *** lac tons in the near future. The domestic industry's performance during the injury period and their future plans demonstrate no likelihood of recurrence of dumping causing injury.
- xxxv. Overall market share of imports from subject countries has decreased from 2.27% in 2013-14 to 1.65% during POI(A). In the same period, profits of the domestic industry increased from 100 indexed points in 2013-14 to 341 indexed points in the POI(A). Profits of the domestic industry sharply increased by 241 indexed points during the injury period. It was also able to maintain overall ***% share during the injury period, while the market share of other Indian producers slightly declined from ***% in 2013-14 to ***% in the POI (A). This demonstrates that there is no likelihood of recurrence of injury if the anti-dumping duty lapses.
- xxxvi. Capacity utilisation in 2013-14 was ***%, which declined to ***% during the POI(A). It is reasonable expectation in any industry that when capacities are substantially increased, such capacities may not get utilized immediately. The decline in capacity utilization is a natural

consequence of the sudden increase in capacities by 37% during the injury period. Furthermore, imports of the subject goods declined more sharply, by 17% during the injury period. Thus, imports of the subject goods did not cause any decline in the domestic industry's capacity utilization. The domestic industry, according to industry sources, has been operating at full capacity during 2018, and will be adding another *** tons in annual capacities. The additional capacities will enable the domestic industry to capture a much larger share of the Indian market.

- xxxvii. Despite increases in annual capacity and production, the domestic industry has been able to manage its stocks well. While there was a decline from 100 indexed points in 2013-14 to 74 in 2014-15, the stocks increased to 127 in the 2015-16 period, and marginally increased to 129 indexed points during the POI(A). Exports fell from 100 indexed points in 2013-14, to 36 in 2014-15, to a further 17 in 2015-16, before sharply increasing to 159 during the POI(A), helping the domestic industry to prevent further increase in stocks.
- xxxviii. While overall employment fell from 100 indexed points in 2013-14 to 85 indexed points in the POI(A), wages paid out increased sharply over the same period from 100 to 133 indexed points. Interestingly, profits were on the rise despite higher wages, as profits in of the domestic industry went up from 100 indexed points in 2013-14 to 341 indexed points. This strongly demonstrates that there is no likelihood of continuation or recurrence of injury if the anti-dumping duty lapses.
- xxxix. The domestic industry's capacity increased from 100 indexed points in 2013-14 to 137 indexed points in the POI, accompanied by a growth in capital employed in the same period, from 100 to 162. RoCE increased from 100 to 167 indexed points as well. Imports have had no impact on the ROCE earned by the domestic industry during the injury period.
- xl. When imports of the subject goods decreased from 100 to 79 indexed points from the period of 2013-14 to 2014-15, the profits increased to 231 indexed points and PBIT increased to 183 indexed points. Imports of the subject goods declined to 41 indexed points in 2015-16, and profits sharply increased to 364 indexed points while PBIT increased to 287 points.
- xli. The cost of sales of the domestic industry declined from 100 indexed points to 85 from 2013-14 to the POI, while the selling price of the domestic industry increased from 100 indexed points to 107 indexed points in the same period.
- xl.ii. The domestic industry claims price undercutting due to imports from each subject country as well as overall price undercutting in the range of 20% - 30%. However, such price undercutting has had no visible impact on the performance of the domestic industry.
- xl.iii. In the Truck and Bus Tyres case, the Hon'ble CESTAT annulled the imposition of antidumping on the basis that the injury findings of the Designated Authority were flawed, and opined that "... if there was really any such price undercutting and price underselling as determined by the DA, then the domestic industry would have been hard put to maintain its sales volumes rather show such an increase in sales." In the present case, the domestic sales of the domestic industry increased over the entire injury period with increase in demand for the subject goods. The mere fact that the domestic industry managed to expand its sales in India despite the alleged price undercutting demonstrates the absence of injury and no likelihood of continuation or recurrence of injury.
- xliv. The domestic industry's claim of ***% return on capital employed is illegal as the norm is to consider the historical rate of return in light of the Hon'ble CESTAT's ruling in *Indian Spinners Association v Designated Authority*, 2004 (170) ELT 144 (Tri – Del). The domestic industry's unsubstantiated request that ***% ROCE should be adopted is without logic and should be

- rejected, and the Designated Authority should examine the ROCE enjoyed by the soda ash industry globally and in India and only then adopt an appropriate ROCE for this case.
- xliv. Any alleged injury suffered by the Petitioners has absolutely no correlation to imports from the subject countries. It is submitted that when the subject imports allegedly increased from 2015-16 to POI, there was an improvement in the Petitioner's Performance, with the alleged increase in imports from 2015-16 to POI being accompanied by an increase in the Petitioner's domestic sale and sales values. HUL submits that admittedly there is no injury suffered by the Petitioners during the injury period on account of the alleged increase in imports in absolute or relative terms.
- xlvi. However, in para 51 of the Petition, the Petitioners have stated that there was increase in imports on account of quantum of anti-dumping duty being low. In light of the Petitioners' admission that anti-dumping duty has provided adequate protection and helped them improve in the Indian market is itself sufficient to establish that the duty was adequate. Rising imports can instead be linked to rising demand, which the domestic industry seems unable to fulfil. HUL accordingly requests the DA to reject the Petitioners' submission in this regard.
- xlvi. Vide para 16 & paras 18 – 25, Petitioners have averred that the current market share is immaterial and what is relevant is the likely effect of imports on the market share in case current duty is allowed to cease. HUL submits that determination of market share of domestic industry becomes essential while making either an injury or likelihood analysis in an SSR investigation. Hence, the submissions made by the Petitioners in this behalf ought to be rejected. HUL submits that if the Petitioners were suffering alleged injury due to subject imports, they should have also experienced a decline in market share, and a similar increase in the market share for the imports from the Subject Countries. However, in the present case, the market shares of the Petitioners increased by 1.49% in the POI in comparison to the base year, while on the other hand, the market share of imports from the Subject Countries reduced during the same period. Thus, the subject imports have not impacted the market share of the Petitioners.
- xlvi. The landed price of the subject imports has not impacted the selling price of the Petitioners, and not caused any price suppression/depression. Despite the decrease in landed price from 2015-16 to POI, the selling price of the Petitioners has remained stable during the same period (and most of the injury period). The selling price of the Petitioners show a positive trend throughout the injury period in comparison to the base year.
- xlix. From para 53 to para 55 of the Petition, the Petitioners have averred that the landed price is below the selling price and hence imports were undercutting the prices of domestic industry. Vide paras 26 – 48, Petitioners have averred in their Petition that the selling price should be compared with landed price only after adding transportation costs/freight for fair comparison in price undercutting and injury margin. At para 53 of the Petition, Petitioners have stated that they have added post ex-factory expenses paid by the Petitioners on the domestic product while making its injury analysis. HUL submits that the averments made are erroneous and contrary to the DA's past practice of comparing selling price and landed price at ex-factory level and therefore ought to be rejected by the DA. Admittedly, based on the past practice of the DA, the notional fair selling price/NIP and the landed price of the subject imports are determined at the place of importation. The NIP is determined based on the principles laid down in Annexure III of the AD Rules. In determining the same, the DA allows a 22% rate of ROCE on the subject product. Further, since landed price is considered at the place of importation, the NIP is also calculated at ex-factory level in order to ensure the fair comparison of prices. The Petitioners are herein not right in requesting the DA to deviate from past practice and add the post factory

costs/transportation costs/freight before making a comparison between selling price and landed price.

1. It is imperative to assess the impact of the alleged dumped imports by analysing various economic factors as per Annexure II (iv) of the AD Rules. Petitioners vide their Petition at page 18 have admitted that the economic parameters including production, sales volume have all shown a positive trend in the injury period as well as the POI.
- li. Domestic sales volume and value figures have been growing steadily throughout the injury period as well as the POI, showing that the domestic industry's sales performance has been profitable irrespective of subject imports. Furthermore, the production of the Petitioners has also increased throughout the injury period.
- lii. The Profit per Unit for the Petitioners has risen by 193 points from the base year to the POI. Their profit before tax has also risen by 170 index points in the POI from the base year, while one of the Petitioners, namely Nirma Ltd. (vide their 2016-17 Annual Report) have seen an increase in profits in absolute terms, despite reduced profit per unit due to new capacities being commissioned by the company. Petitioners at para 58 of their petition have determined the profitability of a new plant separately and have stated that it is low. HUL submits that the plant referred to by the Petitioners is a new plant, it is certain that the Petitioners would have incurred certain production costs and overheads etc., consequently affecting the pricing structure of the domestic industry in respect of the PUC and thereby, the profitability and return on investment of the new plant. Hence, when the Petitioners have in the first place expanded their capacities on account of recovering from the anti-dumping duty and in anticipation of demand for PUC and have incurred low profits in respect of the new plant, it cannot now under the garb of obtaining protection attribute slightest self-inflicted injury to imports.
- liii. HUL thus submits that the domestic industry is clearly not suffering any injury, and the continuation of an injury that has ceased to exist is not possible. Therefore, the only analysis to be conducted remains the one with regard to likelihood of recurrence of injury.
- liv. Petitioners have identified in their Annual Reports the reasons for their alleged injury, which are not inclusive of the imports from Subject Countries. DCW Ltd, one of the Petitioners, has reported vide page 4 of its Annual Report of 2016-17 that imports were not a threat and that the company was capable of facing international competition. Furthermore, they reported on page 3 that there was a loss in turnover of upto ***% in comparison to the previous year due to shut down of its soda ash division. It would thus be untenable to imply that the consequent loss in revenue can be attributed to the subject imports.
- lv. The Petitioners have failed to provide sufficient information, or have provided inconsistent information and data, in the following instances. On page 36 of the Petition, Petitioners have provided calculations for arriving at price undercutting for imports from Turkey and Russia. They have calculated no undercutting for PUC from Russia for 2013-14 period, while the undercutting has been reported for the same period from both countries as 10-20%. Calculations carried out by the Petitioners are thus completely erroneous and therefore should be completely disregarded. Petitioners have relied on return on investment and cash profits in their injury analysis, but have failed to provide any data on the same in Proforma IV-A. If the said information is not available, other interested parties cannot conduct an effective analysis of the same.
- lvi. HUL submits that the DA should terminate the present investigation forthwith as *first*, the domestic industry's data is incomplete and insufficient; *second*, there is an absence of continued injury, as no injury has been suffered by the domestic industry in the POI in its critical

economical parameters, and no post-POI data has been provided by the Petitioners; and *third*, there is no injury or likelihood of injury caused to the domestic industry. However, any injury suffered is solely self-inflicted and caused by inefficiencies and cannot be attributed to the imports from Subject Countries.

- lvii. Vide para 17 of the Petition, the Petitioners have averred that one of them, namely M/S Nirma as well as GHCL have undertaken significant capacity expansions in anticipation of an increase in demand. At para 16, Petitioners have admitted that they have become capable to carry out such expansion due to an absence of injury. When the Petitioners have, on their own accord, increased capacities on account of an absence of injury or perceived increase in demand, it is clear evidence that there is no longer a need for duties to be in force. The purported objective of anti-dumping duties is not to provide the Petitioners with a security cover for their future investments. In the *SSR Investigation concerning imports of "Melamine" originating in or exported from EU, Iran, Indonesia and Japan*, No. 7/14/2017-DGAD dated 19/02/18, the DA noted that future production plans which are yet to come up pursuant to future capacity expansions cannot be addressed in an ongoing SSR. Accordingly, the DA may take the said precedent into consideration and reject the Petitioners' averments in this regard.
- lviii. Vide para 16 & paras 18 – 25, Petitioners have averred that taking into consideration the sales volume for top five consumers, the sales have declined and there is loss of sales of subject goods. HUL submits that while making an injury analysis, the DA ought to take into consideration the effect of imports on total sales of the domestic industry and not domestic sales made to top five consumers as proposed by the Petitioners. It is reiterated that since the sales of the Petitioners have increased throughout the injury period, the averment above does not stand and evidently, there is no injury to the Petitioners.
- lix. In respect of imports in relation to production and consumption, HUL submits that the imports in relation to production and demand/consumption have declined in the POI, hence, there is no alleged injury to the Petitioners. The imports in relation to production declined in the POI not only by ***% in comparison to the base year but also by ***% in comparison to 2014-15. Further, the imports in relation to demand/consumption declined in the POI when compared to the base year.
- lx. Vide para 16 & paras 18 – 25, Petitioners have averred that producers in Turkey and Russia can give an undertaking that their volume of exports shall remain limited provided the Petitioners would consider not pursuing their request for extension of anti-dumping duty. HUL submits that there is no injury or likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry on account of the Petitioners performing significantly well throughout the injury period. Hence, there being no necessity to continue the levy of anti-dumping duty on account of the Petitioners performance, the question of a volume undertaking by the Subject Countries does not arise in the first place. The submissions made by the Petitioners in this regard should be rejected by the DA.
- lxi. Vide paras 26 – 48, Petitioners have averred in their Petition that price undercutting should be determined only after considering those import transactions whose landed price of imports is below selling price of the domestic industry. HUL submits that the averments here are erroneous and contrary to the DA's past practice. The Petitioners' proposal is akin to zeroing, a practice that has been unanimously held to be unreasonable and in violation of the AD Agreement. In the *Anti-Dumping Investigation concerning imports of Caustic Soda originating in and exported from Japan and Qatar*, a similar proposal by the domestic industry was rejected by the DA, which noted that undercutting would be calculated taking into consideration the

- DGCI&S data & not selected transactions. The DA is thus requested to accordingly reject the Petitioners' averment in this regard.
- lxii. Petitioners have at pages 33 – 35 of their Written Submissions made submissions in respect of capacity expansion in non – subject countries. HUL submits that the same is irrelevant for the purpose of conducting a likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury to domestic industry on account of imports from *Subject Countries* and the Petitioners' averments made in this regard ought to be rejected by the DA.
 - lxiii. The Petitioners vide paragraphs 95 – 102 have made submissions in respect of relevance of price undercutting in the POI and the post-POI while examining if cessation of anti-dumping duty would lead to recurrence of injury. The Petitioners have specifically averred that even if one of the situations as mentioned in para 95 is positive, the DA should hold that cessation of duty is likely to lead to recurrence of injury. HUL submits that the averments made by the Petitioners in this behalf are baseless. It is well-settled that the determination of likelihood is a holistic determination, a practice upheld consistently by the DA in the past. Effectively, the Petitioners are requesting the DA to continue duties after discarding a majority of the evidence on record, which is not only in violation of the AD Rules, but also the principles of natural justice. Hence, the averments made by the Petitioners in this behalf ought to be rejected.
 - lxiv. The Authority is requested to examine the performance and production parameters of other domestic producers not forming part of the domestic industry. The WTO Appellate Body in *EC – Fasteners (China)* case has held that an investigating authority has to ensure that there is no material risk of distortion while defining the domestic industry.
 - lxv. A WTO Panel in *China – Anti-dumping and Countervailing Duty Measures on Broiler Products from United States* noted that an investigating authority is not allowed to ignore the situation of other domestic producers in its injury determination. In the instant case, exclusion of other domestic producers distorts the picture completely, particularly in view of the fact that the applicant industry is suffering on account of several extraneous factors.
 - lxvi. Other producers in India are doing much better than the domestic industry and producers like Tata Chemicals and GHCL are playing a major role in determination of the prices of the subject goods in the country. As observed in the *Polyester Staple Fibre* case, other producers in India hold major share of the demand and playing a major role in determination of prices of the subject goods.
 - lxvii. The selling prices of the subject goods in India are governed by the prices determined by the domestic producers. The cost of sales of the domestic industry decreased by 15%, the selling price of domestic producers increased by around 7% during the POI. Production has increased by 18% while capacity utilisation has marginally decreased. The same is solely on account of increase in capacities of the domestic industry.
 - lxviii. Soda ash industry has low dependency on imported raw material as the same is abundantly available in India. Thus, there is no effect on cost of the domestic industry due to raw material.
 - lxix. Soda ash industry will continue to reap the advantage of local raw material and import-parity pricing with the increased value of Rupee. It is also a matter of fact that the Rupee has been over INR 65 per USD since 2016, which clearly establishes beyond an iota of doubt that there is no reason for continued imposition of the anti-dumping duties.
 - lxx. The Authority may examine parameters related to threat of injury for the purpose of likelihood analysis as laid out in *Nirma Ltd. v. Union of India*, order dated 23.02.2017 read with para (vii) of Annexure II of the Anti-dumping Rules, 1995.

- lxxi. The imports of the subject goods have declined from 62,103 MT in the base year to 51,668 MT in the POI(A).
- lxxii. The evidence presented by the domestic industry is of current capacities and not of any freely disposable or increased capacities. The petitioners have to establish beyond doubt that such capacities with the exporters are not being fully utilised to meet demand in their home country or other export markets and the likelihood of their being diverted to India is imminent. The mere existence of excess or idle capacities does not mean dumping or injury to the domestic industry is imminent. The domestic industry is doing very well despite existence of capacities elsewhere in the world. The domestic industry has failed to establish a case of surplus capacity.
- lxxiii. The domestic industry has failed to substantiate a case of price suppression/depression.
- lxxiv. No material has been presented in the petition to demonstrate any affect on the domestic industry's inventories. It is clear from the above that there is no likelihood of dumping and injury.
- lxxv. The claim of the domestic industry that only transactions involving positive price undercutting should be considered for determining the existence of overall price undercutting, is baseless and bereft of any logic. The WTO Panel report cited by the domestic industry is in a different context and does not, in any manner, establish any particular methodology of carrying out the price undercutting analysis. Therefore, the Authority will be perfectly justified to follow its consistent practice to carry out the price undercutting analysis on an overall basis.
- lxxvi. The claims of the domestic industry that freight should be included in determining injury margin is devoid of sound economic reasoning. The Authority's consistent practice is based on the sound economic principle that the comparison should be made at the first point where the imported goods and the domestically produced goods enter the mainstream commerce of the country and are first available for actual consumption.
- lxxvii. The reference of India's paper on lesser duty rule is misconceived and misleading. India's paper was in the context of persuading other members of the WTO to also practice the lesser duty rule. It would be mischievous to suggest that it was India's stand that comparison should be made closest to the point of consumption. In fact, it is India's practice to make the comparisons at the first point where the goods are available to the customer.
- lxxviii. It is also pertinent to note that Annexure III was introduced much after the said paper was floated in the WTO. Therefore, it clearly proves that not only the legal provisions do not permit inclusion of freight for injury margin calculations, it is not even India's intention to make the comparison at the point of consumption.
- lxxix. There are other factors causing alleged injury to the domestic industry, which information is missing from the petition, such as information on market competition among domestic producers, petitioners not producing enough quantities to meet domestic demand, users of the subject goods tending to import the subject countries from other countries.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 49. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry.
- 50. As regards the contention of the domestic industry for consideration of freight incurred by domestic industry as a factor in injury analysis, the Authority notes that NIP has been determined in terms of Annexure III of the AD Rules. The Authority further notes that the comparison between NIP and Landed Value for injury margin determination has been done at the same level as per the consistent

practice of the Authority.

51. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

Cumulative assessment

52. Attention is invited to Annexure II para (iii) of the AD Rules which provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to an anti-dumping investigation, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

- i. the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three per cent of the import of like article or where the export of individual countries is less than three per cent, the imports collectively account for more than seven per cent of the import of like article; and
- ii. cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

53. In this regard, the Authority observes that:

- i. the margins of dumping from each of the subject countries are more than the limits prescribed above;
- ii. the volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed;
- iii. The subject goods supplied from various subject countries and by the domestic industry are like articles.
- iv. Imported and domestic product are being used interchangeably and there is direct competition between the domestic product and imported product.

54. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from Turkey and Russia on the domestic industry in the light of conditions of competition between the imported product and like domestic product.

55. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. Annexure II of the AD Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products. While examining the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to price effect of dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree or prevent price increase which would have otherwise occurred to a significant degree.

56. As regards the impact of dumped imports on the domestic industry, para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”

57. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such further indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.
58. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, 1975, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time-to-time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of the order of such extension.
59. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries.

Demand and market share

60. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of the domestic industry and other Indian producers have been added to the total imports into India and the same have been summarized below:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI (A)
Demand in India - Including Captive					
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>99</i>	<i>111</i>	<i>122</i>
Sales of Other Indian producers	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>105</i>	<i>110</i>
Total Domestic Sales	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>107</i>	<i>115</i>
Imports- Subject Countries	MT	62,355	49,071	25,674	51,668
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>79</i>	<i>41</i>	<i>83</i>
Imports- Other Countries	MT	506,611	674,148	607,588	628,901
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>133</i>	<i>120</i>	<i>124</i>
Total Demand	MT	2,833,341	3,024,370	3,059,141	3,279,345
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>107</i>	<i>108</i>	<i>116</i>
Market Share in Demand					
Domestic Industry	%	***	***	***	***
Other Indian Producers	%	***	***	***	***

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI (A)
Indian Producers as a whole	%	***	***	***	***
Subject Countries	%	2.2%	1.6%	0.8%	1.6%
Other <i>Countries</i>	%	17.9%	22.3%	19.9%	19.2%

61. The Authority notes that demand has increased during the POI (A) as compared to the base year. The growth in demand during the POI over base year was 16%. Market share of domestic industry increased while that of subject countries declined during the injury period. The Authority notes that market share of subject countries in demand during the POI (A) was 1.6%, while market share of the domestic industry was 34% and Indian producers as a whole accounted for 79% market share in the same period.

L. VOLUME EFFECTS OF DUMPED IMPORTS

Import Volume and Market Share

62. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analysed as under:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI	POI (A)
Turkey	MT	62,355	42,114	16,325	51,181	34,121
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>68</i>	<i>26</i>	<i>-</i>	<i>55</i>
Russia	MT	0	6,957	9349	26,321	17,547
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-</i>	<i>100</i>	<i>134</i>	<i>-</i>	<i>252</i>
Subject Countries	MT	62,355	49,071	25,674	77,502	51,668
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>79</i>	<i>41</i>	<i>-</i>	<i>83</i>
Other Countries	MT	506,611	674,148	607,588	943,351	628,901
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>133</i>	<i>120</i>	<i>-</i>	<i>124</i>
Total Imports	MT	568,965	723,219	633,261	1,020,853	680,568
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>127</i>	<i>111</i>	<i>-</i>	<i>120</i>
Turkey	%	11%	6%	3%	5%	5%
Russia	%	0%	1%	1%	3%	3%
Subject Countries	%	11%	7%	4%	8%	8%
Other Countries	%	89%	93%	96%	92%	92%
Total	%	100%	100%	100%	100%	100%

63. The Authority notes that imports from the subject countries have decreased in absolute terms from 62,355 MT in the base year to 51,688 MT in the POI (A). Imports from Turkey reduced from 62,355 in the base year to 34,121 MT in the POI (A). Even though imports from Russia increased to 17,547 MT in the POI (A), these imports comprised only 3% of the total imports to India of the subject goods. The Authority notes that market share of subject countries in demand during the POI (A) was mere 1.6%.

M. PRICE EFFECTS OF THE DUMPED IMPORTS ON THE DOMESTIC INDUSTRY

64. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

Price suppression and depression effects of the dumped imports

65. The price suppression and price depression effect of the dumped imports has also been examined with reference to the cost of production, net sales realization and the landed values of the subject goods from the subject countries during the injury period including the POI.

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Landed price of Subject Imports	Rs./MT	14,729	16,508	18,394	14,808
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	112	125	101
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	93	83	85
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	107	109	107

66. From the above information, the Authority notes that the landed price of the imports from the subject countries has increased from Rs. 14,729/MT during the base year to Rs. 14,808/MT during the POI. While the cost of sales of the domestic industry declined during the injury period, the selling price of domestic industry increased during the injury period and was significantly higher than the landed value of imports from the subject countries.

Price Undercutting

67. While working out the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been deducted. The landed value of imports has been calculated by adding 1% landing charge and applicable basic customs duty and education cess to the CIF prices from the subject countries, as reported by in DGCI&S data. The domestic industry contended that freight should be included for determination of price undercutting. The Authority notes that the comparison between Net Sales Realization and Landed Value for price undercutting determination has been done at the same level as per the consistent practice of the Authority.

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Turkey					
Landed price of imports	Rs./MT	14,729	16,548	19,572	14,946
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	15-20%	10-15%	0-5%	20-25%
Russia					
Landed price of imports	Rs./MT	-	16,548	16337	14,540
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	-	10-15%	15-20%	25-30%
Subject countries as a whole					
Landed price of imports	Rs./MT	14,729	16,508	18,394	14,808
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	15-20%	15-20%	5-10%	20-25%

68. The Authority notes that during the POI, the price undercutting effect of dumped imports is positive in respect of each of the subject countries. The Authority has carried out further analyses on economic parameters of the domestic industry and likelihood or recurrence of dumping and injury in subsequent paragraphs for a holistic understanding of the situation.

N. EXAMINATION OF OTHER ECONOMIC PARAMETERS OF DOMESTIC INDUSTRY

Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization

69. The Production, Capacity and Capacity Utilization details are as follows:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI (A)
Installed capacity	MT	1,111,000	1,111,000	1,236,000	1,524,000
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>111</i>	<i>137</i>
Production	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>110</i>	<i>118</i>
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>99</i>	<i>86</i>
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>99</i>	<i>111</i>	<i>122</i>
Demand	MT	2,833,341	3,024,370	3,059,141	3,279,345
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>107</i>	<i>108</i>	<i>116</i>

70. From the above information, the Authority notes that the installed capacity of the domestic industry has increased during the injury period including the POI (A). Both production and sales have increased during the POI (A) as compared to the base year in line with increase in demand. Capacity utilization remained almost same from 2013-14 to 2015-16 but declined during the POI (A) due to increase in capacities

Inventories

71. Data relating to inventories is as follows:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI (A)
Opening	MT	***	***	***	***
Closing	MT	***	***	***	***
Average	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>74</i>	<i>127</i>	<i>129</i>

72. It is noted that average inventories declined from 2013-14 to 2014-15 but increased in the subsequent period to 127 indexed points in 2015-16. Thereafter, despite significant increase in capacity during the POI (A), average inventories increased merely by 2 indexed points.

Profits and actual and potential effects on the cash flow

73. With regard to Profit/Loss and cash flow, it is noted that the profitability of domestic industry in terms of profit, profit before tax and interest cash profit has remarkably increased in the POI as compared to base year.

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI (A)
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>93</i>	<i>83</i>	<i>85</i>
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>107</i>	<i>109</i>	<i>107</i>
Profit/Loss	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>229</i>	<i>325</i>	<i>293</i>
Profit/Loss	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>231</i>	<i>364</i>	<i>341</i>
PBIT	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>183</i>	<i>287</i>	<i>270</i>
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>189</i>	<i>292</i>	<i>277</i>
Return of investment	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>188</i>	<i>282</i>	<i>171</i>

Employment, wages and productivity

74. The data relating to employment, wages and productivity is as follows:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI (A)
Employment	Nos.	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>101</i>	<i>85</i>
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>113</i>	<i>125</i>	<i>133</i>

75. It is noted that there was marginal increase in the number of employees from 2013-14 to 2015-16 but the same declined during the POI (A). Wages have increased during the entire injury period.

Magnitude of dumping

76. It is observed from the section pertaining to Dumping Margin above that dumping margins in respect of the imports of the subject goods from the subject countries are positive and substantial during the POI. However, the same has had no visible impact on the economic parameters of the Petitioners.

Growth

77. The Authority notes that the growth of the domestic industry was positive in terms of improvement in production, sales, profit, profit before tax and interest, cash profit and return on investment during the POI.

Ability to raise funds

78. It is noted that the domestic industry has enhanced its capacity of production of the subject goods in the year 2015-16 and the POI. The domestic industry has made significant capital investment at present and has further planned investments for enhancing capacities. This signifies that their ability to raise capital investment has not been affected adversely.

O. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

79. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during POI. The injury margin thus determined is as under:

Country	Producer	Exporter	NIP US\$/MT	Landed Value US\$/MT	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin %	Injury Margin % Range
Turkey	Soda Sanayii A.S.	Soda Sanayii A.S.	***	***	***	***	5-10%
Turkey	Any other	Any other	***	***	***	***	5-10%
Russia	Trade House Ltd «Bashkirian Chemistry»	Trade House Ltd «Bashkirian Chemistry»	***	***	***	***	5-10%
Russia	Open Joint Stock Company “Berezniki Soda Works”	Trade House Ltd «Bashkirian Chemistry»	***	***	***	***	5-10%
Russia	Any other	Any other	***	***	***	***	10-15%

P. CONCLUSION ON MATERIAL INJURY

80. The Authority notes that the performance of the domestic industry improved in terms of production, sales volumes, market share, profit, cash profit, return on capital employed and inventory during the POI as compared to the base year. The domestic industry has also admitted in its submissions that it was not suffering injury during the injury investigation period. Selling price of the domestic industry has increased over the injury period and remains much higher than the cost of sales despite cost associated with addition of capacities.

Q. OTHER KNOWN FACTORS & CAUSAL LINK

81. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting and price suppression and depression effects, other indicative parameters listed under the AD Rules and AD Agreement have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry, as follows:-

a. Volume and prices of imports from third countries

The Authority notes that during the POI, imports of the subject goods from countries other than the subject countries have remained very high in volume.

b. Contraction of demand and changes in the pattern of consumption.

The Authority notes that there is no contraction in the demand during the POI. On the contrary, overall demand for subject goods has shown improvement during the POI.

c. Developments in technology

The Authority notes that none of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

The Authority notes that the subject goods are freely importable. The domestic industry is the major producer of the subject goods and accounts for significant domestic production and sales. Further there is no perceptible competition among the domestic producers, except that is obvious of a market economy.

e. Export performance of the domestic industry:

The table below summarises the performance of the domestic industry in respect of exports made by them.

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI (A)
Exports	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>36</i>	<i>17</i>	<i>159</i>

82. The Authority notes that the exports by the domestic industry have increased significantly during the POI (A) as compared to the base year. The domestic industry's performance in the export markets has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance in the Indian market. The Authority conducted its assessment based solely on information pertaining to the domestic sales. Injury on account of domestic sales has been isolated and examined, to the extent possible.

83. From the above analysis, the Authority notes that neither the listed known parameters nor the other factors analysed above show any continued injury to the domestic industry. The economic health of the domestic industry has improved.

R. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

84. In a review investigation, the Authority has to determine as to whether the subject goods are continuing to enter or likely to enter the Indian market at dumped prices and whether injury to the domestic industry is likely to recur due to these dumped imports if the duty is removed. The Authority is examining the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the AD Rules, which states as under:

“A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter alia, such factors as;

a. a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.

b. Sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.

c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely to increase demand for further imports and,

d. Inventories of the article being investigated.”

Submissions made by the Petitioners

85. Following submissions have been made by the Petitioners:

- i. In case of a sunset review, it is necessary to determine the likelihood of dumping and injury to the petitioning domestic industry. Thus, the following aspects need to be examined – (a) whether the dumping and/or injury is continuing; and if so, whether it is likely to continue in the event of cessation of the ADD; (b) in case dumping and/or injury did not continue, whether the dumping would recur in the event of cessation of the ADD.
- ii. The AD Rules do not prescribe any specific methodologies for examination of the likelihood of dumping or injury in a SSR investigation. However, if there are positive dumping margins in respect of exports of the subject goods over the POI, it is likely that dumping would continue leading to consequent injury in case the ADD in force is allowed to expire. In the absence of continued dumping and injury, likelihood of recurrence of dumping and injury needs to be seen. Given the facts of the present case, it can very well be said that dumping and consequent injury to the petitioning domestic industry is likely in the event of cessation of anti-dumping duties.
- iii. During the Original Investigation, the DA determined dumping margins for Turkey and Russia at 55-65% and 65-75% respectively. Consequently, in the First Review Investigation, the margins were found to be 25 – 35% for the Subject Countries. In the subsequent review investigation, the margins remained the same at 25-35% for both subject countries
- iv. Imports from subject countries will continue to be dumped in the event of cessation of ADD and are likely to cause injury to the Domestic Industry. This is established by the following – present and potential difference in the prices of imported product and domestic product is very significant and is therefore likely to increase demand for imports; significant price difference and consequent potential increase in imports is likely to have significant depressing effect on domestic prices; subject exporters are holding significant freely disposable capacity indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account

the availability of other export markets to absorb any additional steps. The ADD was imposed after an elaborate determination that dumping of the product was causing injury to the domestic industry. The performance of the domestic industry started improving post imposition of ADD but has started to decline in the POI. In any case, absence of continued injury to the domestic industry in the investigation period is not sufficient to warrant cessation of ADD. If the injury suffered by the domestic industry in the past was due to dumping, improvement of performance or absence of injury is a natural result of imposition of ADD. Therefore, the DA must come to a conclusion that the injury to the Domestic Industry is not likely to continue or recur, if the ADD ceases to exist.

- v. Imports from subject countries have increased in the POI after declining till 2015-16. Imports from Turkey are highest in the POI. Further, there was a surge in imports in the post POI period. Increase in imports at dumped prices indicates that imports are likely to enter in significant volume at dumped price in the event of cessation of ADD. Imports for the POI on annualized basis were 51,668 MT and imports post POI in one quarter alone (Q1 2017-18) are 52,658 MT, thus registering 400% growth. Thus, the potential of imports from Turkey alone is sufficient to take away the legitimate market of the subject countries and cause injury to the domestic industry.
- vi. The imports over the injury period did not have suppressing or depressing effects on the Domestic Industry for the reason that the ADD was in force and new Turkish capacities had not been commercialized. However, import prices have started declining significantly and have started having a suppressing effect on the prices of the domestic industry as soon as new Turkish capacities have commercialized. Should the present ADD be allowed to cease, the domestic industry would be forced to reduce the prices almost immediately. Thus, cessation of ADD would cause significant depressing effect on the prices of the domestic industry in the market.
- vii. Exporters in subject countries have capacities far in excess of Indian demand. The subject foreign producers are holding huge surplus and significant production capacities. New 3 million MT of low cost Turkish capacity has already partially commenced production and remaining shall start shortly. ETI Soda has installed additional capacity of 6 lac MT with ongoing investments in February 2017. Ciner Group, of which ETI Soda is also a part, through its subsidiary Kazan Soda has come up with a new plant located in North-West of Ankara to produce 2.5 million MT of Dense Soda Ash. The demand supply gap in Turkey as per IHS Market 2017 World Soda Ash Report is 2.1 million MT. Moreover, the consumption growth of Turkey is declining whereas its production growth remains stable every quarter indicating further increase in demand supply gap in the near future.
- viii. The Bashkir Soda Company, one of the major Russian soda ash producers, producing 65% of domestic soda ash, has undergone large scale reconstruction, further enhancing the capacities by 50%.
- ix. Turkish producers are expanding their production in spite of the fact that there is a significant demand-supply gap prevalent in Turkey as their production is significantly more than the consumption in the country. The reason for expansion is to promote exports. Research also shows that the producers in Russia also cater to a global market. The sales Geography of Russian Producers indicates Europe, CIS countries, Asia, Latin American and Middle East as markets for their product. The domestic industry has also analysed volume and value of exports from Subject Countries to various other countries and seen that majority of exports made by them are both at significantly dumped and injurious prices. Global expansion of capacities is further threatening increased imports into the domestic market with positive demand. Further,

there is a huge demand-supply gap globally which indicates that exports are likely to get diverted to Indian markets in view of its consistent growth in demand.

- x. Even though the present investigation concerns Turkey and Russia, given that the global surpluses and capacity enhancement become relevant wherever the domestic market demand is less than the capacities, it is relevant to consider capacity expansions in other markets as well. Exporters from Pakistan are also expanding capacities. The capacity expansion appears to cater to export markets. Petitioners are able to get information of the demand-supply gap in Pakistan, as provided in the IHS Chemical Week, which indicates ICI Pakistan is entering expansion plans, along with Olympia Chemicals. IHS data shows that the market in Pakistan is oversupplied.
- xi. China also has capacity expansions lined up, despite existing significant surplus capacities and showing that the Chinese producers can afford such massive capacity expansions when they are already hugely surplus, defying any rationality for these investments barring the greed to export in large global market, taking advantages of lower costs as compared to producers in several countries.
- xii. The current volume of imports from Turkey is clear evidence that the exporters are actually misleading the DA in believing that there shall not be significant increase in imports. The governments and exporters of Russia and Turkey can give an undertaking that volume of exports shall not exceed past the volumes registered in the present POI, but if the exporters wish to enhance their exports to the extent what the Turkish producers have already done till June 2018 and what they are expected to do by December 2018, Petitioners submit that there is not even an iota of doubt that there shall be a flood of imports post cessation of ADD. Petitioners have consolidated information with regard to their sales volumes to the top 5 consumers of the goods and imports made by them. It will be seen that sales by domestic industry have declined from *** MT to about less than *** MT. This loss in itself provides a preview of the loss of market that the domestic industry is bound to suffer if the current duties are allowed to cease.
- xiii. Price undercutting without ADD is positive and significant. It is evident that if ADD is withdrawn at this premature stage, the imports would cause significant price undercutting which would cause injury to the Domestic Industry.
- xiv. The Indian market is highly price sensitive, with consumers deciding procurement on the basis of price. Availability of low priced imports from subject countries would thus cause an adverse impact on the domestic industry. Vulnerability of the domestic industry relates to whether the industry would be susceptible to material injury in the event of revocation of anti-dumping duty imposed. In the event of cessation of current ADD at premature stage, the domestic industry will have to either reduce selling price by the amount of ADD or lose sales volumes. In either case, the domestic industry would suffer. In the event of withdrawal of current ADD and if Domestic Industry is constrained to sell at import prices, the profitability of the Domestic Industry would significantly decline. The return on investment and cash profit would also decline significantly. Therefore, cessation of ADD would have significant adverse effect on the prices in the market. The level of inventories available with the producers in subject countries could not be ascertained by the Domestic Industry. However, in view of the significant capacity available with the producers of the same, it can fairly be assumed that the foreign producers can scale up production in a short period.
- xv. The subject exporters should establish on the basis of their information that dumping is unlikely to continue, intensify or recur in the event of cessation of ADD.

- xvi. In a number of review investigations, the DA has examined whether cessation of ADD is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry. For this purpose, the DA is required to undertake the following tests – a) whether price undercutting and injury margin in respect of exports to India during POI is positive; b) whether price undercutting and injury margin in respect of exports to India during post-POI is positive; c) whether price undercutting and injury margin in respect of various third countries during POI is positive; d) whether price undercutting and injury margin in respect of various third countries during post-POI is positive; e) the volume of exports to third countries during POI which were at a price below selling price of the domestic industry and export price to India, and whether such volume of exports is significant having regard to Indian demand. Only in a situation where the DA has come to a conclusion that price undercutting in all above situations are negative, the DA can hold that the Indian Market is not attractive to the foreign producers and intensified dumping post cessation of ADD is unlikely to occur. Otherwise, the DA should hold that the cessation of anti-dumping duties is likely to lead to recurrence of injury to the Domestic Industry. When the injury margin principle has been applied by the DA in a number of investigations, the DA can no longer apply this principle as far as injury margin is concerned. However, a principle of price undercutting is required to be applied for the same purpose. The relevant determinations made by the Authority in the past investigations wherein the said principle of injury margin have been applied are – MTR Investigation in respect of the ADD imposed on imports of Acetone originating in or exported from Chinese Taipei; MTR Investigation concerning import of Phenol originating in or exported from Korea RP; MTR of ADD imposed in respect of imports of Phenol originating in or exported from the EU, South Africa and Singapore; SSR Investigation concerning imports of Ductile Iron Pipes originating in or exported from China PR; Final Findings in the SSR of ADD imposed on import of Zinc Oxide originating in or exported from China PR; SSR Investigation of ADD on imports of Polypropylene originating in or exported from Singapore; and SSR review of ADD imposed in respect of imports of Acetone originating in or exported from the EU, South Africa, Singapore and USA.
- xvii. The causal link has already been established in the original investigation. The DA has to examine whether injury to domestic injury is likely to continue or recur in the event of cessation of ADD. It is evident from earlier submissions that cessation of ADD is likely to lead to intensified injury to the domestic industry – (a) Volume Effect: price undercutting -> consumers preferring imported material -> domestic industry losing sales -> inventory increasing -> decline in production -> decline in capacity utilization; (b) Price Effect: Price undercutting -> Domestic industry prevented from effecting price increases -> decline in profitability -> decline in gross profits earned in the product -> decline in cash profits -> decline in return on capital employed.
- xviii. In view of the same, injury to Domestic Industry is likely to be caused from dumped imports in the event of cessation of existing ADD. The Domestic industry submits that a) product under consideration is exported to India at dumped prices from subject countries. Dumping is likely to intensify from subject countries; b) there is likelihood of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of ADD; and c) the ADD is required to be extended further for a period of five years.
- xix. The argument of interested party AIGMF implies that the parameters relevant for determination of continuation of injury are also relevant for determination of likelihood of injury. There is no legal and factual basis for such an assumption. On the contrary, the parameters relevant for actual injury or continued injury are different from the parameters relevant for threat or recurrence of injury. Therefore, it is inappropriate to consider the parameters of continued injury to determine likelihood of recurrence of injury. If potential decline in parameters is required to

be considered as a parameter for determination of likelihood of recurrence of injury, then, the past data becomes entirely irrelevant and the authority must decide based on the potential data for the subsequent period. The primary parameter that forms the basis of an analysis in a SSR investigation is the analysis of likelihood of continuation or recurrence of injury to the Domestic Industry. Other interested parties have failed to appreciate the fact that if the ADD has had the desired effect there would be no obvious current injury to the domestic injury, the condition of the domestic industry is expected to have improved during the protective regime of the ADD. In the present investigation, the domestic industry agrees that there has been an improvement in various parameters of the domestic industry but that is the result of imposition of the existing ADD. Further, these parameters have started showing decline in the POI, with an increase in imports. While the absolute parameters would not show material injury, yet the condition of the industry is extremely fragile. However, since this is a SSR investigation what is to be primarily seen is the likelihood of continuation or recurrence of dumping/injury to the domestic industry in case of cessation/revocation of the existing duties.

- xx. The averment that if domestic industry supplies adequate volumes the imports are bound to go down further, simply does not hold any merit. Without prejudice to the settled position that demand supply gap does not justify dumping in the country, the Petitioners submit that only *** MT is the alleged demand-supply gap in the country, whereas imports from subject countries and other countries attracting ADD is almost 6 times more than the gap which exists. The Domestic Industry exports only when it does not get a favourable market. Considering the increase in capacity that was made in view of the increasing demand, the domestic industry was not able to gather the sales volume as should have been rightfully theirs. From the base year of the injury investigation till 2015-16, the volume of dumped imports from the subject countries declined but increased significantly in the POI. Further, since this is a SSR investigation, the movement of imports post POI may also be seen to examine likely behaviour of exporters. Increase in imports at dumped prices indicates that imports are likely to enter in significant volumes at dumped price in the event of cessation of ADD.

Submissions made by other interested parties

86. Following submissions have been made by other interested parties:

- i. Petitioner is obliged to provide information on likelihood and has failed to supply the authority with even prima facie evidence in this regard. There must be evidence pertaining to relevant parameters while seeking initiation of investigation.
- ii. There is no causal relationship between the likelihood of continuation or recurrence of dumping and likelihood of continuation or recurrence of injury in the event of cessation of anti-dumping duty. The alleged increase in dumped imports has not impacted the production, capacity utilization and domestic sales of the Petitioners. As demonstrated earlier, any alleged price undercutting has had no impact on the financial performance of the domestic industry.
- iii. The Indian Industry has added close to *** lac tons of annual capacity and there are further plans to add *** lac tons of annual capacity, as recorded in the final findings dated 14/12/2018. The domestic industry's strong presence would impede the flow of any surplus capacities in the subject countries to India.
- iv. In case the price undercutting claimed by the domestic industry had any actual detrimental impact, the domestic industry would not have been able to maintain its domestic sales or increase them. The mere fact that the domestic industry managed to expand its domestic sales despite alleged price undercutting demonstrates the absence of injury and no likelihood of continuation or recurrence of injury.

- v. Selling price of the domestic industry continuously increased during the injury period, while profitability increased by more than three times during the POI when compared with the base year 2013-14, despite alleged dumping. The data on record does not show that the domestic industry was forced to lower its prices during the injury period.
- vi. With decline in imports of the subject goods, the domestic industry installed additional capacities and earned good returns on the same. The ROCE increased from 100 indexed points in 2013-14 to 167 indexed points during the POI.
- vii. The evidence on record shows that with increase in demand, the domestic industry added capacities, increased its production, domestic sales and profitability, despite alleged dumping. This is a trend that shall continue even if the anti-dumping duty lapses. Furthermore, there is no evidence that if the anti-dumping duty is revoked, customers would end up switching to imports.
- viii. The domestic industry's condition has improved exceptionally and now there is no further need of protection. In view of all of the above, this review should be terminated given the absence of evidence suggesting likelihood of continuation or recurrence of dumping causing any likelihood of injury to the domestic industry.
- ix. HUL submits that price attractiveness cannot be considered as a reason for likelihood of injury in the present instance. The difference in price between Turkey's exports to the three countries and to India is significant due to which the presence or absence of the anti-dumping duty would have no effect. Turkey's export prices to third countries are already at prices much lower than its price to India even after incorporating the presently levied anti-dumping duty. If India's market is price attractive, there should already have been a considerable increase in Turkey's exports to India irrespective of whether duties are allowed to expire or not. However, such an increase in exports to India has not been observed even though producers in Turkey could get much more remunerative prices on making sales to India even after absorbing anti-dumping duties. This implies that even if duties were to expire, there would be no significant change in price attractiveness for producers from Turkey, whereby there is no likelihood of a sudden increase in dumped imports to India.
- x. Further, Petitioners vide pages 33 and 45 – 46 of their Written Submissions have made submissions in respect of exports made by the subject countries to third countries at dumped prices and likely diversion of exports to third countries into India. HUL submits that, from the data provided by the Petitioners vide their Petition at pages 81 – 87, it can be seen that the main markets of Turkey are Italy, Egypt and Saudi Arabia and the main markets of Russia are Kazakhstan, Belarus and Ukraine. It can also be seen that not only the imports to these countries are significant but also are "not" at dumped prices (specifically at more than the export price to India). Hence, it can be concluded that the main markets of Turkey and Russia would remain as the above despite the existence or cessation of the anti-dumping duty in India. Therefore, the exports from Subject Countries to third countries becomes irrelevant while making a likelihood analysis in the present factual matrix.
- xi. Petitioners have not provided any post-POI data with respect to price suppression/depression, nor has it made any substantiated submissions with respect to the same. However, HUL has presented detailed submissions which evidences that no price suppression/depression has occurred during the POI. HUL thus submits that the depressing or suppressing selling price of the Petitioners could not be attributed to the price of the subject imports, whose alleged effect should have significant, as opposed to the non-existent effect in the present factual matrix.

- xii. The Petitioners have not provided any post-POI data with respect to inventory level in the Subject Countries, nor have they made any substantiated submissions with respect to the same.
- xiii. Vide para 75 of the Petition, Petitioners stated that there was significant dumping of the PUC in the domestic market in earlier investigations. However, it is submitted that the mere existence of dumping in previous investigations is not the crux of a SSR and there must be explicit evidence of an increase of dumped imports into India. The Petitioners have failed to conclusively prove a likelihood of recurrence or continuation of dumping of Subject Countries' imports, as highlighted in earlier submissions. Even if a likelihood of continued dumped imports is assumed (but not conceded), it is evident that the dumping in the injury period has absolutely no causal link to the performance of the Petitioners.
- xiv. There is no current dumping nor is there any likelihood of dumping in the future. The absence of current injury is a robust indicator that the injury is not likely to recur. It has been the opinion of the Authority in recent sunset reviews that even the existence of dumping is not enough when the same has not caused any material injury to the domestic industry. The same position emerges from various recently concluded investigations included caustic soda from Japan and Qatar in the sunset review final findings dated 10.01.2018 and Nylon Filament Yarn from China PR, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand and Korea RP in the sunset review final findings dated 05.01.2018.
- xv. In view of the above, it is submitted that the petitioners have failed to demonstrate any likelihood of injury in the absence of anti-dumping duties. The petitioners have also admitted that imports from the subject countries have not caused them any injury.

Examination by the Authority

87. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the AD Rules. While considering the likelihood aspect under clause (vii) of Annexure II to the AD Rules, the Authority considered, inter alia, the following factors:

1. Present and continued imports

88. The Authority has undertaken analysis of the volume of imports of the subject goods into India from the subject countries during the injury period and post-POI period as well. The Authority notes that the volume of the imports from subject countries into India registered decline from 62,355 MT in the base year to 51,668 MT during the POI (A). The authority also notes that the import from subject countries have however increased to 2,20,791 MT in the post-POI period (October 2017 to September 2018). As established in earlier sections, the performance of the domestic industry improved in terms of production, sales volumes, market share, profit, cash profit, return on capital employed and inventory during the POI as compared to the base year. The domestic industry has also admitted in its submissions that it was not suffering injury during the injury investigation period. Selling price of the domestic industry has increased over the injury period and remains much higher than the cost of sales despite cost associated with addition of capacities. Despite present dumping, the domestic industry suffered no injury from imports of the subject goods. Further, subject imports only comprised 1.6% of the total demand in India during the POI (A). All these factors show that the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury is not established in the present case.

2. Surplus Capacities

89. This parameter for ascertaining the threat of material injury requires evaluation of existing surplus capacities and capacity addition, if any, to explore the possibility of diversion of disposable quantity to Indian market. Domestic industry has claimed that the producers in subject countries are already

faced with significant surplus capacities and that these producers are exporting the product to a large number of countries, a very significant proportion of which is being exported at a price below the prices in respect of India, thus showing likelihood of diversion of these exports to India in the event of withdrawal of anti-dumping duty.

90. While participating producers/exporters and other interested parties have not provided any evidence and information with regard to existing surplus capacities, the domestic industry has furnished information from IHS Chemical journal and extracts from the annual report of certain producers in subject countries providing data/statements regarding Soda Ash manufacturing in the subject countries viz. existing capacity, existing production, unutilized capacity, capacity expansion, investments, etc. The information provided by domestic industry shows that there has been an expansion of capacity in subject countries. IHS Chemical Report extracts provided by the domestic industry shows that producers in Turkey are expanding capacities by around 25 Lakhs MT from July, 2018 to December, 2019 to cater to the global demand. However, it is not established that any such alleged surplus capacities in subject countries shall be diverted to India if anti-dumping duties were to be revoked.

3. Price Attractiveness

91. The domestic industry has provided Turkey Customs data in respect of exports by Turkey to rest of the world. WTA data is not available for post POI period. However, for the POI, the WTA export data from Turkey to the rest of the world (aggregate data as well as segregated data in regard to below-India price exports) is as under:

Export to rest of world--Volume	Unit	POI Annualised	POI Annualised (As per WTA Data)	Post POI (Oct 2017-Sept 2018)
Total	MT	1,393,227	16,06,891	26,60,570
Price lower than India	MT	900,547	10,64,490	20,97,451
Price Higher than India		492,680	5,42,401	563,119
Export to rest of world-Price				
Total	\$/MT	181	180	176
Price lower than India	\$/MT	170	171	171
Price Higher than India	\$/MT	200	199	193

92. The domestic industry has claimed that exports from Turkey to world has increased significantly in post POI (Oct., 2017 to Sept' 2018) as compared to POI. They have submitted that exports from Turkey to world during the POI was 13,93,227 MT which increased to 26,60,570 MT in the post POI. They have further claimed that significant exports to rest of the world have been made at price lower than average price to India and that out of 26,60,570 MT of exports made by Turkey to rest of the world, 20,97,451 MT, i.e., almost 79% of exports have been made at price below the average price at which goods have been exported to India. The total demand in the country is to the 32,79,345 MT in the POI.

4. Price suppression and Price depression

93. The cost of sales of the domestic industry is claimed to have increased in the post-POI period (October 2017-March 2018) by 11% as compared to POI whereas selling price of DI during the same period increased by 3% only. However, it is also observed that the selling price of the domestic industry during POI has been much higher than its cost of sales.

5. Level of inventories

94. The level of inventories available with the producers in subject countries could not be ascertained in view of lack of sufficient cooperation.

6. Level of current margin

95. The Authority notes that dumping margin in the original investigation was positive. In the present sunset review, dumping margin is positive during the POI for imports from the subject countries.

96. However, after overall assessment of all parameters, the Authority holds that there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in case anti-dumping duties are revoked.

S. POST DISCLOSURE COMMENTS**Submissions made by the Petitioners**

97. Following submissions have been made by the Petitioners:

- i. Non-confidential version of the communications sent by the Authority, copy of the replies and submissions filed by the interested parties, and the normal value be disclosed in order to enable them to come to a meaningful conclusion.
- ii. Market share of subject imports declined to 0.8% and then again increased to 1.6% in the POI. With increase in imports post POI, the market share has increased further.
- iii. Import volumes declined till 2015-16 and increased significantly thereafter in the POI. Imports increased by almost 100%. Further, imports increased very significantly in the post-POI period after commencement of operation of additional capacities in Turkey.
- iv. Subject imports have started having suppressing effect on the prices of the domestic industry during the last six months of the POI. Even if there is no suppression/depression on overall basis over the injury period, the fact that the imports have started having suppressing/depressing effect is clearly indicative of the likely situation. Petitioners further submit that the end of POI situation is all the more important than overall situation particularly when the trend in the post POI shows a worsening position.
- v. Whereas the domestic industry's capacity increased by 37%, production increased only by 18% and sales increased only by 16%.
- vi. Even though the domestic industry is earning profit, it declined in the POI as compared to the previous year. Profits declined by almost 50 % in the last six months of POI as compared with 2016-17. The end of POI situation is more important than overall situation particularly when the trend in the post POI shows a worsening position.
- vii. Even though there is no current injury, performance of the domestic industry within the POI shows vulnerability of the domestic industry, which is a very important and relevant parameter for likelihood determination.
- viii. In regard to level of inventories available with the producers in subject countries, adverse inference is required to be drawn against the exporters in view of lack of sufficient cooperation.
- ix. Even if inventory levels are low, the same is immaterial, as the Turkish producers are exporting about 81% of Indian demand to third countries market at lower price and this volume is sufficient enough to cause injury.
- x. The Authority has rightly held that the petitioners satisfy the requirement of standing under the AD rules. Thus, the petitioners form eligible domestic industry.

- xi. The Authority rightly accepted the confidentiality claims of the domestic industry. However, petitioners believe that the foreign producers have resorted to excessive confidentiality.
- xii. In respect of non-cooperating producers/ exporters from Turkey, the dumping margins are very significant. The dumping margins for exporters from Turkey and Russia have increased as compared to the original investigation and mid-term review investigation. Dumping by these producers has in fact intensified.
- xiii. The domestic industry reiterates that transportation cost/freight cost should be considered while examining price undercutting and injury margin for the following reasons:
 - a) Transportation cost forms a very substantial portion of the cost of production in case of subject goods as production takes place mainly in Gujarat (due to availability of raw material) whereas sales have to be made throughout India.
 - b) The subject goods are a comparatively lower price product. Thus, the incidence of transportation cost per MT of the product works out to be very substantial when compared with the selling price of the product.
 - c) The issue of freight is very unfortunately wrongly being linked to NIP. This as an issue of fair comparison for injury margin.
- xiv. Demand has increased steadily throughout the injury investigation period. Anticipating the increase in demand for the PUC in India, the domestic industry has undertaken significant capacity addition.
- xv. The import price has declined significantly in the present POI whereas the cost of production increased globally. As the import price declined in H1, 2017-18, the import volumes increased significantly, showing 370% increase in imports as compared to 2016-17.
- xvi. The import volumes will increase further, given the kind of capacities that have been commercialized by the Turkish producers and the remaining capacities that shall be commercialized in future.
- xvii. Market share of the subject imports has increased in the POI. Nonetheless, what is to be seen is the likely effect of the imports on the market share in case the current duty is allowed to cease.
- xviii. The Authority may kindly consider only those transactions that were, in fact, undercutting the prices of the domestic industry while examining price undercutting as that alone will show the extent of actual undercutting.
- xix. The domestic industry's cost of production declined till 2016-17 and then increased thereafter in the last six months of the present investigation period; whereas selling price increased till 2015-16 and then declined thereafter in the POI. Import prices have also declined in the last six months of the POI. Thus, imports have started having suppressing effect on the domestic industry's prices during the last six months of the POI.
- xx. While investments of Rs. 3,225 crores have already been made, further investments of Rs. 10,000 crores are being planned. The impact of possible cessation of ADD on these investments should be considered while undertaking injury analysis. The likely effect on these investments in the event of cessation of duty would be significantly adverse.
- xxi. Interest and depreciation costs have declined despite increase in capacity. Thus, increase in capacity is not the reason for decline in profits. The profits have declined because of decline in import price from Turkey and increase in such dumped imports from Turkey.

- xxii. Thus, if the domestic industry has earned good profits, the same is only because of investments made by the domestic industry. As far as new investments are concerned, the domestic industry is likely to achieve a meagre ROI if the domestic industry maintains the current level of price and cost structures. However, post cessation of anti-dumping duty, the domestic industry is likely to reduce these prices, leading to further decline in ROI.
- xxiii. With expansion of capacities in the subject countries the market share of these countries has started showing increasing trend, even in the presence of anti-dumping duty. The market share of the petitioners has remained about the same while that of the other Indian producers shows a decline.
- xxiv. The average inventory of the petitioning domestic industry has increased very significantly in the POI, having almost doubled.
- xxv. Though wages have shown improvement in the injury period, employment and wages are not solely dependent on the subject goods performance. They are not reflective of the adverse effects of the dumping on the domestic industry, as these factors are governed by overall operations of the company and the economy.
- xxvi. The growth of the domestic industry in terms of production and domestic sales volume was positive. However, growth in terms of profits and return on investment was positive only till 2015-16 and became negative in the POI.
- xxvii. The parameters analysed by the Authority clearly establishes likelihood of continuation of dumping and recurrence of injury as can be seen below:
- a. The volume of subject imports has increased from 51,668 MT in the POI (Annualised) to 2,20,791 MT in the post-POI period which means an increase of 327%.
 - b. There has been significant expansion of capacity of producers in Russia and Turkey.
 - c. The Turkish producers are exporting about 81% of Indian demand in third countries market at lower price. If this volume is diverted to India even at the prices at which Turkey is currently exporting goods to India, the domestic industry will incur losses.
 - d. The domestic industry's cost of sales has increased in the post-POI period (October 2017-March 2018) by 11% as compared to the POI whereas the domestic industry's selling price during the same period increased by 3% only. Thus, imports have started having suppressing and depressing effects on the prices of the domestic industry.
 - e. Majority of exports made from the subject countries to third countries are both at significantly dumped and injurious prices.
 - f. Global expansion of capacities is further threatening to cause increased imports into the domestic market with positive demand. Further, there is huge demand supply gap globally which indicates that exports are likely to get diverted to the Indian market in view of its consistent growing demand.
 - g. Price undercutting without anti-dumping duty is positive and significant. Thus, it is evident that if anti-dumping duties are withdrawn at this premature stage, the imports would cause significant price undercutting which would cause injury to the Domestic Industry.
 - h. The Indian market is highly price sensitive. Availability of such low-priced imports from subject countries in the market is definitely causing an adverse impact on the domestic industry

- i. In a situation where significant exports of the PUC from the subject countries to the rest of the world are below the domestic industry's selling price and export price from subject countries to India, the Authority is required to examine whether diversion of these low-priced exports to India is likely to cause injury to the domestic industry post cessation of anti-dumping duty.
- xxviii. Exporters are highly export oriented. Further there is a global demand supply gap which is further threatening increased imports into the domestic market with positive demand.
- xxix. There is definite likelihood of intensified imports in case existing anti-dumping duty ceases to exist.
- xxx. Anti-dumping duty should be imposed only as fixed quantum of anti-dumping duty expressed as US\$/MT.

Submissions made by other interested parties

98. Following submissions have been made by other interested parties:

- i. As per the UN Comtrade statistical data, exports of soda ash from the Russian Federation to India during the investigation period (April 2016 – September 2017) were only 2.8% of the total soda ash imported by India during that period. Such low import volumes from the Russian Federation should be regarded as insignificant in accordance with the provisions of Art. 5.8 of the AD Agreement, as the imports from the Russian Federation did not exceed 3% of the total amount of imports of Soda Ash to India. Such low imports cannot be considered as dumped under the provisions of Art. 2.1 of the AD Agreement.
- ii. The Russian Federation supports the opinion of the investigating body about the lack of injury to the domestic industry under the provisions of Art. 3 of the AD Agreement as there are stable positive dynamics of production and economic indicators of the domestic industry of India over the last few years.
- iii. During the period 2014 to 2017 (including the investigation period), the situation of the industry improved. The Russian side believes that there is no injury to the domestic industry under provisions of Art. 3.4 and 3.5 of the AD Agreement.
- iv. There is lack of evidence regarding any dumping and threat of resumed injury to the domestic industry. Thus, anti-dumping duty should be immediately cancelled under Art. 11.2 of the AD Agreement.
- v. There is no causal link between goods imported from the Russian Federation and expected injury to the domestic industry of India under provisions of Art. 3.4 of the AD Agreement, because the import volume of the goods originating from the Russian Federation were insignificant - during the investigation period it amounted to 2.8% of the total amount of imports of soda ash to India. Further, profitability of the domestic industry of India during the investigation period, as well as in 2014-15 and 2015-16 was more than twice higher than similar indicators of 2013-14, which confirms the lack of injury to the domestic industry of India and contradicts the assumption of resumed injury in case of cancellation of the current anti-dumping measure.
- vi. Considering the above, the anti-dumping measure against the Russian Federation should be cancelled in accordance with the provisions of Art. 11.1 of the AD Agreement.
- vii. It is apparent that the domestic industry has filed data on record for the post POI period in a partial and haphazard manner. Post POI data has not been made available in a consolidated manner to Soda Sanayii, Hindustan Unilever Limited and other interested parties. Non-

- provision of critical information is in violation of the obligation to disclose all essential facts and also in violation of the principles of natural justice. This is in clear breach of the judgment by the Hon'ble High Court of Gujarat in *Nirma Ltd. v. Union of India*, 2017 (358) ELT 0146 Guj.
- viii. Post POI data has been used partially and in favour of the petitioners. Only import volume has been disclosed for the post POI period, but there is no information on profitability, ROCE and other key performance parameters of the petitioners for the post POI period.
 - ix. Petitioners have not substantiated that dumping and injury are likely to continue or recur if anti-dumping duty were to be revoked. There is no substantial information in the disclosure statement regarding likelihood of recurrence of injury on account of dumped imports from Russia. The Authority should allow the duty against Russia to expire.
 - x. It is unclear whether the Authority has investigated why there was a sudden surge in imports during the post POI period, particularly when duties continue to be in force. There is no analysis of the impact of these increase imports on the domestic industry. There is no analysis whether the increased volume of imports in the post POI was at dumped prices.
 - xi. There is no adverse impact on the performance of the petitioners as per the data on record. There is no causal link between alleged injury suffered and subject imports.
 - xii. The Authority is requested to make available IHS Chemical report in non-confidential manner to the interested parties including Soda Sanayii. The expanding capacities in Turkey for most part of July 2018 to December 2019 is a projection and not existing capacities or data pertaining to the POI or post POI. Mere forecast of expansion of capacities or existence of surplus capacity does not mean that the additional capacity will be utilised towards exports to India.
 - xiii. Even independent analysis of the market indicates that any additional capacity in Turkey is likely to be offset by rapidly growing demand.
 - xiv. The difference in price between Turkey's exports to third countries and to India is significant due to which the presence or absence of the anti-dumping duty would have no effect. As observed from page 84 of the petition, Turkey's export prices to third countries are already much lower than its price to India even after incorporating the presently levied anti-dumping duty.
 - xv. Petitioners have failed to provide information on price suppression, price depression and level of inventories. The Authority has not provided information on post POI data/trend for the factors relevant for determining price suppression or depression. Interested parties have been deprived of an opportunity to provide meaningful comments on the same.
 - xvi. Even assuming there is continued dumping, there is lack of material injury or continued injury to the domestic industry – thus proving that even if dumping continues, the domestic industry will not be injured.
 - xvii. Other than GHCL and Rohit Surfactants, even Nirma and Tata Chemicals have initiated substantial expansions in their capacities for the product under consideration. It seems counterintuitive to invest substantial capital into the production of the PUC if there is a serious likelihood of recurring injury from dumped imports. This is clearly indicative of the fact that the domestic industry is prospering in India, and there is no likelihood or threat of recurring injury from dumped imports in the foreseeable future.
 - xviii. In respect of normal value for M/s. Soda Sanayii A.S., Turkey (Producer/Exporter), at paragraph no. 31 of the Disclosure Statement, the Authority has noted that it has taken into

- consideration the sales made only to unrelated customers for arriving at normal value. The Authority noted that the prices to related customers were lower than the prices to unrelated customers. In response, Soda Sanayii submits that, even if the prices to the related customers are lower than the prices to unrelated customers, the sales to such related customers have been made in the ordinary course of trade. Therefore, the Authority must consider both, sales made to related/affiliated and unrelated/unaffiliated customers in the domestic market of Turkey as reported in Appendix 4A and 4B (CONFIDENTIAL) of the questionnaire response filed by Soda Sanayii while calculating the normal value.
- xix. In respect of the observation made by the Authority on cost of production, and profitable sales in the confidential version of “Dumping Margin Calculation – Soda Sanayii - Turkey”, Soda Sanayii submits that it agrees with the same. Accordingly, the same may be recorded in the final findings.
- xx. In respect of foreign exchange gain/loss and billing adjustment as part of post factory expenses claims made by Soda Sanayii in the Appendix 4A and 4B (details of domestic sales), it is submitted that the Authority has not considered the claims as made by Soda Sanayii. The Authority is requested to take into consideration the said expense claims made by Soda Sanayii and determine the normal value accordingly.
- xxi. While determining the export price, according to paragraph no. 38 of the Disclosure Statement, the Authority has made adjustments only towards inland freight, credit cost, handling expenses, commission, insurance and overseas freight and rejected foreign exchange gain/loss. Soda Sanayii requests the Authority to take into consideration the foreign exchange/loss while making adjustments and re-determine export price accordingly.
- xxii. Soda Sanayii submits that the Authority has determined dumping margin combining the sales and costs for both forms of PUC i.e. Soda Ash Dense and Soda Ash Light. In this behalf, Soda Sanayii submits that, it has exported only Soda Ash Dense to India during the POI, whereas it has sold both, Soda Ash Dense and Soda Ash Light in its domestic market. Further, Soda Sanayii submits that it has provided the data for the sales and cost separately for both the grades of PUC. It may be noted that there is substantial price difference between both the grades of the PUC. In view of the same, the Authority is requested to determine margin of dumping for Soda Sanayii based on the domestic sales of Soda Ash Dense only for the purpose of fair comparison of the prices.
- xxiii. As per the confidential normal value calculation provided by the Authority, it can be seen that the Authority has considered the average exchange rate of TL (Turkish Lira) to USD at 0.31USD/TL. In this regard, Soda Sanayii submits that, the Turkish Lira has substantially fluctuated during the POI and considering an average exchange rate for the entire POI, will not depict the fair picture of the actual prices realized by Soda Sanayii. In view of the same, the Authority is requested to consider the daily exchange rate for each of the transaction for both domestic sales and exports to India.
- xxiv. Soda Sanayii agrees with the Authority’s observation made at paragraph no. 77 of the Disclosure Statement that the domestic industry’s performance improved in production, sales volume, market share, profit, cash profit, return on capital employed and inventory in POI in comparison to base year. Accordingly, Soda Sanayii requests the Authority to record the same vide its final findings.
- xxv. The Authority is requested to conclude that there is no material injury in the period assessed; injury, if any, is self-inflicted; there is no continued injury; there is no evidence on record that establishes a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury if duties are

- terminated; and accordingly, the Authority may kindly terminate the investigation. If at all duties must be continued, the lesser duty rule should be duly observed.
- xxvi. Pursuant to the orders of the Hon'ble High Court of Gujarat, the Director General of Trade Remedies initiated the present sunset review investigation. It is hereby submitted that with the same situation, same period of investigation, the judgment of the Authority cannot be ignored altogether. Earlier examination of the Authority may be relied upon in the present investigation that there is no injury to the domestic industry and the anti-dumping duty has served its purpose.
- xxvii. Imports from the subject countries are not causing any injury to the domestic industry. The average profit of the domestic industry was 41% of cost of sales during the POI, which was way above the one (i.e. 5%) permitted by the Director General while constructing normal value in an anti-dumping investigation. The ROCE of petitioner is 29% of NFA during POI whereas the Director General allows 22% while computing NIP in all anti-dumping cases. Therefore, there is no existence of injury to the domestic industry and thus question of its continuation does not arise.
- xxviii. It is hereby submitted that anti-dumping duty is not perpetual in nature and considering the facts of the case, there does not exist any special/exceptional circumstances calling for continuance of anti-dumping duty on the subject goods from subject countries. Thus, in view of the above, the anti-dumping duty shall not to be continued and present investigation should be terminated on the same grounds.
- xxix. From the disclosure statement, it is clear that there was no injury to the domestic industry during the POI and thus, present investigation should be terminated.
- xxx. A comparative analysis of the facts established in the sunset review final findings dated 14th December, 2018 concerning China PR, the EU, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA with the facts disclosed in the present disclosure statement dated 8th February, 2019 in respect of the present investigation establish that anti-dumping duty should not be continued and the investigation should be terminated on this ground.
- xxxi. In the last three years, on many occasions, the Director General has found that there is no injury and no likelihood of recurrence of injury due to imports of Soda Ash from Turkey and Russia; and imports of Soda Ash from China PR, the EU, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA. Considering all the various final findings and the present disclosure statement, it is clear that anti-dumping duty has served its purpose and there is no injury to the domestic industry. The domestic industry is making bumper profits as shown in their annual reports and as per the above final findings.
- xxxii. Joint Stock Company<<Bashkir Soda Company>> has not increased its capacity by 50% as has been claimed by the petitioners. Joint Stock Company<<Bashkir Soda Company>> and OJSC operate on a high rate and don't have further plans to expand capacities in the nearest future. Trade House Ltd. <<Bashkirian Soda Company>> sells 90% of Soda Ash in Russia CIS market and does not have free volumes and resources for export expansion.
- xxxiii. Basis of 22% ROCE was designed in the year 1987, when all parameters like interest rate and corporate tax were different, those cannot be termed as reasonable after 30 years in the year 2018. In 1987, the rate of interest was around 18% and corporate tax was 40%. Now both, interest rate around 10% and corporate tax (30%) have come down. Therefore, it is submitted that the DGTR is giving undue protection to the domestic industry by applying 22% ROCE to determine NIP. In *Bridge Stone Tyre Manufacturing & others v. Designated Authority*, 2011 (270) ELT 696 (Tri-Del.), the Hon'ble CESTAT has observed that the practice of 22% ROCE

adopted by the Designated Authority was not correct as calculating the NIP by assuming such a high rate of return gives an inflated picture of price underselling. The EU practice establishes that the profit margin allowed by an investigating authority to the domestic industry should be the amount of profit that the domestic industry could reasonably count on under normal conditions of competition, in the absence of dumped imports. Adoption of 22% profit margin based on some hypothetical considerations is totally illogical and cannot be termed as reasonable.

- xxxiv. M/s Saint Gobain India Pvt. Ltd. is one of the major users of soda ash in the country. The current anti-dumping duties on imports of soda ash from Turkey and Russia are not justified and ought to be withdrawn as early as possible.
- xxxv. The Petitioners have intentionally not included profitable Indian producers in the petition. In the original investigation, four Indian producers comprised of domestic industry but in the present sunset review, only two Indian producers comprise as domestic industry.
- xxxvi. The Petitioners have intentionally not included Tata Chemicals as domestic industry on the logic that Tata Chemicals has a related producer in Kenya. The same logic should be applied to M/s Nirma Ltd., one of the Petitioners, as it has a related producer in USA.
- xxxvii. The domestic industry has admitted it is not suffering injury on account of the alleged dumped imports from the subject country. This fact also finds mention in the disclosure statement.
- xxxviii. The Authority's order dated 5.4.2018 demonstrates clearly that the domestic industry has been earning whopping profits to the tune of 58% (by Nirma Ltd.) and around 29% ROCE. Further, the Authority after considering all the facts and circumstances on record stated that there was no likelihood of injury to the domestic industry. The said observation of the Authority still holds true as there is no likelihood of any injury to the domestic producers even after withdrawal of the anti-dumping duties, as is evident from the disclosure statement.
- xxxix. It is a known fact that the selling prices of the subject goods in India are governed by the prices determined by the domestic producers. While the cost of sales of the domestic industry decreased by 15%, the selling price of domestic producers increased by around 7% during the POI.
- xl. The production of the domestic industry has increased by 18%. While capacity utilisation has marginally decreased, the same is solely on account of increase in the capacities of the domestic industry.
- xli. The domestic sales of the domestic industry increased by 16%, captive transfer increased by 70% and domestic sales value increased by 25%.
- xl.ii. Profit per unit of the domestic industry increased by 193%. Total profits increased by 241%. ROI on GFA basis increased by 41% and ROI on NFA basis increased by 62%. ROCE of the domestic industry increased by 67%. The share of imports from the subject countries decreased despite overall increase in demand.
- xl.iii. It is important to mention that soda ash has none or extremely low dependency on imported raw material. In effect, while the domestic producers enjoy the benefits of devalued Rupee in terms of the increased landed value, there is no effect on their costs due to the fact that domestic producers are using raw material which is abundantly available in India itself.
- xl. iv. It is reiterated that the soda ash industry will continue to reap the advantage of local raw material and import parity pricing with the increased value of Rupee. It is also a matter of fact

- that the Rupee has been over Rs. 65 per USD since 2016 which clearly establishes beyond an iota of doubt that there is no reason for continued imposition of the anti-dumping duties.
- xliv. The Authority should examine parameters related to threat of material injury for the purpose of likelihood examination in the present review. This is consistent with the judgment of the Hon'ble High Court of Gujarat in *Nirma Ltd. v. Union of India*, judgment dated 23.02.2017.
 - xlvi. The imports of the subject goods declined from 62,103 MT in the base year to 51,668 MT in the POI(A). Even though the disclosure statement states that the volume of imports in the post POI period has increased, the same cannot be seen in alienation but has to be seen in light of the increase in demand of the subject goods. It is a known position that the demand of the subject goods has steeply increased in the past. This is the precise reason why the domestic industry kept on increasing its capacity throughout the injury investigation period.
 - xlvi. Mere existence of excess or idle capacity cannot lead to the conclusion that the likelihood of dumping or injury to the domestic industry is imminent. It is important to note that the domestic industry is admittedly doing well despite the existence of capacities elsewhere in the world. Thus, the domestic industry has failed to make out a case with regard to surplus capacity.
 - xlvi. The petition does not make any claim as regards inventories and no material has been presented to establish the same. It is clear from the above that there is no likelihood of recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.
 - xlix. All India Glass Manufacturers Federation ("AIGMF") is a responding interested party in this investigation and its submissions should be recorded and examined in the Final Findings.
 - 1. The Petitioners only technically satisfy the requirement of standing under Rule 2(b). However, injury data from only two producers grossly distorts and undermines the examination of injury and likelihood examination. Large profitable producers like GHCL have not been included in the petition, which has vitiated the injury information. The petition could not satisfy the requirements of Rule 2(b) in its actual meaning and thus, the examination of injury does not meet the essential standard set by the WTO in *Russia – ADD on LCV from Germany and Italy*.
 - li. AIGMF requests the Authority to rule that the data submitted by the petitioners is not representative of the factual economic position of the domestic industry concerning soda ash and they do not have standing to be treated as domestic industry as envisaged under Rule 2(b) of the AD Rules.
 - lii. Since the performance of DI on various injury parameters is very strong, the dumping figures are of no consequential effects.
 - liii. Imports from subject countries declined significantly over the years whereas the landed price of imports did not decrease. This shows that dumping was not followed as any means to export more volume to India.
 - liv. Had there been any exportable excess capacity available with the exporters which will be predictably diverted to India in the event of expiry of existing AD duties, the position of imports during the injury period would have been different. Such trend would have clearly reflected in the trend of import even though AD duties are in force and this point may kindly be considered by the Authority. Also, the post POI imports to India is not adduced and considered in the Disclosure Statement.
 - lv. A minor decline in capacity utilization over the base year should be seen considering the significant capacity additions made during the injury period. In fact, imports declined

significantly by about 10,687 MT in the POI vis-a-vis the base year whereas the landed price remained stable. The NSR of the DI increased over the years whereas the COP declined significantly leading to very high profits. This shows the DI is enjoying strong pricing power and in fact, the pricing behaviour is highly monopolistic. The imports are, thus, not creating any adverse effect on the price or volume of the DI. This is when dumping margin is claimed to be positive. The positive price undercutting is only on paper and such positive PU is the result of very high price charged by the DI. The Authority may conclude that landed price of imports did not create any adverse effects on the DI nor there is any likely injury from such imports in the future even if the duties are allowed to expire.

- lvi. Profitability of the DI moved from 100 basis point in the base year to 293 points in the POI and ROCE moved from 100 basis points in the base year to 177 points in the POI. Such increases should be seen as commendable growth. In fact, in a recent fresh matter concerning DMF, the Authority found no duty is warranted to be imposed when the profitability moved from 100 points in the base year to 15 points in the POI with less than 6% ROCE in the POI. Any continuation of duty in the facts of the present case is clearly not warranted when such yardsticks are applied.
- lvii. The ROCE earned by the DI though declined in the POI over the previous years on the trend line, the actual ROCE percentage still remains high rendering the fall in trend deceptive and meaningless. The Authority permits 22% ROCE for the purpose of NIP and in our understanding, the DI is earning an average ROCE in the range of 25% to 35%. These levels of ROCE and profit margin clearly show levels of profits earned by the DI. The DI is in no way vulnerable to further injury.
- lviii. The petitioner has relied upon WTA data to say that the exportability from Turkey is high. But the claims are flawed. The contention of the petitioner is that the export from Turkey to rest of the world doubled in the post POI and significant part of it is at a price lower than India. However, it needs to be noted that when Turkey was exporting more than 13 Lakh MT in POI as per the claim of the petitioner itself, their exports to India reduced from a 62,000 MT level in the base year to about 34,000 MT level and the landed prices also increased by about 2% over the base year. Thus, Turkey's export to India when they were exporting 13 Lakhs tons was continuously reducing with an increase in price. This shows that the claim of the petitioner that there is probability of increased export from Turkey has no truth. Turkish exporters enjoy larger favourable market elsewhere which is evident from the fact that exports from Turkey declined significantly and the prices were increasing. Also, the petitioner has not provided post POI export from Turkey to India. Also, the performance of the DI, as can be seen from published details of DCW (petitioner) and other companies, clearly show strong performance even in the post POI period. There is no adverse effect of imports taking place in the post POI period also on DI which conclusively rules out any likelihood of injury in the event of expiry of duties as well. AIGMF requests the Authority not to recommend continuation of anti-dumping duties on imports of subject goods from subject countries.
- lix. Detergent Manufacturers Association of India (DMAI) agrees with the Authority's fact finding in paragraph 63 of the disclosure statement that the cost of sales of the domestic industry decreased during the POI (A) as compared to the base year. Further, the Designated Authority is correct in finding that the selling price of the domestic industry also increased during the injury period. This shows that the selling price of the domestic industry moved independent of the landed price of imports of the subject goods and continued to increase during the POI as mentioned by us in our earlier submissions and explained again in the subsequent paragraphs.

- lx. Imports of the subject goods decreased even though there was a sharp gap in demand and supply of the subject goods in India. Cost of sales of the domestic industry declined from 100 indexed units to 85 indexed units during the injury period. Selling price of the domestic industry continuously increased during the injury period from 100 indexed units to 107 indexed units. The data on record does not show that the domestic industry was forced to lower its prices during the injury period. In fact, from the disclosure statement, we understand that the selling price of the domestic industry was significantly higher than the landed value of imports of the subject goods as well as the non-injurious price of the domestic industry. As a result, profitability of the domestic industry increased almost three-times during the POI (A) when compared with the base year 2013-14. The claim of the domestic industry in paragraph 90 of the disclosure statement is incorrect that its cost of sales during post-POI period increased by 11% but selling price increased only by 3%. It is impossible for cost of sales to increase by 11% during post-POI period. We further submit that the selling price of the domestic industry rather increased by more than 10% in the post-POI period. A detailed note in this regard is enclosed as Confidential Exhibit 1. We submit that any anti-dumping duty will only lead to imports of finished goods, i.e. detergents, to India, thereby adversely impacting the domestic detergent industry.
- lxi. The domestic industry also failed to establish that if anti-dumping duty were to be revoked, consumers would switch to imports of the subject goods. The subject goods have users in detergent as well as glass industry, which use the subject goods on a large scale. With Indian Rupee continuously depreciating against the US Dollar during the POI and post POI period, it had become more and more expensive to import the subject goods. The user industry in India will continue to rely on local supplies of the subject goods and import the subject goods only when there is a shortfall in supply.
- lxii. We understand that in paragraph 87 of the disclosure statement, the Designated Authority has relied on the information provided by the Petitioners regarding surplus capacities in the subject countries, which is based on data taken from IHS Chemical journal. In paragraphs 88 and 89 of the disclosure statement, the Designated Authority has relied on the information provided by the Petitioners regarding the volume of exports and prices of the subject goods from Turkey to rest of the world, which is based on data taken from World Trade Atlas ("WTA"). We submit that this approach is inconsistent with the ruling of the Hon'ble Supreme Court in Secretary (Revenue), GOI v. Dyestuffs Manufacturers Association of India, 2015 (322) ELT 3 (SC). In this case, the Hon'ble Supreme Court had confirmed the Hon'ble CESTAT's ruling that trade journals cannot be relied upon in anti-dumping investigations. In the light of the Hon'ble Supreme Court's judgment, we submit that the Designated Authority ought to disregard information based on IHS Chemical journal and WTA in this case.
- lxiii. We would like to draw the Designated Authority's attention to the judgment by the Hon'ble CESTAT in the Truck and Bus Tires case. In this case, the Hon'ble CESTAT had annulled the imposition of anti-dumping duty on the basis that the injury findings of the Designated Authority were flawed.
- lxiv. In the present case, the domestic sales of the domestic industry increased to 115 indexed points over the injury period. In case the price undercutting claimed had any actual detrimental impact, the Petitioners would not have been able to maintain their domestic sales or increase them. The mere fact that the Petitioners managed to expand their sales in India despite the alleged price undercutting demonstrates the absence of injury.
- lxv. We submit that if at any stage before the final findings, the Designated Authority revises the essential facts under consideration disclosed in the present disclosure statement including but

not limited to constructed normal value, ex-factory export price, dumping margin, methodology in arriving at the dumping margin, non-injurious price, landed value, price underselling/injury margin, price undercutting, price suppression, price depression, any parameters on volume effects and price effects of the domestic industry, injury determination, causal link examination, likelihood determination or any other observation in the disclosure statement dated 8 February 2019, DMAI requests the Designated Authority to inform about such changes in the essential facts under consideration pursuant to Rule 16 of the AD Rules and also provide it with an opportunity to comment on such changed essential facts under consideration.

Examination by the Authority

99. The examination of post-disclosure comments is as under:

- i. As regards the comments received from the Russian Federation on the disclosure statement, it is noted that the same were received by the Authority after the timeline stipulated in the disclosure statement. However, the Authority has taken a lenient view of this and has examined the comments of the Russian Federation.
- ii. As regards the submission that there was no price suppression and price depression because anti-dumping duty was in force during the injury period, it is observed that the Authority had conducted such analysis without addition of anti-dumping duty in the landed value of imports and still found no price suppression and price depression.
- iii. As regards the submission that due concern should be given to the submissions of the domestic industry, it is observed that the Authority has examined the submissions of the domestic industry and other interested parties and dealt with them at appropriate places in the present findings.
- iv. As regards the submission that transportation cost should be taken into account for determination of injury margin, it is noted that the Authority has determined NIP as per Annexure-III to the AD Rules and the comparison between NIP and the landed value for determination of injury margin has been done at the same level of trade as per the consistent practice of the directorate.
- v. As regards the submission that imports of the subject goods have increased in the post POI period and shall further increase in the event of cessation of anti-dumping duty, it is observed that analysis of economic parameters of the domestic industry do not show injury due to the dumped imports. Further, it is not established that injury is likely to continue or recur due to dumped imports if the anti-dumping duty on the subject goods were to be revoked.
- vi. As regards the submission that price undercutting is positive and significant for subject countries, it is observed that in a sunset review, price undercutting is not the only determinative factor. The Authority has holistically examined all the relevant economic parameters of the domestic industry for volume effects and price effects, as well as examined the dumping margin and injury margin in this case. The analysis indicates that the Petitioners have performed well financially during the injury period including the POI in terms of profit, ROCE, capacity expansion, production and sales. There is absence of price suppression and price depression. The Petitioners have not been able to establish that dumping caused injury or that injury is likely to continue or recur in the event anti-dumping duty were to be revoked on the subject goods. In fact, fresh capacities are added/ being added by Nirma, GHCL and other Indian producers, as has been admitted by the Petitioners. Petitioners have further conceded that capacity enhancements are being planned at this stage because the Indian market for the product has remained viable. ROCE of the Petitioners has remained high despite significant cost incurred in capacity expansion.

- vii. As regards the submission that the Authority has not carried out sufficient analysis on likelihood or recurrence of dumping and injury, it is observed that the Authority has carried out detailed analysis in this regard at appropriate places of the present findings.
- viii. As regards the submission that the Authority should consider the submissions filed by various interested parties, it is observed that the Authority has recorded such submissions and examined the same at appropriate places in the present findings.
- ix. As regards the submission that interested parties have not been provided with post POI data, it is observed that as per the procedure prescribed by the DGTR, interested parties can request for post POI import data. No interested party has approached the Authority with regard to procurement of post POI import data as per the prescribed procedure.

T. Conclusions and Recommendations

100. Having examined the contentions of various interested parties and on the basis of the above facts, circumstances, and analysis, the Authority concludes as under:
- i. The financial and economic parameters of Domestic Industry (both volume and price) are stable and not evidencing deterioration requiring continuation of anti-dumping duty.
 - ii. The Petitioners have performed well financially during the injury period including the POI in terms of profit, ROCE, capacity expansion, production and sales.
 - iii. There was no price suppression and price depression.
 - iv. The Petitioners have not been able to establish that dumping caused injury during the injury period.
 - v. The Petitioners have not been able to establish that dumping is causing injury or that the injury is likely to continue or recur in the event anti-dumping duty were to be revoked on the subject goods.
 - vi. The factors submitted by the Petitioners on likelihood of recurrence of injury on withdrawal of anti-dumping duty are not supported by the price realisations and price trends of the subject goods during the POI.
 - vii. Due to improvement in the performance of the Petitioners, fresh capacities are either added or being added by Nirma (one of the constituents of the domestic industry) and other Indian producers.
 - viii. ROCE of the Petitioners has remained high despite incurring significant cost in capacity expansion.
101. The Authority on account of the aforesaid concludes that continuation of anti-dumping duty is not warranted and hereby recommends no further extension of anti-dumping duty on the subject goods from the subject countries.

U. FURTHER PROCEDURE

102. An appeal against this notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the decision of the Hon'ble High Court of Delhi in M/s Jindal Poly Film Ltd. v. Designated Authority, W.P. (Civil) No. 8202/2017.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. and Director General.